राष्ट्रीय संस्करण

# दैनिक जागरण

वर्ष 3 अंक 220

मूल्य ₹6.00, नई दिल्ली, शुक्रवार, 17 जनवरी 2020

www.jagran.com

पृष्ठ 16

अमेरिका की तरह आतंकवाद से निपटना होगा : बिपिन रावत

>> 3

## सरोकार

### 'पौधे वाली दीदी' बन सरिता ने बदल दी इलाके की सूरत

**लखीसराय** : बिहार के लखीसराय जिले के नक्सल प्रभावित बंजर क्षेत्र कुंदर में

प्रकृति प्रेम की मिसाल बन चुकी हैं सरिता देवी। उन्होंने एक लाख से अधिक पौधे लगाकर इलाके की सूरत बदल दी है। लोग उन्हें पौधे वाली दीदी कह कर पुकारते है। (पेज-6)

## जागरण विशेष

### खूबसूरती में चार चांद लगा रहा फीलनगर का चुटीला

शाहजहांपुर : जुल्फों को संवारने का ढंग भले ही बदलता गया, लेकिन चुटीले

के चटख रंग आज भी लुभाते हैं। उप्र के शाहजहांपुर जिले में एक गांव ऐसा भी है, जिसकी पहचान ही इसी से है। करीब ढाई हजार लोग इसी रोजगार से जुड़े है। (पेज-15)

## न्यूज गैलरी

**नेशनल कैपिटल** ▶ पृष्ठ 2

### सीए की परीक्षा में नोएडा के सूर्यांश को देश में पहला स्थान

**नोएडा** : इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने चार्टर्ड अकांउटेंटेट (सीए) परीक्षा का नतीजा जारी कर दिया है। नोएडा के सूर्यांश अग्रवाल व कोलकाता के अभय बाजोरिया ने संयुक्त रूप से देश में पहला स्थान प्राप्त किया है।

**राज-नीति** ▶ पृष्ठ 4

### भाजपा में विलय के लिए हेमंत का साथ छोड़ेंगे मरांडी

**रांची** : झारखंड के सियासी घटनाक्रम में सबकी नजर झाविमो प्रमुख बाबूलाल मरांडी के रुख पर है। हालांकि भाजपा में विलय पर वह जवाब नहीं दे रहे हैं, लेकिन बताया जाता है कि वह हेमंत सरकार से समर्थन वापस लेकर भाजपा का दामन थामेंगे।

**बिजनेस** ▶ पृष्ठ 12

### पहली बार 42,000 को पार कर लौटा सेंसेक्स

**मुंबई** : अमेरिका-चीन में पहले चरण की कारोबारी सहमति पर हस्ताक्षर के चलते घरेलू शेयर बाजारों में निवेशकों ने खुलकर दांव लगाया। बीएसई का 30-शेयरों वाला प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स पहली बार 42,059.45 अंक तक गया।

**अंतरराष्ट्रीय** ▶ पृष्ठ 13

### मिखाइल मिशस्टीन बने रूस के नए प्रधानमंत्री

**मॉस्को** : रूस में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मजबूत सियासी पकड़ साबित करते हुए गुरुवार को पीएम पद के लिए मिखाइल मिशस्टीन का नाम प्रस्तावित किया, जिस पर पार्टी ने मुहर लगा दी। पुतिन की इच्छा पर बुधवार को पीएम दिमित्री मेदवेदेव ने मंत्रिपरिषद के साथ इस्तीफा दे दिया था।

**बराबरी का मुकाबला**

दूसरा वनडे
भारत vs ऑस्ट्रेलिया

दोपहर 1:30 बजे से
स्थान : राजकोट
प्रसारण : स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क

# कश्मीर पर मिला सभी बड़े देशों का साथ

**फिर मिली मात** ▶ सुरक्षा परिषद में मुद्दा उठाने की चीन और पाकिस्तान की कोशिश नाकाम

### भारत के साथ अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस, चीन पड़ गया अकेला

**जयप्रकाश रंजन, नई दिल्ली**

कश्मीर से अनुच्छेद-370 हटाने के फैसले को लेकर अंतरराष्ट्रीय जगत पर जो सुगबुगाहट हुई थी, भारत को उन पर कूटनीतिक सफलता मिलती दिख रही है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) के पांच स्थायी सदस्यों में से एक चीन को छोड़कर अन्य सभी देश कश्मीर मुद्दे पर भारत के साथ खड़े हो गए हैं। यहां तक कि ब्रिटेन में बोरिस जॉनसन की अगुआई वाली नई सरकार का रुख भी अब बदला हुआ है। उसने भी कश्मीर पर चीन और पाकिस्तान के प्रलाप को मानने से मना कर दिया है। अमेरिका और फ्रांस पहले की तरह अब भी भारत के साथ चट्टान की तरफ खड़े हैं। रूस भी अपने पारंपरिक मित्र भारत का साथ छोड़ने को तैयार नहीं है। जर्मनी जैसे बड़े देश भी चीन और पाक की चाल को बखूबी समझने लगे हैं। यही वजह है कि यूएनएससी में कश्मीर मुद्दा उठाने की चीन और पाक की कोशिशें फिर से नाकाम हो गई हैं।

विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक अगस्त, 2019 में अनुच्छेद 370 हटाने के तुरंत बाद ही चीन इस मुद्दे को लेकर यूएनएससी में गया था। उस समय बाकी चार स्थायी सदस्य देशों के रुख और अब इन देशों के रुख में काफी बदलाव आ गया है। भारत ने जिस तरह से पिछले तीन-चार महीनों में कश्मीर में शांति बहाल रखी है और अब धीरे-धीरे वहां हालात को सामान्य किया जा रहा है उससे विदेशी राजनयिकों को समझाने में काफी मदद मिली है। हाल ही में विदेशी राजनयिकों के दल को केंद्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर ले जाने का भी असर हुआ है। साथ ही जिस तरह से वैश्विक अस्थिरता का एक दौर चल रहा है उसमें कोई भी देश यह नहीं चाहता कि दक्षिण एशिया में तनाव और बढ़े।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार के मुताबिक, यूएनएससी के अधिकांश सदस्यों का यह कहना कि कश्मीर पर चर्चा करने के लिए यह उचित मंच नहीं है, अपने आप में भारत के पक्ष का समर्थन है। पाकिस्तान की तरफ से आधारहीन आरोप लगाने को दुनिया नहीं मान रही है। पाकिस्तान को शायद यह अब महसूस हो कि अगर भारत के साथ उसकी कोई समस्या है तो उसका समाधान द्विपक्षीय वार्ता से ही हो सकता है। हालांकि ऐसा लगता नहीं है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को अभी भी यह बात समझ में आ रही है। संयुक्त राष्ट्र में उनकी बात का समर्थन पुराने मित्र राष्ट्र चीन के अलावा और किसी ने नहीं किया, लेकिन फिर भी इमरान खान ने अपनी जनता के सामने हकीकत से उलट पक्ष पेश करने की कोशिश की।

उन्होंने यह दावा किया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में कश्मीर पर चर्चा हुई और वह उसका स्वागत करते हैं। यही नहीं उन्होंने यह भी कहा, 'परिषद ने यह मान लिया है कि कश्मीर एक गंभीर मुद्दा है जिसका समाधान परिषद के संबंधित प्रस्तावों और कश्मीरी जनता की इच्छा के मुताबिक होना चाहिए। पाकिस्तान कश्मीर की जनता को वैचारिक, राजनीतिक और कूटनीतिक मदद मुहैया कराता रहेगा।' हकीकत यह है कि यूएनएससी की जिस बैठक का वह दावा कर रहे हैं उसकी तरफ से न तो इसकी पुष्टि की गई है और न ही कोई बयान दिया गया है।

### इमरान को भी एससीओ सम्मेलन का न्योता देगा भारत

**नई दिल्ली, आइएएनएस** : भारत इस साल के आखिर में नई दिल्ली में होने वाले शंघाई

सहयोग संगठन (एससीओ) के शीर्ष सम्मेलन के लिए पाकिस्तान समेत सभी आठ सदस्य देशों, चार पर्यवेक्षक देशों और अन्य अंतरराष्ट्रीय वार्ता साझेदारों को न्योता देगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने गुरुवार को यह जानकारी दी। हालांकि निमंत्रण के बावजूद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के इस सम्मेलन में आने की संभावना नहीं है। इस्लामाबाद में उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया कि इमरान खान अपने स्थान पर सम्मेलन में किसी जूनियर मंत्री या विदेश मंत्री को भेज सकते हैं। इसकी वजह यह है कि बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद दोनों देशों के रिश्तों में आए तनाव के चलते उन्हें अपनी भारत यात्रा को जायज ठहरा पाना बेहद मुश्किल होगा। उल्लेखनीय है कि एससीओ में चीन, रूस, किर्गिस्तान, कजाखस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान सदस्य देश हैं। चीन की अध्यक्षता में 2001 में इस संगठन की स्थापना हुई थी और तीन साल पहले ही इसमें भारत और पाकिस्तान को शामिल किया गया है।

# एनपीआर के विरोध पर अलग-थलग पड़ा बंगाल

**नीलू रंजन, नई दिल्ली**

- सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और जनगणना निदेशकों की आज बैठक
- बंगाल को छोड़कर सभी राज्यों ने जताई बैठक में हिस्सा लेने पर सहमति

राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) के विरोध को लेकर बंगाल अलग-थलग पड़ गया है। जनगणना और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से बुलाई गई बैठक में शामिल होने के लिए बंगाल को छोड़कर सभी राज्यों ने सहमति दे दी है। बैठक में सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और जनगणना निदेशकों को बुलाया गया है। इसमें केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला और गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय मौजूद होंगे।

गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि शुक्रवार को बैठक के दौरान जनगणना के पहले चरण में मकानों की गणना और इसके साथ-साथ राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) के लिए आंकड़े जुटाने के तौर तरीकों के बारे में चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि बंगाल को छोड़कर अन्य सभी राज्यों ने बताया है कि उनके अधिकारी बैठक में भाग लेने के लिए दिल्ली आ रहे हैं। उल्लेखनीय है कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सार्वजनिक तौर पर घोषणा की है कि वह केंद्र सरकार की ओर से बुलाई गई इस बैठक में अपने अधिकारियों को नहीं भेजेंगी।

उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार नई दिल्ली में आयोजित इस बैठक में सभी राज्यों में जनगणना और एनपीआर के आंकड़े जुटाने के लिए समय निर्धारित करने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने कहा कि दरअसल, इसके लिए एक अप्रैल से 30 सितंबर तक का समय है, लेकिन हकीकत में किसी राज्य में सभी आंकड़े जुटाने में 40-45 दिन का समय लगता है। सभी राज्य अपनी-अपनी सुविधा के अनुसार एक अप्रैल से 30 सितंबर के बीच कोई भी 40-45 दिन का समय आंकड़े जुटाने के लिए तय कर सकते हैं। गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि कुछ राज्यों ने जनगणना और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर की प्रक्रिया को तय ही नहीं कर लिया है बल्कि इसके बारे में सूचित भी कर दिया है। उन्होंने कहा कि बाकी बचे राज्यों को भी इसे तय करने को कहा जाएगा।

साफ होगा रुख, दस्तावेज दिखाने का दबाव नहीं डाला जाना चाहिए पेज>>5

# अडानी एंटरप्राइजेज, एनसीसीएफ के तीन पूर्व अफसरों पर केस दर्ज

- कोयला आपूर्ति ठेका मामले में सीबीआइ ने धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए

**नई दिल्ली, प्रेट्र** : कोयला आपूर्ति ठेके में अनियमितता बरतने के मामले में सीबीआइ ने अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड और भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ लिमिटेड (एनसीसीएफ) के तीन पूर्व अधिकारियों के खिलाफ धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के आरोप में मामला दर्ज किया है। यह मामला आंध्र प्रदेश के बिजली उत्पादन प्लांट को कोयला आपूर्ति के लिए जारी निविदा के बाद कंपनी का चुनाव करने में अनियमितता से संबंधित है।

आंध्र प्रदेश विद्युत उत्पादन कारपोरेशन (एपीजीईएनसीओ) ने समुद्र के रास्ते आयात किए गए छह लाख मीट्रिक टन कोयले की आपूर्ति करने के लिए 29 जून 2010 को निविदा जारी की थी। चेन्नई, विशाखापत्तनम, कृष्णापत्तनम और काकीनाड़ा बंदरगाहों से विजयवाड़ा के नरला टाटा राव थर्मल पावर प्लांट और कड़पा के रायलसीमा थर्मल पावर प्लांट तक कोयला पहुंचाया जाना था। यह निविदा एनसीसीएफ समेत सात पीएसयू को भेजी गई थी।

सीबीआइ ने एनसीसीएफ के तत्कालीन चेयरमैन विरेंदर सिंह और तत्कालीन प्रबंध निदेशक जीपी गुप्ता और इसके वरिष्ठ सलाहकार एससी सिंघल के खिलाफ आपराधिक साजिश से संबंधित आइपीसी की विभिन्न धाराओं तथा भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के धोखाधड़ी से संबंधित प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया है। इन लोगों ने कथित रूप से दिशानिर्देशों का उल्लंघन कर अहमदाबाद की कंपनी का पक्ष लिया था। अडानी एंटरप्राइजेज ने भेजे गए सवाल का कोई उत्तर नहीं दिया है।

सीबीआइ ने आरोप लगाया है कि एनसीसीएफ अधिकारियों की गतिविधि एक सरकारी सेवक के लिए उचित नहीं है। उन्होंने कंपनी के साथ साजिश रची। एफआइआर में कहा गया है कि अधिकारियों ने बोली लगाने वालों का चुनाव करने में हेराफेरी कर अनियमितता बरती। अयोग्य ठहराए जाने के बावजूद अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड का अनुचित तरीके से पक्ष लिया।

# 'टेलीकॉम कंपनियां हफ्तेभर में चुकाएं 1.47 लाख करोड़'

**जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली**

- सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज की दूरसंचार कंपनियों की पुनर्विचार याचिका
- एयरटेल और वोडाफोन ने सुप्रीम कोर्ट से आदेश पर पुनर्विचार का आग्रह किया था

एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (एजीआर) मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी उम्मीदें लगाए बैठी टेलीकॉम कंपनियों को निराशा हाथ लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इस मामले में भारती एयरटेल तथा वोडाफोन आइडिया की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया। साथ ही यह साफ हो गया है कि इन कंपनियों को एक हफ्ते में करीब डेढ़ लाख करोड़ रुपये का भुगतान करना ही होगा। भारती एयरटेल व वोडाफोन आइडिया दोनों ने कोर्ट के फैसले पर निराशा जताते हुए क्यूरेटिव याचिका समेत अन्य कानूनी विकल्पों पर विचार करने की बात कही है।

एयरटेल ने कहा, हम कोर्ट के निर्णय का सम्मान करते हैं, पर हमारा मानना है कि एजीआर की परिभाषा पर चला आ रहा विवाद उचित था। बकाये का 75 फीसद हिस्सा ब्याज, जुर्माना व जुर्माने पर ब्याज का है। इस राशि का बेहतर उपयोग डिजिटल मिशन पूरा करने में हो सकता था। वोडाफोन ने कहा कंपनी क्यूरेटिव याचिका समेत अन्य कानूनी विकल्पों पर विचार कर रही है।

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले वर्ष 24 अक्टूबर को टेलीकॉम कंपनियों से सरकार को लाइसेंस फीस और स्पेक्ट्रम यूजेज चार्ज के मद में 1.47 लाख करोड़ रुपये बकाया भुगतान का आदेश दिया था। टेलीकॉम कंपनियों ने याचिका में कोर्ट से उस आदेश में संशोधन का अनुरोध किया था। याचिका खारिज होने के बाद अब टेलीकॉम कंपनियों के समक्ष बकाया अदा करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। टेलीकॉम कंपनियां इतनी बड़ी राशि अदा करने में असमर्थता जता चुकी हैं। वोडाफोन आइडिया के चेयरमैन कुमारमंगलम बिड़ला कह चुके हैं कि सरकार से मदद नहीं मिली तो टेलीकॉम कंपनियों को कारोबार बंद करना पड़ेगा।

जस्टिस अरुण मिश्रा, एसए नजीर तथा एमआर शाह वाली पीठ ने चैंबर में हुई सुनवाई में यह कहते हुए पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया कि इसमें कोई दम नहीं है। टेलीकॉम कंपनियों ने पुनर्विचार याचिका पर खुली अदालत में सुनवाई करने का अनुरोध किया था। परंतु सर्वोच्च अदालत ने चैंबर के भीतर ही सुनवाई की परंपरा का पालन करने का निर्णय लिया।

इससे पहले संचार मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने पिछले वर्ष नवंबर में संसद को जानकारी दी थी कि टेलीकॉम कंपनियों पर सरकार का 1.47 लाख करोड़ रुपये बकाया है। उन्होंने यह भी कहा था कि लाइसेंस फीस तथा स्पेक्ट्रम यूजेज चार्ज पर ब्याज और जुर्माने को माफ करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

रविशंकर प्रसाद के मुताबिक, टेलीकॉम कंपनियों पर लाइसेंस फीस के रूप में 92,642 करोड़ तथा स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज के रूप में 55,054 करोड़ रुपये का बकाया है। दूरसंचार विभाग के मुताबिक एयरटेल पर लाइसेंस फीस का 21,682.13 करोड़ और वोडाफोन पर 19,823.71 करोड़ रुपये बकाया है। जबकि रिलायंस कम्यूनिकेशंस पर 16,456.47 करोड़, बीएसएनएल पर 2,098.72 करोड़ तथा एमटीएनएल पर 2,537.48 करोड़ रुपये रुपये की लाइसेंस फीस बाकी है।

सुप्रीम कोर्ट फाइल फोटो

### क्या है मामला

सुप्रीम कोर्ट ने एजीआर की दूरसंचार विभाग की परिभाषा को उचित ठहराया था और इसे लेकर टेलीकॉम कंपनियों की आपत्तियों को बेजा करार दिया था। कोर्ट ने कहा था, एजीआर की गणना में टेलीकॉम सेवाओं से इतर सेवाओं से प्राप्त राजस्व भी शामिल माना जाएगा। कोर्ट ने बकाया राशि पर ब्याज व जुर्माने को उचित ठहराते हुए कहा था कि अब इस विषय पर आगे सुनवाई नहीं की जाएगी। कोर्ट ने बकाया अदायगी के लिए 23 जनवरी, 2020 की समय-सीमा तय की थी।

# निर्भया के गुनहगारों के डेथ वारंट पर लगी रोक

**जागरण संवाददाता, नई दिल्ली**

निर्भया सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले के दोषियों के खिलाफ जारी डेथ वारंट पर फिलहाल रोक लग गई है। पटियाला हाउस की एक अदालत ने कहा, डेथ वारंट पर फिर से विचार नहीं कर सकते। चूंकि एक दोषी ने दया याचिका दायर की है तो ऐसे में खुद ही फांसी टल जाएगी।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सतीश कुमार अरोड़ा ने तिहाड़ जेल प्रशासन से भी रिपोर्ट मांगी है कि आप ने अब तक क्या किया है? दोषी मुकेश की दया याचिका के बाद क्या कदम उठाए गए हैं? यह रिपोर्ट शुक्रवार तक अदालत में दाखिल करनी होगी। इस बीच, सभी दोषियों को तिहाड़ की जेल संख्या में तीन में स्थानांतरित कर दिया गया है, जहां उन्हें फांसी दी जानी है।

हाई कोर्ट में बुधवार को डेथ वारंट के खिलाफ अर्जी दायर की गई थी। हाई कोर्ट ने इसे जारी करने वाली निचली अदालत में ही जाने को कहा था। गुरुवार को पटियाला हाउस में सुनवाई के दौरान अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर ने कहा कि उन्होंने डेथ वारंट जारी करने के आदेश को चुनौती नहीं दी है, बल्कि इस पर रोक लगाने की मांग की है, क्योंकि मुकेश ने दया याचिका दायर की है। ऐसे में जब तक दया याचिका पर कोई फैसला नहीं आता, फांसी नहीं दी जा सकती, जो 22 जनवरी के लिए तय की गई थी। अगर दया याचिका खारिज हो जाती है तो भी फांसी देने के लिए 14 दिन का नोटिस दिया जाता है।

वहीं, निर्भया के परिजनों की तरफ से अधिवक्ता सीमा कुशवाहा ने अदालत को बताया कि दोषी मुकेश की दया याचिका राष्ट्रपति के पास विचाराधीन नहीं है, बल्कि अभी सिर्फ दायर की गई है। इस आधार पर डेथ वारंट पर रोक नहीं लगा सकते। निर्भया की मां ने अदालत के बाहर कहा, एक से दूसरी अदालत के चक्कर लगा रहे हैं। अगर उन लोगों के पास हक है, तो हमें भी न्याय पाने का हक है। सजायाफ्ता मुकेश सिंह (32), विनय शर्मा (26), अक्षय कुमार सिंह (31) और पवन गुप्ता (25) को तिहाड़ जेल में 22 जनवरी को सुबह सात बजे फांसी दी जानी थी। सात जनवरी को पटियाला कोर्ट ने डेथ वारंट जारी किया था।

जेल प्रशासन ने सरकार से मांगा निर्देश पेज>>6

मुकेश कुमार फाइल

**एक दोषी की याचिका के चलते 22 को नहीं दी जा सकती फांसी अदालत ने कहा, डेथ वारंट पर फिर से विचार नहीं, सिर्फ रोक**

# इंदिरा गांधी पर बयान से पीछे हटे शिवसेना के नेता संजय राउत

- कहा, मुंबई के इतिहास की जानकारी नहीं रखने वालों ने बयान को 'तोड़ा-मरोड़ा'

**मुंबई, प्रेट्र** : कांग्रेस द्वारा आलोचना किए जाने के बाद शिवसेना नेता संजय राउत ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के गैंगस्टर करीम लाला से मुलाकात वाली टिप्पणी गुरुवार को वापस ले ली। राउत ने ट्वीट किया कि वे (करीम लाला) पख्तून-ए-हिंद नाम के संगठन का नेतृत्व करते थे। पठान समुदाय के नेता के तौर उन्होंने इंदिरा गांधी सहित कई शीर्ष नेताओं से भेंट की। हालांकि, जिन्हें मुंबई के इतिहास की जानकारी नहीं है, वे मेरे बयान को तोड़-मरोड़ रहे हैं।

कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा व मुंबई कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष संजय निरुपम ने राउत के बयान की निंदा करते हुए बयान वापस लेने को कहा था। देवड़ा ने कहा था, जो पीएम जीवित नहीं हैं, उनकी विरासत विकृत नहीं की जानी चाहिए। निरुपम ने कहा, यदि राउत इंदिरा गांधी के खिलाफ झूठा अभियान जारी रखेंगे, तो उन्हें पछताना पड़ेगा।

राउत ने आलोचना के बाद कहा, 'अगर किसी को लगता है कि मेरे बयान से इंदिरा गांधी की छवि को क्षति पहुंची या किसी की भावनाएं आहत हुईं, तो मैं उसे वापस लेता हूं।' मैंने पहले भी इंदिरा गांधी का पक्ष लिया है और उन लोगों से लड़ा हूं जिन्होंने उनकी छवि धूमिल करने का प्रयास किया। ऐसे मामलों में तो कुछ कांग्रेसियों ने भी चुप्पी साधे रखी। ज्ञात हो, पुणे के एक कार्यक्रम के दौरान राउत ने कहा था इंदिरा गांधी पायधुनी में करीम लाला से मिला करती थीं।

इंदिरा गांधी की प्रशंसा करने से कभी परहेज नहीं किया : राउत पेज>>4

### बिहार में नीतीश के नेतृत्व में ही लड़ेंगे चुनाव : अमित शाह

**वैशाली** : भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एलान किया है कि राजग बिहार विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ेगा। उन्होंने दो टूक कहा कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व पर किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए। (पेज-4)

### सीएए पर बिना बताए कोर्ट जाने से केरल के राज्यपाल नाराज

**तिरुअनंतपुरम** : केरल में राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच तनातनी जारी है। राज्यपाल आरिफ मुहम्मद खान ने कहा कि उन्हें बताए बगैर नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ राज्य सरकार का सर्वोच्च न्यायालय में अपील करना किसी भी तरह से उचित नहीं था। इस मामले में अपना रुख स्पष्ट करते हुए राज्यपाल ने कहा कि वह एक रबर स्टैंप नहीं है। (पेज-5)

**बोर्ड का फैसला**

बीसीसीआइ ने इस बारे में पहले ही पूर्व भारतीय कप्तान को किया था सूचित, 2018-19 के सत्र के केंद्रीय करार में ए ग्रेड में थे धौनी

# बीसीसीआइ के करार से धौनी बाहर, भविष्य पर सवाल

**अभिषेक त्रिपाठी, नई दिल्ली**

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने (बीसीसीआइ) पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धौनी को पहले ही सूचित कर दिया था कि नियमों के मुताबिक उन्हें 2019-20 सत्र के केंद्रीय अनुबंध से बाहर करना होगा क्योंकि उन्होंने पिछले साल विश्व कप सेमीफाइनल के बाद से कोई भी अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं खेला है और मौजूदा नियम के तहत उसी खिलाड़ी को केंद्रीय अनुबंध दिया जा सकता है जिसने कम से कम तीन टेस्ट या आठ वनडे या इतने टी-20 मैच खेले हों। धौनी 2018-19 सत्र के केंद्रीय करार में ए ग्रेड में थे, जिसके लिए उन्हें बीसीसीआइ से पांच करोड़ रुपये मिले थे।

बीसीसीआइ ने गुरुवार को दोपहर 1.56 पर ईमेल जारी कर केंद्रीय करार के बारे में जानकारी मीडिया को दी। हालांकि यह बात धौनी को पहले से ही पता थी। यही कारण है जिस समय बोर्ड ने 2019-20 सत्र के करार की आधिकारिक घोषणा की उससे करीब तीन घंटे पहले धौनी गृहनगर रांची में अभ्यास करने उतरे। शायद वह यह संदेश देना चाह रहे थे कि बोर्ड ने भले ही उन्हें केंद्रीय करार से बाहर कर दिया है लेकिन उन्होंने अभी बल्ला छोड़ा नहीं है और 29 मार्च से शुरू होने वाले आइपीएल के जरिये वह अगले साल अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया में होने वाले विश्व कप से पहले वापसी की कोशिश करेंगे। धौनी ने बल्लेबाजी अभ्यास के लिए नई बॉलिंग मशीन भी खरीदी है।

**विराट, रोहित और बुमराह शीर्ष ग्रुप में** : अक्टूबर 2019 से सितंबर 2020 तक के इस करार में कप्तान विराट कोहली, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह को ए+ के शीर्ष ग्रेड में रखा गया है। इन्हें प्रति वर्ष सात करोड़ रुपये मिलेंगे। वहीं रवींद्र जडेजा, भुवनेश्वर, मुहम्मद शमी, चेतेश्वर पुजारा, केएल राहुल, अंजिक्य रहाणे, शिखर धवन, इशांत शर्मा, कुलदीप यादव व रिषभ पंत को ए ग्रेड में रखा गया है। ग्रेड-बी में शामिल खिलाड़ियों को प्रति वर्ष तीन करोड़ जबकि ग्रेड-सी के खिलाड़ियों को एक-एक करोड़ रुपया मिलेगा।

महेंद्र सिंह धौनी फाइल फोटो

### धौनी ने भारत को बहुत कुछ दिया

**नई दिल्ली** : भारत को अपनी कप्तानी में 2011 विश्व कप दिला चुके धौनी ने टीम इंडिया के लिए 90 टेस्ट, 350 वनडे और 98 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं। वह टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। इस फॉर्मेट में उन्होंने कुल 4876 रन बनाए। वहीं वनडे में उनके नाम 10773 और टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 1617 रन दर्ज हैं। 23 दिसंबर 2004 को बांग्लादेश के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय पदार्पण करने वाले धौनी ने पिछले साल इंग्लैंड में विश्व कप सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना आखिरी मैच खेला था। उस मैच में उन्होंने 50 रन बनाए थे।

**ग्रेड-ए+ (सात करोड़ रुपये)** : विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह

**ग्रेड-ए (पांच करोड़ रुपये)** : आर अश्विन, रवींद्र जडेजा, भुवनेश्वर कुमार, मुहम्मद शमी, चेतेश्वर पुजारा, केएल राहुल, अंजिक्य रहाणे, शिखर धवन, इशांत शर्मा, कुलदीप यादव, रिषभ पंत

**ग्रेड-बी (तीन करोड़ रुपये)** : रिद्धिमान साहा, उमेश यादव, युजवेंद्रा सिंह चहल, हार्दिक पांड्या, मयंक अग्रवाल

**ग्रेड सी (एक करोड़ रुपये)** : केदार जाधव, नवदीप सैनी, दीपक चाहर, मनीष पांडेय, हनुमा विहारी, शार्दुल ठाकुर, श्रेयस अय्यर, वाशिंगटन सुंदर।

# भारत में निवेश करना अमेजन का एहसान नहीं : पीयूष गोयल

- कहा - कंपनी के घाटे की भरपाई के लिए हुए निवेश से देश को क्या लाभ
- ई-कॉमर्स कंपनियों को क्षति आश्चर्य की बात, इस पर निगाह रखने की जरूरत

**नई दिल्ली, प्रेट्र** : भारत में निवेश करना ई-कॉमर्स दिग्गज अमेजन का एहसान नहीं है। अगर कंपनी कीमतों को जानबूझकर कम रखने की नीति के कारण होने वाली क्षति की भरपाई के लिए एक अरब डॉलर का निवेश करती है, तो इसका क्या मतलब रह जाता है। रायसीना डायलॉग में एक सत्र को संबोधित करते हुए केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को यह बात कही। ज्ञात हो, भारत दौरे पर आए अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस ने एक दिन पहले ही यहां एक अरब डॉलर (7,100 करोड़ रुपये) निवेश का एलान किया है। गोयल की अब तक बेजोस से भेंट नहीं हुई है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा, ई-कॉमर्स कंपनियों को भारत में नियमों का पालन करना होगा। उन्हें मल्टी ब्रांड रिटेल सेग्मेंट में पिछले दरवाजे से घुसने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। पीयूष गोयल ने कहा, ई-कॉमर्स कंपनियों को घाटा क्यों उठाना पड़ता है। इस बात पर निगाह रखने की जरूरत है। गोयल ने कहा, अगर मार्केट प्लेस मॉडल में 10 अरब डॉलर के टर्नओवर वाली कंपनी को एक अरब डॉलर का नुकसान होता है, तो सवाल तो उठेगा कि यह नुकसान हुआ कैसे? ऐसा तभी संभव है, अगर ये कंपनियां कीमतों को जानबूझकर गिराएं और कारोबार का गलत तरीका अपनाएं। गोयल ने कहा, 'यही असली सवाल है और मुझे भरोसा है कि इस मामले को देख रहे प्राधिकरण जरूर इसका जवाब खोजेंगे और ई-कॉमर्स कंपनियों को भी जवाब देना होगा।'

भारत के ई-कॉमर्स मार्केट में विक्रेता और खरीदार पूरी तरह स्वतंत्र पेज>>12

**21** नए मामले दर्ज किए गए हैं चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन में। इनमें से ज्यादातर मामले गैर राजनीतिक दलों के खिलाफ हैं। चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन में अब तक कुल 87 मामले दर्ज हुए हैं।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शुक्रवार 17 जनवरी 2020

## चुनावी हलचल

### अवतार सिंह के समर्थकों ने आतिशी को दिखाए काले झंडे

**नई दिल्ली** : कालकाजी से आप विधायक अवतार सिंह कालका का टिकट कटने से नाराज उनके समर्थकों ने आप उम्मीदवार आतिशी को काले झंडे दिखाए और गो बैक के नारे लगाए। कालकाजी से आप के टिकट पर चुनाव लड़ने वाली आतिशी गुरुवार को इलाके में ही अपने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करने आई थीं। यहां राज्यसभा सदस्य व पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह भी आने वाले थे, लेकिन वह नहीं आए। वहीं, इस बारे में आतिशी के एक प्रतिनिधि ने बताया कि प्रदर्शन करने वाले 20-25 लोग थे। यह कोई बड़ा प्रदर्शन नहीं था। हो सकता कि ये लोग किसी मजबूरी में प्रदर्शन करने आए हों। बाद में प्रदर्शनकारी भी कह रहे थे कि वे आतिशी के साथ हैं। (जासं)

### ऑटो चालकों का समर्थन हासिल करने में जुटी भाजपा

**नई दिल्ली**: भाजपा विधानसभा चुनाव में ऑटो चालकों का समर्थन हासिल करने की कोशिश में जुट गई है। पार्टी के प्रदेश कार्यालय में जनशक्ति ऑटो तिपहिया चालक संघ के प्रतिनिधियों की बैठक भाजपा नेताओं के साथ हुई। उन्होंने चुनाव में भाजपा को हरसंभव सहयोग देने का एलान किया। भाजपा नेता व ऑटो संघ संरक्षक बेगराज खटाना, वीर सिंह चौहान, प्रवेश दिवाकर सहित अन्य प्रतिनिधियों ने ऑटो चालकों की समस्या राज्यसभा सदस्य व पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री विजय गोयल के सामने रखी। गोयल ने उनकी समस्याएं हल करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल सरकार पिछले पांच वर्षों से ऑटो चालकों के साथ छल कर रही है। भारी जुर्माना, गलत धाराएं लगाकर ऑटो बंद करने, जरूरी दस्तावेज जमा कराने जैसी समस्याओं से चालक जूझ रहे हैं। राजनीतिक दल उन्हें वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने पर ऑटो चालकों की समस्याओं को हल किया जाएगा। (जासं)

### भाजपा और कांग्रेस छोड़ कई आप में शामिल

**नई दिल्ली** : आप ने भाजपा के ओबीसी मोर्चा के नजफगढ़ जिला के उपाध्यक्ष विकास यादव को उनके समर्थकों के साथ पार्टी में शामिल कराया। पार्टी मुख्यालय में आप के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने आप नेता नरेश बाल्यान व बलराज शर्मा की मौजूदगी में सदस्यता दिलाई। उन्होंने कहा कि विकास यादव उत्तम नगर क्षेत्र में मजबूत पकड़ रखते हैं। उनके शामिल होने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। (जासं)

# इस बार विस चुनाव में प्रियंका होंगी कांग्रेस का ट्रंप कार्ड

**संजीव गुप्ता, नई दिल्ली**

इस विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस का ट्रंप कार्ड होंगी। प्रचार के दौरान पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने में उनकी बड़ी भूमिका रहेगी। वह सिर्फ रोड शो और जनसभा तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि कुछ विधानसभा क्षेत्रों में उनकी पदयात्राएं भी रखी जाएंगी। इस दौरान वह आम जन से रूबरू भी होंगी।

दिल्ली में वजूद बचाने के लिए संघर्ष कर रही कांग्रेस के लिए यह चुनाव काफी अहम है। पार्टी ऐसी कोई कसर बाकी छोड़ना नहीं चाह रही, जिससे वह चूक जाए। इसीलिए हर मोर्चे पर इस बार पुख्ता रणनीति के साथ चला जा रहा है। पार्टी हर रोज ही किसी न किसी मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी एवं भाजपा पर हमला बोल रही है। वहीं इस चुनाव में अपने सभी वरिष्ठ नेताओं पर भी दांव लगा रही है।

इसी कड़ी में पार्टी चुनाव प्रचार को भी धारदार बनाने के लिए जोरदार रणनीति बना रही है। प्रचार में शीला दीक्षित सरकार की उपलब्धियों को तो भुनाया ही जाएगा, पार्टी घोषणा पत्र की खास-खास बातों को भी जन-जन तक लेकर जाएगी। प्रचार को दमदार बनाने के लिए पार्टी सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मनमोहन सिंह और प्रियंका गांधी वाड्रा के कार्यक्रमों का भी पूरा शेड्यूल तैयार कर रही है। मनमोहन सिंह के कार्यक्रम सिख बहुल इलाकों पर फोकस होंगे, जबकि दिल्ली के सात लोकसभा क्षेत्रों के हिसाब से राहुल व सोनिया की चुनावी जनसभाएं, रैलियां और रोड शो रखे जाएंगे।

पार्टी इस बार गांधी परिवार में से प्रियंका गांधी वाड्रा को सर्वाधिक तवज्जो देते हुए चल रही है। रोड शो, जनसभाओं और रैलियों से इतर इनकी पदयात्रा भी रखी जाएंगी। ये पदयात्रा उन तमाम विधानसभा क्षेत्रों में होंगी, जहां पार्टी इसका फायदा उठा सकेगी। पदयात्रा का शेड्यूल कुछ इस तरह रहेगा ताकि प्रियंका चिर-परिचित अंदाज में बच्चों, बुजुर्गों, युवाओं और महिलाओं से मुलाकात भी कर सकें। प्रियंका स्वयं दिल्ली विस चुनाव के लिए हरसंभव योगदान देने का वायदा कर चुकी हैं। पिछले दिनों दिल्ली के वरिष्ठ पार्टी नेताओं के साथ बैठक में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि उन्हें जहां कहीं भी चलने को कहा जाएगा, वह वहां जाएंगी।

## हुड्डा, पायलट, कैप्टन व शत्रुघ्न सिन्हा भी करेंगे चुनाव प्रचार

**राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली**: दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए प्रचार में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के शीर्ष नेता भी सक्रियता से शामिल होंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा करीब 40 स्टार प्रचारकों की सूची को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, कैप्टन अमरिंदर सिंह, शत्रुघ्न सिन्हा और राज बब्बर भी शामिल रहेंगे। आप के सघन प्रचार अभियान की तुलना में कांग्रेस का प्रचार अभियान बेहद धीमा है। इससे कांग्रेस को त्रिकोणीय संघर्ष में सशक्त दल के रूप में नहीं आंका जा रहा है। कांग्रेस नेतृत्व इस स्थिति से उबरना चाहता है। इस कमजोर स्थिति से उबरने के लिए ही पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने लोकसभा चुनाव लड़े सभी नेताओं को विधानसभा चुनाव लड़ने को कहा है और स्वयं भी प्रचार में सक्रिय रहने के संकेत दिए हैं। बताया जाता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अन्य सहयोगियों के साथ जाट बाहुल्य इलाके में प्रचार करेंगे। अन्य नेता भी पूरे चुनाव प्रचार में छोटी सभाओं के लिए भी उपलब्ध होंगे। आक्रामक चुनाव प्रचार की रूपरेखा को अंतिम रूप देने के लिए सोनिया गांधी ने हरी झंडी दे दी है। इसके आधार पर ही प्रचार अभियान की रूपरेखा तैयार की गई है। कांग्रेस की चुनावी रणनीति में इस बार रोड शो पर ज्यादा जोर दिया जाएगा। रोड शो में भीड़ भरे इलाकों सहित गलियों में भी मतदाताओं तक जाकर सीधे जनसंपर्क किया जाएगा। बड़ी चुनावी रैली की तुलना में रोड शो में उम्मीदवार को कम परिश्रम करना होगा, साथ ही गली-गली तक बड़े नेता आम जन तक जनसंपर्क कर सकेंगे।

यूं तो गांधी परिवार सहित पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार करेंगे, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा अबकी बार खास तौर पर सक्रिय रहेंगी। उनका विशेष प्रोग्राम चार्ट तैयार किया जा रहा है।

**-कीर्ति आजाद, अध्यक्ष, प्रचार अभियान समिति, दिल्ली कांग्रेस**

## संकल्प पत्र के लिए भाजपा को मिले 11.65 लाख सुझाव

**राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली** : संकल्प पत्र (घोषणा पत्र) बनाने को लोगों से सुझाव लेने के लिए भाजपा ने 'मेरी दिल्ली मेरा सुझाव' अभियान शुरू किया गया था। इसके तहत पार्टी को 11.65 लाख सुझाव मिले हैं। यह जानकारी प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी ने प्रेस वार्ता में दी।

उन्होंने कहा कि लोगों के सुझाव को ध्यान में रखकर संकल्प पत्र बनाने का काम चल रहा है। 3 से 15 जनवरी तक चले अभियान में विधानसभा क्षेत्रों में वीडियो रथ भेजकर, सुझाव पेटी लगाकर, मिस्ड कॉल और ईमेल के जरिये लोगों से सुझाव लिए गए। लोगों ने जलभराव, दिल्ली की बदहाल सड़कें, प्रदूषण, परिवहन, बेराजगारी, दूषित पानी, दिल्ली के स्कूलों में खाली पड़े शिक्षकों और प्राचार्यों के पद भरने, संविदा कर्मचारियों को नियमित करने, रेहड़ी पटरी वालों की समस्या, आयुष्मान भारत योजना लागू करने, बेघर लोगों को घर देने, महिला सुरक्षा को लेकर अपने सुझाव दिए। इसके साथ ही लोगों ने नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में सुझाव दिए।

# 'आम बजट में दिल्ली के लिए खूब सारी घोषणाएं करे केंद्र'

**सीएम बोले** ▶ चुनाव के चलते दिल्ली का विकास नहीं रुकना चाहिए

### चुनाव आयोग से केंद्रीय बजट को टालने की सिफारिश नहीं करेगी दिल्ली सरकार

**राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली**

दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए जारी हो चुकी अधिसूचना के बाद आप ने एक फरवरी को संभावित केंद्र सरकार के वार्षिक बजट को लेकर भी अपनी स्थिति साफ कर दी है। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि चुनाव के कारण दिल्ली का विकास नहीं रुकना चाहिए। इसलिए हम नहीं चाहेंगे कि दिल्ली में चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण केंद्र सरकार का बजट टाला जाए। आचार संहिता के कारण दिल्ली के लिए कोई नई घोषणाएं नहीं हो सकती। इस कारण आम बजट को टालने की सिफारिश करने का मुझ पर दबाव था। इसे दरकिनार कर मैंने निर्णय लिया है कि चुनाव आयोग से एक फरवरी को पेश होने वाले केंद्रीय बजट को टालने की सिफारिश नहीं करूंगा।

केजरीवाल ने कहा कि वह केंद्र को पत्र लिखेंगे कि वह आम बजट में दिल्ली के लिए खूब सारी घोषणाएं करे। बजट में प्रदूषण, सीवर, ट्रांसपोर्ट व यमुना पर खूब घोषणाएं हों। दिल्ली के विकास को चुनाव से परे रखने की जरूरत है। केंद्र सरकार खूब घोषणाएं करे और जीतकर आने वाली पार्टी उस फंड का इस्तेमाल कर दिल्ली का विकास और तेज करेगी।

आम आदमी पार्टी कार्यालय में पत्रकार वार्ता करते मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। जागरण

पार्टी मुख्यालय में प्रेसवार्ता कर केजरीवाल ने कहा कि हम सभी दिल्ली का विकास चाहते हैं। सभी पार्टियां चुनाव घोषणापत्र में भी इस बात को मानेंगी कि यहां प्रदूषण कम होना चाहिए। यहां की यातायात व्यवस्था बेहतर होनी चाहिए। मेट्रो का विस्तार होना चाहिए। यमुना की सफाई होनी चाहिए। घर-घर तक सीवर की लाइन पहुंचनी चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार बजट में दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए उचित राशि का प्रावधान करे। पंजाब और हरियाणा में जलाई जा रही पराली से निजात दिलाने के लिए उचित फंड का प्रावधान करे।

उन्होंने कहा कि दिल्ली की यातायात व्यवस्था को विश्वस्तरीय बनाने के लिए आवश्यक राशि बजट में मुहैया कराया जाए। घर-घर तक पीने का स्वच्छ पानी पहुंचाने के लिए आवश्यक राशि दिल्ली सरकार को मुहैया कराया जाए। दिल्ली में मेट्रो के विस्तार और संपूर्ण दिल्ली की सफाई के लिए आवश्यक फंड मुहैया कराया जाए। उन्होंने कहा कि सभी पार्टियां यह चाहती भी हैं और सभी पार्टियां यह घोषणाएं भी करेंगी।

केजरीवाल ने नगर निगम को लेकर कहा कि हम नगर निगम को भी राजनीति से दूर रखना चाहते हैं। दिल्ली नगर निगम में इस समय फंड की बहुत अधिक कमी है। केंद्र और दिल्ली नगर निगम में भाजपा है। केंद्र सरकार से अपील है कि वह दिल्ली नगर निगम को पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराए ताकि नगर निगम दिल्ली को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी को बेहतर तरीके से निभा सकें। हम इसका समर्थन नहीं करते हैं कि बजट को स्थगित किया जाए।

## सभी 15 विधायक मेरे परिवार का हिस्सा : केजरीवाल

**राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली** : टिकट काटे जाने से नाराज हुए विधायकों को लेकर गुरुवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गंभीर दिखे। उन्होंने पार्टी मुख्यालय में इस बारे में पूछे जाने पर कहा कि सभी 15 विधायक उनके परिवार का हिस्सा हैं। ये लोग उनसे दूर नहीं हो सकते।

कुछ विधायकों द्वारा टिकट बेचे जाने के आरोप लगाए जाने के बारे में पूछे जाने पर केजरीवाल ने कहा कि यह कोई नई बात नहीं है। टिकट कट जाने से नाराज होने पर इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं। जब उनसे पूछा गया कि कांग्रेस ने बयान दिया कि ये सभी 15 विधायक उनके संपर्क में हैं तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि चुनाव के माहौल में सभी लोग अपनी ओर करने की कोशिश करते हैं। कोई कहीं नहीं जा रहा है। सभी हमारे साथ रहेंगे। उधर, पार्टी सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री ने सभी को अलग-अलग बुलाकर समझाया और मना लिया है। इस बारे में पूछे जाने पर पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने कहा है कि टिकट आती-जाती रहती है। ये सभी पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं। इन सभी को आने वाले समय में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी। उन्होंने पार्टी में किसी तरह की नाराजगी होने से इन्कार किया है। भाजपा द्वारा आप के पूर्व विधायक कपिल मिश्रा को नई दिल्ली सीट पर उनके सामने उतारने की चल रहीं अटकलों के बारे में पूछे जाने पर मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि लोकतंत्र में किसी को कहीं से भी चुनाव लड़ने का अधिकार है।

# पानी बचाने पर कांग्रेस देगी 30 पैसे प्रति लीटर का कैशबैक

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पानी बचाओ दिल्ली बचाओ योजना के बारे में जानकारी देते प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा (बाएं) और प्रवक्ता मुकेश शर्मा। जागरण

**राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली**

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा ने घोषणा की कि दिल्ली में कांग्रेस के सत्ता में आने पर दिल्लीवासियों को पानी बचाने के लिए प्रोत्साहित करने की नीयत से कैशबैक योजना लागू की जाएगी। इसके तहत पानी बचाने वालों को 30 पैसे प्रति लीटर की दर से कैशबैक मिलेगा। वह गुरुवार को पार्टी कार्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे।

चोपडा ने 'पानी सबका अधिकार-भविष्य का रखना खयाल' नारा देते हुए कहा कि पानी बचाओ-दिल्ली बचाओ अभियान शुरू करने की नीयत से कैशबैक योजना लागू करेंगे। केजरीवाल सरकार ने वोट के लालच में इस फ्री पानी योजना को लागू किया था। हम इस योजना को जारी रखेंगे, लेकिन हमें भविष्य में दिल्ली में होने वाले वाटर वार की भी चिंता है, इसलिए हमने यह प्रोत्साहन योजना शुरू की है। उन्होंने कहा कि 20,000 लीटर पानी में जितना पानी उपभोक्ता बचाएगा, उसे 30 पैसे की दर से सरकार पैसा वापस देगी जो उपभोक्ता के खाते में सीधा स्थानांतरित किया जाएगा। चोपड़ा ने आंकड़ों के हवाले से इस पर चिंता भी जताई कि दिल्ली में पिछले छह सालों में 70 फीसद तक जमीन का पानी नीचे चला गया है। आज दिल्ली में गंदे पानी की समस्या की वजह से लगभग 25 फीसद पानी बर्बाद हो रहा है। इसके लिए दिल्ली सरकार सीधे तौर पर जिम्मेदार है। चोपड़ा ने कहा कि सेंटर ग्राउंड वाटर बोर्ड की रिपोर्ट में बाकायदा पानी बचाने के लिए विशेष योजना को लाए जाने को जरूरी बताया गया है।

# सिसोदिया सहित 13 उम्मीदवारों ने भरा पर्चा

**राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली**

विधानसभा चुनाव में नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के चौथे दिन 11 विधानसभा क्षेत्रों में 13 उम्मीदवारों ने पर्चा दाखिल किया। इनमें आप से मनीष सिसोदिया सहित दो प्रत्याशियों ने नामांकन कराया, जबकि पांच निर्दलीय के अलावा छह अन्य दलों के उम्मीदवार शामिल हैं।

मनीष सिसोदिया लगातार दो बार (वर्ष 2013 व 2015) पटपड़गंज से विधायक रहे हैं। तीसरी बार भी उन्होंने यहीं से पर्चा दाखिल किया है। वहीं आप के नितिन त्यागी पिछले विधानसभा चुनाव में लक्ष्मी नगर सीट से जीते थे। वह दूसरी बार इस सीट से प्रत्याशी हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कार्यालय के अनुसार सुल्तानपुर माजरा सीट से महिला उम्मीदवार भारती ने राष्ट्रवादी जनता पार्टी से पर्चा भरा है। वहीं, मुस्तफाबाद से टीपू सुल्तान पार्टी से इमरान खान नामक उम्मीदवार ने पर्चा भरा। करावल नगर से एसएन सिंह, इसी विधानसभा क्षेत्र से विपिन कुमार तिवारी ने राष्ट्रीय राष्ट्रवादी पार्टी से पर्चा भरा। महरौली सीट से डीके चोपड़ा ने ऑल इंडिया फॉवर्ड ब्लॉक के उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भरा।

मंडावली में गुरुवार को नामांकन से पूर्व समर्थकों के साथ पदयात्रा करते उपमुख्यमंत्री और आप प्रत्याशी मनीष सिसोदिया। हरीश कुमार

द्वारका से बलजीत यादव ने राष्ट्रीय राष्ट्रवादी पार्टी से पर्चा भरा। बिजवासन से अनिल, बादली से जयपाल, शकूरबस्ती से राजकुमार व तुगलकाबाद से अनिता कुमारी ने निर्दलीय पर्चा भरा है। इसके अलावा बादली सीट से विजय कुमार ने आपकी अपनी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भरा। चार दिनों में अब तक कुल 23 उम्मीदवार 25 नामांकन पत्र दाखिल कर चुके हैं।

## उपमुख्यमंत्री ने दिखाया दमखम

**जागरण संवाददाता, नई दिल्ली** : उपमुख्यमंत्री और पटपड़गंज से आप के प्रत्याशी मनीष सिसोदिया ने नामांकन दाखिल करने से पहले पदयात्रा निकालकर दमखम दिखाया। मंडावली के तालाब चौक से उपमुख्यमंत्री ने पैदल यात्रा की शुरुआत की। गुरुवार को नामांकन करने से पहले सिसोदिया सबसे पहले वेस्ट विनोद नगर के बद्रीनाथ मंदिर में पहुंचे। यहां माथा टेककर प्रभु का आशीर्वाद लिया। इस बीच मंदिर परिसर में उत्तराखंडी लोगों से भी मिले। पदयात्रा के दौरान रास्ते में उन्हें कोई बुजुर्ग दिखा तो उससे भी आशीर्वाद लेते रहे। इसके बाद वह वापस तालाब चौक पहुंचे और अपनी पत्नी सीमा सिसोदिया के साथ जीप में सवार होकर यात्रा को आगे बढ़ाया। यह यात्रा मंडावली, वेस्ट विनोद नगर, नालंदा चौक, श्रीराम चौक व प्रीत विहार से विकास मार्ग होकर गीता कॉलोनी स्थित एसडीएम कार्यालय पहुंची। इसमें कई लोग मोटरसाइकिल व कार से नारेबाजी करते हुए चल रहे थे। उपमुख्यमंत्री के नामांकन में आप का कोई बड़ा नेता नहीं दिखा।

## नेशनल कैपिटल

# सीए की परीक्षा में नोएडा के सूर्यांश को देश में पहला स्थान

**जागरण संवाददाता, नोएडा**

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आइसीएआइ) ने गुरुवार को चार्टर्ड अकाउंटेंटेट (सीए) की फाइनल परीक्षा का परिणाम जारी किया।

सूर्यांश अग्रवाल

नवंबर में हुई फाइनल परीक्षा (नए कोर्स में) में नोएडा के सूर्यांश अग्रवाल और कोलकाता के अभय बाजोरिया ने संयुक्त रूप से देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। कोलकाता के ही ध्रुव कोठारी दूसरे और अहमदाबाद के दर्शन शाह तीसरे स्थान पर हैं।

फाइनल परीक्षा में पूरे देश में 15,003 छात्र दोनों ग्रुप (नए और पुराने कोर्स) में शामिल हुए थे। इनमें से 15.12 फीसद छात्रों को सफलता मिली है। पुराने कोर्स में विजयवाड़ा (आंध्र प्रदेश) के गुराम नागा श्रीकृष्ण प्रनीथ ने फाइनल परीक्षा में टॉप किया। केरल के मन्नार्कड़ की वारादा केपी दूसरे और मुंबई के धवल चोपड़ा तीसरे स्थान पर हैं। नए और पुराने दोनों कोर्स के सात टॉपरों में वारादा अकेली छात्रा हैं। पुराने कोर्स में परीक्षा में शामिल हुए 8,021 विद्यार्थियों में 10.2 फीसद छात्र सफल हुए हैं। नोएडा के सेक्टर-41 में रहने वाले सूर्यांश ने 75.38 फीसदी अंकों के साथ यह प्रतिष्ठित परीक्षा टॉप की। उन्होंने 800 में से 603 अंक प्राप्त किए हैं। पिछले साल नवंबर में आयोजित सीए फाइनल परीक्षा के दोनों कोर्स के परिणाम पहले 16 और 17 जनवरी को घोषित किया जाना था। लेकिन इसे 16 जनवरी को घोषित कर दिया गया है। सूर्यांश ने बताया कि उन्होंने सीए फाइनल की परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत की थी। परीक्षा से तीन-चार महीने पहले वह रोजाना 15 घंटे तक पढ़ते थे। वह दो साल से इस परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। इस दौरान परिवार का पूरा सहयोग मिला।

## पुलिस मुख्यालय पर प्रदर्शन मामले में केस दर्ज

**जागरण संवाददाता, नई दिल्ली** : दिल्ली पुलिस मुख्यालय के सामने दिल्ली पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों की ओर से पांच नवंबर को किए गए प्रदर्शन और सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से न्यायपालिका से जुड़े लोगों के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने के मामले में पुलिस शिकायत प्राधिकरण ने मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही 12 फरवरी से इस मामले की नियमित सुनवाई करना तय किया गया है। साकेत कोर्ट के कई वकीलों ने इस संबंध में 12 नवंबर को लिखित शिकायत दी थी।

साकेत कोर्ट के अधिवक्ता मोहित कुमार गुप्ता ने बताया कि पांच नवंबर को पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने पुलिस मुख्यालय पर प्रदर्शन किया था। पुलिसकर्मियों और अधिकारियों द्वारा किसी प्रदर्शन में शामिल होने के साथ ही वर्दी में एक जगह एकत्रित होना पुलिस बल एक्ट 1966 के खिलाफ है। आइपीएस एसोसिएशन ने भी एक प्रस्ताव पास किया था, जो कि पुलिस एक्ट 1966 का उल्लंघन है।

# परेड की रिहर्सल के चलते आज डायवर्जन

**जागरण संवाददाता, नई दिल्ली**

▶ **17, 18, 20 और 21 जनवरी को विजय चौक से इंडिया गेट होते हुए राजपथ पर सी-हैक्सागन तक होगी परेड की रिहर्सल**

राजधानी में गणतंत्र दिवस के मौके पर होने वाली परेड की रिहर्सल शुक्रवार से शुरू होगी। 17, 18, 20 और 21 जनवरी को विजय चौक से इंडिया गेट होते हुए राजपथ पर सी-हैक्सागन तक आयोजित होने वाली रिहर्सल परेड के दौरान कई मार्गों पर वाहनों का प्रवेश बंद होगा और कई मार्गों पर डायवर्जन किया जाएगा।

यातायात पुलिस के मुताबिक राजपथ पर परेड की निर्बाध आवाजाही को सुगम बनाने के लिए रफी मार्ग, जनपथ और मानसिंह रोड पर सुबह नौ बजे से दोपहर 12 बजे तक यातायात पर प्रतिबंध रहेगा। विजय चौक से इंडिया गेट तक भी राजपथ यातायात के लिए बंद रहेगा। इस दौरान यातायात पुलिस ने वाहन चालकों से धैर्य बनाए रखने और यातायात पुलिस कर्मियों के निर्देश को मानने की अपील की है। यातायात पुलिस द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार यातायात का मार्ग परिवर्तित होने के कारण इन कई मार्गों पर जाम रहने की आशंका है। केंद्रीय सचिवालय आने और जाने वालीं दक्षिण दिल्ली की बसें विश्व युवक केंद्र, चाणक्यपुरी, त्यागराज मार्ग, कृष्ण मेनन मार्ग और मौलाना आजाद रोड से होकर नहीं गुजरेंगी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाने वाली अन्य बसों को सरदार पटेल मार्ग, साइमन बोलिवर मार्ग, ऊपरी रिज रोड, शंकर रोड और पार्क स्ट्रीट-मंदिर मार्ग होते हुए जाने की सलाह दी गई है।

उत्तरी दिल्ली और दक्षिणी दिल्ली के बीच वाहन चालक रिंग रोड होते हुए राजघाट जाने के लिए रिंग रोड, आश्रम चौक, सराय काले खां, आइपी फ्लाईओवर का प्रयोग करें। मंदिर मार्ग जाने के लिए यात्री लोधी रोड टी-प्वाइंट होते हुए अरबिंदो मार्ग, एम्स चौक, रिंग रोड-धौला कुआं और शंकर रोड का इस्तेमाल कर सकते हैं।

पूर्वी दिल्ली से पश्चिमी दिल्ली आने-जाने वाले वाहन चालक मथुरा रोड और लोधी रोड पर रिंग होते हुए भैरों मार्ग का प्रयोग करें। एम्स चौक जाने के लिए यात्री मंदिर मार्ग होते हुए रिंग रोड-धौला कुआं से जा सकते हैं। रिंग रोड-आइएसबीटी जाने के लिए वाहन चालक चंदगी राम अखाड़ा होते हुए आइपी कॉलेज और आजादपुर तथा पंजाबी बाग होते हुए मॉल रोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। विनय मार्ग और शांति पथ से आने वाले और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और उससे आगे जाने वाले वाहन चालकों को सरदार पटेल मार्ग या पार्क स्ट्रीट होते हुए मंदिर मार्ग से आगे उत्तरी दिल्ली या नई दिल्ली जाने की सलाह दी गई है।

## रणनीति

कांग्रेस के 66 और राजद के चार सीटों पर चुनाव लड़ने की संभावना, दिल्ली में पहली बार कांग्रेस गठबंधन कर चुनाव लड़ेगी

# राजद के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेगी कांग्रेस

**संजीव गुप्ता, नई दिल्ली**

महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावी नतीजों से सबक लेते हुए कांग्रेस ने दिल्ली में भी गठबंधन में चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। यह गठबंधन राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के साथ किया जा रहा है। कांग्रेस 66 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि राजद चार सीटों पर। हालांकि, गुरुवार देर रात तक भी इसे लेकर औपचारिक स्तर पर पुष्टि नहीं हो सकी थी। बताया जा रहा है कि शनिवार को दोनों पार्टियां संयुक्त पत्रकार वार्ता कर सभी 70 उम्मीदवारों की घोषणा करेंगी। दिल्ली के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा, जब कांग्रेस गठबंधन में चुनाव लड़ेगी।

सूत्रों के मुताबिक, पार्टी आलाकमान की सहमति से ही राजद के साथ गठबंधन का फैसला लिया जा रहा है। इसका मुख्य मकसद बिहार व पूर्वांचल के मतदाताओं को साधना है। राजद ने पांच से 10 सीटों की मांग रखी हैं, जबकि कांग्रेस ने चार सीटें उत्तम नगर, बुराड़ी, किराड़ी और करावल नगर की पेशकश की है। इन सीटों पर पूर्वांचल के मतदाताओं की संख्या अधिक है। बातचीत बदरपुर सीट को लेकर भी चल रही है। सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस ने गुरुवार देर रात तक 42 सीटों पर उम्मीदवार तय कर दिए हैं, जबकि शेष सीटों पर शुक्रवार रात तक तय कर दिए जाएंगे। राजद ने भी अपने उम्मीदवारों के नाम अंदरखाने तय कर दिए हैं। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने माना कि राजद के साथ सीटों के बंटवारे पर बातचीत चल रही है। प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा ने सिर्फ यही कहा कि अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है।

### नेताओं के बच्चों और युवाओं पर भी दांव लगा रही पार्टी

**जासं, नई दिल्ली** : विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कद्दावर नेताओं के साथ-साथ युवाओं पर भी दांव खेलने जा रही है। इनमें कुछ वरिष्ठ नेताओं के बच्चे हैं, जबकि कुछ सीटें युवा कांग्रेस और एनएसयूआइ के खाते में दी गई हैं। विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक गुरुवार देर रात तक जिन 42 सीटों पर नाम करीब-करीब तय कर लिए गए हैं, उनमें कालकाजी से प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा की बेटी शिवानी चोपड़ा, आरके पुरम से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष योगानंद शास्त्री की बेटी प्रियंका सिंह, मॉडल टाउन से पूर्व विधायक कुंवर करण सिंह की बेटी आकांक्षा ओला, मुस्तफाबाद से पूर्व विधायक हसन अहमद के बेटे अली मेहंदी व नांगलोई जाट से पूर्व विधायक विजेंद्र सिंह के बेटे मनदीप सिंह का नाम भी शामिल है। चांदनी चौक से पूर्व विधायक अलका लांबा के ही नाम पर सहमति बनी है। संगम विहार से पूर्व क्रिकेटर और दिल्ली कांग्रेस की प्रचार अभियान समिति के अध्यक्ष कीर्ति आजाद की पत्नी पूनम झा आजाद को उम्मीदवार बनाया गया है। कई सीटों पर पार्टी ने जिलाध्यक्षों को भी उम्मीदवार बनाया है। शुक्रवार सुबह एक बार फिर पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने जा रही है। इस बैठक में बाकी बचे नामों पर भी मुहर लगा दिए जाने की संभावना है।

**2008** में 31 दिसंबर को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) अस्तित्व में आई। यह देश में आतंकवाद से संबंधित मामलों की जांच करती हैं, जो राज्य सरकारों की विशेष इजाजत के बगैर केंद्र के अधीन काम करती है। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्यों के अधिकार का हनन का हवाला देकर इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।



# अमेरिका की तरह निपटना होगा आतंकवाद से

## खरी बात ▶ सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने पाकिस्तान को फिर दी परोक्ष चेतावनी

### कहा, कोई देश आतंक से बाज नहीं आता तो कठोर कार्रवाई ही विकल्प

**जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली**

आतंकवाद का पालन-पोषण बंद नहीं करने पर पाकिस्तान को और सख्त कार्रवाई की चेतावनी देते हुए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल बिपिन रावत ने कहा कि जब तक आतंक का जड़ से सफाया नहीं हो जाता तब तक भारत की लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने आतंकवाद पर अमेरिका की तर्ज पर भारत के भी सख्त कार्रवाई करने के इरादे जाहिर किए। पाकिस्तान को परोक्ष चेतावनी देते हुए उन्होंने यह भी कहा कि आतंकी फंडिंग के लिए ब्लैकलिस्ट होने के बाद भी कोई देश आतंक की हिमाकत से बाज नहीं आता तो फिर कठोर कार्रवाई ही विकल्प रह जाएगा।

सुरक्षा और कूटनीति से जुड़े रायसीना डायलॉग को संबोधित करते हुए सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने कहा कि आतंकवाद तब तक खत्म नहीं होगा जबतक राष्ट्रों के स्तर पर इसका पालन-पोषण करने से लेकर धन और हथियार उपलब्ध कराया जाता रहेगा। उन्होंने कहा कि इसीलिए अगर आतंक का अंत करना है, तो फिर 9/11 के बाद अमेरिका ने वैश्विक स्तर पर आतंकवाद के खिलाफ जैसी कार्रवाई शुरू की उसी तरह के सख्त कदम उठाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आतंक की जड़ को समझते हुए हमें इसकी बुनियाद पर प्रहार करना होगा। नाम लिए बिना आतंक पर पाक के दोहरे चरित्र को बेनकाब करते हुए रावत ने कहा कि जो देश आतंक का समर्थन करते हैं, वे इसके खिलाफ वैश्विक लड़ाई का हिस्सा नहीं हो सकते। रावत ने कहा कि आतंक को पनाह देने वाले देशों को कूटनीतिक रूप से अलग-थलग कर उन्हें सबक सिखाना ही होगा।

**रायसीना डायलॉग में गुफ्तगू** : भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टॉफ जनरल बिपिन रावत गुरुवार को नई दिल्ली में चल रहे रायसीना डायलॉग-2020 में अफगानिस्तान-पाकिस्तान के लिए ब्रिटेन के विशेष प्रतिनिधि गैरेथ बेली के साथ गुफ्तगू करते नजर आए। गैरेथ बेली ब्रिटेन की विदेश और कॉमनवेल्थ ऑफिस में दक्षिण एशियाई मामलों के निदेशक भी हैं। प्रेट्र

आतंकी फंडिंग के लिए एफएटीएफ की ब्लैकलिस्ट में पाकिस्तान को डाले जाने की जरूरत बताते सीडीएस ने कहा कि जो भी देश आतंक का समर्थन करता है, उसे सबक सिखाना होगा। इस लिहाज से एफएटीएफ की ओर से ब्लैकलिस्ट किया जाना अच्छा कदम है। फिर भी कोई देश इससे बाज नहीं आता तो और सख्त कार्रवाई करने की जरूरत होगी।

रावत ने अफगानिस्तान सरकार और तालिबान के बीच चल रही शांति वार्ता का समर्थन किया, मगर यह भी कहा कि सौदेबाजी दीर्घकालिक समाधान के लिए होनी चाहिए। यह अस्थायी नहीं होनी चाहिए। तालिबान हो चाहे कोई भी आतंकी संगठन, उसे पहले हथियार डालना होगा, तभी मुख्यधारा की राजनीतिक प्रकिया में शासन का विकल्प उसको मिलेगा।

राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में कट्टरपंथ की चुनौतियों की चर्चा करते हुए रावत ने कहा कि कश्मीर में हमने देखा है कि कट्टरपंथ का मुकाबला किया जा सकता है। उन्होंने इस संदर्भ में कहा कि हम आज देख रहे कि छोटे-छोटे बच्चों के दिमाग में कट्टरपंथ का जहर भरा जा रहा है। इसीलिए जरूरी है कि ऐसे लोगों की पहचान की जाए और उन्हें हम कट्टरपंथ से मुक्त करने वाले कैंपों (डि-रेडिक्लाइज कैंप) में भेजें।

सीडीएस बिपिन रावत ने कट्टरपंथी विचाराधारा की चुनौती को थामने के लिए ऑनलाइन कट्टरपंथ पर भी लगाम की बात कही। वहीं, कश्मीर में पैलेट गन से बड़ी तादाद में लोगों के घायल होने की घटनाओं से जुडे सवाल पर उन्होंने कहा कि सेना पर अतिरेक कार्रवाई का आरोप लगाना सही नहीं है। हम आक्रामक होते तो फिर हमारे सैनिक इतनी ज्यादा संख्या में नहीं मारे जाते। साथ ही यह भी कहा कि अब पत्थरबाजी सरीखी घटनाओं से निपटने के लिए हमने नई रणनीति बनाई है और पैलेट गन का विशेष परिस्थितियों में ही इस्तेमाल किया जाता है।

# ओआइसी के लिए जरूरी होगा ईरान का साथ

**जयप्रकाश रंजन, नई दिल्ली**

अपने रणनीतिक साझेदार और मित्र देश अमेरिका के गुस्से की चिंता किए बगैर अगर भारत ईरान के साथ हमदर्दी दिखाने में जुटा है तो इसके पीछे भी कश्मीर मुद्दा है। पाकिस्तान ने हाल में सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात से बात की है कि इस्लामिक देशों के संगठन ओआइसी में कश्मीर पर विशेष बैठक बुलाई जाए। अगर ऐसा होता है तो भारत को ईरान की मदद चाहिए जो ओआइसी का बड़ा सदस्य है। ईरान के विदेश मंत्री जवाद जरीफ भारत के तीन दिनों के दौरे पर आए हुए हैं।

ईरान पर अभी अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध हैं, इसलिए ईरान के लिए ज्यादा जरूरी अभी कारोबार है। नई दिल्ली में ईरान के विदेश मंत्री की रूस, यूरोपीय संघ समेत कई देशों के विदेश मंत्रियों से बात हुई है। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने गुरुवार को ईरान के विदेश मंत्री जवाद जरीफ के साथ हालिया क्षेत्रीय घटनाक्रमों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने ईरान व वैश्विक शक्तियों के बीच 2015 में हुए परमाणु समझौते पर भी चर्चा की।

**आस्ट्रेलिया, डेनमार्क व हंगरी के विदेश मंत्रियों से मुलाकात** : जयशंकर ने गुरुवार को आस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री मारिसे पायने, हंगरी के विदेश मंत्री पीटर सिज्जार्तो और डेनमार्क के विदेश मंत्री जिप्पे कोफोड से मुलाकात और उनके साथ द्विपक्षीय महत्व के मसलों पर चर्चा की।

### 'हिंद-प्रशांत का मकसद किसी को अलग-थलग करना नहीं'

**नई दिल्ली, प्रेट्र** : हिंद-प्रशांत का उद्देश्य क्षेत्र में चीन के दबदबे को रोकने वाला बताने पर अमेरिका व भारत ने गुरुवार को रूस पर निशाना साधा। दोनों ने कहा कि इसका मकसद किसी देश को अलग-थलग करना नहीं बल्कि यह 'सिद्धांत आधारित सोच' है। रायसीना डायलॉग में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा था कि इसका मकसद मौजूदा क्षेत्रीय ढांचों को नुकसान पहुंचाना है। अमेरिकी उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मैथ्यू पॉटिंगर ने कहा कि यह उन देशों का समुदाय है जो कानून के शासन का सम्मान करता है, समुद्री क्षेत्र व आसमान में परिवहन की आजादी का समर्थन करता है। भारतीय विदेश सचिव विजय गोखले ने कहा, 'सदियों से भारत का चीन व दक्षिण पूर्व एशिया से संपर्क रहा है। यह औपनिवेशिक काल में टूट गया...वैश्विक साझा क्षेत्र बेहद अहम हैं व हिंद प्रशांत एक वैश्विक साझा क्षेत्र है।'

## न्यूज गैलरी

### सीमा शुल्क उपायुक्त की 3.56 करोड़ की संपत्ति जब्त

**नई दिल्ली** : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सीमा शुल्क विभाग के उपायुक्त रैंक के एक अधिकारी की 3.56 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है। ईडी के मुताबिक यह कार्रवाई मनी लांड्रिंग और आय से अधिक संपत्ति मामले में की गई है। जांच एजेंसी की ओर से जारी बयान में कहा कि जब्त संपत्ति में बैंकों में जमा 47.58 लाख रुपये, म्यूचुअल फंड में 91.75 लाख रुपये, 74 लाख रुपये की बीमा पालिसी, झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में 52.43 लाख रुपये मूल्य की जमीन, पटना में 35 लाख रुपये कीमत का एक फ्लैट, 40.33 लाख रुपये के आभूषण और अधिकारी से जब्त किए गए 14.50 लाख रुपये नकद शामिल हैं। जांच एजेंसी के अनुसार अधिकारी का शुरुआती नाम शशिकांत है। ईडी ने अधिकारी और उनके परिवार के नाम की संपत्ति जब्त करने के लिए प्रोविजनल आदेश जारी किया था और संपत्ति का कुल मूल्य 3.56 करोड़ रुपये है। एजेंसी ने एक बयान में कहा कि आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति एकत्र करने के मामले में अधिकारी की जांच की जा रही है। ईडी ने कहा कि उसने सीवीसी की टिप्पणी और अधिकारी के खिलाफ दर्ज सीबीआइ की प्राथमिकी के आधार पर मनी लांड्रिंग कानून के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया है। (प्रेट्र)

### एस्क्रो खाते से सुरक्षित होगा यमुना एक्सप्रेस वे का सफर

**ग्रेटर नोएडा** : यमुना एक्सप्रेस-वे पर सुरक्षा उपायों को लागू कराने के लिए एस्क्रो खाता खोला गया है। खाता खुलवाने के लिए यमुना प्राधिकरण ने जेपी इंफ्राटेक को आदेश दिए थे। एक्सप्रेस वे पर प्रतिदिन वसूल किए जाने वाले टोल से कुछ धनराशि इस खाते में जमा की जाएगी। यह धनराशि सुरक्षा उपायों को लागू करने में खर्च होगी। यमुना एक्सप्रेस-वे पर वाहन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए आइआइटी दिल्ली से सुरक्षा ऑडिट कराया गया था। आइआइटी ने एक्सप्रेस वे के लिए कई सुझाव दिए थे ताकि हादसों को रोका जा सके। इसके तहत मेडियन (दोनों मार्ग के बीच की जगह) के दोनों ओर क्रैश बीम बैरियर लगाना, एक्सप्रेस-वे पर दोनों किनारों पर लगे क्रैश बीम बैरियर की ऊंचाई बढ़ाना, रंबल स्ट्रिप, स्पीड गन, कैमरों की संख्या बढ़ाना आदि शामिल है। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रेटर नोएडा से आगरा तक एक्सप्रेस-वे पर रोशनी के लिए एलईडी लगाने के निर्देश दिए थे। इन सुरक्षा उपायों में कुछ को जेपी इंफ्राटेक ने लागू किया। लेकिन अहम उपायों को धनराशि की कमी के कारण लागू नहीं किया गया। (जासं)

# परीक्षा पे चर्चा : पीएम से इस बार 60 से ज्यादा बच्चे पूछेंगे सवाल

**जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली**

- विदेशों में रहने वाले भारतीय बच्चे के भी हो सकते हैं सवाल
- कार्यक्रम में 50 दिव्यांग बच्चे भी खासतौर पर होंगे शामिल

छात्रों के साथ होने वाली 'परीक्षा पे चर्चा' में पिछले सालों के मुकाबले इस बार ज्यादा बच्चों को पीएम से सीधे सवाल पूछने का मौका मिलेगा। फिलहाल अब तक इस चर्चा में पीएम से करीब 15 छात्रों के सवाल ही होते थे, लेकिन इस बार करीब 60 छात्रों को पीएम से सवाल करने का मौका दिया जाएगा। हालांकि इनमें से प्रत्येक तीन से चार छात्रों के सवाल आपस में मिलते-जुलते या एक जैसे विषयों पर आधारित होंगे। पीएम से साथ परीक्षा पे चर्चा का यह कार्यक्रम फिलहाल 20 जनवरी को प्रस्तावित है। इस कार्यक्रम में पहली बार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से बराबर की संख्या में बच्चों का चयन किया गया है। साथ ही इनमें छात्र और छात्राओं की प्रतिशत भी करीब बराबर का ही रखा गया है। इसके अलावा इस पूरे कार्यक्रम का देश भर के करीब 15 लाख शैक्षणिक संस्थानों और स्कूलों से सीधे प्रसारण की भी योजना बनाई गई है। यानि जो बच्चे कार्यक्रम में नहीं शामिल हो पाएंगे, वह स्कूल में ही बैठकर इसे देख सकेंगे।

पीएम 2018 से छात्रों के साथ इस तरह की चर्चा करते आ रहे है। इस बार कार्यक्रम में दो हजार बच्चे शामिल होंगे जिसमें करीब 50 दिव्यांग बच्चों को भी शामिल किया जा रहा है। इन बच्चों का भी चयन देश भर से किया गया है।

### 20 देशों में रहने वाले भारतीय बच्चों ने भी पूछे है सवाल

प्रधानमंत्री की छात्रों के साथ होने वाली 'परीक्षा पे चर्चा' कार्यक्रम को लेकर उत्साह सिर्फ भारतीय छात्रों में ही नहीं है, बल्कि विदेशों में रहने वाले भारतीय बच्चों में भी है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए करीब 20 देशों में रहकर पढ़ाई कर भारतीय बच्चों ने भी सवाल भेजे है। फिलहाल जिन देशों से भारतीय बच्चों के सवाल आए है, उनमें रूस, ईरान, नेपाल, बहरीन, यूएई, सिंगापुर, कतर और जापान जैसे देश शामिल है।

# फेमा मामले में ईडी के सामने पेश हुए कांग्रेस नेता केजे जार्ज

**बेंगलुरु, प्रेट्र** : फेमा मामले से जुड़े कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केजे जार्ज गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों के सामने पेश हुए। पूर्व मंत्री से ईडी विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) का उल्लंघन के बारे में पूछताछ कर रही है।

ईडी के सामने पेश होने के बाद जार्ज ने कहा कि उन्होंने अधिकारियों के सवालों का उत्तर दिया है और आगे सहयोग करते रहेंगे। कोई ब्योरा दिए बगैर उन्होंने कहा, 'ईडी ने मुझे समन किया था। कानून से बंधे नागरिक होने के नाते मैंने उत्तर दिए और जो दस्तावेज उन्होंने मांगे वह उनके हवाले किया। आगे भी वे मुझे बुलाते हैं तो मैं सहयोग करूंगा और आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध करा दूंगा।' जार्ज ने कहा कि ईडी ने उनके परिवार के सदस्यों को समन जारी नहीं किया है। उन्होंने कहा, 'यदि जरूरत पड़ी तो वे (ईडी) मुझे फिर से बुला सकते हैं और मैं सहयोग करने के लिए तैयार हूं।'

पिछले वर्ष कर्नाटक राष्ट्र समिति के अध्यक्ष रवि कृष्ण रेड्डी ने ईडी को शिकायत सौंप कर जार्ज और उनके परिवार के सदस्यों की अमेरिका में संपत्ति और मनी लांड्रिंग की जांच करने की मांग की थी।

# ब्रू जनजाति के लोग अब त्रिपुरा के होंगे निवासी

**जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली**

पूर्वोत्तर भारत की ब्रू जनजातियों की दो दशक पुरानी समस्या का समाधान निकल आया है। मिजोरम से भागकर आए और त्रिपुरा के शरणार्थी शिविरों में रह रहे 30 हजार से अधिक ब्रू जनजातियों को अब वापस जाने पर मजबूर नहीं किया जाएगा। केंद्र, त्रिपुरा, मिजोरम और ब्रू जनजातियों के प्रतिनिधियों के बीच समझौते के बाद अब उन्हें त्रिपुरा में ही बसाया जाएगा। इसके लिए गृहमंत्री अमित शाह ने 600 करोड़ रुपये के पैकेज का एलान किया है।

अमित शाह ने कहा कि ब्रू जनजातियों को त्रिपुरा में घर के लिए जमीन दी जाएगी। पांच हजार से अधिक परिवारों में से प्रत्येक परिवार के खाते में चार लाख रुपये का फिक्स्ड डिपोजिट किया जाएगा, जिसे वे दो साल बाद निकाल सकेंगे। उन्हें दो साल के लिए हर महीने पांच हजार रुपये की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। इसके अलावा, उन्हें प्रति व्यक्ति के हिसाब से दो साल तक खाने के लिए मुफ्त राशन भी उपलब्ध कराया जाएगा। त्रिपुरा सरकार की ओर से दी गई जमीन का मालिकाना हक मिलने के बाद उन्हें डेढ़ लाख रुपये मकान बनाने के लिए दिए जाएंगे। अमित शाह ने कहा कि वे अब त्रिपुरा के निवासी माने जाएंगे।

त्रिपुरा के शरणार्थी शिविरों में रह रहे ब्रू जनजातियों के मुद्दे पर गुरुवार को नई दिल्ली में समझौते पर हस्ताक्षर के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (मध्य में), त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव (दाएं) और मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरामथांगा (बाएं)। प्रेट्र

### मिजोरम में 30 हजार से अधिक ब्रू शरणार्थी

मिजोरम के 30 हजार से ज्यादा ब्रू जनजाति के लोगों को शरणार्थी का जीवन बिताना पड़ रहा है। 1997 में मिजो जनजाति से संघर्ष के बाद ब्रू जनजाति के ये लोग स्थायी रूप से त्रिपुरा में रह रहे हैं।

**कौन हैं ब्रू जनजाति** : ब्रू या रिआंग जनजाति के लोग पूर्वोत्तर के राज्यों में बसते हैं। खासतौर से ये मिजोरम, त्रिपुरा और दक्षिणी असम में बसे हैं। यह मिजोरम के ममित और कोलासिब जिलों में बसे थे।

### ऐसे शुरू हुआ संघर्ष

1995 में मिजो और ब्रू के बीच संघर्ष के बाद युवा मिजो एसोसिएशन और मिजो स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने ब्रू जनजाति को राज्य में मताधिकार से वंचित किए जाने की मांग की। विवाद था कि ये मिजोरम के स्थायी निवासी नहीं हैं। इसके बाद उग्रवादी संगठन बीएनएलएफ और बीएनयू अस्तित्व में आए। 21 अक्टूबर 1997 में बीएनएलएफ उग्रवादियों ने मिजोरम में एक वन अधिकारी को मार गिराया। इसके जवाब में जातीय हिंसा शुरू हो गई। बीएनयू ने स्वायत्तशासी आदिवासी जिले बनाने की मांग की।

# रक्षा मंत्री ने देश को समर्पित किया स्वदेशी के-9 वज्र टैंक

**राज्य ब्यूरो, अहमदाबाद**

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को सूरत के हजीरा में लार्सन एंड टुब्रो (एल एंड टी) के आर्मर्ड सिस्टम्स कांप्लेक्स में निर्मित के-9 वज्र टैंक देश को समर्पित किया। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत यह पूरी तरह देश में निर्मित तोप है।

टैंक की फ्लैगशिप सेरेमनी में राजनाथ सिंह ने बताया कि लार्सन एंड टुब्रो को भारतीय सेना ने सौ के-9 वज्र टैंक बनाने का ऑर्डर दिया है। अब तक 51 टैंक तैयार किए जा चुके हैं। यह टैंक जैविक हमले से सुरक्षित है और 15 सेकेंड में एक साथ तीन गोले छोड़ने में सक्षम है। 100 हॉर्सपावर का इंजन इस टैंक को ताकतवर बनाता है। ऑटोमैटिक लोडेड क्षमता से लैस यह टैंक 40 किमी तक दुश्मन को मार गिराने में सक्षम है।

रक्षा मंत्री ने कहा कि भारतीय सेना आज पहले से काफी मजबूत और आधुनिक हथियारों से सुसज्जित हुई है। इसी कड़ी में देश में पहली बार डिफेंस इंवेस्टमेंट सेल का गठन होगा जो देश के आर्मर्ड सिस्टम को आत्मनिर्भर बनाने के साथ-साथ इसके आधुनिकीकरण और निवेश को देखेगा। उन्होंने कहा कि इससे पहले देश में यह बात सोची ही नहीं गई कि सैन्य क्षेत्र में निजी भागीदारी हो सकती है। इसका सबसे अधिक लाभ सेना को ही होगा। लार्सन एंड टुब्रो रक्षा क्षेत्र का रणनीतिक साझीदार है जो टैंक बना रहा है, अब आर्मर्ड व्हीकल भी बनाए जाएंगे।

राजनाथ ने कहा कि देश की सेना की जरूरत के 500 कंपोनेंट अभी विदेश से आयात किए जा रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में इनमें से अधिकतर का मेक इन इंडिया के तहत देश में ही निर्माण संभव होगा। वर्ष 2025 तक देश के सैन्य साजो-सामान का टर्नओवर एक लाख 70 हजार करोड़ रुपये या करीब 26 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। इस क्षेत्र में 23 मिलियन युवाओं को रोजगार देने की क्षमता है। समारोह में लार्सन एंड टुब्रो के ग्रुप चेयरमैन एम. नायक भी मौजूद थे।

गुजरात के सूरत में गुरुवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वदेश निर्मित के-9 वज्र टैंक को विधिपूर्वक पूजा-अर्चना के साथ देश को समर्पित किया। इस दौरान टैंक पर स्वास्तिक बनाते राजनाथ सिंह। प्रेट्र

### भारतीय तटरक्षकों को 50 जहाज और 16 एडवांस हल्के हेलीकॉप्टर मिलेंगे

**चेन्नई, प्रेट्र** : भारतीय तटरक्षकों के बेड़े में 50 नये जहाज और 16 एडवांस हल्के हेलीकॉप्टर और जुड़ जाएंगे। इसके साथ ही भारतीय तटरक्षकों के पास वर्ष 2025 तक कुल 200 जहाज और 100 विमान होंगे। तटरक्षक महानिदेशक कृष्णस्वामी नटराजन ने गुरुवार को बताया कि अमेरिका के बाद जापान के पास दुनिया का दूसरे सबसे बड़े तटरक्षक सुरक्षा बल हैं। 145 जहाजों और 62 विमानों के साथ भारतीय तटरक्षकों को दुनिया का चौथा सर्वश्रेष्ठ तटरक्षक होने का दर्जा हासिल हुआ है। उन्होंने बताया कि इस समय विभिन्न भारतीय शिपयार्ड में 50 जहाज निर्माणाधीन हैं। इसके अलावा, बेंगलुरु स्थित एचएएल में 16 एमके3 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टरों का उत्पादन हो रहा है। चेन्नई के तट से 50 नॉटिकल मील दूर भारत-जापान के 19वें संयुक्त अभियान के बाद नटराजन ने बताया कि मार्च 2020 तक ट्विन इंजन वाला पहला हेलीकॉप्टर दस्ते में शामिल होने की उम्मीद है।

# नई शिक्षा नीति के लिए मिल सकता है खास पैकेज

**जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली**

▶ प्रस्तावित नीति की ज्यादातर सिफारिशों को पांच साल में ही अमल करने का है प्रस्ताव

बजट में इस बार शिक्षा क्षेत्र को मजबूती देने वाली कुछ बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। वैसे भी नई शिक्षा नीति के माध्यम से इसे मजबूती देने का पूरा मसौदा तैयार है। अभी इसकी अधिकारिक घोषणा शेष है, लेकिन इसके अमल को लेकर सरकार को एक बड़ी पूंजी की जरूरत होगी। ऐसे में सरकार इसके लिए एक पैकेज की घोषणा कर सकती है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने भी इसे लेकर वित्त मंत्रालय को अपनी राय दी है।

वैसे भी पिछले वर्षों में सरकार का जोर शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने पर दिखा था। ऐसे में माना जा रहा है कि अब शिक्षा को लेकर जो भी प्रावधान होगा, वह नई शिक्षा नीति को केंद्रित करते हुए ही होगा। स्कूली शिक्षा की तर्ज पर इस बार उच्च शिक्षा के बिखरे ढांचे को भी समेटने की कोशिश हो सकती है। इसमें विश्वविद्यालय, तकनीकी संस्थान, प्रबंधन संस्थान और टीचर एजुकेशन जैसे क्षेत्रों में बंटी पूरी उच्च शिक्षा को एक दायरे में लाया जा सकता है। दो साल पहले प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक जैसे स्कूली शिक्षा को एक साथ जोड़कर समग्र शिक्षा के दायरे में लाया गया था।

सूत्रों के मुताबिक, प्रस्तावित नई शिक्षा नीति के अमल का फिलहाल जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है, उसके तहत अगले पांच वर्षों में उसे पूरी तरह से लागू करने की सिफारिश की गई है। ऐसे में इस बदलाव के लिए सरकार को भारी भरकम बजट की भी जरूरत होगी। मौजूदा समय में शिक्षा का जो बजट है, उनमें प्रस्तावित नई शिक्षा नीति की सिफारिशों को लागू करना संभव नहीं है। मौजूदा समय में देश में शिक्षा का कुल बजट करीब 94 हजार करोड़ रुपये है। इनमें स्कूली शिक्षा के लिए करीब 56 हजार करोड़ रुपये और उच्च शिक्षा के लिए करीब 38 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

## हाई-फाई ट्रेन

रेल मंत्री पीयूष गोयल हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना, आइआरसीटीसी की दूसरी लग्जरी ट्रेन की अहमदाबाद से होगी शुरुआत, मुख्यमंत्री रूपाणी रहेंगे मौजूद

# अहमदाबाद-मुंबई तेजस को आज हरी झंडी

**नई दिल्ली, प्रेट्र** : रेल मंत्री पीयूष गोयल व गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी शुक्रवार को अहमदाबाद-मुंबई तेजस एक्सप्रेस को अहमदाबाद से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। यह दूसरी ऐसी ट्रेन है, जिसका संचालन रेलवे की खानपान व पर्यटन इकाई आइआरसीटीसी करेगी। इस प्रकार की पहली ट्रेन पिछले साल लखनऊ से दिल्ली के बीच चलाई जा चुकी है।

रेलवे ने बताया कि इस ट्रेन का परिचालन 19 जनवरी को अहमदाबाद से किया जाएगा। टिकट की बुकिंग ऑनलाइन होगी। आइआरसीटीसी की वेबसाइट और उसके ऑनलाइन साझीदार पेटीएम, फोनपे, मेक माई ट्रिप, गूगल, आइबीबो, रेल यात्री आदि एप के माध्यम से टिकट बुक किए जा सकते हैं। ट्रेन संख्या 82902/82901 अहमदाबाद-मुंबई-अहमदाबाद का संचालन हफ्ते में छह दिन किया जाएगा। गुरुवार को ट्रेन का मेंटेनेंस कार्य होगा। पूरी तरह वातानुकूलित तेजस में एक्जक्यूटिव क्लास चेयर कार की दो बोगियां होंगी, जिनमें 56-56 सीटें होंगी। इसके अलावा चेयर कार की आठ बोगियां होंगी और प्रत्येक में 78 साटों का प्रावधान होगा। इस ट्रेन की कुल क्षमता 736 यात्रियों की है। अहमदाबाद से यह सुबह 6:40 बजे चलेगी और दोपहर 1:10 बजे मुंबई पहुंचेगी। इस बीच यह नांदेड़, वडोदरा, भरूच, सूरत, वापी और बोरीवली में रुकेगी। वापसी में मुंबई से अपराह्न 3:40 बजे चलेगी और अहमदाबाद में रात 9:55 बजे पहुंचेगी।

पीयूष गोयल फाइल फोटो

इसके टिकट में किसी भी प्रकार की रियायत नहीं मिलेगी। पांच साल से ज्याद उम्र के बच्चों का भी पूरा टिकट लगेगा और उन्हें सीट आवंटित की जाएगी। बुकिंग के दौरान पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों का उल्लेख करना होगा। हालांकि, इनका न तो किराया लगेगा, न ही सीट आवंटित होगी। तेजस में डायनेमिक फेयर का प्रावधान होगा। यानी, व्यस्त और कम व्यस्त तथा मांग के अनुरूप किराये में बदलाव होगा। इसमें तत्काल कोटा नहीं होगा।

**यात्रियों को 25 लाख का मुफ्त बीमा** : आइआरसीटीसी तेजस में यात्रा करने वाले सभी लोगों को 25 लाख का यात्रा बीमा मुफ्त में देगी। इसमें यात्रा के दौरान यात्रियों के सामान की चोरी और डकैती जैसी वारदातों के लिए भी एक लाख के बीमा का प्रावधान शामिल है।

**विदेशी पर्यटकों के लिए 18 सीटें रहेंगी आरक्षित** : इस ट्रेन में विदेशी पर्यटकों के लिए कुल 18 सीटें आरक्षित रहेंगी। इनमें ईसी की छह और सीसी की 12 सीटें शामिल हैं।

**ट्रेन देर हुई तो आइआरसीटीसी यात्रियों को देगी मुआवजा** : अन्य खास सुविधाओं के साथ-साथ अहमदाबाद-मुंबई तेजस एक्सप्रेस के यात्रियों के लिए आइआरसीटीसी ने पहली बार मुआवजे का प्रावधान किया है। इसके अनुसार, अगर ट्रेन एक घंटे से ज्यादा लेट होती है तो आइआरसीटीसी प्रत्येक यात्री को 100 रुपये का मुआवजा देगी, जबकि दो घंटे से ज्यादा लेट होने पर 250 रुपये का भुगतान करेगी।

# मैच फिक्सर संजीव चावला 20 को लाया जाएगा भारत

**जासं, नई दिल्ली** : वर्ष 2000 में भारत-दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टेस्ट सीरीज में भारत की जीत सुनिश्चित करने के लिए दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान हैंसी क्रोनिए को मैच फिक्सिंग करने के एवज में 30 हजार डॉलर देने का ऑफर करने वाले मैच फिक्सर संजीव चावला को 20 जनवरी को लंदन से प्रत्यर्पण पर भारत लाया जाएगा। लंदन हाई कोर्ट ने चावला की अपील खारिज कर दी है। टेस्ट सीरीज के तीसरे दिन भारत की जीत सुनिश्चित करने के लिए चावला ने हैंसी क्रोनिए को मैच हारने को कहा था। दोनों की बात लीक होने पर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच द्वारा केस दर्ज करते ही चावला लंदन भाग गया था। भारतीय पासपोर्ट रद होने पर लंदन की नागरिकता ले ली। मुख्य आरोपित चावला के लंदन में होने के कारण क्राइम ब्रांच उक्त केस की तफ्तीश नहीं कर पा रही थी। 20 साल बाद इस केस की जांच अब आगे बढ़ेगी।

## कह के रहेंगे

माधव जोशी

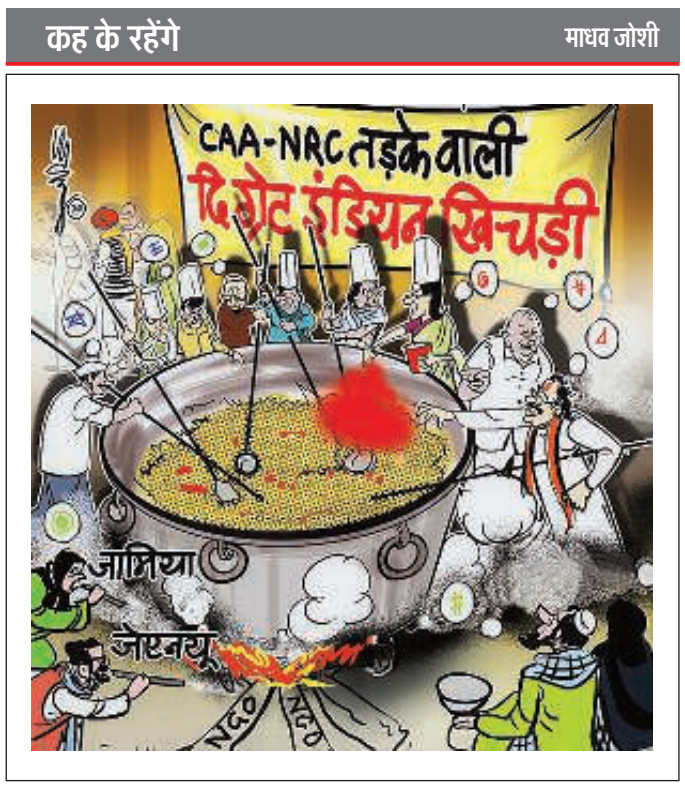

**2.97** करोड़ रुपये खर्च हुए महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली कैबिनेट के शपथग्रहण समारोह में। सूचना का अधिकार (आरटीआइ) के तहत मांगी गई जानकारी में ये तथ्य सामने आए हैं। तीन लाख रुपये तो सिर्फ फूलों की सजावट पर खर्च किए गए हैं।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शुक्रवार 17 जनवरी 2020

## न्यूज गैलरी

### चुनाव आयोग ने केरल कांग्रेस का चुनाव चिह्न फ्रीज किया

**नई दिल्ली** : चुनाव आयोग ने केरल कांग्रेस (मणि) के चुनाव चिह्न दो पत्तियों को अस्थायी रूप से फ्रीज कर दिया है। आयोग दो घटकों के पार्टी पर दावे को लेकर चल रहे विवाद की जांच कर रहा है। आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने गुरुवार को यह जानकारी दी। (प्रेट्र)

### कांग्रेस ने सैलजानाथ को आंध्र प्रदेश का अध्यक्ष नियुक्त किया

**नई दिल्ली** : कांग्रेस ने साके सैलजानाथ को आंध्र प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। उन्हें एन. रघुवीरा रेड्डी को हटकर कमान दी गई है। पार्टी ने एन. तुलसी रेड्डी और शेख मस्तान वली को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। एक बयान जारी कर कांग्रेस ने एन. रघुवीर रेड्डी के योगदान की सराहना की है। (प्रेट्र)

### बंगाल के बांकुड़ा में जलाया भाजपा कार्यालय

**कोलकाता** : बंगाल के बांकुड़ा में बुधवार की रात भाजपा के कार्यालय को जला दिया गया। भाजपा ने बांकुड़ा में पार्टी कार्यालय को जलाए जाने के लिए सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते हुए राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर प्रहार किया। साथ ही आरोप लगाया कि तृणमूल की ओर से पार्टी के नेताओं को डराने की कोशिश की जा रही है। बताया गया कि बांकुड़ा जिले के चंदाई में बुधवार रात को भाजपा के कार्यालय को जला दिया गया। इस घटना के लिए भाजपा ने तृणमूल कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। भाजपा उपाध्यक्ष व मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस घटना के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला बोला। उन्होंने ट्वीट किया कि बंगाल के बांकुड़ा जिले के चंदई ग्राम इलाके में बीती रात भाजपा कार्यालय में आग लगा दी गई। (जासं)

### पूर्व सीएम जोगी के बंगले में कर्मी की मौत पर बवाल

**बिलासपुर** : छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बंगले मरवाही सदन में एक कर्मचारी की मौत पर बवाल मच गया है। कर्मचारी के परिजनों और ग्रामीणों ने गुरुवार को सड़क पर शव रख कर प्रदर्शन किया। वर्तमान में यह बंगला पूर्व सीएम की पत्नी व विधायक डॉ. रेणू जोगी के नाम पर आवंटित है। गौरतलब है कि जोगी के बंगले में काम करने वाले कर्मचारी मनवा उर्फ संतोष कौशिक (30) का शव बुधवार की शाम को फंदे पर लटकता मिला था। गुरुवार को पोस्टमार्टम के बाद ग्रामीण व परिजनों ने ने चक्काजाम कर दिया। नाराज ग्रामीण व परिजन इस मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग कर रहे थे। साथ ही परिजन को मुआवजा राशि देने की मांग कर रहे थे। अधिकारियों ने जांच का भरोसा दिलाया, तब मामला शांत हुआ। (नईदुनिया)

# 'नीतीश के नेतृत्व में ही लड़ेंगे बिहार विस चुनाव'

**गृहमंत्री शाह बोले** ▶ जदयू-भाजपा का गठबंधन अटूट, लालटेन से एलईडी युग में लेकर आएं हैं राज्य को

### नागरिकता संशोधन कानून पर विपक्षी पार्टियों पर दंगे कराने का लगाया आरोप

**जागरण संवाददाता, वैशाली**

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एलान किया है कि राजग बिहार विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ेगा। उन्होंने दो टूक कहा कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व पर किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए। वह गुरुवार को नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) पर वैशाली में आयोजित जन जागरूकता सभा को संबोधित कर रहे थे। करीब आधे घंटे के संबोधन में शाह विपक्षी दलों पर जम कर बरसे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की अगुआई में विपक्षी पार्टियां सीएए के विरोध में दंगे करा रही हैं। राजद-कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए शाह ने कहा कि जंगलराज में बिहार 3 फीसद की दर से विकास कर रहा था, जबकि राजग की सरकार में 11 फीसद की दर से विकास हुआ हैं। लालू बिहार को लालटेन युग में छोड़ कर गए थे, हम एलईडी युग लेकर आए हैं। लालू लूट-ऑर्डर का राज चलाते थे, हम लॉ एंड ऑर्डर का राज चला रहे हैं।

**मत के लालच में मारी गई है मति** : शाह ने कहा कि राहुल बाबा, लालू, ममता और केजरीवाल पाकिस्तान के साथ सुर से सुर मिला रहे हैं। इमरान खान के साथ सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक का सुबूत मांग रहे हैं। सीएए और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) पर जनता को गुमराह कर रहे हैं। मत (वोट) के लालच में विपक्षियों की मति मारी गई हैं।

**फिर दोहाराया, नागरिकता देने के लिए है सीएए** : बकौल शाह, सीएए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक रूप से प्रताड़ित हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए लाया गया है। इससे किसी की नागरिकता छीनने का सवाल ही पैदा नहीं होता है।

विपक्षी पार्टियां राजनीतिक स्वार्थ के लिए युवाओं को खासकर मुस्लिम भाइयों को गुमराह कर रहीं हैं। कहा, मैं मुसलमान भाइयों से अपील करता हूं कि वे सीएए को पढ़ें। राहुल बाबा, लालू यादव, अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी को भी कहना चाहता हूं कि वे भ्रम फैला कर देश की जनता को गुमराह करना बंद करें।

**दलितों के साथ अन्याय कर रहा विपक्ष** : शाह ने कहा कि दूसरे देशों से भारत में अपनी इज्जत बचाने आए हिंदू शरणार्थियों में 70 फीसद से अधिक दलित हैं। देश के दलित और आदिवासी आज यह देख रहे हैं कि कांग्रेस, सपा ,बसपा, राजद, तृणमूल, आप और कम्युनिस्ट पार्टियां किस तरह दलितों के खिलाफ काम कर रही हैं।

**अयोध्या में बनेगा गगनचुंबी मंदिर** : भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि कश्मीर से अनुच्छेद 370- 35ए हटाने, तत्काल तीन तलाक कानून, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद अयोध्या में गगनचुंबी मंदिर बनाने जैसी नरेंद्र मोदी की पहल से विपक्षी पार्टियां बौखला गई हैं। सभा में मुख्य मंच पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय, अश्विनी चौबे, उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी, बिहार भाजपा के संगठन महामंत्री नागेंद्र नाथ और आबिहार सरकार में शामिल भाजपा के मंत्री उपस्थित थे।

बिहार के वैशाली में गुरुवार को भाजपा की ओर से आयोजित जनजागरण सभा में दरभंगा के सांसद गोपालजी ठाकुर (मिथिला पेंटिंग उठाते) ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पारंपरिक मिथिला टोपी और मखाना की माला पहनाने के बाद मिथिला पेंटिंग भेंट कर स्वागत किया। साथ हैं बाएं से, केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय और उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी। जागरण

### बिहार में महागठबंधन में रह सबसे अधिक मजबूती से चुनाव लड़ेगी कांग्रेस

**राज्य ब्यूरो, पटना**

प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी सचिव अजय कपूर ने कहा कि कांग्रेस महागठबंधन में रहकर सबसे अधिक मजबूती से चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि राजद को भले ही सब अधिक मजबूत मानते हैं, लेकिन कांग्रेस पूरी तैयारी से चुनावी मैदान में उतरेगी। राज्य सरकार के खिलाफ कांग्रेस अपना आंदोलन भी तेज करेगी। आंदोलन का नया प्रारूप तैयार किया जा रहा है। पार्टी सभी 243 सीटों पर चुनावी तैयारी कर रही है और वहां संगठन सुदृढ़ करने का प्रयास आरंभ हो गया है। वे गुरुवार को यहां पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे।

कपूर ने कांग्रेस के अकेले चुनाव लड़ने की संभावना को खारिज करते हुए कहा कि गठबंधन तो राष्ट्रीय स्तर पर समय की पुकार है। उन्होंने कहा कि पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी यह चुनाव के समय आलाकमान तय करेगा, लेकिन हम सभी सीटों पर खुद को मजबूत करेंगे ताकि महागठबंधन को इसका पूरा लाभ मिले। राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार शिक्षा, नौकरी, आर्थिक आदि सभी मोर्चों पर विफल साबित हो चुकी है। उम्मीद थी कि यह सरकार विकास करेगी लेकिन यह फेल निकली।

### बिरला बोले, सदन में मर्यादा का पालन करना जरूरी

**राज्य ब्यूरो, लखनऊ** : लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गुरुवार को कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन (सीपीए) के सातवें सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए जनप्रतिनिधियों को न सिर्फ नसीहत दी, बल्कि सदन की मर्यादा बनाए रखने का आह्वान भी किया। उन्होंने कहा कि भारतीय लोकतंत्र निश्चित ही सहमति व असहमति का रहा है लेकिन, लोकतांत्रिक मापदंड सदैव ऊंचे रहे हैं। जनप्रतिनिधियों को मर्यादा का पालन करते हुए जनता के मुद्दे उठाने चाहिए।

लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि लोकतंत्र में निर्वाचित जनप्रतिनिधि जनता तक एक सेतु के रूप में काम करते हैं। उनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य कानून बनाना है। इसके लिए वाद-विवाद भी चलता है लेकिन, मर्यादा का बना रहना बहुत जरूरी है। संसद व विधान मंडल जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। सरकार की गतिविधियों पर भी निगरानी रखने का दायित्व है। संसदीय समितियों के माध्यम से अपनी बात को कहने का सुझाव देते हुए ओम बिरला ने बजटीय प्रावधानों की समीक्षा करने पर बल दिया। बजट का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, इसका ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि सारा देश चिंतित रहता है कि सदन बिना व्यवधान के कैसे चले? इसके लिए नियम बनाए जाने चाहिए। उन्होंने विपक्ष की बातों को ध्यान से सुनने का आग्रह भी किया। वहीं सीएमयोगी ने कहा कि लोकतंत्र में तमाम चुनौतियां भी हैं जिनका समाधान ऐसे सम्मेलनों से निकलेगा।

# मध्य प्रदेश के सिंधिया के सम्मान में डिनर 'डिप्लोमेसी' ने बढ़ाई सियासी सरगर्मी

**नईदुनिया, भोपाल**

मध्य प्रदेश में कांग्रेस अध्यक्ष, राज्यसभा चुनाव और आने वाले नगरीय निकाय चुनाव के पहले कांग्रेस में एक और 'डिनर डिप्लोमेसी' (रात्रि भोज) ने पार्टी की सियासत गरमा दी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के सम्मान में परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के निवास पर आयोजित रात्रि भोज को शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है।

सुर्खियों में रहे इस भोज में केवल मंत्री-विधायक ही आमंत्रित थे। कांग्रेस में 'डिनर डिप्लोमेसी' का यह पहला अवसर नहीं था। इसके पहले स्वास्थ्य मंत्री तुलसीराम सिलावट और विधायक आरिफ मसूद भी विधायकों को भोज देकर सुर्खियां बटोर चुके हैं। करीब चार महीने बाद गुरुवार को भोपाल प्रवास पर आए सिंधिया के सम्मान में मंत्री राजपूत ने यह आयोजन किया था। राजपूत के निवास पर भोज में मुख्यमंत्री कमलनाथ के आने को लेकर देर रात तक अटकलें चलती रहीं। इससे पहले दिल्ली में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से हुई उनकी मुलाकात भी मीडिया की सुर्खियां बनी थी।

भोज में मंत्री डॉ. गोविंद सिंह, डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ, बाला बच्चन, सुखदेव पांसे, इमरती देवी, जयवर्धन सिंह, बृजेंद्र सिंह राठौर, लाखन सिंह, प्रदीप जायसवाल, कमलेश्वर पटेल, ओमकार सिंह मरकाम एवं मंत्री महेंद्र सिंह के अलावा बसपा विधायक रामबाई, निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस विधायकों ने शिरकत की।

**भूरिया से बोले- कड़कनाथ खिलाओ:** सिंधिया ने राजपूत के निवास पर मौजूद वरिष्ठ नेता कांतिलाल भूरिया से हंसी-ठिठोली भी की। देखते ही बोले- आपको क्या कहूं? सांसद, विधायक अथवा मंत्री...। फिर उन्होंने शिकायती अंदाज में कहा कि आपने मुझे कभी झाबुआ नहीं बुलाया। अब जल्द बुलाओ और कड़कनाथ सहित आदिवासियों के लोकप्रिय क्षेत्रीय आयटम भी खिलाओ।

**विस अध्यक्ष से मिलने पहुंचे:** भोपाल आने के बाद सिंधिया ने पूर्व विधायक महेंद्र सिंह यादव के यहां शादी समारोह में शिरकत की। उसके बाद वह विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति से मिलने उनके निवास भी पहुंचे।

**राजनीति में संयम और मर्यादा बनाए रखता हूं : सिंधिया**

एक सवाल के जवाब में सिंधिया ने कहा कि मैं राजनीति में संयम और मर्यादा के स्तर को बनाए रखता हूं। मेरे पिताजी ने भी राजनीति में मर्यादा का एक स्तर बनाकर रखा था।

- सिंधिया समर्थक मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के घर रात्रि भोज पर जुटे मंत्री-विधायक
- मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा के चुनाव के पहले सक्रियता ने बढ़ाई अटकलें

# मोदी ने कहा, संघर्ष टालने का भारतीय तरीका बातचीत का, ना कि कठोर बल

**नई दिल्ली, प्रेट्र** : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया जब बददिमाग नफरत, हिंसा, संघर्ष और आतंकवाद से निजात की राह ढूंढ रही है तो भारतीय जीवन पद्धति उनके लिए आशा की किरण है। उन्होंने कहा कि संघर्ष को टालने का भारतीय तरीका कठोर बल प्रयोग नहीं बल्कि बातचीत की शक्ति है।

प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को वीडियो के जरिए केरल के कोझिकोड में 'भारतीय विचारों का वैश्वीकरण' पर एक सेमिनार को संबोधित करते हुए कहा, 'जब खुलापन होता है तो विभिन्न विचारों और खोजों के प्रति आदर स्वाभाविक रूप से आता है।' उन्होंने कहा कि शोध के प्रति भारतीयों के उत्साह के चलते विश्व का ध्यान देश की ओर खिंच रहा है।

दुनिया भारत की ओर उसके शांति, एकता और भाईचारे के गुणों के चलते ही देख रही है। विभिन्न भाषाओं, परंपराओं, आदतों और विश्वासों के बावजूद सदियों से हम शांति से रहते आ रहे हैं। सदियों से अपनी भूमि पर हमने दुनिया का स्वागत किया है। हमारी सभ्यता समृद्ध होती गई जबकि बहुतों के साथ ऐसा नहीं हुआ। किस लिए, क्योंकि यहां उन्हें शांति और समरसता मिली।

पीएम मोदी ने कहा कि भारत की ताकत ही यही है कि उसके विचार अब जीवंत परंपराएं बन चुकी हैं। सरल और संवर्द्धित परंपराओं में कठोरता नहीं है। वैश्विक शांति का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि दशकों से भारत संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक शांति अभियानों का सबसे बड़ा हिस्सा रहा है। अगर दुनिया के सबसे संघर्ष वाले इलाकों में शांति की हल्की सी भी गुंजाइश रही है तो हमारे सैनिकों ने वहां महती भूमिका निभाई है।

मोदी ने कहा कि भारत का मानना है कि अगर वह प्रगति करेगा तो विश्व प्रगति करेगा। जब विश्व समृद्ध होगा तो भारत को भी उसका लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि भारतीय सभ्यता समृद्ध होती रही क्योंकि वह हर अच्छी चीज को आत्मसात करने को तत्पर है।

विश्व को भारतीय योगदान का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि शून्य की खोज ने गणित के अध्ययन की दिशा ही बदल गई। हमारा देश ऊर्जावान युवाओं से भरपूर है। हमारी विविधता भरी आबादी हमें निवेश के लिए सर्वोच्च बनाती है। उद्योग जगत से हर कोई आज भारत में होना चाहता है। प्रधानमंत्री ने आइआइएम कैंपस में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का भी अनावरण किया।

- कहा-शोध के प्रति भारतीयों के उत्साह के चलते विश्व का ध्यान देश की ओर खिंच रहा
- भारत प्रगति करेगा तो विश्व प्रगति करेगा, विश्व समृद्ध होगा तो भारत को भी लाभ होगा

प्रधानमंत्री मोदी। फाइल

# फिल्म 'तान्हाजी' को लेकर महाराष्ट्र में सियासत तेज

**नई दिल्ली, जेएनएन**

फिल्म 'तान्हाजी, द अनसंग वॉरियर' रिलीज के पहले हफ्ते में ही 100 करोड़ से ज्यादा का कारोबार करने वाली साल की पहली फिल्म बन गई है। एक तरफ 'तान्हाजी' 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो गई है तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र के इस वीर मराठा सरदार की कहानी पर बनी फिल्म को उत्तर प्रदेश सरकार ने सबसे पहले टैक्स फ्री कर दिया। इसके बाद हरियाणा सरकार ने भी फिल्म को टैक्स फ्री करने की घोषणा कर दी। राजनीति के जानकारों का कहना है कि योगी सरकार के इस कदम के बाद शिवसेना पर 'तान्हाजी' को टैक्स फ्री करने का दबाव बढ़ गया है। महाराष्ट्र की राजनीति पर पैनी नजर रखनेवाले राजनीतिक विश्लेषक अभय देशपांडे के अनुसार, 'शिवसेना के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार को पहले ही फिल्म तान्हाजी के बारे में फैसला लेना चाहिए था। लेकिन, जिस तरह से सरकार अभी ठीक से काम करना भी शुरू नहीं कर पाई है, उससे लगता है कि इस मसले पर भी चूक हो गई। शायद, कौन सा मंत्रालय फिल्म तान्हाजी को टैक्स फ्री करने प्रस्ताव कैबिनेट के पास भेजे, इसको लेकर भी भ्रम बना रहा और भाजपा की राज्य इकाई की मांग के बावजूद इसपर फैसला नहीं हो सका।' भाजपा शासन वाले दो राज्यों द्वारा तान्हाजी के संघर्ष पर बनी फिल्म को टैक्स फ्री करने को लेकर महाराष्ट्र में भी सरगर्मी जारी है। कांग्रेस नेता से लेकर महाराष्ट्र के डिब्बावाला एसोसिएशन ने भी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मराठा सरदार और शिवाजी के सहयोगी रहे तान्हाजी पर बनी इस फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग की है। शिवसेना पर इस बात को लेकर चौतरफा दबाव बन रहा है कि वह 'तान्हाजी' को टैक्स फ्री करे। बुधवार देर शाम महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री बालासाहेब थोराट ने लिखा कि 'तान्हाजी फिल्म को टैक्स फ्री करने के संदर्भ में बुधवार को मंत्रिमंडल में एकमत से निर्णय लिया गया। राज्य सरकार ने एसजीएसटी वापस लेने का निर्णय लिया है। इसकी घोषणा जल्दी ही मुख्यमंत्री करेंगे।' इस ट्वीट के 24 घंटे बाद भी कोई फैसला नहीं हो पाया।

# सत्ता की सहूलियत और अवसरवाद पर बना है महाराष्ट्र का गठबंधन : जावडेकर

**नई दिल्ली, प्रेट्र** : इंदिरा गांधी की गैंगस्टर करीम लाला से मुलाकात से संबंधित अपने बयान से शिवसेना नेता संजय राउत के पलटने के बाद भाजपा ने महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ गठबंधन को अवसरवादी करार दिया है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने गुरुवार को कहा कि हर दिन बयान से पलटने से पहले कुछ 'सच' उजागर होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं पर अक्सर मुंबई बम धमाकों के आरोपित दाऊद इब्राहिम के देश से भागने में मदद करने के आरोप लगते रहे हैं।

गठबंधन पर निशाना साधते हुए जावडेकर ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि आने वाले समय में हर तरह के 'सिनेमाई अनुभव' होंगे। वापस लिए जाने से पहले प्रतिदिन एक सच्चाई सामने आएगी। उन्होंने कहा कि यह गठबंधन सत्ता की सहूलियत और अवसरवाद पर बना है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राउत का बयान कांग्रेस की 'सांप्रदायिक राजनीति' को दिखाता है कि वह एक गैंगस्टर को समुदाय का नेता मानती थी और वोट बैंक के लिए उससे समुदाय के प्रतिनिधि के तौर पर व्यवहार करती थी। शिवसेना पर निशाना साधते हुए जावडेकर ने कहा कि उसके नेता अब बाल ठाकरे को 'हिंदू हृदय सम्राट' के तौर पर प्रस्तुत नहीं करते।

### इंदिरा गांधी की प्रशंसा करने से कभी परहेज नहीं किया : राउत

▶ प्रथम पृष्ठ से आगे

राउत ने अन्य एक ट्वीट में शिवसेना विधायक आदित्य ठाकरे, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजीव सातव को टैग करते हुए कहा, 'मैंने लौह महिला के रूप में इंदिरा गांधी की प्रशंसा करने से कभी परहेज नहीं किया, जो कड़े निर्णय लेती थीं। हैरानी की बात यह है कि जो लोग इंदिराजी का इतिहास नहीं जानते वे ही शोर मचा रहे हैं।

विवाद में शामिल होते हुए महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने सवाल किया कि क्या यह राज्य में 'राजनीति के अपराधीकरण' की शुरुआत थी और क्या कांग्रेस ने मुंबई में हमला करने वालों का 'समर्थन' किया था? क्या उन दिनों चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस को बाहुबलियों की जरूरत पड़ती थी?

इससे पहले राउत की टिप्पणी को गलत बताते हुए महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष बाला साहेब थोराट ने कहा कि उनकी पार्टी ऐसी टिप्पणियों को बर्दाश्त नहीं करेगी और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को नाराजगी से अवगत करा दिया गया है। उद्धव सरकार में राजस्व मंत्री थोराट ने राउत समेत सभी नेताओं को आगाह किया कि वे महान नेताओं पर टिप्पणी से परहेज करें। थोराट ने इंदिरा गांधी को गैंगस्टरों पर लगाम लगाने का श्रेय दिया।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ने एक कदम आगे बढ़कर कहा कि पार्टी दिवंगत प्रधानमंत्री पर टिप्पणी बर्दाश्त नहीं करेगी और इसके लिए कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार है।

# भाजपा में विलय के लिए सरकार से समर्थन वापस लेंगे मरांडी

**राज्य ब्यूरो, रांची**

झारखंड के सर्वाधिक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम में सबकी नजर झाविमो प्रमुख बाबूलाल मरांडी के रुख पर है। गुरुवार को वह एक सप्ताह के विदेश भ्रमण के बाद रांची पहुंचे और आते ही गतिविधियां तेज कर दीं। बाबूलाल मरांडी सारी तैयारियां भीतर ही भीतर कर रहे हैं और भाजपा में विलय को लेकर गोलमोल जवाब दे रहे हैं। अलबत्ता यह तय हो गया है कि वह अपनी पार्टी का विलय करेंगे और इसके लिए आवश्यक तकनीकी जटिलताओं को दूर करने में लगे हैं। जल्द ही वे झाविमो की नई कार्यकारिणी का गठन करेंगे। इसके अलावा वह राज्य में नवगठित हेमंत सोरेन की सरकार से समर्थन वापस लेंगे। झारखंड विकास मोर्चा के तीन विधायकों ने सरकार को बाहर से बिना शर्त समर्थन दे रखा है। हालांकि इससे हेमंत सोरेन की सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

**दोनों विधायकों को मनाने की कोशिश** : बाबूलाल मरांडी की हरसंभव कोशिश है कि वह अपने दोनों विधायकों प्रदीप यादव और बंधु तिर्की को अपने साथ रहने के लिए राजी करें। संभावना है कि प्रदीप यादव देर-सवेर साथ आएं, लेकिन बंधु तिर्की के मानने की गुंजाइश कम है। दोनों विधायकों ने बगावती तेवर दिखाए तो बाबूलाल मरांडी उन्हें दल से निष्कासित कर देंगे। ऐसी स्थिति में दोनों विधायक किसी अन्य दल में जाने की स्थिति में भी नहीं होंगे और बाबूलाल मरांडी को पार्टी के विलय में कोई अड़चन नहीं आएगी। दरअसल भाजपा की ओर से यही संदेश झाविमो को दिया गया है कि पार्टी का पूर्ण विलय किया जाए।

**संभावित योजना**

- झाविमो की नई कार्यसमिति गठित करेंगे, जल्द बुलाएंगे बैठक।
- कार्यसमिति की मंजूरी लेकर करेंगे भाजपा में विलय का एलान।
- बाबूलाल भरसक कोशिश करेंगे कि दोनों विधायक आएं उनके साथ।
- अगर साथ आने को राजी नहीं हुए तो दोनों विधायक को निष्कासित कर देंगे।

**विवाद के आसार**

10 निगम और 16 परिषद होंगी निकाय विभाग से अलग, सिर्फ 57 नगर पालिकाएं रहेंगी शहरी निकाय विभाग में शामिल

# अब टूटेगा विज का शहरी निकाय विभाग

**राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़**

हरियाणा में सीआइडी को गृह विभाग से अलग करने की अटकलों के बीच प्रदेश सरकार सभी 10 नगर निगमों और 16 नगर परिषदों को शहरी निकाय विभाग से अलग करने की तैयारी कर रही है। यदि ऐसा हुआ तो शहरी निकाय विभाग के पास सिर्फ नगर पालिकाएं रह जाएंगी। तब नगर निगम व नगर परिषदों का अलग अस्तित्व होगा। खास बात यह है कि गृह विभाग की तरह शहरी निकाय विभाग के मंत्री भी अनिल विज ही हैं। ऐसे में फिर से विवाद बढ़ने की आशंका जताई जा रही है।

उल्लेखनीय है कि अनिल विज सभी शहरी निकायों का स्पेशल ऑडिट कराने की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं।वहीं सीआइडी को गृह विभाग से अलग करने की तैयारी संबंधी विवाद पहले ही भाजपा हाईकमान के पास पहुंच चुका। विवाद को बढ़ने से रोकने के लिए हाईकमान शहरी निकाय विभाग को बांटने की तैयारी पर भी ब्रेक लगा सकता है। पिछले दिनों शहरी स्थानीय निकाय विभाग के एक बड़े अधिकारी ने बैठक में निगम और परिषद आयुक्तों को स्पष्ट संकेत दिया कि अब वे खुद ही अपना खर्चा उठाने की तैयारी कर लें। सरकार की ओर से उन्हें ग्रांट नहीं मिलेगी।

हरियाणा में 83 शहरी स्थानीय निकाय हैं, जिनमें 57 नगर पालिकाएं शामिल हैं। यदि ऐसा कोई प्रस्ताव सिरे चढ़ता है तो पहले कैबिनेट की मुहर जरूरी है, लेकिन कई विधायक नगर निगमों व परिषदों को शहरी स्थानीय निकाय विभाग से अलग करने के हक में नहीं हैं। शहरी निकायों की अपनी खुद की भी आय है और सरकार भी सालाना बजट देती है।

दरअसल शहरी निकायों के पास कमाई के सीमित संसाधन हैं, लेकिन खर्चे इससे कहीं अधिक हैं। सभी निकाय अपना वार्षिक बजट भी पेश करते हैं।

हरियाणा के नगर निगमों व नगर परिषदों को विभाग से अलग कर स्वतंत्र काम करने की जिम्मेदारी सौंपने की प्रक्रिया की मुझे जानकारी नहीं है। हो सकता है कि मुख्यमंत्री कार्यालय में कुछ चल रहा हो। इस बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता। मेरे पास यदि कोई फाइल आती है, तभी कुछ बता सकूंगा। अगर ऐसा कोई फैसला होता है तो फिर शहरी निकाय विभाग का कोई औचित्य नहीं रहेगा।

**-अनिल विज, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री, हरियाणा**

# 'गवाह व दस्तावेज में मेल नहीं, केस महज साजिश'

**राज्य ब्यूरो, रांची**

रांची के डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में आरोपित राजद प्रमुख लालू प्रसाद ने गुरुवार को सीबीआइ की विशेष अदालत में अपना बयान दर्ज कराया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हुजूर, हमारी छवि खराब करने के लिए सीबीआइ ने यह मुकदमा दर्ज किया है। फरवरी 1996 में जैसे ही मामला वित्त विभाग मेरे संज्ञान में लाया तो मैंने तुरंत केस दर्ज कराने का आदेश दिया था। बयान के दौरान लालू प्रसाद से कुल 34 सवाल पूछे गए और उन्होंने सभी सवालों का जवाब दिया। इस दौरान लालू प्रसाद करीब सवा दो घंटे तक अदालत में रहे। बयान दर्ज कराने के बाद निकलते समय लालू प्रसाद ने सीबीआइ के विशेष जज एसके शशि से हाथ जोड़कर विनती की। कहा- हुजूर, दुर्भावना से ग्रसित होकर मेरे खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। गवाह कुछ कहता है दस्तावेज कुछ और बयां करते हैं। दोनों में कोई मेल ही नहीं है।

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद रांची के सीबीआइ कोर्ट में चारा घोटाला के डोरंडा कोषागार से जुड़े मामले में अपना बयान दर्ज कराने पहुंचे। उन्होंने मुस्कुराकर सबका अभिवादन भी किया। जागरण

लालू प्रसाद सुबह 10:30 बजे ही अदालत पहुंचे गए। चारा घोटाला के चार मामलों में सजायाफ्ता लालू प्रसाद का रिम्स में इलाज चल रहा है। गुरुवार को बयान दर्ज कराने के लिए भारी सुरक्षा के बीच लालू को सीबीआइ कोर्ट लाया गया। सीबीआइ की ओर से 575 गवाह और कई हजार दस्तावेज अदालत में पेश किए गए हैं। इस मामले के 111 गवाहों में 110 की गवाही पूरी हो चुकी है। अदालत ने लालू प्रसाद सहित अन्य आरोपितों द्वारा अपने बचाव के लिए गवाहों की सूची सौंपने की तिथि 20 जनवरी निर्धारित की है। लालू से 34 सवाल पूछे गए। अदालत ने जब उनसे आरके राणा के माध्यम से 10 करोड़ रुपये लेने का सवाल पूछा तो उन्होंने कहा - जज साहब, नियम ऐसा टाइट है कि करोड़ों तो छोड़िये, बिना जांच के ट्रेजरी अफसर 10 रुपये नहीं देगा।

**33** लोगों के खिलाफ विशेष जांच दल (एसआइटी) ने बच्चों को नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान पत्थरबाजी करने के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। मामला उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का है।

## संविधान का अनुच्छेद 131
## अहम है यह प्रावधान

**नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ सड़कों पर हिंसक रोष के बाद अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उधर, छत्तीसगढ़ सरकार भी यूपीए सरकार के बनाए राष्ट्रीय जांच एजेंसी कानून को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। इन दोनों मामलों में एक बात समान है और वो अनुच्छेद 131 है। जिसके तहत राज्य सरकारें सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं। केंद्र और राज्य के बीच जब भी विवाद होता है यह अनुच्छेद सामने आता है। आइए जानते हैं क्या है यह अनुच्छेद और कैसे करता है काम।**

### यह है अनुच्छेद 131

सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में तीन तरह के मामले आते हैं, जिनमें वास्तविक, अपीलीय और परामर्श शामिल हैं। इनमें वास्तविक अधिकार क्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट के पास निर्णय देने की विशेष शक्तियां होती हैं। अनुच्छेद 131 के तहत मुकदमा तभी दाखिल किया जा सकता है जब वह केंद्र और राज्य सरकार के बीच हो। साथ ही इसमें कानून और तथ्यों को लेकर सवाल होना चाहिए। जिस पर राज्य या केंद्र के कानूनी अधिकार का अस्तित्व निर्भर करता है। 1978 में कर्नाटक राज्य बनाम भारत संघ के बीच विवाद को लेकर न्यायमूर्ति पीएन भगवती ने कहा था कि अनुच्छेद 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट को एक मुकदमे को स्वीकार करने के लिए, राज्य को यह दिखाने की आवश्यकता नहीं है कि उसके कानूनी अधिकार का उल्लंघन किया गया है, लेकिन विवाद में कानूनी सवाल शामिल होना चाहिए।

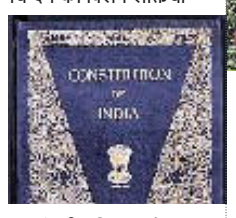

### विवादों के निपटारे के लिए सुप्रीम कोर्ट

संविधान के अंतर्गत बनाए गए कानूनों को उस वक्त तक संवैधानिक माना जाता है जब तक कि कोई अदालत उस पर रोक नहीं लगा देती है। हालांकि भारत के अर्द्ध संघीय ढांचे में अंतर सरकारी विवाद असामान्य नहीं है। संविधान निर्माताओं ने ऐसे मतभेदों की पहले से ही अपेक्षा की थी। यही कारण है कि उन्होंने समाधान के लिए सुप्रीम कोर्ट के वास्तविक मूल अधिकार क्षेत्र को जोड़ा। 1950 में अर्द्ध संघीय ढांचे की परिकल्पना की गई थी। इस परिकल्पना में राज्यों की शक्तियों को सम्मिलित किया गया था।

### अन्य याचिकाओं से ऐसे अलग

केरल सरकार के अतिरिक्त कई और याचिकाएं भी सीएए के खिलाफ दायर की गई हैं। हालांकि सीएए को चुनौती देने वाली दूसरी याचिकाओं को संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर किया गया है। यह मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर अदालत को रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। राज्य सरकार इस प्रावधान के तहत अदालत का रुख नहीं कर सकती है, क्योंकि केवल लोग और नागरिक मौलिक अधिकारों का दावा कर सकते हैं। अनुच्छेद 131 के तहत, चुनौती तब दी जाती है जब किसी राज्य या केंद्र के अधिकार और शक्ति का प्रश्न हो। हालांकि सीएए के खिलाफ दायर दोनों ही तरह की याचिकाओं में इस कानून को असंवैधानिक बताया गया है।

### राजनीतिक मतभेद सुलझाने के लिए नहीं

अनुच्छेद 131 का उपयोग विभिन्न दलों के नेतृत्व वाली राज्य और केंद्र सरकारों के बीच राजनीतिक मतभेदों को सुलझाने के लिए नहीं किया जा सकता है।

### केंद्र दे सकता है निर्देश

केंद्र के पास यह सुनिश्चित करने के लिए शक्तियां होती हैं, जिससे कानूनों को लागू किया जा सके। संसद द्वारा पारित कानून को लागू कराने के लिए केंद्र, राज्य सरकार को निर्देश दे सकता है। यदि राज्य सरकार इन निर्देशों का पालन नहीं करती है तो केंद्र सरकार अदालत को कानून के अनुपालन के लिए बाध्य करने के लिए राज्यों के खिलाफ एक स्थायी निषेधाज्ञा मांग सकती है। अदालत के आदेशों का पालन न करने पर अदालत की अवमानना हो सकती है, और अदालत आमतौर पर कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार राज्यों के मुख्य सचिवों को दोषी मानती है।

# बिना बताए सुप्रीम कोर्ट जाने पर आरिफ को आपत्ति

**सीएए का मामला** ▶ केरल के राज्यपाल ने कहा–प्रोटोकाल तोड़ना गलत, मैं रबर स्टैंप नहीं हूं

### सरकार को कहा–संविधान उन्हें किसी भी मुद्दे पर विचार करने का अधिकार सुनिश्चित करता है

**तिरुअनंतपुरम, एजेंसियां** : केरल में राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच तनातनी जारी है। राज्यपाल आरिफ मुहम्मद खान ने कहा कि उन्हें बताए बगैर नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ राज्य सरकार का सुप्रीम कोर्ट जाना उचित नहीं था। इस मामले में अपना रुख स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि वह एक 'रबर स्टैंप' नहीं हैं।

राज्यपाल खान ने गुरुवार को एयरपोर्ट पर संवाददाताओं से कहा कि अखबारों से खबर मिलने के बजाय प्रोटोकाल के मुताबिक उन्हें इस बारे में पहले से जानकारी दी जानी चाहिए थी। यहां तक कि विधायी नियमों के मुताबिक भी विधानसभा में ऐसे किसी भी विषय पर चर्चा नहीं होनी चाहिए जो उनके अधिकार क्षेत्र में न आता हो। उन्होंने कहा कि अगर वह सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो मुझे इस बात से कोई परेशानी नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि राज्य के संवैधानिक प्रमुख को इसकी जानकारी दिए बगैर जाना उचित नहीं है। मुझे इस मामले को देखना होगा।

राज्यपाल ने कहा कि इसके बावजूद केरल सरकार के सुप्रीम कोर्ट जाने में उन्हें कुछ गलत नहीं लगता क्योंकि संविधान ने यह अधिकार सुप्रीम कोर्ट को दिया हुआ है। लेकिन प्रोटोकाल के तहत उन्हें इस बारे में सबसे पहले जानकारी दी जानी चाहिए थी। उन्होंने इस बात पर भी आश्चर्य जताया कि क्या राज्यपाल की मंजूरी के बगैर राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट जा भी सकती है।

तिरुअनंतपुरम में गुरुवार को नागरिकता संशोधन कानून के मुद्दे पर केरल सरकार के सुप्रीम कोर्ट जाने पर मीडिया को प्रतिक्रिया देते राज्यपाल आरिफ मुहम्मद खान। प्रेट्र

इस रिपोर्ट पर कि उन्होंने केरल पंचायती राज अधिनियम 1994 पर दस्तखत करने से इन्कार कर दिया था, खान ने कहा कि वह रबर स्टैंप नहीं हैं। संविधान उन्हें किसी भी मुद्दे पर विचार करने का अधिकार सुनिश्चित करता है। उन्हें यह देखना होता है कि किसी अधिनियम का इस्तेमाल किसी अतिवादी मकसद के लिए न हो। वह इसे सुनिश्चित करते रहेंगे।

उल्लेखनीय है कि केरल सरकार ने विगत 13 जनवरी को सीएए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। माकपा के नेतृत्ववाली एलडीएफ सरकार का कहना था कि यह कानून संवैधानिक मूल्यों के विरुद्ध है।

### सीएए देश से किसी भी नागरिक को भगाने के लिए नहीं है : प्रज्ञा

**नईदुनिया, भोपाल** : भोपाल से भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह की ओर से जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 हटाए जाने के बाद जाकिर नाइक से समर्थन मांगे जाने के बयान में कोई सत्यता नहीं है। उन्होंने कहा कि सीएए देश से किसी भी नागरिक को भागने के लिए नहीं है। यह पाकिस्तान सहित अन्य पड़ोसी देशों में रह रहे हिंदू, सिंख, जैन, ईसाई, बौद्ध, पारसी के लिए हैं, जो धर्म के कारण वहां उपेक्षित हो रहे हैं। सीएए के विरोध में कोई अवॉर्ड वापसी नहीं हुई। ऐसे लोग जिन्होंने अवॉर्ड वापस किए थे, वे पाकिस्तान में रहकर देख लें, पता चल जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि जिन्होंने भगवा को आतंकवाद कहा, भोपाल की जनता ने उसे सजा दे दी। साध्वी ने नाम लिए बिना कहा कि जो भगवा को आंतकवाद कहते हैं, उनकी वंशावली बता दूं तो लोग उनको राजा कहना बंद कर देंगे।

### टुकड़े-टुकड़े गैंग को मिल रही विदेशी मदद : रिजिजू

**राज्य ब्यूरो, लखनऊ** : जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) सहित कुछ शैक्षिक संस्थानों में गर्माए माहौल के बीच केंद्रीय खेल एवं युवा कार्यक्रम राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) किरेन रिजिजू ने देशभर से जुटे युवाओं को राष्ट्रप्रेम का पाठ पढ़ाया। राष्ट्रीय युवा उत्सव के समापन समारोह में कहा कि जो लोग भारत के टुकड़े करने की बात करते हैं, उन्हें विदेशी मदद मिल रही है। युवा उन पर ध्यान न दें और 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' को ही अपना लक्ष्य बनाएं। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित पांच दिवसीय 23वें राष्ट्रीय युवा उत्सव का समापन गुरुवार को हुआ। केंद्रीय राज्यमंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि हमें मिलकर एक भारत, श्रेष्ठ भारत बनाना है। इसके लिए हमारी सोच और लक्ष्य अर्जुन की तरह मछली की आंख पर होनी चाहिए। खेल, शिक्षा या किसी भी क्षेत्र में रहें, लक्ष्य यही हो कि देश को महान बनाना है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग कॉलेज-विवि में भारत के टुकड़े-टुकड़े करने की बात करते हैं। वे संख्या में ज्यादा नहीं हैं। इनमें कुछ कॉलेज के लोग और कुछ फिल्मी दुनिया से हैं। उन्हें विदेशी ताकत मिलती है। उनके लिए योजना और पैसा बाहर से आ रहा है। खास तौर पर इनकी मुहिम सोशल मीडिया पर चलती है। रिजिजू ने कहा कि आप लोगों को इन पर ध्यान नहीं देना है। वहीं मुख्य अतिथि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति का आधार उसकी सांस्कृतिक विरासत में छिपा होता है। परंपरा को छोड़ने का अर्थ है अपनी जड़ों से कट जाना। युवाओं का दायित्व है कि वह अपनी समृद्ध संस्कृति को समझें और संरक्षित करें।

### असम में नागरिकता आवेदन के लिए मिल सकता है तीन माह का समय

**नई दिल्ली, प्रेट्र** : नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) लागू होने के बाद असम में भारत की नागरिकता पाने के लिए आवेदन करने वालों को केंद्र सरकार तीन महीने का समय दे सकती है। असम में सीएए लागू करने के लिए नियमों में कुछ विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, असम में रह रहे लोगों को नागरिकता का आवेदन करने के लिए महज तीन महीने का समय दिए जाने की संभावना है। दिसंबर में संसद द्वारा सीएए पारित किए जाने के बाद से विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है। अधिकारी ने कहा कि सीएए के तहत नियमों को अगले दो सप्ताह में जारी किया जा सकता है। एक अन्य अधिकारी ने कहा कि नागरिकता के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को साबित करना होगा कि उसका धार्मिक आधार पर उत्पीड़न किया जा रहा था। इसके अलावा 31 दिसंबर, 2014 से पहले भारत आने की बात भी उसे साबित करनी होगी। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और उनके वित्त मंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से पिछले सप्ताह मुलाकात की थी। उन्होंने सीएए के तहत नागरिकता हासिल करने के लिए सीमित समयसीमा देने और असम के लोगों के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए जाने का अनुरोध किया था। सीएए के खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों के बारे में पूछे जाने पर सरमा ने गुरुवार को कहा कि थोड़ा इंतजार कीजिए।

### सीएए पर उत्तर भारतीयों की सर्वाधिक सहमति

**सीएए (नागरिकता संशोधन कानून) के पक्ष और विपक्ष में दलीलें थम नहीं रही हैं। इस मसले पर बहस से ज्यादा प्रदर्शन हुए, हिंसक घटनाएं हुईं और आपराधिक मामले दर्ज हुए। यह बात और है कि देश का बड़ा हिस्सा सीएए को लेकर एकमत है, वो इस कानून से सहमत है। आइएएनएस सी वोटर स्नैप पोल के मुताबिक उत्तर भारतीयों में यह प्रतिशत सबसे ज्यादा है जबकि असहमति के पक्ष में असम खड़ा है।**

#### असम में सिर्फ 31 फीसद समर्थन

नागरिकता संशोधन कानून को लेकर असम के अलावा देशभर इसके पक्ष में आधी से ज्यादा आबादी है। पोल के मुताबिक 67.7 प्रतिशत उत्तर भारतीयों की आवाज सीएए के पक्ष में है। पश्चिम में यह प्रतिशत 64.2, दक्षिण में 58.5, पूर्व में 57.3, उत्तर पूर्व में 50.6 और असम में 31 है।

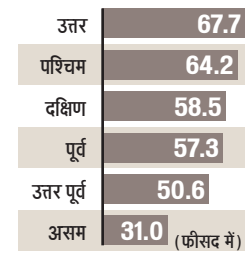


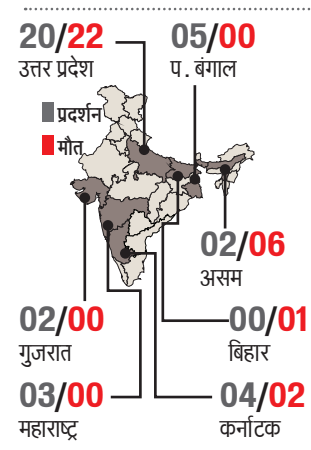


#### यूपी में सबसे ज्यादा घटनाएं

सीएए पर दो हिस्सों में बंटा देश अपनी तरह से सहमति और असहमति जता रहा था लेकिन 6 जनवरी का हिंसक प्रदर्शन 31 लोगों की मौत का सबब साबित हुआ। सबसे ज्यादा हिंसा उत्तर प्रदेश ने सही। जहां करीब 20 जिलों में प्रदर्शन के दौरान हादसे, आपराधिक घटनाएं और 22 लोगों की मौत के मामले दर्ज किए गए। इस दौरान हुई हिंसा में कर्नाटक में 2, असम में 6 और बिहार में एक मौत हुई। कुल 14 राज्यों के करीब 94 जिलों में सीएए को लेकर प्रदर्शन और हिंसा हुई।

### साफ होगा रुख, दस्तावेज दिखाने का दबाव नहीं डाला जाना चाहिए

▶ प्रथम पृष्ठ से आगे

केंद्र सरकार की ओर से सभी राज्यों को एक बार फिर साफ कर दिया जाएगा कि आंकड़े लेते समय किसी पर भी कोई दस्तावेज दिखाने का दबाव नहीं डाला जाना चाहिए। यही नहीं, जनगणना कर्मी लोगों को यह भी समझाने की कोशिश करें कि एनपीआर के तहत दिए गए आंकड़े किस तरह उनके लिए लाभकारी हो सकते हैं। मालूम हो कि एनपीआर और जनगणना के लिए फंड की मंजूरी देते समय कैबिनेट बैठक में ही यह साफ कर दिया गया था कि इस बार एनपीआर के दौरान कोई बायोमेट्रिक नहीं ली जाएगी और न ही कोई दस्तावेज मांगा जाएगा।

# समर्थन में कई राज्यों में निकाली गईं रैलियां

पंजाब के तहत संगरूर में गुरुवार को सीएए के पक्ष में निकाली गई जागरूकता रैली में भाग लेते हुए राष्ट्रीय एकता मंच के सदस्य। जागरण

**जेएनएन, नई दिल्ली**: नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के समर्थन में गुरुवार को भी जगह-जगह प्रदर्शन हुए। पंजाब, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में भाजपा और दूसरे संगठनों ने रैली निकाली, गोष्ठियां की और हस्ताक्षर अभियान चलाए गए।

सीएए के समर्थन में भाजपा व अन्य संगठनों ने जगह-जगह रैली निकाली और कानून को लेकर उत्पन्न भ्रांतियों को दूर करने की कोशिश की। मध्य प्रदेश के धार और खरगोन में तिरंगा लेकर निकले जनसमूह में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल रहीं। हजारों लोगों ने भारत माता की जय के नारे लगाते हुए सीएए का समर्थन किया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में नागरिक जागरण मंच के नेतृत्व में निकाली गई रैली में बड़ी संख्या में आम लोग शामिल हुए। पंजाब के संगरूर में राष्ट्रीय एकता मंच ने जोरदार रैली निकाली। पठानकोट में देश बचाओ मंच ने विभिन्न गांवों में तिरंगा यात्रा निकाली। बिहार के भागलपुर और मुजफ्फरपुर के विभिन्न इलाकों में सीएए के समर्थन में रैलियां आयोजित हुईं। जमुई में भाजपा की ओर से गुरुवार को रैली निकाली गई है। उसमें लोगों को सीएए के बारे में जानकारी दी गई। खगड़िया में भाजपा कार्यकर्ता लगातार हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। उत्तर बिहार में भी कई जगह कार्यक्रम हुए। मधुबनी में भाजपा ने जनसंपर्क अभियान चलाया। शिवहर में भाजपा ने जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन कर सीएए के फायदे बताए और हस्ताक्षर अभियान चलाया।

### कमलनाथ ने सीएए लागू करने से किया इन्कार हाई कोर्ट में चुनौती

**नईदुनिया, जबलपुर** : मध्य प्रदेश में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) लागू नहीं करने की मुख्यमंत्री कमलनाथ की घोषणा को चुनौती दी गई है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने दायर जनहित याचिका स्वीकार कर ली है। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एके मित्तल व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की खंड पीठ मामले की सुनवाई 29 जनवरी को करेगी।

मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदेश में सीएए लागू नहीं करने को लेकर 25 दिसंबर को बयान दिया था। इसी को चुनौती देते हुए अखिल भारतीय मलयाली संघ के अध्यक्ष और अधिवक्ता सोमन के. मेनन समेत चार संस्थाओं ने जनहित याचिका दायर की है। याचिका में मुख्यमंत्री के बयान को गैरजिम्मेदाराना और राष्ट्रीय एकता के खिलाफ बताया गया है। कहा गया कि राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद सीएए को देश भर में लागू किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 10 जनवरी 2020 को कानून लागू करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, जिसके बाद राज्य को इसमें हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है। अधिवक्ता आशा तिवारी के अनुसार, याचिका में यह भी मांग की गई कि बयान को लेकर कमलनाथ नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दें।

# संघ प्रचारक इंद्रेश कुमार पर हमले की कोशिश

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

नागरिक संशोधन कानून (सीएए) पर मुस्लिम धर्म गुरुओं को जागरूक करने के लिए आयोजित मुस्लिम राष्ट्रीय मंच (एमआरएम) की कांफ्रेंस में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश कुमार पर हमले की कोशिश हुई है। बतौर वक्ता इंद्रेश जैसे ही मंच पर पहुंचे, नौ लोग 'नो सीएए और नो एनआरसी' लिखे कागज लहराते हुए मंच की ओर बढ़ने की कोशिश करने लगे। हालांकि वहां मौजूद लोगों और सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें रोक लिया। इस दौरान हल्की धक्कामुक्की भी हुई। बाद में इनमें से कुछ को हिरासत में लेकर पुलिस संसद मार्ग थाना ले गई। आयोजकों और विहिप ने दावा किया कि यह इंद्रेश पर प्रायोजित हमला था जो कांग्रेस और उसकी बी टीम जैसी पार्टियों के इशारे पर था।

जमात उलेमा के अध्यक्ष सुहैब कासमी के नेतृत्व में कांस्टीट्यूशन क्लब में आयोजित कांफ्रेंस में कई राज्यों से 100 से अधिक लोग शामिल हुए, जिसमें धर्म गुरुओं के साथ शिक्षाविद् व मुस्लिम महिलाएं भी थीं। अपने संबोधन में इंद्रेश कुमार ने विरोध करने वालों के लिए सद्बुद्धि की कामना करते हुए कहा कि उन पर हमला नहीं हुआ है। यह महज विरोध था। इनमें से एक को वह पहचानते भी हैं, लेकिन उसका नाम नहीं बताएंगे, क्योंकि कोई कार्रवाई नहीं चाहते हैं। उन्होंने कहा कि यह कानून किसी की नागरिकता लेने वाला या नागरिकता लेने में अवरोध पैदा करने वाला नहीं है। यह नागरिकता देने वाला है। विश्व के 137 देशों में भारतीय रहते हैं। वह वहां के नागरिक एक मानक के तहत बने हैं। कोई अपने घर में किसी की घुसपैठ नहीं चाहता। उन्होंने कहा कि मस्जिद साझी हो सकती है, घर साझा नहीं हो सकता है। बहुत सारे मुल्कों में मुस्लिम रहते हैं। वह वहां के राष्ट्रगीत, कानून और झंडे से प्यार करते हैं। उन्हें कोई परेशानी नहीं आती। यहीं पर क्यों दिक्कत आती है।

नई दिल्ली में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच द्वारा आयोजित उलमा कांफ्रेंस में आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश कुमार (बीच में), मौलाना कोकब मुस्तबा (बाएं) व मौलाना सुहैब कासमी (दाएं)। जागरण

**विहिप ने कहा-चुनाव के कारण हो रहा है विरोध-प्रदर्शन** : विहिप के कार्याध्यक्ष आलोक कुमार ने दावा किया कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव के कारण विरोध-प्रदर्शन हो रहे हैं। इसके पीछे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी हैं। इन प्रदर्शनों के सहारे दोनों दल सांप्रदायिक गोलबंदी का प्रयास कर रहे हैं। कांफ्रेंस में किछौछा शरीफ से मौलाना इरफान, शिया आलिम कौकब मुस्तबा, मेरठ से कारी मुजिब, बिजनौर से मौलाना जलील चिश्ती, मुंबई से मौलाना अहमद हसन व भोपाल से मौलाना नुरुउल्लाह समेत अन्य राज्यों से भी धार्मिक गुरु पहुंचे थे।

**दो टूक**

संघ प्रमुख ने जिज्ञासा और समाधान सत्र में स्वयंसेवकों के सवालों के दिए जवाब, कहा, एनआरसी राष्ट्रीयता का प्रमाण, पूरे देश में इसे लागू किया जाना चाहिए

# राम मंदिर ट्रस्ट बनने के बाद संघ हस्तक्षेप नहीं करेगा : भागवत

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख डॉ. मोहन भागवत ने गुरुवार शाम जिज्ञासा और समाधान सत्र में स्वयंसेवकों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि राम मंदिर बनने के बाद आरएसएस की भूमिका नहीं होगी। जिस दिन राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट का गठन हो जाएगा, संघ उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। स्वयंसेवकों ने राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनआरसी) पर मचे हंगामे को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। एनआरसी को पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए। इससे हमारी राष्ट्रीयता का प्रमाण मिलता है।

चार दिन के प्रवास पर उप्र के मुरादाबाद आए संघ प्रमुख सुबह कार्यक्रम स्थल मुरादाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एमआइटी) में लगी शाखा से शामिल हुए। शाम को चार बजे से साढ़े पांच बजे तक जिज्ञासा और समाधान सत्र में स्वयंसेवकों ने सर संघचालक से देश की वर्तमान स्थिति पर सवाल पूछे। सभी का पूरी सादगी से उत्तर दिया।

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में गुरुवार को मुरादाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एमआइटी) में आरएसएस की प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने के बाद बाहर निकलते संघ प्रमुख मोहन भागवत। जागरण

**देश को परम वैभव पर पहुंचाना हम सभी का कर्तव्य** : शाखा में शामिल होने के बाद प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। इससे पहले एकात्मता स्रोत और आपस में पदाधिकारियों की बैठक हुई। इसमें संघ प्रमुख ने स्वयंसेवकों को देश प्रेम के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि जन-जागरण और अपने कार्य में सतत लगे रहें। देश को परम वैभव पर पहुंचाना हम सभी का कर्तव्य है। उन्होंने स्वयंसेवकों को देश सेवा के लिए निरंतर कार्य करने का मंत्र भी दिया। एकात्मता स्रोत के माध्यम से देवी-देवताओं को आह्वान किया गया। चार सत्रों में प्रांत और क्षेत्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। इसमें मौजूद प्रांत और क्षेत्रीय कार्यकारिणी के दायित्व निभाने वाले स्वयंसेवकों को दायित्व निर्वहन के बारे में विस्तार से बताया। कहा कि देश सेवा से सभी को जोड़ने के लिए पूरी तन्मयता से लोगों से संपर्क करना होगा।

**मथुरा और काशी संघ के एजेंडे में नहीं रहा** : सीएए लागू होने के बाद देश में हुई हिंसक घटनाओं के सवाल का जवाब देते हुए संघ प्रमुख ने कहा कि यह कानून नागरिकता देने वाला है, इसका विरोध नहीं होना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण के लिए दो बच्चों की अनिवार्यता के सवाल पर कहा कि संघ जनसंख्या नियंत्रण कानून के पक्ष में है लेकिन, कानून का मसौदा सरकार को बनाना है। अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून बनता है तो देश विकास के मार्ग पर चलेगा। मथुरा और काशी संघ के एजेंडे में रहेगा कि नहीं, इस सवाल का जवाब देते हुए संघ प्रमुख ने कहा कि काशी और मथुरा कभी भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एजेंडे में नहीं रहा है।

# सीएए और एनपीआर पर रोक के लिए आइयूएमएल पहुंची सुप्रीम कोर्ट

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आइयूएमएल) ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जियां दाखिल कर नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और नेशनल पापुलेशन रजिस्टर (एनपीआर) पर रोक लगाने की मांग की है। केंद्र सरकार को यह स्पष्ट करने का निर्देश देने की मांग की है कि नेशनल रजिस्टर आफ सिटीजन (एनआरसी) और नेशनल पापुलेशन रजिस्टर (एनपीआर) का आपस में कोई संबंध है या नहीं।

आइयूएमएल की ओर से ये दोनों अर्जियां सीएए कानून को चुनौती देने वाली उसकी पहले से लंबित रिट याचिका में दाखिल की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट मामले पर 22 जनवरी को सुनवाई करेगा। गुरुवार को दाखिल अर्जी में आइयूएमएल ने सीएए के तहत दी जाने वाली नागरिकता पर सवाल उठाते हुए कहा है कि केंद्र सरकार ने गत 10 जनवरी को अधिसूचना जारी कर सीएए कानून लागू कर दिया है। मीडिया में आई खबर का हवाला देते हुए कहा गया है कि कानून लागू होने के तत्काल बाद 13 जनवरी को उत्तर प्रदेश सरकार ने करीब 40,000 शरणार्थियों की सूची केंद्र को भेजी है। इन्हें सीएए के तहत नागरिकता दी जानी है। अर्जी में कहा गया है कि ऐसे में न्याय के हित में यही होगा कि सीएए कानून पर अंतरिम रोक लगा दी जाए। कहा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार की गैर मुस्लिमों को नागरिकता देने के लिए आंकड़ा जमा करने की त्वरित कार्यवाही से साफ हो जाता है कि शरणार्थियों को नागरिकता देने का काम शुरू हो गया है। कहा गया है कि अगर कोर्ट सीएए कानून के अमल विशेषकर धारा 6बी पर रोक नहीं लगाता है तो यह मामला महत्वहीन हो जाएगा। कहा गया है कि जबतक सीएए की वैधानिकता का मसला कोर्ट में लंबित है तबतक के लिए सीएए लागू करने की अधिसूचना पर रोक लगा दी जाए। दूसरी अर्जी में कहा गया है कि पूरे देश में एनआरसी लागू करने और एनआरसी के एनपीआर से संबंध को लेकर मंत्री और प्रधानमंत्री के लगातार विरोधाभासी बयान आ रहे हैं।

▶ इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की

**12** करोड़ स्टांप चोरी का मामला दर्ज हुआ है फोरलेन और नेशनल हाईवे के दो टोल प्लाजा संचालकों पर। तेनुआ टोल प्लाजा संचालक फर्म पर 11.5 करोड़ रुपये व नयनसर टोल प्लाजा पर 52 लाख रुपये की स्टांप चोरी का मामला दर्ज है।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शुक्रवार 17 जनवरी 2020

## न्यूज गैलरी

### गुजरात में पूर्व विधायक पेंशन-भत्ते की मांग को लेकर देंगे धरना

**अहमदाबाद** : पेंशन, मुफ्त यात्रा, मेडिकल सुविधाओं की मांग को लेकर गुजरात के पूर्व विधायकों ने रूपाणी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पूर्व मंत्री जयनारायण व्यास ने कहा कि पूर्व विधायकों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो वे प्रेशर कूकर की तरह फट भी सकते हैं। पेंशन, यात्रा सुविधा, मेडिकल व अन्य भत्तों की मांग को लेकर पूर्व विधायक 27 जनवरी को गांधीनगर में धरना देंगे। गुजरात पूर्व विधायक काउंसिल की गांधीनगर में हुई बैठक में पूर्व विधायकों ने राज्य सरकार के समक्ष अपनी कई मांगें रखीं। काउंसिल के अध्यक्ष पूर्व मंत्री बाबू मेघजी शाह ने बताया कि देश के 27 राज्यों में पूर्व विधायकों को पेंशन, भत्ते मिलते हैं। केवल गुजरात के विधायकों को ही पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है। राज्य में 560 पूर्व विधायक हैं इनमें से 231 का निधन हो चुका है। शाह ने बताया कि वर्तमान विधानसभा के दो तिहाई विधायक करोड़पति हैं, लेकिन कई पूर्व विधायकों को खाने व इलाज के लिए भी तकलीफ उठानी पड़ रही है। बैठक में भाजपा सरकार के ही पूर्व मंत्री भरत बारोट व पूर्व मंत्री मायाबेन कोडनानी आदि भी शामिल हुईं। (राब्यू)

### छात्रवृत्ति घोटाले में 12 शैक्षिक संस्थानों के खिलाफ मिले साक्ष्य

**ऊधमसिंह नगर** : छात्रवृत्ति घोटाले की जांच कर रही एसआइटी को उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश (मप्र) के 12 शैक्षिक संस्थानों के खिलाफ छात्रवृत्ति हड़पने के साक्ष्य मिले हैं। इन संस्थानों के खिलाफ एसआइटी की जल्द मुकदमा दर्ज कराने की तैयारी है। छात्रवृत्ति घोटाले के पहले चरण में एसआइटी अभी बाहरी राज्यों के शैक्षिक संस्थानों की जांच कर रही है। 3024 विद्यार्थियों में से करीब दो हजार से अधिक से पूछताछ कर उत्तर प्रदेश व हरियाणा के 15 शैक्षिक संस्थानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर 10 बिचौलियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। एसआइटी को अब बाहरी राज्यों के 12 और शैक्षिक संस्थानों के खिलाफ साक्ष्य मिले हैं। इनमें हरियाणा, उप्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान के शैक्षिक संस्थानों ने बिचौलियों की मदद से छात्रों का कॉलेजों में अलग-अलग कोर्स के नाम पर प्रवेश दिखाया और छात्रवृत्ति हड़प ली। (जासं)

### मप्र के पूर्व एडीजी को धोखाधड़ी में पांच साल की जेल

**भोपाल** : भोपाल की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) की विशेष अदालत ने भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी मामले के आरोपित पूर्व एडीजी को पांच साल कैद और आठ लाख 75 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट के निर्णय के बाद झारखंड की राजधानी रांची में रह रहे पूर्व एडीजी राजेंद्र चतुर्वेदी को जेल भेज दिया गया। विशेष न्यायाधीश संजीव कुमार पांडेय ने गुरुवार फैसला सुनाया। अभियोजन के अनुसार मामला एक जनवरी से 26 मई 2003 के बीच केंद्रीय जेल भोपाल का है। तत्कालीन एडीजी (जेल) राजेंद्र चतुर्वेदी ने अपने पद और रुतबे का उपयोग करते हुए 16 बेरोजगारों को जेल विभाग में प्रहरी व लिपिक के पद पर नियुक्त कराने का झांसा दिया था। इसके लिए चतुर्वेदी ने उक्त बेरोजगारों से नौकरी दिलाने के नाम पर 18 लाख रुपये ऐंठ ली थी। धोखाधड़ी के शिकार सभी बेरोजगारों ने संयुक्त रूप से इसकी शिकायत सीआइडी पुलिस मुख्यालय में की थी। सीआइडी ने इसकी जांच ईओडब्ल्यू को सौंप दी। ईओडब्ल्यू ने जांच के बाद आरोपित एडीजी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत धोखाधड़ी और साक्ष्य छुपाने का अपराध कायम कर मामले का चालान विशेष अदालत में पेश किया था। (नईदुनिया)

### दंतेवाड़ा में एक लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार

**दंतेवाड़ा** : छत्तीसगढ़ में एसटीएफ और अरनपुर थाना फोर्स ने गुरुवार को तलाशी अभियान के दौरान कोंडासावली इलाके से एक नक्सली को गिरफ्तार किया है। उसकी पहचान मुचाकी मासा के रूप में हुई। वह नक्सलियों के दंडकारण्य आदिवासी किसान मजदूर संगठन का अध्यक्ष था। उस पर एक लाख रुपये का इनाम घोषित है। (नईदुनिया)

# श्रीनगर को दहलाने की आतंकी साजिश नाकाम

**मुस्तैदी** ▶ पांच गिरफ्तार, गणतंत्र दिवस पर आत्मघाती हमलों में इस्तेमाल होने वाली विस्फोटकों से लैस जैकेट भी बरामद

### सरहद पार बैठे हैंडलर के साथ संपर्क में थे आतंकी : डीआइजी

**राज्य ब्यूरो, श्रीनगर**

पुलिस ने श्रीनगर में जैश-ए-मोहम्मद की गणतंत्र दिवस पर बड़े आत्मघाती हमले की साजिश को नाकाम बना दिया। गुरुवार को जैश के एक मॉड्यूल को नेस्तनाबूद करते हुए पुलिस ने पांच आतंकियों को गिरफ्तार किया है। आतंकियों के पास से विस्फोटकों से लैस एक जैकेट, रिमोट ट्रिगर वाला बायोफेंग वाकी टाकी समेत भारी मात्रा में गोलाबारूद भी बरामद किया गया है। ऐसी जैकेट आतंकी आत्मघाती हमले के लिए पहनते हैं। पकड़े गए पांचों आतंकी श्रीनगर में बीते पांच महीनों के दौरान हुए विभिन्न ग्रेनेड हमलों में भी शामिल थे।

डीआइजी सेंट्रल कश्मीर रेंज वीके बिरदी ने बताया कि जैश-ए-मुहम्मद ने श्रीनगर को दहलाने की साजिश रची थी। आतंकी संगठन का इरादा कश्मीर में बहाल होती समान्य जिंदगी को फिर से खौफ के माहौल में बदलना था। आतंकी लगातार सरहद पार बैठे अपने हैंडलर के साथ संपर्क में थे। इन्हें अलग-अलग छापों में श्रीनगर में ही पकड़ा गया है।

श्रीनगर में पकड़े गए जैश-ए-मुहम्मद के पांच आतंकियों की फाइल फोटो। सौजन्य पुलिस

**ग्रेनेड हमले में मिला था इन आतंकियों का सुराग** : डीआइजी ने बताया कि इन आतंकियों का सुराग आठ जनवरी को हबक इलाके में हुए ग्रेनेड हमले के दौरान मिला था। इस हमले में लिप्त आतंकियों को पकड़ने के लिए चलाए गए अभियान के दौरान ही हजरतबल में सक्रिय जैश के पांच सदस्यीय मॉड्यूल का पता चला। इन्हीं आतंकियों ने पिछले वर्ष 26 नवंबर को कश्मीर विश्वविद्यालय के सर सईद गेट के सामने ग्रेनेड हमला किया था। इसके अलावा पांच अगस्त के बाद से जबरन बंद, हिंसक प्रदर्शन और बंद का विरोध करने वालों के साथ मारपीट की वारदात में भी आतंकी शामिल थे।

**आतंकियों ने कबूला बड़ी वारदात की फिराक में थे** : डीआइजी ने बताया कि पुलिस ने गिरफ्तार आतंकियों से पूछताछ की तो खुद इन आतंकियों ने भी माना कि वह गणतंत्र दिवस के दौरान या उससे पहले श्रीनगर में बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने का मौका तलाश रहे थे। यह पूछे जाने पर कि विस्फोटकों से लैस जैकेट का इस्तेमाल यह खुद करने वाले थे या किसी अन्य आतंकी को आत्मघाती बनने के लिए तैयार किया जा रहा था तो डीआइजी ने कहा कि अभी इस मामले में पूछताछ हो रही है।

**गिरफ्तार आतंकियों की पहचान** : पकड़े गए आतंकियों की पहचान एजाज अहमद शेख (38), उमर हमीद शेख (28), इम्तियाज अहमद चिकला उर्फ इमरान (31), साहिल फारूक गोजरी (26) और नसीर अहमद मीर (25) के रूप में हुई है। ये सभी श्रीनगर के हजरतबल इलाके के रहने वाले हैं।

**पेशे से कोई चालक तो कोई ठेला लगाता है आतंकी** : पकड़ा गया आतंकी एजाज पेशे से वाहन चालक है, जबकि उमर ठेला लगता है। इमरान की खेल सामग्री की दुकान है, नसीर का अपना कारोबार है और साहिल एक प्राइवेट फर्म में नौकरी करता है।

**आतंकियों से ये हुआ बरामद** : विस्फोटकों और बियरिंग से लैस जैकेट, 143 जिलेटिन रॉड, 42 डेटोनेटर, सात सेकंडरी एक्सप्लोसिव, एक साइलेंसर, क्षतिग्रस्त सीडी ड्राइव, देसी कट्टा, हथौड़ी, वायरलेस सेट, तीन बैटरी, बैटरी चार्जर और ढाई लीटर एसिड।

#### लश्कर का भी एक आतंकी पकड़ा

सुरक्षाबलों ने गुरुवार को दक्षिण कश्मीर में अवंतीपोरा से लश्कर-ए-तैयबा के एक स्थानीय आतंकी को पकड़ लिया। आतंकी की पहचान इशफाक अहमद डार उर्फ महीद के रूप में हुई है। वह पुलवामा में डांगरपोरा का रहने वाला है। इशफाक पडगामपोरा, सोनरीगुंड, गुलजारपोरा, बेगीपोरा और उसके साथ सटे इलाकों में सक्रिय था। वह आम लोगों के साथ मारपीट करने, पंच-सरपंचों को धमकाने, उनपर हमला करने और सुरक्षाबलों पर ग्रेनेड हमले की विभिन्न वारदातों में वांछित था। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि इशफाक की निशानदेही पर पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार और गोलाबारूद भी बरामद किया है।

## पूर्व सांसद सहित 10 लोगों पर 27 को तय होंगे आरोप

**जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर** : भड़काऊ भाषण देने सहित विभिन्न आरोपों में दर्ज मुकदमे में आरोपित पूर्व सांसद व पूर्व विधायकों के कोर्ट में पेश न होने के कारण आरोप तय नहीं हो सके। कोर्ट ने आरोप तय करने की तिथि अब 27 जनवरी नियत की है। गुरुवार को 10 में से केवल पांच आरोपित ही कोर्ट में पेश हुए। सात सितंबर 2013 को मुजफ्फरनगर जिले में सांप्रदायिक दंगा भड़कने से पूर्व 30 अगस्त 2013 को शहीद चौक पर सभा का आयोजन किया गया था।

इस पर शहर कोतवाली पुलिस ने पूर्व सांसद कादिर राना, पूर्व गृह राज्यमंत्री सईदुज्जमां, पूर्व विधायक नूरसलीम राना, पूर्व विधायक मौलाना जमील अहमद कासमी, असद जहां एड., सुल्तान मुशीर, मुशर्रफ, नौशाद कुरैशी, सलमान सईद सहित 10 लोगों के विरुद्ध भड़काऊ भाषण सहित विभिन्न संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। कोर्ट ने आरोप तय करने की तिथि 10 जनवरी मुकर्रर कर दी थी, लेकिन सभी आरोपितों के पेश न होने के कारण इस मामले में 16 जनवरी की तिथि लगी थी। अधिवक्ता ने बताया कि गुरुवार को सहायक जिला एवं सत्र न्यायालय-4 में एड. असद जमां, सुल्तान मुशीर, मुशर्रफ कुरैशी, नौशाद कुरैशी व अहसान कुरैशी कोर्ट में पेश हुए।

# कश्मीर में दो पूर्व विधायकों सहित पांच नेता रिहा

**राज्य ब्यूरो, जम्मू**

केंद्रीय मंत्रियों के जम्मू-कश्मीर के शुरू हो रहे दौरे से पूर्व गुरुवार को प्रशासन ने पांच और नेताओं को रिहा कर दिया है। यह नेता पांच अगस्त को हिरासत में लिए गए थे। इसके साथ ही उपजेल एमएलए हॉस्टल में अभी हिरासत में रखे नेताओं की संख्या लगभग 21 है। फिलहाल, तीनों पूर्व मुख्यमंत्रियों डॉ. फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती के अलावा पीपुल्स कांफ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन और जम्मू कश्मीर पीपुल्स मूवमेंट के शाह फैसल बंद ही रहेंगे।

गौरतलब है कि 18 से 25 जनवरी तक जम्मू-कश्मीर में 36 केंद्रीय नेता अलग-अलग जिलों व शहरों का दौरा करेंगे। गुरुवार दोपहर को रिहा किए गए नेताओं में पहलगाम से नेशनल कांफ्रेंस के पूर्व विधायक अल्ताफ अहमद कालू, नेशनल कांफ्रेंस की युवा इकाई के प्रदेश प्रधान, श्रीनगर नगर निगम के पूर्व मेयर सलमान सागर, शौकत गनई, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के पूर्व विधायक निजामदीन बट और मुख्तार बाबा शामिल हैं।

#### उमर और महबूबा को घर के पास किया जा सकता है स्थानांतरित

अधिकारियों ने उमर अब्दुल्ला को हरि निवास से गुपकार स्थित उनके आधिकारिक निवास के पास स्थित सरकारी गेस्ट हाउस एम-4 में जल्द ही स्थानांतरित किए जाने की पुष्टि करते हुए बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को उनके घर में ही बंदी बनाकर रखे जाने की योजना पर विचार किया जा रहा है। अंतिम फैसला संबंधित सुरक्षा एजेंसियों की क्लीयरेंस के आधार पर ही होगा।

गौरतलब है कि पांच अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम का फैसला लेने से पहले प्रशासन ने नेशनल कांफ्रेंस, पीडीपी, पीपुल्स कांफ्रेंस, माकपा, पीडीएफ, एनडीपी, जेकेपीएम और कांग्रेस समेत विभिन्न राजनीतिक दलों नेताओं को एहितयातन हिरासत में ले लिया था। इनमें तीनों पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। डॉ. फारूक अब्दुल्ला को गुपकार मार्ग पर स्थित उनके घर में, उमर अब्दुल्ला को हरि निवास में और महबूबा मुफ्ती को ट्रांसपोर्ट लेन स्थित सरकारी गेस्ट हाउस में हिरासत में रखा गया है।

**बिना बांड भरे कोई रिहाई नहीं होती** : रिहा किए जाने वाले नेताओं को हालात सामान्य बनाए रखने में सहयोग करने व कोई भड़काऊ बयानबाजी न करने का बांड भरना होता है, लेकिन रिहा नेताओं ने यह बांड भरा है या नहीं, इसकी किसी ने देर शाम गए तक पुष्टि नहीं की थी। संबंधित अधिकारियों ने कहा कि बिना बांड कोई रिहाई नहीं होती।

**कुछ नेता नहीं बांड भरने को तैयार** : संबंधित अधिकारियों ने बताया कि उपजेल एमएलए हॉस्टल में इस समय हिरासत में रखे गए नेताओं में नेशनल कांफ्रेंस के अली मुहम्मद सागर, पीडीपी के नईम अख्तर, सरताज मदनी, वहीद पारा, पीपुल्स कांफ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन और जेकेपीएम के डॉ. शाह फैसल के नाम उल्लेखनीय हैं। लोन, पारा, शाह फैसल, सागर और नईम अख्तर को हाल-फिलहाल में रिहा किए जाने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि पांचों रिहाई के लिए बांड भरने को तैयार नहीं हैं।

# निर्भया के आरोपित की याचिका खारिज करने की सिफारिश

**नई दिल्ली, प्रेट्र** : दिल्ली के उपराज्यपाल ने गृह मंत्रालय से निर्भया सामूहिक दुष्कर्म व हत्याकांड में मौत की सजा पा चुके मुकेश सिंह की दया याचिका खारिज करने की सिफारिश की है। उसने कुछ दिनों पहले ही दया याचिका दाखिल की है। अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

गृह मंत्रालय के अधिकारी ने बताया, 'उपराज्यपाल ने खारिज करने की सिफारिश के साथ गृह मंत्रालय को दया याचिका अग्रसारित की है। उसका परीक्षण चल रहा है और उस पर उचित निर्णय लिया जाएगा।' वर्ष 2012 के निर्भया सामूहिक दुष्कर्म व हत्याकांड में मौत की सजा पा चुके चार अपराधियों में से एक मुकेश ने दिल्ली सरकार के समक्ष दया याचिका दाखिल की है। दिल्ली सरकार ने बुधवार को याचिका को खारिज करने की संस्तुति के साथ उपराज्यपाल को अग्रसारित कर दिया था। साथ ही सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट को बताया था कि सजायाफ्ता मुकेश की तरफ से दया याचिका दाखिल किए जाने के कारण अब 22 जनवरी को फांसी संभव नहीं हो पाएगी।

सजायाफ्ता मुकेश सिंह (32), विनय शर्मा (26), अक्षय कुमार सिंह (31) और पवन गुप्ता (25) को तिहाड़ जेल में 22 जनवरी को सुबह सात बजे फांसी दी जानी थी।

#### जेल प्रशासन ने दिल्ली सरकार से मांगा निर्देश

▶ प्रथम पृष्ठ से आगे

जेल प्रशासन से दिल्ली सरकार के समक्ष मौजूदा वस्तुस्थिति बयां कर अगले कदम के बारे में निर्देश देने का आग्रह किया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जेल प्रशासन की ओर से गुरुवार को पत्र भेजा गया। सरकार के निर्देश के अनुसार फांसी के बारे में निर्णय लिया जाएगा। डेथ वारंट के बाबत नया आदेश नहीं मिलने तक फांसी पर लटकाने की तिथि 22 जनवरी ही मानी जाएगी।

## फांसी के दौरान दोनों लीवर एक ही जल्लाद दबाएगा

**जासं, नई दिल्ली** : अब यह तय हो चुका है कि तिहाड़ में फांसी देने के लिए उत्तर प्रदेश जेल विभाग की ओर से एक ही जल्लाद उपलब्ध कराया जाएगा। जेल सूत्रों का कहना है कि फांसी घर में हुए विस्तार के बाद अब एक साथ चार दोषियों को फांसी पर लटकाया जा सकता है। एक लीवर से फांसी के दो फंदे जुड़े हैं। चारों दोषियों को फांसी पर लटकाने के लिए दो अलग-अलग लीवर बनाए गए हैं। सूत्रों के अनुसार, दोनों लीवर को जल्लाद ही दबाएगा।

इस प्रक्रिया को समझने के लिए ही जल्लाद को फांसी की तय तिथि से पहले बुलाया जा रहा है ताकि वह इस प्रक्रिया को समझ ले और पुतले को लटकाकर अभ्यास भी कर ले। गौरतलब है कि फांसी से जुड़े पिछले दो मामलों में दोषियों को लटकाने का काम जल्लाद ने नहीं बल्कि जेल कर्मचारी ने किया था। इस बार चार दोषियों को देखते हुए ही जेल प्रशासन जल्लाद की सेवाएं ले रहा है।

# बसों में ट्रैकिंग डिवाइस, इमरजेंसी बटन के लिए मिलेगी केंद्र से मदद

**जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली**

▶ निर्भया स्कीम के तहत सार्वजनिक वाहनों में लगने थे ये उपकरण

▶ राज्यों में मॉनिटरिंग सेंटर स्थापित नहीं हो पाने से रुकी प्रगति

केंद्र सरकार ने निर्भया स्कीम के तहत सार्वजनिक वाहनों और बसों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (वीएलटी) तथा इमरजेंसी बटन लगाने के लिए सभी राज्यों को मदद देने का निर्णय लिया है। इसके तहत केंद्र सरकार राज्यों को 60 फीसद सहायता प्रदान करेगी। 40 फीसद राशि राज्यों को खुद लगानी होगी।

सरकार ने निर्भया स्कीम के तहत कुछ वर्ष पहले सभी सार्वजनिक वाहनों तथा राज्य परिवहन निगमों की बसों में वीएलटी डिवाइस तथा इमरजेंसी बटन लगाना अनिवार्य किया था। इस संबंध में 28 नवंबर, 2016 को केंद्रीय सड़क मंत्रालय की ओर से अधिसूचना जारी की गई थी। इसके अनुसार यात्री सवारी ले जाने वाले सभी सार्वजनिक वाहनों में 1 अप्रैल, 2018 से पहले सभी पंजीकृत वाहनों में वीएलटी डिवाइस और इमरजेंसी बजट लगाए जाने थे।

राज्यों को अधिकार दिया गया था कि जब तक वे इस संबंध में अधिसूचना नहीं निकालते तब तक 31 दिसंबर, 2018 तक पंजीकृत वाहनों को वीएलटी डिवाइस व इमरजेंसी बटन लगाने से छूट दे सकते हैं। इन उपकरणों से सुसज्जित वाहनों की निगरानी के लिए राज्यों में कमांड एंड कंट्रोल सेंटरों (मॉनिटरिंग सेंटरों) की स्थापना की जानी थी। परंतु धन की कमी के कारण बहुत कम राज्यों में ये केंद्र स्थापित किए जा सके हैं। नतीजतन योजना का प्रभावी कार्यान्वयन नहीं हो सका है। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों को वित्तीय मदद देने का निर्णय लिया है। ये मदद 37 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को दी जाएगी। इसके लिए इन्हें वाहनों की संख्या तथा क्षेत्रफल के आधार पर कुछ श्रेणियों में विभाजित किया गया है।

पर्वतीय व दुष्कर भौगोलिक इलाकों वाले राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों को केंद्र सरकार परियोजना की 60 फीसद राशि देगी। राज्यों को केवल 40 फीसद राशि वहन करनी होगी। कठिन भौगोलिक परिस्थितियों वाले राज्यों को केंद्र से 90 फीसद राशि मिलेगी और उन्हें केवल 10 फीसद स्वयं लगानी होगी। केंद्रशासित प्रदेशों को शत-प्रतिशत केंद्रीय सहायता मिलेगी।

पूरे देश में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस तथा इमरजेंसी बटन की एकसमान उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सड़क मंत्रालय ने 140 मानक जारी किए हैं। राज्यों को इन्हीं के अनुसार इन उपकरणों की खरीद करनी होगी। ऐसा नहीं करने पर कार्रवाई की जाएगी।

## नेकां के पूर्व वित्त मंत्री का बेटा हिलाल गिरफ्तार

**जागरण संवाददाता, जम्मू** : एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने जम्मू-कश्मीर के पूर्व वित्त मंत्री और नेशनल कांफ्रेंस के वरिष्ठ नेता अब्दुल रहीम राथर के बेटे हिलाल राथर को गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया है। हिलाल ने 2012 में जम्मू-कश्मीर (जेके) बैंक से 177 करोड़ रुपये का ऋण लिया था, लेकिन यह पैसा नहीं लौटाया। यह ऋण भी बैंक नियमों का उल्लंघन करके जारी हुआ था, जिसमें एंटी क्रप्शन ब्यूरो कई बैंक अधिकारियों से भी पूछताछ कर रहा है। हिलाल राथर से भी कई महीनों से पूछताछ जारी थी और अब उसे हिरासत में ले लिया गया है।

हिलाल ने जम्मू के नरवाल बाला में पैराडाइज एवेन्यू टाउनशिप बनाने के लिए यह ऋण लिया था। राथर ने पैराडाइज एवेन्यू के नाम से एक पार्टनरशिप फर्म बनाई। इसमें सन्नत नगर, श्रीनगर के डॉ. रिजवान रहीम डार, बारामुला निवासी गुलाम मोहम्मद भट्ट तथा जम्मू निवासी दलजीत वडेरा और दीपशिखा जम्वाल हिलाल राथर के पार्टनर बने। जम्मू-कश्मीर बैंक के नियमानुसार एक पार्टनरशिप फर्म को 40 करोड़ रुपये से अधिक ऋण मंजूर नहीं हो सकता था, लेकिन बैंक के तत्कालीन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने पहले चरण में ही इस फर्म के लिए 74.27 करोड़ रुपये का ऋण मंजूर किया। हिलाल स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन से भी ऋण ले चुका था और न चुकाए जाने पर कॉरपोरेशन ने वन टाइम सेटलमेंट के तहत पैसे वसूल किए थे।

## फांसी घर के और करीब पहुंचे निर्भया के दोषी

**जागरण संवाददाता, नई दिल्ली** : निर्भया के चारों दोषियों और फांसी घर की दूरी अब चंद कदमों की रह गई। अलग-अलग जेलों में बंद इन दोषियों को गुरुवार दोपहर जेल संख्या-तीन में भेज दिया गया, जहां इन्हें हाई सिक्योरिटी सेल में रखा गया है। सेल और फांसी घर के बीच की दूरी चंद कदमों की है। जेल प्रशासन दोषियों के हाव-भाव पर नजर रख रहा है।

गौरतलब है कि निर्भया के दोषियों में विनय जेल संख्या-चार और अक्षय, पवन व मुकेश जेल संख्या-दो में बंद थे। दोपहर के समय इन्हें दो अलग-अलग गाड़ियों में कड़ी सुरक्षा के बीच जेल संख्या-तीन में ले जाया गया। चारों को अलग-अलग सेल में रखा गया है। यहां इनकी सुरक्षा को लेकर जेलकर्मी सतर्कता बरत रहे हैं। इनके सेल के पास तमिलनाडु पुलिस के जवानों की ड्यूटी 24 घंटे लगाई गई है। सूत्रों का कहना है कि एक सुरक्षाकर्मी को इनके पास छह घंटे से अधिक नहीं रहने दिया जा रहा।

इन्हें ऐसे सेल में रखा गया है, जो सीसीटीवी कैमरे के दायरे में है। इन कैमरों से न सिर्फ सेल के आसपास बल्कि सेल की ओर आने वाली तमाम सड़कों पर भी नजर रखी जा रही है। सीसीटीवी फुटेज पर जेल के कंट्रोल रूम में बैठे सुरक्षाकर्मी के अलावा जेल अधीक्षक भी 24 घंटे नजर रख रहे हैं।

# फांसी टलने पर भाजपा और आप में राजनीतिक घमासान

**राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली**

निर्भया के दोषियों की फांसी टलने पर दिल्ली के राजनीतिक गलियारे में घमासान मचा हुआ है। भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने इसके लिए आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। कहा कि महिला अपराध के मामले में आप सरकार असंवेदनशील हो गई है। वहीं उपमुख्यमंत्री सिसोदिया ने कहा कि केंद्र सरकार का एक मंत्री इतने संवेदनशील मुद्दे पर इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकता है। दिल्ली सरकार दोषियों को जल्द फांसी दिलाने के पक्ष में है।

केंद्रीय मंत्री जावडेकर ने केजरीवाल सरकार से सवाल किया कि पिछले ढाई वर्षों में दया याचिका दायर करने के लिए दोषियों को दिल्ली सरकार ने नोटिस क्यों नहीं दिया? इस मुद्दे को लेकर दोनों दलों के नेताओं के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2017 में दोषियों की अपील को खारिज कर दिया था और उन्हें मौत की सजा सुनाई थी। अगर सरकार ने इसके एक सप्ताह के भीतर सभी दोषियों को नोटिस दिया होता तो उन्हें अब तक फांसी की सजा मिल गई होती। उन्होंने कहा कि आप सरकार ने पिछले ढाई साल में तिहाड़ जेल को विस्तृत कानूनी प्रक्रिया मुहैया कराने में जो रवैया दिखाया है, उससे पता चलता है कि वह दुष्कर्मियों और हत्यारों के साथ खड़ी है। सांसद मीनाक्षी लेखी ने कहा कि इस मामले में आप का असली चेहरा सामने आ गया है। वहीं भाजपा पर पलटवार करते हुए मनीष सिसोदिया ने कहा कि जावडेकर का बयान सुनकर बड़ा दुख हुआ है कि केंद्र सरकार के एक मंत्री, इतने संवेदनशील मुद्दे पर इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं। सच्चाई यह है कि दिल्ली सरकार दोषियों को जल्द से जल्द फांसी दिलवाने के पक्ष में है।

उन्होंने भाजपा नेता को घेरते हुए कहा कि पुलिस प्रशासन और गृह मंत्रालय आपके हाथ में है। तिहाड़ के महानिदेशक की नियुक्ति आपके हाथ में और आप कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार ने नहीं किया। आप से राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने कहा कि दिल्ली की कानून व्यवस्था एवं पुलिस पूरी तरह से केंद्र में आसीन भाजपा सरकार के हाथ में है। निर्भया के दोषियों की फांसी में जो भी विलंब हो रहा है, उसके लिए सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है।

## जीवन की सरिता

नक्सल प्रभावित बंजर क्षेत्र में प्रकृति प्रेम की अद्भुत मिसाल बनीं सरिता देवी, एक लाख से अधिक पौधे लगाकर बंजर को हरियाली से भर दिया

पर्यावरण संरक्षण

# 'पौधे वाली दीदी' बन सरिता ने बदल दी इलाके की सूरत

**अजय कुमार अजय, चानन (लखीसराय)**

फिर नए पत्ते आए हैं, फिर हरियाली छाई है, उन पेड़ की टहनियों पर देखो, मुस्कान एक नई आई है...।

बिहार में लखीसराय जिले के चानन प्रखंड के कुंदर गांव की सरिता देवी की आंखों की चमक यही कहती प्रतीत होती है। सर्द-गर्म हवाओं के बीच हरे-भरे पेड़ों की टहनियों पर मंद-मंद मुस्कुराती पत्तियां ही अब उनकी मुस्कान हैं।

नक्सल प्रभावित बंजर क्षेत्र कुंदर में प्रकृति प्रेम की अद्भुत मिसाल बन चुकीं सरिता देवी को लोग 'पौधे वाली दीदी' कहकर पुकारते हैं। सरिता ने पिछले डेढ़ दशक में एक लाख से अधिक पौधे लगाकर इलाके की सूरत बदल दी है। ये सभी पौधे अब पेड़ बन लहलहा रहे हैं। इससे न सिर्फ इलाके की खूबसूरती बढ़ी है, बल्कि साफ हवा भी उपलब्ध हुई है। सरिता देवी ने अपनी जमीन पर एक समृद्ध नर्सरी भी तैयार की, जिससे हर वर्ष 20 हजार पौधे निश्शुल्क बांटती हैं।

लखीसराय में पौधों के बीच सरिता देवी। जागरण

कभी यह क्षेत्र 'लाल इलाके' के रूप में जाना जाता था, अब यहां हरियाली ही हरियाली है। सरिता इन पौधों की सुरक्षा के प्रति भी सजग हैं। यही वजह है कि उनके लगाए हुए पौधे पेड़ बनकर लहलहा रहे हैं। धरा पर हरियाली का श्रृंगार करने की बीड़ा उठा चुकीं सरिता की मुहिम जारी है। वे खुद भी खाली जगहों पर पौधारोपण कर रहीं हैं और लोगों को इसके लिए प्रेरित भी कर रही हैं। कहती हैं, कोई पौधा नहीं मिलने का बहाना न बना सके, इसलिए अपनी नर्सरी तैयार की है।

ग्रामीण माहौल में पली-बढ़ी सरिता आठवीं तक पढ़ी हैं। कहती हैं कि कभी सोचा भी नहीं था कि मात्र पेड़-पौधों के कारण उनकी पूछ बड़े-बड़ों के बीच होने लगेगी। वर्ष 2000 में वन क्षेत्र समिति कुंदर के उपाध्यक्ष पद पर उनका चयन हुआ। इसके बाद समूह बनाकर लगातार वन क्षेत्र में घूम-घूमकर जंगल की कटाई के खिलाफ उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की। 2006 में वन क्षेत्र कुंदर समिति के अध्यक्ष पद का दायित्व मिला तो इलाके की बंजर भूमि पर हरियाली लाने की कवायद शुरू कर दी। तब 50 हेक्टेयर जमीन पर 55 हजार आसन, बांस, गंभार, आंवला, महुवनी, महुआ, बबूल, खैर आदि के पौधे लगाए। हर वर्ष पौधारोपण जारी रखने के साथ पहले से लगाए गए पौधों की सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक रखा। इसी का नतीजा है कि अब सारे पौधे पेड़ बन चुके हैं।

#### निजी भूमि पर बनाई है नर्सरी...

सरिता देवी ने बताया कि पति पंचानंद पंडित ने 2016 में मुख्यमंत्री निजी पौधशाला के तहत अपनी निजी पांच कट्ठे जमीन पर 20 हजार पौधे की एक नर्सरी तैयार कर दी। यहां से वे सारे पौधे निश्शुल्क वितरित करती हैं। कहती हैं, जो पौधे ले जा रहे हैं वे इनकी सही देखभाल करते रहें, इस पर भी नजर रखती हूं। सरिता देवी के उत्कृष्ट कार्य को देखते हुए राज्य के वन एवं पर्यावरण मंत्री उन्हें पुरस्कृत कर चुके हैं।

सरोकार की अन्य खबरें पढ़ें
www.jagran.com/topics/positive-news

# बिहार में ट्रेन की चपेट में आई बैलगाड़ी, पांच यात्रियों की मौत

**जागरण संवाददाता, समस्तीपुर**

जासं, समस्तीपुर : बिहार में समस्तीपुर-खगड़िया रेलखंड पर गुरुवार को दिन में करीब 3 बजे हसनपुर रोड रेलवे स्टेशन के समीप सकरपुरा रेलवे फाटक के पास गेटमैन की लापरवाही से गन्ना लदी बैलगाड़ी से ट्रेन की चपेट में आ गई। इस घटना में पांच रेल यात्रियों की मौत हो गई, वहीं दो लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घायलों को स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। जहां से एक को गंभीर हालत में रेफर कर दिया गया।

**ऐसे हुई दुर्घटना** : महुआ गांव की ओर से गन्ना लदी बैलगाड़ी आ रही थी। उस वक्त ढाले का बूम खुला हुआ था। गाड़ीवान ने बैलगाड़ी को अंदर ले लिया, लेकिन आगे बढ़ते ही गाड़ी ट्रैक के गड्ढे में फंस गई। ट्रेन को आता देख गाड़ीवान ने बैलों को खोल कर भगा दिया और बैलगाड़ी को आगे से उठा दिया

**11** महीने का प्रशिक्षण दिया जाएगा गगनयान अभियान के लिए। यह भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है और इसके तहत चालक दल और सेवा का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा।



# एयर एशिया के सीईओ और अधिकारियों से पूछताछ करेगी ईडी

## केंद्रीय एजेंसी ने मनी लांड्रिंग मामले में समन जारी कर सीईओ टोनी फर्नांडीज को 20 को तलब किया

**नई दिल्ली, प्रेट्र :** एयर एशिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) टोनी फर्नांडीज व अन्य अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ईडी ने मनी लांड्रिंग मामले में फर्नांडीज व अन्य को पूछताछ के लिए समन जारी कर अगले हफ्ते तलब किया है। एयरलाइन के मौजूदा व पूर्व अधिकारियों को मामलों से संबंधित दस्तावेज भी साथ लाने के लिए कहा गया है।

अधिकारियों ने बताया कि फर्नांडीज को 20 जनवरी को उपस्थित रहने के लिए कहा गया है, जबकि अन्य को आगामी दिनों में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। ईडी ने 2018 में एयरलाइन व उसके अधिकारियों के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। वह मामले की जांच विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत कर रही है। जांच एजेंसी पूर्व में एयरलाइन के कुछ अधिकारियों से पूछताछ कर भी चुकी है। सीबीआइ की तरफ से रिपोर्ट दर्ज करने और ठिकानों पर छापेमारी के बाद एयर एशिया ने कहा था कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया। ईडी की कार्रवाई पर एयर एशिया समूह और एयर एशिया इंडिया से प्रतिक्रिया मांगी गई, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया गया।

टोनी फर्नांडीज। फाइल

### मिस्त्री के आरोप पर जांच शुरू

मामले की जांच टाटा समूह के पूर्व चेयरमैन सायरस मिस्त्री के आरोपों के बाद शुरू की गई थी। मिस्त्री ने आरोप लगाया था कि एयरलाइन को शामिल करते हुए भारत व सिंगापुर के पक्षों के बीच 22 करोड़ रुपये के सौदे हुए। हालांकि, जिन पक्षों के बीच सौदे दिखाए गए वास्तव में वे थे ही नहीं।

### नियमों को बदलने के लिए की गई अनुचित कोशिश

सीबीआइ की शिकायत के अनुसार, एयर एशिया इंडिया को अनुमति मिलने के बाद से ही फर्नांडीज अंतरराष्ट्रीय परिचालन की कोशिश करने लगे थे। आरोप है कि फर्नांडीज और उनके भारतीय साझीदार टाटा संस अपने नॉमिनी वेंकटरमणनन के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय परिचालन की अनुमति के लिए सरकार में अनुचित कोशिशें करने लगे। वे चाहते थे कि एयरलाइन को हर हाल में अंतरराष्ट्रीय परिचालन की अनुमति मिले, चाहे उसके लिए नियम (5/20) में संशोधन या बदलाव ही क्यों न करना पड़े। नियम के मुताबिक एयरलाइन को अंतरराष्ट्रीय परिचालन की अनुमति के लिए पांच साल के अनुभव व फ्लीट में 20 विमानों की उपलब्धता जरूरी है। एयर एशिया इंडिया फिलहाल भारत की 21 जगहों के लिए उड़ानों का संचालन करती है। एक वेबसाइट के मुताबिक उसके पास 29 एयरबस ए320 विमानों की फ्लीट है।

### एयर एशिया के अधिकारियों समेत अन्य पर दर्ज हैं मुकदमे

सीबीआइ और ईडी ने अपनी प्राथमिकियों में एयर एशिया समूह के सीईओ फर्नांडीज, एयर एशिया बेरहाद मलेशिया के डिप्टी ग्रुप सीईओ टी. कनागालिंगम उर्फ बो. लिंगम, एयर एशिया इंडिया लिमिटेड बेंगलुरु के निदेशक आर. वेंकटरमणनन, एयर एशिया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और एयर एशिया बेरहाद को नामजद किया है। सीबीआइ ने सिंगापुर की एचएनआर ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक राजेंद्र दूबे, मुंबई की टोटल फूड सर्विस के चेयरमैन सुनील कपूर, नई दिल्ली की डीटीए कंसल्टिंग के प्रिंसिपल और फाउंडर दीपक तलवार तथा एचएनआर ट्रेडिंग कंपनी को भी नामजद किया है। तलवार को पिछले ही साल दुबई से भारत लाया गया है। आरोप है कि नामजद लोगों ने वर्ष 2014 के आम चुनाव से पहले अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए विमानन नियमों में बदलाव की अनुचित कोशिश की।

# पीएमसी घोटाला : जेल में ही रहेंगे एचडीआइएल के प्रमोटर

▶ सुप्रीम कोर्ट ने वधावन पिता-पुत्र को घर में शिफ्ट करने के हाई कोर्ट के आदेश पर लगाई रोक

**नई दिल्ली, प्रेट्र :** पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक घोटाले के आरोपित हाउसिंग डेवलेपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एचडीआइएल) के पिता-पुत्र प्रमोटरों राकेश वधावन और सारंग वधावन को जेल में ही रहना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बांबे हाई कोर्ट के उस आदेश पर आंशिक रोक लगा दी जिसमें वधावन पिता-पुत्र को उनके घर में शिफ्ट करने की अनुमति दी गई थी और घर पर दो जेल गार्ड तैनात करने को कहा गया था।

प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने जांच एजेंसियों की ओर से दायर याचिका पर उक्त रोक लगाई। उन्होंने बांबे हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। ईडी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हाई कोर्ट द्वारा नियुक्त समिति की देखरेख में आरोपित प्रमोटरों की संपत्तियों की बिक्री जैसे हाई कोर्ट आदेश के अन्य पहलुओं को बरकरार रहने देना चाहिए। उनकी आपत्ति सिर्फ वधावन पिता-पुत्र की जेल से रिहाई को लेकर है। शीर्ष अदालत ने मामले के प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर चार हफ्ते में जबाव तलब किया है।

मेहता ने पीठ के समक्ष कहा कि पीएमसी बैंक घोटाला 7,000 करोड़ रुपये का है और हाई कोर्ट ने बुधवार को जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए बेहद असाधारण आदेश जारी किया था। पिता-पुत्र इस समय मुंबई की ऑर्थर रोड जेल में न्यायिक हिरासत में हैं। अगर हाई कोर्ट के आदेशानुसार उन्हें उनके घर में शिफ्ट किया गया तो यह उन्हें जमानत प्रदान करने जैसा होगा। मालूम हो कि पीएमसी बैंक घोटाला पिछले साल सितंबर में उस वक्त उजागर हुआ था जब रिजर्व बैंक को पता चला कि बैंक ने लगभग दिवालिया हो चुकी एचडीआइएल को दिए 4,355 करोड़ रुपये के कर्ज को छिपाने के लिए कथित रूप से फर्जी खाते बनाए हैं।

## न्यूज गैलरी

### कलकत्ता हाई कोर्ट में लगेगा जस्टिस क्लॉक

**कोलकाता :** कलकत्ता हाई कोर्ट परिसर में जल्द ही एक जस्टिस क्लॉक (न्याय घड़ी) स्थापित किया जाएगा। एक अधिकारी ने बताया कि जस्टिस क्लॉक के जरिए हाई कोर्ट में निपटाए जाने वाले मामलों का हर दिन का अपडेट और लंबित मुकदमों की स्थिति जानी जा सकेगी। इसके साथ ही इसके माध्यम से लोगों को राज्यभर की जिला और निचली अदालतों में मुकदमों की स्थिति के बारे भी जानकारी मिलेगी। जस्टिस क्लॉक एक इलेक्ट्रोनिक एलईडी डिस्प्ले बोर्ड है जहां राज्य के सभी न्यायालयों के मामलों के बारे में जानकारी मिल सकेगी। एलईडी बोर्ड पर हाई कोर्ट एवं जिला व अधीनस्थ न्यायालयों की रैंकिंग भी दिखाई जाएगी जो सबसे ज्यादा मुकदमे के निपटारे व उनके प्रदर्शन के आधार पर होगा। (जासं)

### गगनयान के चार अंतरिक्ष यात्रियों को रूस में प्रशिक्षण

**नई दिल्ली :** गगनयान परियोजना के लिए चुने गए चार अंतरिक्ष यात्रियों को रूस में 11 महीने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने यह जानकारी दी। परमाणु ऊर्जा एवं अंतरिक्ष राज्यमंत्री ने एक बयान में बताया कि रूस में अंतरिक्ष यात्रियों के प्रशिक्षण की शुरुआत जनवरी के तीसरे सप्ताह से होगी। बयान के अनुसार, '11 महीने तक रूस में प्रशिक्षण पाने के बाद अंतरिक्ष यात्रियों को भारत में मॉड्यूल विशेष का प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्हें इसरो द्वारा तैयार किए गए चालक दल व सेवा का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा।' 10 हजार करोड़ की इस परियोजना को आजादी की 75वीं सालगिरह के अवसर पर वर्ष 2022 में लांच किए जाने की उम्मीद है। (प्रेट्र)

### इंजन में खराबी से इंडिगो के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग

**मुंबई :** पुणे से जयपुर जा रहे इंडिगो के विमान को मुंबई में उतरने के लिए बाध्य होना पड़ा। एयरबस ए320 के एक इंजन में गड़बड़ी पैदा होने के कारण उसे मुंबई की ओर मोड़ना पड़ा। हालांकि, विमान में यात्रियों की संख्या की जानकारी नहीं मिली है। सूत्रों ने कहा, 'गुरुवार सुबह इंडिगो के विमान ने पुणे से जयपुर के लिए उड़ान भरी थी। उड़ान के दौरान पायलट ने इंजन में कंपन होने की जानकारी दी इसके बाद उसे मुंबई की ओर मोड़ना पड़ा। विमान ने सुबह में आपात लैंडिंग की।' इंडिगो ने एक बयान में जयपुर जा रहे विमान के मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की ओर मोड़ने की पुष्टि की है। वर्तमान में विमान को मुंबई में जांच के लिए रखा गया है। सभी यात्रियों को दूसरे विमान से जयपुर भेजा गया। (प्रेट्र)

**मौसम का मिजाज** ▶ दिल्ली में न्यूनतम तापमान में जारी रहेगी गिरावट, हिमाचल में 165 सड़कें बंद रहीं

# उत्तर भारत में बर्फबारी के बाद बारिश से बढ़ी ठंड

## उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में बारिश शुरू

**जागरण टीम, देहरादून**

उत्तर भारत में बर्फबारी और बारिश का दौर लगातार जारी है। पहाड़ी इलाकों में जहां बर्फबारी से दिक्कतें बनी हुई हैं। वहीं, दिल्ली एनसीआर समेत पूरे मैदानी इलाके, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में गुरुवार को पूरे दिन बारिश होती रही। इससे मौसम ठंडा बना हुआ है।

पश्चिमी विक्षोभ के कारण दिल्ली और एनसीआर में गुरुवार को बारिश से दिल्ली का मौसम ठंडा हो गया। आने वाले दिनों में दिल्ली में घना कोहरा छाए रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को लोधी रोड में सबसे अधिक 6.4 मिलीमीटर बारिश हुई। बारिश के कारण दिल्ली का अधिकतम तापमान गिरकर 16.4 डिग्री पर पहुंच गया। वहीं, न्यूनतम तापमान 9.5 डिग्री रहा। विभाग की माने तो बारिश के कारण शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 8 डिग्री तक गिर सकता है। विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में गिरावट होगी जो 20 जनवरी तक जारी रहेगा।

**उत्तराखंड और हिमाचल में आज भी भारी बारिश :** उत्तराखंड में बदरीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के साथ ही उच्च हिमालयी क्षेत्रों में दोपहर बाद बर्फबारी शुरू हो गई। निचले स्थानों में बारिश से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने प्रदेश में शुक्रवार के लिए भारी बर्फबारी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं, हिमाचल में गुरुवार को शिमला, कुफरी, नारकंडा, किन्नौर, लाहुल स्पीति, डलहौजी, पांगी व सराज में बर्फबारी और कई निचले क्षेत्रों में बारिश हुई। कुल्लू के सोलंगनाला और नेहरूकुंड में पर्यटक बर्फ के फाहों में झूमे। वहीं, बीआरओ ने भारत-चीन सीमा को जोड़ने वाले मार्ग पर आवाजाही बहाल कर दी है। जोशीमठ से मलारी तक 66 किलोमीटर लंबे हाईवे से बर्फ हटा ली गई है। हिमाचल में बर्फबारी व बारिश के कारण प्रदेश में 165 सड़कें बंद रहीं।

### ग्वालियर में बारिश ने तोड़ा 94 साल का रिकॉर्ड

मध्य प्रदेश और उससे लगे दक्षिण-पूर्वी राजस्थान पर ऊपरी हवा का चक्रवात सक्रिय होने से गुरुवार को प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हुई। ग्वालियर में 24 घंटे में 47.2 मिली मीटर पानी बरसा। ऐसे में यहां 94 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। क्योंकि 94 साल बाद जनवरी में इतनी बारिश हुई है। इससे पहले आठ जनवरी 1926 को 24 घंटे में 52.6 मिमी पानी बरसा था।

नई दिल्ली में गुरुवार को घना कोहरा छाने के बाद बारिश हुई। इस दौरान बारिश में ही वाहनों से गुजरते नजर आए लोग। एएफपी

# 'पनडुब्बी परियोजना मामले पर प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री चुप क्यों'

**नई दिल्ली, प्रेट्र :** कांग्रेस ने प्रोजेक्ट 75-आइ (पनडुब्बी परियोजना) में एक निजी समूह को फायदा पहुंचाने के अपने आरोप को लेकर गुरुवार को सवाल किया कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चुप क्यों हैं? पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा, '45 हजार करोड़ रुपये की पनडुब्बी परियोजना पर प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री की चुप्पी से कई संदेह पैदा होते हैं।' उन्होंने सवाल किया, 'भाजपा सरकार क्या छिपा रही है? प्रधानमंत्री एवं रक्षा मंत्री खामोश क्यों हैं? सरकार ने रक्षा खरीद प्रक्रियाओं का उल्लंघन क्यों किया?'

सुरजेवाला ने बुधवार को आरोप लगाया था कि नरेंद्र मोदी सरकार 45 हजार करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट 75-आइ (पनडुब्बी परियोजना) में एक निजी समूह को फायदा पहुंचाने के लिए रक्षा खरीद प्रक्रियाओं (डीपीपी) का उल्लंघन कर रही है। उन्होंने दावा किया था कि अगले कुछ दिनों के भीतर इस परियोजना के लिए आवेदन करने वाली चार कंपनियों में से एक के चुनाव पर निर्णय होना है और ऐसे में कांग्रेस राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए इस विषय को उठा रही है। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने ट्विटर पर कहा है, 'भारत की रक्षा तैयारी ढीली हो गई है और मेक इन इंडिया क्रोनी कैप्टलिज्म का प्लेटफार्म बन गया है। रक्षा प्लेटफार्मों के घरेलू उत्पादन के साथ समझौता किया जा रहा है। पीएमओ मध्यस्थता और उद्योगपतियों पर उदारता बरत रहे हैं।'

# बैंक फर्जीवाड़े को लेकर दिल्ली-फरीदाबाद में सीबीआइ ने मारे छापे

**नई दिल्ली, प्रेट्र :** सीबीआइ ने विभा ओवरसीज एग्जिम प्राइवेट लिमिटेड व उसके निदेशकों के खिलाफ 166 करोड़ रुपये के बैंक लोन फर्जीवाड़े की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद गुरुवार को दिल्ली और फरीदाबाद में दो स्थानों पर छापेमारी की। कंपनी और उसके निदेशकों पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को नुकसान पहुंचाने का आरोप है। अधिकारियों ने बताया कि जांच एजेंसी ने विभा ओवरसीज एग्जिम प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों आलोक गुप्ता व विभा गुप्ता के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

सीबीआइ ने कंपनी निदेशकों के नई दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित आवास और हरियाणा के फरीदाबाद स्थित दफ्तर पर छापेमारी की। अधिकारियों की ओर से बताया गया कि कंपनी के निदेशकों ने अज्ञात लोगों के साथ षड्यंत्र करके अपनी कर्ज क्षमता बढ़ाने के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के समक्ष गलत स्टॉक और देनदारों की सूची जमा की। सीबीआइ के अनुसार, 'कंपनी के निदेशकों ने कर्ज की राशि का गलत उपयोग किया।

# फर्जी मंत्री बनकर गोवा में की मौज-मस्ती, पहुंचा जेल

▶ गेस्ट हाउस कर्मचारियों के ऑनलाइन जांच करने पर सामने आई धोखाधड़ी

**निशांत यादव, लखनऊ**

गोवा में क्रिसमस और नया साल मनाने के लिए एक जालसाज फर्जी मंत्री बन गया। उसने राजाजीपुरम में लगे एक बेसिक फोन नंबर से गोवा के कलेक्टर को फैक्स किया। यूपी के मंत्री के स्वागत के लिए गोवा प्रशासन ने एयरपोर्ट पर सरकारी गाड़ी व ड्राइवर, सुरक्षा में पुलिस और ठहरने के लिए गेस्ट हाउस बुक कराया। जालसाज अपने चार साथियों के साथ 12 दिनों तक सरकारी खर्चे पर पहले गेस्ट हाउस फिर महंगे होटल में मौज करता रहा। भनक लगने पर जब क्राइम ब्रांच ने पूछताछ की तब गोवा सरकार के साथ धोखाधड़ी का पता चला।

कुर्सीरोड के गौरा बाग के रहने वाले सुनील कुमार सिंह ने कार्यालय-प्रोटोकाल विभाग उत्तर प्रदेश शासन सचिवालय के नाम से एक सरकारी पत्र बनवाया। जिस पर सचिव प्रोटोकाल उत्तर प्रदेश शासन की ओर से लिखा गया कि मंत्री सुनील कुमार सिंह अपने तीन अर्दली के साथ अति आवश्यक कार्य से उत्तरी गोवा जा रहे हैं। उनके ठहरने के लिए अतिथि गृह की व्यवस्था की जाए। लखनऊ के बेसिक नंबर 0522-2419752 से यह पत्र 23 दिसंबर को फैक्स किया गया। नार्थ गोवा प्रोटोकाल आफिस ने यह फैक्स पुलिस अधीक्षक, सीआइएसएफ कमांडेंट और एयरपोर्ट निदेशक को मंत्री की अगवानी के विशेष इंतजाम के लिए भेजा।

मंत्री की सुरक्षा के लिए गोवा पुलिस के कांस्टेबल गोपीचंद को तैनात किया गया। ड्राइवर व कार उपलब्ध कराने के साथ 24 दिसंबर से दो जनवरी तक मडगांव के सर्किट हाउस में ठहरने का इंतजाम किया गया। सरकारी खर्चे पर दो जनवरी तक मौज करने के बाद फर्जी मंत्री के साथ चित्रकूट के अजय कुमार तिवारी, श्रीकांत गर्ग, आशुतोष शुक्ल और धीरज मिश्र को वहां से पणजी के फिडालगो होटल में ठहरने की व्यवस्था की गई थी।

# बंगाल की डांसर ने होटल मालिक के कारण दी थी जान

**नईदुनिया, इंदौर :** इंदौर के चर्चित माय होम होटल में आत्महत्या करने वाली बंगाल की डांसर होटल मालिक जीतू सोनी से परेशान थी। आरोपित ने उसका शारीरिक शोषण किया और उसे बंधक बनाकर रखा था। उसकी कमाई भी हड़प ली। यह राज तीन साल बाद दोबारा जांच में उजागर हुआ है। जीतू व उसके कर्मचारी रामू पर केस दर्ज किया गया है। डीआइजी ने दोषी अफसरों के विरुद्ध भी जांच के आदेश दिए हैं।

गौरतलब है कि मध्य प्रदेश के चर्चित हनी ट्रैप मामले से जुड़े ब्लैकमेलिंग, मानव तस्करी व अन्य मामलों को लेकर फरार होटल मालिक जीतू सोनी के खिलाफ 50 से ज्यादा केस दर्ज हो चुके हैं। इंदौर की पलासिया थाना पुलिस के मुताबिक, मामला 23 जनवरी 2017 का है। जीतू उर्फ जितेंद्र पुत्र जगजीवनदास सोनी के गीता भवन स्थित होटल माय होम में 26 वर्षीय नेहा गौतम मित्रा ने फांसी लगाकर जान दे दी थी। तब पुलिस ने अज्ञात कारणों से आत्महत्या करना बताकर केस दबा दिया था।

# सिंधी लेखक वासदेव मोही को मिलेगा सरस्वती सम्मान

**जेएनएन, नई दिल्ली**

मशहूर सिंधी लेखक वासदेव मोही को उनके कहानी संग्रह 'चेकबुक' के लिए इस वर्ष का सरस्वती सम्मान देने की घोषणा की गई है। इस सम्मान के तहत लेखक को 15 लाख रुपये के साथ प्रशस्ति और प्रतीक चिह्न प्रदान किया जाएगा। केके बिरला फाउंडेशन प्रति वर्ष संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं में से किसी एक भाषा के लेखक की उत्कृष्ट कृति को सरस्वती सम्मान देता है। इसके चयन के लिए सम्मान वर्ष को छोड़कर पिछले 10 वर्ष में पुस्तक का प्रकाशित होना आवश्यक है। केके बिरला फाउंडेशन के निदेशक सुरेश ऋतुपर्ण के मुताबिक, 28 वर्षों में यह पहला अवसर है, जब किसी सिंधी लेखक को सरस्वती सम्मान दिया जाएगा।

वासदेव मोही सिंधी में कहानियों के साथ-साथ कविताएं भी लिखते हैं। उनके 10 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। 2 मार्च, 1944 को अविभाजित भारत के सिंध प्रांत के मीरपुर खास में जन्मे वासदेव मोही को साहित्य अकादमी समेत कई सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। इस वर्ष चयन समिति ने वासदेव मोही के अलावा गिरिराज किशोर के उपन्यास 'बा', स्वराज वीर के पंजाबी नाटक 'हक', मलयालम लेखक पी सच्चिदानंदन के कहानी संग्रह 'कथाकल', असमिया लेखक नगेन साइकिया के कविता संग्रह 'मितभाष समग्र' और नेपाली लेखक राजबहादुर राय के उपन्यास 'मेरो बालकांड' पर भी विचार किया। लोकसभा के पूर्व महासचिव सुभाष कश्यप की अध्यक्षता वाली चयन समिति में हिंदी समेत अन्य भारतीय भाषाओं के विद्वान शामिल हैं।

वासदेव मोही। फाइल

**कहानी संग्रह 'चेकबुक' के लिए दिया जाएगा केके बिरला फाउंडेशन का सम्मान**

**दिलचस्प नजारा**

मनाली के बर्फीले पहाड़ों के बीच इग्लू में रहने के लिए पर्यटकों में होड़, बर्फ के घर में ठहरने और खाने की तमाम सुविधाएं होती हैं उपलब्ध, 2015 में हुई थी मनाली के हामटा में इग्लू बनाने की शुरुआत

# हिमाचल में बना बर्फ का घर, नहीं सर्दी का डर

**जसवंत ठाकुर, मनाली**

बर्फ के घर यानी इग्लू में ठहरने के लिए अब पर्यटकों को फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, नार्वे, स्वीडन या कनाडा जाने की जरूरत नहीं। मनाली में ही कुछ उत्साही युवा इग्लू बनाकर न सिर्फ शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा दे रहे हैं बल्कि पर्यटकों को भी विदेशों का अहसास अपने देश में करवा रहे हैं। इसमें ठहरने, खाने व सोने की तमाम सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं।

मनाली के टशी और विकास ने पांच और शेनव व गुलाहटी ने तीन इग्लू तैयार किए हैं। हामटा में बने ये इग्लू सैलानियों के आकर्षण बने हुए हैं। साढ़े नौ हजार फीट की ऊंचाई पर बनाए इग्लू में रहने के लिए सैलानी रुचि दिखा रहे हैं। हालांकि रात को रुकने की बजाय दिन में ही इनमें समय व्यतीत करने को प्राथमिकता दी जा रही है। विकास व टशी ने बताया कि उन्होंने पहला इग्लू 2015 में मनाली में बनाया था। मनाली आने वाले सैलानी इग्लू में दो महीने तक रह सकते हैं। शेनव और गुलाहटी ने बताया कि बर्फ से तैयार किए घर ऑस्ट्रेलिया व अंटार्कटिका में देखने को मिलते थे। वे अब मनाली में ही पर्यटकों को यह सुविधा देने को तैयार हैं।

**क्या कहते हैं पर्यटक :** कोलकाता के पर्यटक दीपांकर व निरंजन कहते हैं, 'हम ऐसी जगह की तलाश में थे जहां मन को सुकून मिल सके। टशी व विकास से संपर्क होने पर उनकी इच्छा पूरी हो गई। हमने इग्लू के बारे में सुना था लेकिन अब इसमें रहने का मौका भी मिल गया।' गुजरात के पर्यटक विकास शाह ने बताया, 'पिछले साल उनके दोस्त इग्लू में रहे थे। वह भी इग्लू देखने के लिए उत्साहित था। इसमें रहकर बहुत आनंद आया। बाहर ठंड थी लेकिन इग्लू के अंदर तापमान सामान्य था। इग्लू में आरामदायक बिस्तर व खाने की पूरी व्यवस्था है।'

**इग्लू का आविष्कार :** साइबेरिया, अलास्का और ग्रीनलैंड जैसे ठंडे देशों के एस्कीमो (बर्फ में रहने वाले लोग) शिकार कर जीवन यापन करते थे। घर बनाने के लिए लकड़ी या अन्य सामान उपलब्ध न होने से एस्कीमो ने बर्फ से ही घर बनाना सीख लिया। धीरे-धीरे कुछ और देशों ने भी इसे अपना लिया।

**ऐसे बनाया जाता है इग्लू :** इग्लू बर्फ से तैयार किया जाता है। बर्फ के ब्लॉक बनाकर इन्हें आपस में जोड़ दिया जाता है। इसके बाद अंदर व बाहर बर्फ का लेप किया जाता है। ठंड अधिक होने से पूरा ढांचा जमकर मजबूत चट्टान बन जाता है। इग्लू के भीतर जाने के लिए संकरा गलीनुमा प्रवेश द्वार बनाया जाता है ताकि हवा अंदर प्रवेश न कर सके।

हिमाचल प्रदेश में मनाली के हामटा में बर्फ के घर यानी इग्लू, जो पर्यटकों को खूब लुभा रहे हैं। जागरण

बर्फ के घर यानी इग्लू के अंदर का दृश्य। जागरण

### अंदर व बाहर का तापमान

बर्फ में करीब 90 प्रतिशत तक हवा हो सकती है, लेकिन इग्लू जमने के बाद इंसुलेटर काम करता है, जो गर्मी को अंदर ही कैद कर लेता है। इसमें रहने वाले व्यक्ति के शरीर की गर्मी से अंदर का तापमान बढ़ने लगता है। बाहर तापमान माइनस 30 डिग्री सेल्सियस हो तो अंदर का तापमान एक से पांच डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। वहीं, बाहरी सतह जमी होने के कारण अंदर की नहीं पिघलती है।

### कैसे बने मनाली के इग्लू

मनाली के समीप हामटा के सेथन में नौ हजार फीट की ऊंचाई पर सर्दियों में भारी हिमपात होने और तापमान में गिरावट होने से यह इलाका इग्लू बनाने के लिए उपयुक्त था। यू ट्यूब पर वीडियो देखकर विकास और टाशी ने इग्लू बनाना सीखा। उन्होंने दोस्तों की मदद से एक सप्ताह में पहला इग्लू बनाया था।

### इग्लू के अंदर ये सुविधाएं

मनाली में इग्लू के भीतर बर्फ के बिस्तर व मेज बनाए गए हैं। पर्यटकों को गर्म बिस्तर और तकिए दिए जाते हैं। इग्लू में सजावटी लाइट, खाने के लिए कई तरह के व्यंजन, गर्म स्नो सूट, स्कीइंग, स्नो बोर्डिंग, बॉन फायर आदि सामान है।

# मध्य प्रदेश पीएससी की परीक्षा के पहले पेपर के छह प्रश्नों पर भी आपत्ति

**नईदुनिया, इंदौर :** मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (एमपी पीएससी) की ओर से 12 जनवरी को कराई गई राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2019 की मॉडल आंसर शीट जारी होने के बाद अब पहले पेपर के प्रश्नों पर भी असंतोष गहराने लगा है। बुधवार शाम जारी मॉडल आंसर शीट में प्रारंभिक परीक्षा के दूसरे पेपर सामान्य अभिरुचि के पांच प्रश्नों को आयोग ने हटा दिया, लेकिन पहले पेपर के सामान्य अध्ययन से एक भी प्रश्न को नहीं हटाया। उम्मीदवारों ने इसके छह सवालों पर आपत्ति लेते हुए इन्हें भी हटाने की मांग की है।

पहले पेपर के जिन प्रश्नों पर अभ्यर्थी आपत्तियां जता रहे हैं, उनके साथ दिए गए बहुविकल्प में या तो एक भी सही जवाब नहीं था या एक से ज्यादा सही जवाब थे। अब तक उम्मीदवार ऐसे छह प्रश्नों पर आपत्तियां ले चुके हैं। आयोग ने आपत्तियां दर्ज करवाने के लिए 17 से 23 जनवरी तक का समय दिया है। इसके लिए प्रति प्रश्न 50 रुपये की दर से फीस चुकानी होगी। अभ्यर्थियों का कहना है कि ऐसे प्रश्नों पर आपत्ति के लिए वह फीस क्यों जमा करें?

दैनिक जागरण
मन ईश्वर का औजार है, मन का औजार है बुद्धि

# संवैधानिक अराजकता

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार की ओर से जनसंख्या रजिस्टर यानी एनपीआर और जनगणना पर बुलाई गई बैठक का बहिष्कार करने की घोषणा करके अपनी क्षुद्रता भरी राजनीति पर नए सिरे से मुहर लगाने का ही काम किया है। नागरिकता संशोधन कानून और एनपीआर के बाद शायद अब उन्होंने जनगणना में भी कोई खोट निकाल लिया है। राष्ट्रीय महत्व के जरूरी कामों में इस तरह की अड़ंगेबाजी संवैधानिक तौर-तरीकों का अनादर ही नहीं, संघीय ढांचे को सीधे तौर पर दी जाने वाली चुनौती है। इससे तो एक किस्म की संवैधानिक अराजकता ही पैदा होगी। किसी राज्य सरकार से ऐसे अराजक व्यवहार की अपेक्षा नहीं की जाती, लेकिन शायद ममता सरकार को इसकी कहीं कोई परवाह नहीं। उसे राष्ट्रीय ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय महत्व के मामलों में भी अड़ंगा लगाने की आदत है। यदि बांग्लादेश के साथ तीस्ता नदी जल बंटवारे को लेकर कोई समझौता नहीं हो पा रहा है तो इसका कारण ममता की अड़ंगेबाजी ही है। वह केंद्र सरकार के प्रति अंध विरोध से इतना अधिक ग्रस्त हैं कि कई जनकल्याणकारी योजनाओं से भी बंगाल को बाहर किए हुए हैं। इनमें पिछड़े जिलों को विकसित करने की योजना के साथ-साथ किसान सम्मान निधि और आयुष्मान योजना भी शामिल है।

ममता यह समझने को तैयार नहीं कि उनकी जिद राज्य के लोगों का ही अहित कर रही है। यदि यह जनविरोधी राजनीति नहीं तो और क्या है? आखिर बंगाल के निर्धन किसानों और अन्य गरीबों को केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से वंचित रखने का क्या मतलब? मुश्किल यह है कि लोगों को बहकाकर अपनी सस्ती राजनीति चमकाने के फेर में संवैधानिक तौर-तरीकों का उपहास उड़ाने वाले और भी मुख्यमंत्री हैं। बंगाल की तरह केरल सरकार ने भी एनपीआर की प्रक्रिया रोकने की घोषणा की है। वह नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुकी है और वह भी तब जब नागरिकता के मामले में राज्यों की कहीं कोई भूमिका ही नहीं। यदि केंद्र सरकार की किसी पहल से कोई राज्य सरकार संतुष्ट नहीं तो उसे अपनी आपत्ति दर्ज कराने का अधिकार है, लेकिन इसका तो कोई मतलब ही नहीं कि वह झूठ और छल का सहारा लेकर केंद्रीय कानूनों का विरोध करे। आखिर जब एनपीआर तैयार करने का काम पहले भी हो चुका है और उसका मकसद केवल आम जनता की आर्थिक स्थिति जानकर यथोचित नीतियां और कार्यक्रम बनाना है तो फिर उसके विरोध का क्या मतलब? यह तो संवैधानिक दायित्वों के खिलाफ की जाने वाली बगावत है। बंगाल और केरल की सरकारों का आचरण भारतीय राजनीति के चेहरे को विकृत करने वाला ही नहीं, संघीय ढांचे का उपहास उड़ाने वाला भी है।

# स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार

जम्मू-कश्मीर में मरीजों की जिंदगी के साथ जुड़े स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टरों एवं पैरामेडिकल स्टाफ के पद सृजित करने का फैसला सराहनीय कदम है। निःसंदेह इससे बंद पड़े संस्थानों को फिर से शुरू करने में मदद मिलेगी और मरीजों को उनके द्वार पर ही सुविधाएं मिल सकेंगी। विगत दिवस ही जम्मू कश्मीर के स्वास्थ्य क्षेत्र में टीचिंग, नॉन टीचिंग, पैरामेडिकल और अन्य नॉन गजटेड स्टाफ के लिए आठ सौ के करीब पद सृजित करने की मंजूरी मिली है। यह पद सरकारी आयुर्वेदिक कॉलेज अखनूर, सरकारी यूनानी मेडिकल कॉलेज गांदरबल, श्रीनगर के बेमिना स्थित बच्चों के पांच सौ बैड के अस्पताल तथा इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस कश्मीर के लिए हैं। यह किसी से नहीं छुपा है कि आयुर्वेद और यूनानी कॉलेज बने दो वर्ष से अधिक हो गए हैं मगर स्टाफ की कमी के कारण यह कॉलेज मरीजों के लिए नहीं खोले जा रहे हैं। आयुर्वेद कॉलेज विभाग की प्रयोगशाला के लिए बनाई गई इमारत में चल रहा है। यही नहीं 100 बिस्तर वाले अखनूर स्थित आयुर्वेद अस्पताल में इस समय सिर्फओपीडी ही चल रही है। बाल रोग अस्पताल और इंस्टीट्यूट आफ न्यूरो सांइसेस में भी स्थिति कमोबेश ऐसी ही है।

**जम्मू-कश्मीर में स्वास्थ्य से जुड़े करोड़ों रुपये के प्रोजेक्ट ऐसे हैं जहां पर इमारतें तो बना दी गई हैं, मगर स्टाफ की कमी के कारण उनमें ताले लगे हैं।**

होना तो यह चाहिए था कि पूर्व की सरकारें इन कॉलेजों और अस्पतालों को सुचारू ढंग से चलाने के लिए पहले ही यह पद सृजित करतीं, लेकिन उन्होंने इमारतें बनाने के अलावा कुछ भी नहीं किया। सिर्फ यही नहीं, राज्य में स्वास्थ्य से जुड़े करोड़ों रुपये के प्रोजेक्ट ऐसे हैं जहां पर इमारतें तो बना दी गई हैं, मगर स्टाफ की कमी के कारण उनमें ताले लगे हैं। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद विकास को लेकर लोगों को केंद्र सरकार एवं स्थानीय प्रशासन से काफी उम्मीदें हैं। ऐसे में सरकार ने चार अहम प्रोजेक्ट के लिए पद सृजित करके एक नई उम्मीद जगाई है। अब प्रशासन को चाहिए कि इन पदों पर भर्ती के लिए भी जल्दी ही प्रक्रिया शुरू करे ताकि जल्द यह प्रोजेक्ट शुरू हों और मरीजों को इनका लाभ मिले। यही नहीं स्वास्थ्य विभाग में रिक्त पड़े अन्य पदों को भरने के लिए भी प्रक्रिया शुरू किए जाने की जरूरत है।

# इतिहास के पुनर्लेखन में देरी

प्रो. मक्खन लाल

**भारतीय इतिहास और शिक्षा के क्षेत्र में स्वतंत्रता के बाद जो काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था वह अब तक नहीं हुआ, इसमें और देर नहीं होनी चाहिए**

पिछले शनिवार को कोलकाता पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस व्यथा से भारतीय इतिहास एवं विरासत की दुर्दशा पर चर्चा की उस पर एक देशव्यापी चर्चा आवश्यक है। उन्होंने कहा, 'यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि अंग्रेजी शासन के दौरान और स्वतंत्रता के बाद देश का जो इतिहास लिखा गया उसमें कुछ अहम पक्षों को नजरअंदाज किया गया। इतिहास का लेखन एवं विश्लेषण सत्ता और सिंहासन तक ही सीमित रह गया।' उन्होंने गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर के 1903 में 'भारतवर्ष का इतिहास' विषय पर शांति निकेतन में दिए गए भाषण की भी याद दिलाई। इसमें गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि भारत का इतिहास वह नहीं है जो हम परीक्षाओं के लिए पढ़ते और याद करते हैं। जैसे कि कुछ लोग बाहर से आए और सिंहासन के लिए पिता-पुत्र-भाई और स्वजनों की हत्या करते रहे। यह भारत का इतिहास नहीं है, क्योंकि इस इतिहास में यह जिक्र नहीं है कि तब भारत के लोग क्या कर रहे थे? क्या उनका कोई अस्तित्व नहीं था? क्या साहित्य, कला, लोक कला, विज्ञान, स्थापत्य, दर्शन, शिक्षा, जीवन शैली आदि का इतिहास में कोई स्थान नहीं होना चाहिए था? उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर इतिहास के पुनर्लेखन में इन सभी बातों के समावेश की बात की। इस तरह की बात पहले भी अनेक अवसरों पर कही जा चुकी है।

राष्ट्र के जीवन में इतिहास का महत्व इस बात से समझा जा सकता है कि 1990 के बाद कनाडा की संसद की संस्तुति पर इतिहास की पाठ्यपुस्तकों को फिर से लिखा गया, क्योंकि वहां के स्कूलों में पर्याप्त कनाडाई इतिहास छात्रों को नहीं पढ़ाया जाता था, इसलिए इसके बारे में उन्हें पता भी नहीं था। जो इतिहास पढ़ाया जाता था वह पर्याप्त रूप से राष्ट्रीय नहीं था। उसमें कनाडा के अतीत के सकारात्मक पहलुओं का समावेश नहीं था। अपने देश की बात करें तो भारतीय संदर्भ में इतिहास की किताबें और इतिहास लेखन सार्वजनिक क्षेत्र में आते हैं। हाल के समय में यह मीडिया के ध्यान का विषय तब बन गया जब एनडीए-एक सरकार के दौरान एनसीईआरटी ने राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा और सभी विषयों की पाठ्यपुस्तकों को नियमित करने की बात कही। विरोधियों को किसी अन्य विषयों के पाठ्यपुस्तकों में संशोधन से कोई समस्या नहीं थी, लेकिन इतिहास की पाठ्यपुस्तकों की बात आने पर ऐसा लगा जैसे आसमान ही टूट पड़ा। पहले इतिहास की पाठ्यपुस्तकों के लेखन में शामिल रहे कुछ तथाकथित 'प्रख्यात इतिहासकारों और उनके समर्थकों ने एक अभियान शुरू किया कि इतिहास को फिर से लिखा या संशोधित नहीं किया जा सकता। उन्होंने इतिहास के नए तथ्यों को समाहित करती हुई तब की तैयार की गई नई पुस्तकों को सिरे से नकार दिया, क्योंकि ये पुस्तकें वामपंथ से अलग हटकर थीं और गुरुदेव टैगोर के सुझाए गए मार्ग पर थीं।

दुनिया भर में लगभग हर देश, शहर और गांव में लोगों की जरूरतों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अतीत में बड़ी संख्या में मौजूदा इमारतें या भवनें बनाई गईं, जो अब विलीन हो चुकी हैं। कुछ का वजूद मंदिरों, चर्चों, मस्जिदों, घरों, सार्वजनिक भवनों आदि में शेष रह गया है, परंतु अधिकांश प्राचीन समाजों में बनीं ऐतिहासिक इमारतें अब विलुप्त हो गई हैं। इसके अलावा सरकारों, राजनीतिक विचारों, धार्मिक विश्वासों, कला, वास्तुकला, सांस्कृतिक प्रथाओं, शैक्षिक प्रणालियों, रीति-रिवाजों और व्यवहार की प्रणालियां आदि अतीत या हाल ही के उत्पाद हैं।

अतीत सर्वव्यापी है। वास्तव में इसका अर्थ है कि हम इससे बच नहीं सकते। अतीत यह दर्शाता है कि वास्तव में क्या हुआ था? ऐसी घटनाएं हुई हैं जिससे समाज आगे बढ़ा या गिरा? विचारों और संस्थानों, खाने की आदतों, पहनावे का ढंग, आदतों आदि का इतिहास मानव अतीत का अध्ययन है। अतीत हमारी धरोहर है। हम इसका हिस्सा हैं। चाहे यह संस्कृति, व्यवहार, धार्मिक विश्वास, अनुष्ठान, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक प्रणालियों की परंपरा ही क्यों न हो। हमारा अतीत और हमारी धरोहर हमारे दिन-प्रतिदिन के जीवन में परिलक्षित होती है। इतिहास हमारी जड़ों के बारे में भी बताता है। यह हमें हमारे अतीत से जोड़ता है। इतिहास हमें अतीत की गलतियों की पुनरावृत्ति के खिलाफ समकालीन कार्यों के लिए मिसाल प्रदान करके भविष्य में झांकने की अनुमति देता है। निरंतरता की अपनी भावना से इतिहास भूत, वर्तमान और भविष्य को स्पष्ट रूप और उद्देश्य प्रदान करता है। हम वर्तमान को केवल अतीत के प्रकाश में ही पूरी तरह से समझ सकते हैं। हम अतीत को अनदेखा या टाल नहीं सकते। हम जहां भी जाते हैं, अतीत हमें घूरता रहता है।

दुनिया भर में उपनिवेश के अनुभव ने एक अधिक शक्तिशाली संस्कृति के वर्चस्व को दिखाया है। दूसरी संस्कृति को उसने या तो पूरी तरह से नष्ट कर दिया या उसे कम शक्ति वाली एक अधीनस्थ में बदल दिया। उदाहरणार्थ पूरे भारतीय वैदिक एवं ब्राह्मण साहित्य को कपोल कल्पित घोषित कर दिया गया, क्योंकि भारतीय वैदिक साहित्य में ब्रह्मांड की कल्पना अरबों-खरबों सालों की है। काल गणना चतुर्युगों में थी जो अंग्रेजों की मान्यता के खिलाफ थी। उनकी मान्यता के अनुसार तो पूरे ब्रह्मांड की रचना 23 अक्टूबर, 4004 ईसा पूर्व प्रातःकाल 9 बजे हुई थी। ऐसे में वे करोड़ों, अरबों, खरबों सालों के इतिहास की कल्पना कैसे कर सकते थे?

इतिहासकारों के रूप में हमें यह स्वीकारना चाहिए कि अतीत अलग-अलग संस्कृतियों द्वारा अलग-अलग तरीकों से बना माना जाता है। अतीत की व्याख्या, रिकॉर्डिंग, प्रबंधन और सुरक्षा के तरीके भी संस्कृतियों के बीच भिन्न होते हैं। लोग अपने अस्तित्व को, अपनी दुनिया को देखते हैं और सृजन की कहानियों को परिभाषित करते हैं। अपने अतीत को कैसे महत्व देते हैं, व्याख्या करते हैं, प्रबंधित करते हैं और संचारित करते हैं, यह उनके द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी जारी रखा जाता है। बहरहाल भारतीय इतिहास और शिक्षा के क्षेत्र में स्वतंत्रता के बाद जो काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था वह अब तक नहीं हुआ, बल्कि वह और भी विकृत हो गया। जिस दृष्टि की बात श्री अरविंद और गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने की, हमें उस भारतीय दृष्टि से भारतीय इतिहास लेखन के काम को आगे बढ़ना चाहिए। और शिक्षा का भी भारतीयकरण होना चाहिए, जिसकी बात गांधी जी ने की थी। यूनेस्को भी कहता आ रहा है कि शिक्षा की जड़ें सांस्कृतिक परंपरा में होनी चाहिए और उसका उद्देश्य श्रेष्ठ मानव निर्माण का होना चाहिए।

(लेखक इतिहासकार हैं)

response@jagran.com

# सीएए विरोध का खतरनाक रूप

प्रो. निरंजन कुमार

**झूठ के सहारे सीएए का विरोध संवैधानिक और सांस्कृतिक धरातल पर खतरनाक तो है ही, अनैतिक भी है**

नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए दस जनवरी से देशभर में लागू कर दिया गया। इसके बावजूद इस कानून का विरोध राजनीतिक दायरे से बाहर निकलकर संवैधानिक और धार्मिक-सांस्कृतिक धरातल पर भी होने लगा है। केरल की विधानसभा द्वारा इस कानून को रद करने का प्रस्ताव पारित करना अथवा विरोध प्रदर्शन के दौरान फैज अहमद फैज की मजहबी प्रतीकों वाली नज्म हम देखेंगे गाया जाना, फ्री कश्मीर के पोस्टर लहराना और हिंदू विरोधी उत्तेजक धार्मिक नारे लगाया जाना इसी की बानगी है। झूठ के सहारे सीएए का विरोध संवैधानिक और सांस्कृतिक धरातल पर खतरनाक तो है ही, राजनीतिक रूप से भी अनैतिक है। केरल विधानसभा द्वारा सीएए कानून को रद करने का प्रस्ताव अभूतपूर्व और संविधान का पूरी तरह से उल्लंघन है। अब तो केरल सरकार सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गई है। भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची में राज्यों और संघ के मध्य विषयों/अधिकारों के बंटवारे का उल्लेख है। राष्ट्रीय महत्व से संबंधित विषयों को संघ सूची में रखा गया है, जिन पर कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को है। नागरिकता या जनगणना जैसे विषय संघ सूची में ही हैं। संविधान में उल्लिखित अनुच्छेद 245 से 255 का सार यही है कि संसद द्वारा बनाए गए कानून का अनुपालन प्रत्येक राज्य को करना ही पड़ेगा। इसे न मानने का अर्थ है संविधान का उल्लंघन। केरल विधानसभा ने इस संवैधानिक लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किया। वहां के मुख्यमंत्री विभिन्न राज्यों को इस कानून के विरोध के लिए उकसा रहे हैं। इससे तो हमारे संविधान का ढांचा ही चरमरा उठेगा। सीएए विरोधियों का यह तर्क नितांत गलत है कि सीएए अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। कई विधि विशेषज्ञ यह कह चुके हैं कि ऐसा कुछ नहीं है।

सीएए विरोध में धीरे-धीरे मजहबी और ऐसे सांस्कृतिक प्रतीकों का इस्तेमाल हो रहा है जो विवादास्पद हैं। नज्म हम देखेंगे के समर्थकों का दावा है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है और फैज ने पाकिस्तान में जनरल जियाउल हक की तानाशाही के खिलाफ इसे लिखा था, लेकिन जिन फैज को क्रांतिकारी, पंथनिरपेक्ष और मानवतावादी बताया जा रहा है उन्होंने 1971 में पाकिस्तानी सेना द्वारा बांग्लादेश में लाखों लोगों के नरसंहार पर चुप्पी साध ली थी, क्योंकि वह जुल्फिकार अली भुट्टो के समर्थक थे।

सांस्कृतिक प्रतीक देश और काल के सापेक्ष होते हैं और उसी परिप्रेक्ष्य में लोग इसका अर्थ ग्रहण करते हैं। मिसाल के लिए इंग्लैंड आदि देशों में उल्लू बुद्धिमानी का प्रतीक है। क्या हम भारत में भी किसी को उल्लू कह सकते हैं और यह तर्क दे सकते हैं कि वह तो उसकी तारीफ कर रहे थे? फैज की नज्म तानाशाही वाले इस्लामी मुल्कों में ही ठीक है। पाकिस्तान जैसे मुल्कों में जहां इस्लाम राजधर्म है वहां मजहबी प्रतीकों से लबरेज यह नज्म प्रतिरोध के रूप में, शायद गलत नहीं हो, पर भारत जैसे पंथनिरपेक्ष देश में इस तरह के मजहबी प्रतीक गलतफहमियां पैदा करेंगे। पाकिस्तान में इस्लाम का जो कट्टर रूप मौजूद है वह किसी भी दूसरे पंथ-पूजा को बर्दाश्त नहीं कर पाता। भगवान बुद्ध की अफगानिस्तान के बामयान में स्थित चौथी-पांचवीं शताब्दी में बनी प्रतिमाओं को कट्टरपंथी मुसलमानों ने टैंक लगाकर इसलिए उड़ा दिया था कि इस्लाम में बुत या मूर्ति के लिए कोई जगह नहीं है और अल्लाह ही एकमात्र ईश्वर है। पाकिस्तान में आए दिन मंदिर तोड़े जाने और धर्मांतरण आदि की घटनाएं घटती रहती हैं।

सीएए विरोध का एक आयाम राजनीतिक भी है। सीएए के बहाने मोदी सरकार पर निशाना लगाने का विपक्षी राजनीतिक दलों को जैसे मौका मिल गया है। गहराई से देखें तो कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी, टीएमसी, सपा, बसपा, आप, राजद आदि दलों और उनके नेताओं को मुस्लिम वोटों को गोलबंद करने का एक सुनहरा अवसर दिख रहा है। मुसलमानों को अपने-अपने पक्ष में करने के लिए इन राजनीतिक दलों में एक कंपटीटिव पॉलिटिक्स चल रही है। मुस्लिम समुदाय को समझना चाहिए कि सीएए से भारतीय मुसलमानों के किसी भी अधिकार या नागरिकता पर कोई आंच नहीं आने वाली। यह तो कुछ लोगों को नागरिकता देने का कानून है, किसी की नागरिकता लेने का नहीं। विपक्षी दल मुसलमानों का भला की जगह बुरा ही कर रहे हैं। वैसे भी मुसलमानों के असली मुद्दे तो इन दलों की चिंता का विषय शायद ही कभी होते हैं। मुस्लिम समुदाय को अपने राजनीतिक इस्तेमाल के प्रति सचेत होना चाहिए।

पूरे प्रकरण में एक अन्य खतरनाक बात यह है कि मुसलमानों को डराने के लिए मीडिया का एक वर्ग और तथाकथित बुद्धिजीवी किसी भी अतिवाद तक जाने को तैयार हैं। दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में सीएए के विरोध में कुछ लोग एक माह से सड़क पर कब्जा जमाए बैठे हैं। इसके कारण हर दिन लाखों लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन विपक्षी दलों और मीडिया का एक हिस्सा इसकी अनदेखी करने में लगा हुआ है। निःसंदेह ये भी अच्छे संकेत नहीं कि विरोध प्रदर्शनों में फ्री कश्मीर के पोस्टर लहराए जा रहे हैं। सीएए का विरोध नैतिक रूप से भी गलत है। सीएए में इस्लामी पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के मजहबी आधार पर उत्पीड़ित छह धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने की बात है। इन लोगों की वहां क्या हालत है, इसका अंदाजा वहां उनकी तेजी से घटती जनसंख्या से लगा सकते हैं। यह अनायास नहीं कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉ. राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल से लेकर मनमोहन सिंह, अशोक गहलोत, प्रकाश करात अथवा ममता बनर्जी आदि ने पूर्व में मजहबी आधार पर उत्पीड़ितों को भारत में शरण देने की पुरजोर वकालत की थी। छल-प्रपंच का सहारा लेकर सीएए का विरोध एक खतरनाक सियासत है। इसके भयानक दुष्परिणाम हो सकते हैं।

(लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं)

response@jagran.com

## ऊर्जा

### दोषपूर्ण उपलब्धियां

जीवन में सफलता, उच्चस्तरीय रहन-सहन, प्रचुर धन-दौलत की इच्छा अधिकांश लोगों को होती है। ऐसे लोग चाहते हैं कि उनका समाज में खूब दबदबा रहे, उनकी जयजयकार होती रहे, उनके पास सर्वाधिक भौतिक संसाधन हो। इस तरह की इच्छा का होना कोई खराब तो नहीं, लेकिन इसके लिए कड़ी मेहनत की जरूरत होती है। प्रायः देखने में आता है कि अधिकांश लोग इसी मामले में विफल हो जाते हैं। वे इस तरह की सारी उपलब्धियां रातोंरात प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसे लोग इस भाव के चलते परिश्रम, धैर्य की जगह उतावले हो कर नकारात्मक रास्ता अपनाने लगते हैं और छल, धोखा, अनैतिक ढंग से कुछ हासिल कर तो लेते हैं, लेकिन धीरे-धीरे उनमें एक अज्ञात भय भी समाने लगता है। वैसे भी कहा गया है किसी भी उपलब्धि के लिए ठोस आधार उसी प्रकार होना जरूरी है जिस प्रकार किसी भवन या महल के लिए मजबूत आधार की जरूरत होती है।

जीवन में विविध प्रकार की उपलब्धियों के लिए धैर्य और धर्म का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरों का हिस्सा हड़प कर प्राप्त उपलब्धि दोषपूर्ण है। इससे परिवार से लेकर समाज तक में कटुता का वातावरण बनता है। कोई भी सांसारिक सुख प्राप्त करने के पहले मन से खुद बात करनी चाहिए। जो ऐसा नहीं करता है, उसे दुख मिलता है। इसीलिए कहा गया है कि 'बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताय।' स्थिति यह है कि हर कोई एक दूसरे का विश्लेषण तो कर रहा है, पर खुद पर उसका ध्यान नहीं जा रहा है। यदि कोई व्यक्ति दूसरे के घर के कूड़े करकट की सफाई करता है तो उस व्यक्ति का घर साफ हो जाएगा, पर अपने घर में गंदगी बनी रहेगी। जबकि हर व्यक्ति को अपना घर साफ करना चाहिए। यही बात आचरण के लिए भी जरूरी है। व्यक्ति इस बात की चिंता छोड़कर कर कि कौन कैसा है, वह अपने स्वभाव और आचरण को उत्तम बनाए तो उसकी ही छवि उत्तम होगी। एक न एक दिन उसकी ख्याति अवश्य बढ़ेगी।

सलिल पांडेय

# युवा शक्ति को उभारने की दरकार

अनीश कुमार

एक देश किस दिशा में आगे बढ़ेगा, यह बहुत हद तक युवा आबादी की प्रगतिशील सोच पर ही निर्भर करती है। युवा आबादी में उत्पादकता चरम पर होती है। अगर युवा-ऊर्जा का रचनात्मक और सकारात्मक उपयोग कर लिया जाए तो हमारा देश सदैव शिखर पर ही रहेगा। युवा आबादी के ऊपर किशोरों और बुजुर्गों दोनों वर्गों को अपनी श्रमशक्ति से पालन-पोषण करने की जिम्मेदारी होती है। उच्च आर्थिक विकास वाले अधिकांश विकसित राष्ट्र आज जब अपनी वृद्ध होती जनसंख्या से दो-चार हो रहे हैं, तब भारत अपनी युवाशक्ति के बल पर वैश्विक क्षितिज का सिरमौर बनने की तैयारी में है।

आंकड़ों की मानें तो भारत इस वक्त विश्व का सबसे युवा देश है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक भारत की 65 फीसद आबादी की उम्र 35 वर्ष से कम है। हालांकि इस युवाशक्ति पर नाज करना जितना जरूरी है, उतना ही इस सवाल का सामना करना कि क्या देश में युवाओं की क्षमता, कुशलता एवं प्रतिभा का संपूर्ण उपयोग हो पा रहा है? चूंकि किसी देश की युवा आबादी ही उस देश की कार्यशील जनसंख्या होती है। ऐसे में अभी यदि युवा शक्ति का संपूर्ण उपयोग न हो तो कुछ वर्षों बाद यही युवा वर्ग प्रौढ़ावस्था में प्रवेश करके भारशील जनसंख्या में तब्दील हो जाएगा। तब हमारे पास हाथ मलने के सिवा कुछ भी नहीं बचेगा। भले ही आज चीन और जापान विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश हैं, लेकिन एक कड़वी सच्चाई यह भी है कि आज वे अपनी वृद्ध होती जनसंख्या से भी दो-चार हो रहे हैं।

**संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक भारत की 65 फीसद आबादी की उम्र 35 वर्ष से कम है**

वृद्ध होती जनसंख्या एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन तेजी से वृद्ध होती आबादी आर्थिक संकट भी पैदा करती है। बीते दिनों अमेरिका के जनसंख्या संदर्भ ब्यूरो द्वारा किए गए एक अध्ययन में कहा गया कि 2050 तक आज का युवा भारत बूढ़ा हो जाएगा। उस समय देश में 65 साल से अधिक उम्र के लोगों की संख्या तीन गुनी हो जाएगी। ऐसे में यह आवश्यक हो जाता है कि युवा शक्ति का समय रहते भरपूर उपयोग किया जाए।

ऐसा नहीं है कि भारतीय युवाओं में संभावनाएं नहीं हैं। वे क्षमतावान भी हैं, लेकिन मूल्यपरक, गुणवत्तापूर्ण और रोजगारपरक शिक्षा के अभाव में युवाओं की क्षमता का पर्याप्त विकास नहीं हो पाया है। देश में गरीबी और बेरोजगारी का बढ़ता ग्राफ, युवाओं को प्रचलित शासन व्यवस्था के विरुद्ध रोष पैदा कर विरोध का विपथगामी मार्ग अख्तियार करने को विवश करती है, जिससे उग्रवाद, नक्सलवाद और आतंकवाद जैसी विकृतियों को बढ़ावा मिलता है। वहीं विभिन्न प्रकार के मादक पदार्थों के सेवन से कई युवाओं में चारित्रिक पतन हो रहा है। देश के भविष्य के रूप में देखे जाने वाले कई युवा अपने लक्ष्य से भटक रहे हैं, जिससे उनका भविष्य अंधकारमय हो चला है। सामाजिक ताना-बाना और मान-मर्यादा का ख्याल किए बिना असामाजिक कृत्यों की ओर युवाओं का बढ़ता कदम राष्ट्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

## मेलबाक्स

### दलित-मुस्लिम गठजोड़ संभव नहीं

दलित-मुस्लिम गठजोड़ की राजनीति शीर्षक आलेख इस भ्रम तथा अपुष्ट तथ्य पर आधारित है कि बाबासाहब आंबेडकर इस गठजोड़ की बदौलत ही संविधान सभा में पहुंचे और इसलिए वे इस प्रकार के गठजोड़ के हिमायती बन गए। डॉ. आंबेडकर को अपने निर्वाचन के लिए बंगाल असेंबली में कुल 26 वोट चाहिए थे, जिसमें से 25 का प्रबंध उनकी फेडरेशन के पास था, केवल एक अतिरिक्त मत की आवश्यकता और थी। बाबासाहब ने अपने प्रयास से मुस्लिम लीग के स्थान पर एक निर्दलीय वोट का प्रबंध करके चुनाव जीता था, यह तथ्य अब स्पष्ट होता जा रहा है। कारण ये है कि दलित-मुस्लिम गठजोड़ अथवा हिंदू-मुस्लिम गठजोड़ के किसी भी प्रयास को वे निर्वाचन से तत्काल पूर्व प्रकाशित अपनी पुस्तक 'पाकिस्तान ऑर द पार्टीशन ऑफ इंडिया' में फिजूल ठहरा चुके थे। उनकी इस पुस्तक के 5वें अध्याय का शीर्षक है 'हिंदू-मुस्लिम एकता के निष्फल प्रयास'। पहले परिशिष्ट का शीर्षक है 'हिंदू एकता की आवश्यकता'। परिशिष्ट में ही उन्होंने भावी पाकिस्तानी इलाकों में रहने वाले दलितों के लिए कुछ परामर्श जारी किए हैं। इनमें जोगेंद्रनाथ मंडल के लिए कहा गया है कि वे मुस्लिम लीग के झांसे में न रहें, क्योंकि जिन्ना उनका उपयोग सिलहट जिले में होने वाले जनमत संग्रह में दलित वोट पाकिस्तान के पक्ष में प्राप्त करने हेतु कर लेंगे, बदले में मंडल या दलित समाज को सिवाय असुरक्षा के कुछ नहीं मिलेगा। उन्होंने मंडल के लिए सार्वजनिक वक्तव्य भी जारी करके कहा कि वे लीग मंत्रिमंडल छोड़कर भारत लौटें। बाबासाहब का संविधान निर्माण के समय का रुख यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है कि वे लीगी विचार के जड़ से विरुद्ध थे। उनके अलग निजी कानून का उन्होंने मुखर विरोध कर सभी भारतीयों हेतु एक समान नागरिक संहिता बनाने की तर्कपूर्ण वकालत की थी। यही नहीं, मुस्लिमों के लिए किसी भी प्रकार के आरक्षण की मांग उन्होंने अनुचित तथा सेकुलरिच्म-विरोधी बताई। बाबासाहब को दलित-मुस्लिम गठजोड़ का पैरोकार बताना अनुचित है। बद्री नारायण इस गठजोड़ में जो भविष्य की सफल राजनीति खोज रहे हैं, वे पाकिस्तान-बांग्लादेश में दलितों की नारकीय दशा पर जरा तो विचार कर लेते। सीएए का विरोध कर रहे कितने ही मध्यक्रम के मुस्लिम नेता कह चुके कि वक्त आ गया है जब हम बाबासाहब का संविधान उलटकर शरिया-आधारित नई निजामे मुस्तफा कायम करेंगे।

अजय मित्तल, मेरठ

### सुपात्र को ही मिलें पुरस्कार

हर वर्ष की तरह इस साल भी गणतंत्र दिवस पर केंद्र सरकार की ओर से पद्म पुरस्कारों की घोषणा की जाएगी। पिछले कुछ सालों से मोदी सरकार ने इन पुरस्कारों के नामांकन के लिए ऑनलाइन व्यवस्था की है। देश का कोई भी व्यक्ति किसी को इस पुरस्कार के लिए नामांकित करा सकता है। फल स्वरूप पुरस्कार ग्रहण करते कई साधारण से चेहरे देखना एक सुखद अनुभूति होती है। वस्तुतः राष्ट्र निर्माण में कई ऐसे व्यक्तित्व का भी योगदान होता है, जो मूक होकर बिना किसी प्रचार, बिना किसी वितंडा के अपना कार्य कर रहे होते हैं। उन्होंने किसी पुरस्कार या किसी सम्मान प्राप्ति के लिए यह कार्य नहीं किया, अपितु अपनी अंतरात्मा की आवाज, अपने चारों ओर दिखती समस्याओं के निवारण के लिए, स्वतः स्फूर्ति ये पुण्य कार्य निःस्वार्थ भाव से प्रारंभ किए। ऐसे लोग समाज के अवरोधों और उपहासों की परवाह किए बिना, निर्विकार होकर अपनी कार्य सिद्धि के लिए संघर्षरत रहे। फल-स्वरूप समाज, राष्ट्र और मानवता को इन महान विभूतियों से कुछ न कुछ प्राप्त हुआ। वृक्ष- माते इसका सटीक उदाहरण हैं। माउंटेन मैन दशरथ मांझी का कार्य भी युगों युगों तक युवाओं को प्रेरणा देता रहेगा। ऐसे कर्मठ, सुयोग्य और लगनशील व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार मिलना वस्तुतः उनमें स्वयं व संपूर्ण समाज में ऊर्जा और उत्साह का संचार करता है। हवाई चप्पलों में पुरस्कार ग्रहण करते दिखते ये लोग वस्तुतः सच्चे राष्ट्र नायक हैं। इन पुरस्कारों में सरकार ने पारदर्शिता के उच्च मापदंड स्थापित कर एक पुनीत कार्य किया है। दुर्लभता अमूल्य होती है। पुरस्कार कम दिए जाएं, लेकिन सुपात्र को ही मिलें। हीरा दुर्लभ होने पर ही तो बहुमूल्य है। इससे समाज को प्रेरणा मिलती है।

डॉ. मनोज कुमार शर्मा, स्याना

**इस स्तंभ** में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

**अपने पत्र इस पते पर भेजें :**
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संज

**1954** तक रूस का हिस्सा था क्रीमिया, जिसे उस वर्ष यूक्रेन को सौंप दिया गया था। लगभग 60 वर्षों के बाद 2014 में रूस ने फिर से क्रीमिया को अपने कब्जे में ले लिया।

आजकल

# पीओके पर क्रीमिया बन सकता है हमारा रोडमैप

अशोक श्रीवास्तव
वरिष्ठ टीवी पत्रकार

**कुछ माह पूर्व जब अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया गया और जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित क्षेत्र का दर्जा दिया गया, तो उसके बाद से पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर को भी भारत में मिलाने की चर्चा शुरू हुई। हाल ही में नए सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे ने भी इस संबंध में बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से उन्हें यदि आदेश मिले तो निश्चित तौर पर सेना इस संबंध में उचित कार्रवाई कर सकती है। तो क्या ऐसे में रूस द्वारा कुछ वर्ष पूर्व क्रीमिया को यूक्रेन से हासिल करने के रोडमैप को भी ध्यान में रखा जा सकता है ...**

प्रतीकात्मक फोटो।

नए सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर दोटूक बयान देकर भारतीय सैन्य क्षमता और अदम्य इच्छाशक्ति का परिचय दिया है। जनरल नरवाणे से जब पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर के संबंध में सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा कि संसद के प्रस्ताव के अनुसार पूरा जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और संसद जब कभी आदेश देगी, भारतीय सेना पीओके को भारत में शामिल करने के लिए उचित कार्रवाई करेगी। सेना अध्यक्ष के इस बयान के बाद पीओके को लेकर एक बार फिर चर्चा गरम हो गई है। इससे पहले नरेंद्र मोदी सरकार कई बार यह संकेत दे चुकी है कि वह पीओके को भारत में मिलाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद भी यह कहा था कि पीओके को लेकर आज भी उनके दिल में कसक है।

तो क्या पीओके को लेकर मोदी सरकार गुपचुप किसी योजना पर काम कर रही है? यह सवाल पहले भी कई बार उठ चुका है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर यह होगा कैसे? क्या सरकार के पास इस योजना के लिए कोई रोडमैप है? सरकार की क्या योजना है, यह हम नहीं जानते। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह ने बीते दिनों एक टीवी चैनल पर चर्चा के दौरान यह पूछे जाने पर कि पीओके को भारत में कैसे मिलाएंगे, उन्होंने कहा था, 'केंद्र सरकार का जो भी 'प्लान ऑफ एक्शन' या उसका समय है, उसे टीवी डिबेट के दौरान घोषित नहीं किया जा सकता।' अमित शाह ने कहा कि ये सब देश की सुरक्षा से जुड़े संवेदनशील मुद्दे हैं, जिन्हें ठीक उसी तरह से निबटा देना चाहिए, जैसे अनुच्छेद 370 के साथ किया गया। लेकिन इस संबंध में भारत क्या रूस से कुछ सीख ले सकता है?

**क्या रूस की तरह रुख अपनाएगा भारत?** : पिछले दिनों रूस की यात्रा के दौरान, काला सागर स्थित प्रायद्वीप क्रीमिया जाने का भी अवसर मिला। यह वही क्रीमिया है जो वर्ष 2014 से पहले यूक्रेन का हिस्सा था, लेकिन आज यह रूस प्रशासित प्रदेश है। लगभग छह वर्ष पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दृढ़ इच्छाशक्ति दिखाते हुए 'इतिहास की गलतियों' को 'सुधारा' और अपनी सैन्य शक्ति का इस्तेमाल करते हुए क्रीमिया को रूस का हिस्सा बना लिया। हालांकि दुनिया के बहुत से देशों, विशेषकर पश्चिमी देशों ने इस मुद्दे पर रूस का विरोध किया, रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए जो आज तक जारी हैं, लेकिन रूस अपने 'राष्ट्रीय हितों' से समझौता करने को तैयार नहीं और इस विरोध के सामने डट कर खड़ा है। हालांकि क्रीमिया से पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर करीब साढ़े पांच हजार किलोमीटर दूर है, लेकिन क्रीमिया पहुंचने पर बरबस ही पीओके का ध्यान आ जाता है। इसलिए नहीं कि क्रीमिया भी कश्मीर की तरह बेहद खूबसूरत है, बल्कि इसलिए कि क्रीमिया पहुंचने पर मन में बरबस ही यह सवाल उठा कि क्या कभी भारत भी पीओके को उसी तरह अपना हिस्सा बना पाएगा जैसे रूस ने क्रीमिया को बना लिया!

**वर्ष 1954 तक रूस का हिस्सा था क्रीमिया** : सरकार की रणनीति जो भी हो, पर भारत रूस के क्रीमिया प्रकरण से बहुत कुछ सीख सकता है, क्योंकि क्रीमिया और रूस की तुलना अगर आप पीओके और भारत से करेंगे तो दोनों में बहुत अंतर होने के बाद भी बहुत सी समानताएं हैं। क्रीमिया वर्ष 2014 से ही सुर्खियों में आया जब रूस ने यूक्रेन से छीन कर अपना हिस्सा बना लिया, लेकिन यह बहुत कम लोग ही जानते हैं कि वर्ष 1954 तक क्रीमिया रूस का ही हिस्सा था। 1954 में तत्कालीन सोवियत संघ के सर्वोच्च नेता निकिता ख्रुश्चेव ने क्रीमिया को यूक्रेनी-रूसी मैत्री और सहयोग के एक तोहफे के तौर पर इसे यूक्रेन को सौंप दिया था। अधिकांश रूसी मानते हैं कि ख्रुश्चेव ने यह बहुत बड़ी गलती की थी और 2014 में रूस ने 60 साल पुरानी यह भूल सुधार ली।

**नेहरू की एक भूल के कारण पाक के कब्जे में आया यह भूभाग** : पीओके भी तो भारत की भूल के कारण ही पाकिस्तान के कब्जे में है। वर्ष 1948 में जब भारत-पाकिस्तान का पहला युद्ध हुआ था, तब भारतीय सेना लगातार पाकिस्तानी सेना को खदेड़ रही थी। उस वक्त संयुक्त राष्ट्र ने भारत और पाकिस्तान को कश्मीर से अपनी सेना वापस बुला कर सीजफायर यानी युद्धविराम लागू करने का प्रस्ताव पास किया। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एक जनवरी 1949 को सीजफायर लागू कर दिया। लेकिन पाकिस्तान ने अपनी सेना वापस नहीं बुलाई। इसके फलस्वरूप आज तक करीब एक-तिहाई कश्मीर पाकिस्तान के कब्जे में है। उस वक्त पंडित नेहरू ने एकतरफा युद्धविराम की भूल न की होती तो आज पीओके नहीं होता, और पूरा कश्मीर भारत का हिस्सा होता।

**भारत कर सकता है भूल सुधार?** : क्या आज भारत रूस का अनुसरण करते हुए इस भूल को सुधार सकता है? क्यों नहीं। वर्ष 2014 में रूस ने जब क्रीमिया के विलय के समय अपनी सेना भेजी तो इसके पीछे तर्क दिया गया कि वहां रूसी मूल के लोग बहुतायत में हैं और उस वक्त यूक्रेन में जिस तरह की राजनीतिक उठा-पटक चल रही थी उसके बीच रूसी लोगों के हितों की रक्षा करना रूस की जिम्मेदारी है। गौरतलब है कि क्रीमिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या रूसियों की है। इसके अलावा वहां यूक्रेनी, तातार, आर्मेनियाई, पॉलिश और मोल्दावियाई भी हैं।

आज पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर अस्थिरता और उथल-पुथल के दौर से गुजर रहा है। पीओके के लोग विकास ना होने, लगातार बढ़ती महंगाई, शासकों द्वारा नजरअंदाज किए जाने से दुखी और परेशान हैं। भारत पीओके के लोगों को अपना नागरिक मानता है। अब तक जम्मू-कश्मीर की विधानसभा में पीओके के लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली 24 सीटें खाली रहती थीं। तो जिस तरह रूस ने अपने नागरिकों की सुरक्षा और उनके बेहतर जीवन के लिए क्रीमिया का विलय किया, उसी तरह क्या भारत की जिम्मेदारी नहीं बनती कि पीओके में रहने वाले 'अपने नागरिकों' को नारकीय जीवन से निकालने के लिए वह पाकिस्तान के कब्जे वाले इस हिस्से को भारत में शामिल कर ले?

## विश्व जनमत को साथ लाने की बड़ी चुनौती

हालांकि पीओके को भारत में शामिल करने के संदर्भ में हमें समझना होगा कि यूक्रेन पाकिस्तान नहीं, और भारत को भी पीओके में उस तरह की 'एडवांटेज' हासिल नहीं है जैसी रूस को क्रीमिया में हासिल थी। इसलिए रणनीतिक तौर पर भारत क्या करेगा यह एक अलग चुनौती है, लेकिन इस चुनौती को पार करने के बाद भारत को वैसे ही कदम उठाने के लिए तैयार रहना होगा, जैसे कदम वर्ष 2014 के बाद से रूस उठा रहा है और उन मुश्किलों के लिए सतर्क रहना होगा जो मुश्किलें रूस के सामने आईं।

इस मामले में सबसे बड़ी चुनौती अंतरराष्ट्रीय दबावों का सामना करते हुए विश्व जनमत को अपने साथ लाने की होगी। अभी तो भारत ने अपने प्रशासन वाले जम्मू-कश्मीर में ही धारा 370 को हटाया था, तभी पाकिस्तान ने दुनिया भर में जिस तरह से हंगामा किया, दुष्प्रचार किया, उससे हमें यह आभास मिल गया है कि पीओके को लेकर जब भी भारत कोई पहल करेगा तो पाकिस्तान किस तरह प्रतिक्रिया जताएगा। हालांकि इस मसले पर भारत की सफल कूटनीति के कारण अब तक पाकिस्तान को सफलता नहीं मिली है, लेकिन कई मंचों पर भारत को कई तरह के दबावों का सामना अवश्य करना पड़ा है। रूस में क्रीमिया के विलय के बाद रूस को भी कई मंचों पर विरोध का सामना करना पड़ा, उसे जी-8 के समूह से बाहर कर दिया गया। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने रूस पर कई तरह की पाबंदियां लगा दीं। रूस के बैंकों की अंतरराष्ट्रीय कैपिटल मार्केट तक पहुंच पर भी रोक इन प्रतिबंधों में शामिल है। भारत सहित रूस से हथियार खरीदने वाले देशों पर भी अमेरिका ने दबाव बनाया। लेकिन रूस इन दबावों के आगे डट कर खड़ा रहा। क्रीमिया रिपब्लिक के अध्यक्ष सरगेई अक्स्योनोव मानते हैं कि क्रीमिया को इन प्रतिबंधों के कारण बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन वह यह भी कहते हैं कि हम अगले 50 वर्षों तक इन प्रतिबंधों का सामना करने के लिए तैयार हैं। अडिगता से खड़े रहने और इन संघर्षों के लिए रूस की तैयारियों का फायदा उसे धीरे-धीरे मिलता दिख रहा है। जी-7 देशों के समूह में शामिल कई देश अब कहने लगे हैं कि रूस के साथ सहयोग पर फिर से विचार होना चाहिए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जब आगामी जी-7 शिखर सम्मेलन में रूस को आमंत्रित किए जाने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, 'मैं नहीं जानता। लेकिन यह निश्चित तौर पर संभव है।'

क्रीमिया का विलय करने के बाद रूस ने क्रीमिया में जनमत संग्रह कराया जिसमें 97 प्रतिशत लोगों ने रूस के साथ रहने के पक्ष में मतदान किया, लेकिन रूस इससे संतुष्ट होकर बैठा नहीं रहा, बल्कि उसने क्रीमिया के लोगों की जिंदगी में बदलाव लाने के लिए वहां तेजी से विकास के काम शुरू कर दिए। क्रीमिया के सबसे प्रमुख शहर सिम्फरोपोल में वर्ष 2014 के बाद शानदार एयरपोर्ट बनाया गया और आज भी शहर में जगह-जगह सड़कों को बेहतर बनाने और ऐतिहासिक इमारतों के संरक्षण व नया निर्माण होते हुए देखा जा सकता है। वर्ष 2014 में जिस क्रीमिया का सालाना बजट 18 बिलियन रूबल था उसे बढ़ा कर आज 54 बिलियन रूबल कर दिया गया है। क्रीमिया के लोगों की औसत आय आज 29 हजार रूबल तक हो गई है, पर अभी भी वहां 17 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं। रूस की सरकार ने लक्ष्य तय किया है कि वर्ष 2024 तक गरीबी की दर को आठ प्रतिशत तक लाया जाए।

रूस जिस तेजी से क्रीमिया में आर्थिक और सामाजिक बदलावों के लिए काम कर रहा है, उसी का परिमाण है कि आज क्रीमिया के लोगों में यूक्रेन से अलग होने का कोई पछतावा नहीं दिखता, बल्कि उन्हें रूस के साथ अपना भविष्य ज्यादा सुरक्षित लग रहा है। भारत को भी पीओके का विलय करना है तो सिर्फ विलय तक नहीं, बल्कि रूस की तरह उसके बाद के बड़े बदलावों के लिए भी तैयारी करनी होगी। क्या भारत इसके लिए तैयार है?

खरी-खरी

## टूटती सांसों के बीच बच्चे का साक्षात्कार

रामस्वरूप दीक्षित

एक बड़े सरकारी अस्पताल में, जिसमें सैकड़ा भर बच्चे दम तोड़ चुके हैं, वहां एक चैनल का रिपोर्टर जाता है और मौत के सम्मुख पहुंचने वाले एक बच्चे से मुलाकात करता है।

रिपोर्टर : आप मौत के पास जा रहे हैं! कैसा महसूस कर रहे हैं?

बच्चा : बहुत अच्छा लग रहा है। यहां तो कोई साथी बचा नहीं। तो जहां सब साथी गए हैं, वहां जाने की खुशी है। सुना है ऊपर बहुत अच्छी व्यवस्था है। दोनों टाइम रोटी मिलेगी। सब्जी भी। वहां कोई बीमार भी नहीं होता, तो बीमारी से भी छुटकारा मिलेगा। यहां तो मेरे कारण सबको कष्ट था। मरने से अस्पताल वाले भी खुश होंगे कि इलाज के झंझट से छुटकारा मिला। आपके चैनल की टीआरपी बढ़ाने के काम तो आऊंगा ही। अम्मा कहा करती है कि हमें दूसरों के काम आना चाहिए।

रिपोर्टर : आपने इस काम के लिए सरकारी अस्पताल ही क्यों चुना?

बच्चा : जो काम जहां होता है, वहीं तो किया जाएगा। यहां मौत के मुंह में जाने में समय और पैसा नहीं लगता। निजी अस्पताल में तो मरने का पैसा भी लगता है ना!

रिपोर्टर : तुम्हारे मां-बाप दुखी होंगे?

बच्चा : नहीं, जब मैं भूख लगने पर रोटी मांगता था तो अम्मा-बाबा कहा करते थे- हे भगवान ये होते ही मर क्यों न गया! वे खुश होंगे कि रोज-रोज रोटी के झंझट से छुटकारा मिला। मेरे हिस्से की रोटी मेरे दोनों छोटे भाइयों को मिल जाया करेगी।

रिपोर्टर : क्या डॉक्टर ने तुम्हारा इलाज नहीं किया?

बच्चा : किया। उनके इलाज से ही तो मुझमें मौत के मुंह तक जाने की ताकत आई है।

बच्चा अचेत होने लगा। रिपोर्टर 'लाइव कमेन्ट्री' करने लगा- आपने जन्म लेते हुए बच्चा देखा होगा, लेकिन मौत के मुंह में जाते हुए नहीं।

रिपोर्टर उत्साह से कहता है- ये देखिए, आपने अभी-अभी बच्चे के प्राण निकलते लाइव देखा है। इस अस्पताल में मौत के मुंह में जाने वाले बच्चों की संख्या एक सौ पांच का आंकड़ा पर कर चुकी है।

स्टूडियो में एंकर मुस्कुराते हुए कहती है- तो आपने देखा कि कोई बच्चा कैसे मौत के मुंह में जाता है। ये लाइव टेलीकास्ट करने वाला हमारा चैनल देश का पहला चैनल है।

## ट्वीट-ट्वीट

लगातार रन बना रहे मयंक अग्रवाल को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआइ ने बी ग्रेड में रखा है और लगातार फ्लॉप हो रहे ऋषभ पंत को ए ग्रेड में। तीनों फॉर्मेट का फ्लॉप खिलाड़ी ज्यादा अहम है एक फॉर्मेट के शानदार खिलाड़ी से?

सुशांत सिन्हा@SushantBSinha

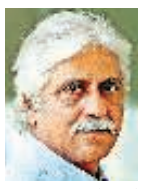

बीसीसीआइ की कांट्रैक्ट लिस्ट से महेंद्र सिंह धौनी के बाहर होने की खबर को कोई कैसे देखे? क्या बीसीसीआइ उन्हें स्पष्ट संकेत दे रही है या दोनों के बीच कोई आपसी समझ कायम हो गई है? याद रखें कि धौनी ने अभी संन्यास नहीं लिया है और वह आइपीएल खेलेंगे। यह भी कि वनडे विश्वकप के बाद से वह मैदान में नहीं उतरे हैं।

क्रिकेटवाला@cricketwallah

यह दोहरापन क्यों? भारत तेरे टुकड़े होंगे-कोई बात नहीं, लेकिन महाराष्ट्र सरकार को मुंबई के एक प्रोफेसर का राहुल गांधी पर दिया बयान पसंद नहीं आया तो उसे छुट्टी पर भेज दिया और कार्रवाई भी करेंगे। अभिव्यक्ति की आजादी का नारा लगाने वाले सब क्रांतिकारी अब चुप क्यों हैं। उन्हें सांप क्यों सूंघ गया है।

मेजर सुरेंद्र पूनिया@MajorPoonia

इंदिरा गांधी करीम लाला से मिलीं और करीम लाला इंदिरा गांधी से मिला, ये दोनों अलग-अलग बातें हैं। और दोनों बातों का मतलब भी अलग है। बात का बतंगड़ बनाना ठीक नहीं।

आचार्य प्रमोद@AcharyaPramodk

## जागरण जनमत

कल का परिणाम

**क्या देविंदर सिंह की गिरफ्तारी को सांप्रदायिक रंग देने से आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई कमजोर होगी?**

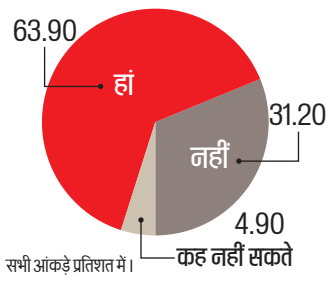


सभी आंकड़े प्रतिशत में।

**आज का सवाल**

क्या ईरान और अमेरिका के बीच शांति स्थापना के लिए भारत को पहल करनी चाहिए?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

## जनपथ

देविंदर क्यूं बन गया तू ऐसा गद्दार,
देशभक्ति को छोड़कर आतंकी का यार।
आतंकी का यार बिका पैसों की खातिर,
बना सिपाही देश लूटने निकला शातिर।
गुरु की पगड़ी धारि पाप बैठाया अंदर,
कोसें गुरु गोविंद स्वर्ग से अब देविंदर!

– ओमप्रकाश तिवारी

झारखंड डायरी

# स्थानीय नीति पर नए बखेड़े की आशंका

प्रदीप शुक्ला
स्थानीय संपादक, झारखंड

खरमास खत्म हो चुका है। मकर संक्रांति भी गुजर गई, लेकिन अभी हेमंत सोरेन के नेतृत्व की गठबंधन सरकार की तस्वीर साफ नहीं हुई है। गठबंधन दलों में मंत्रिपद और विभागों के बंटवारे को लेकर रस्साकसी चल रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली के कई चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन झामुमो-कांग्रेस किसी सर्वमान्य फार्मूले पर नहीं पहुंच सके हैं, ऊपर से स्थानीय नीति का जिन्न और बाहर आ गया है। झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन ने 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति तय करने की बात कहकर नई सरकार के लिए एक संकट खड़ा कर दिया है। फिलहाल मुख्यमंत्री ने टिप्पणी नहीं की है, पर जिस तरह से भाजपा सहित गठबंधन सहयोगी कांग्रेस में इस पर चर्चा शुरू हुई है उससे भविष्य में यह मुद्दा गठबंधन दलों के ही गले की फांस बन सकता है।

**मंत्रिमंडल में पेच** : 29 दिसंबर को हेमंत सोरेन ने झामुमो- कांग्रेस- राजद गठबंधन सरकार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेते ही घोषणा की थी कि खरमास खत्म होते ही मंत्रिमंडल का पूर्ण गठन कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री के साथ उस दिन कांग्रेस के दो और राजद के एक मंत्री ने भी शपथ ली थी। करीब तीन सप्ताह खत्म होने वाले हैं, लेकिन अभी तक कांग्रेस और झामुमो में पूर्ण सहमति नहीं बन पाई है। दरअसल झामुमो कांग्रेस को चार से ज्यादा मंत्रिपद नहीं देना चाहती है और कांग्रेस पांच से कम पर मानने को तैयार नहीं है। इसके अलावा बोर्ड और निगमों पर भी कांग्रेस की नजर है। कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा विधायकों को सरकार में शामिल करवाना चाहती है। वह इतने पर भी संतुष्ट होती नहीं दिख रही है। पद के साथ उसे मलाई वाले विभाग भी चाहिए और यही सब मंत्रिमंडल गठन में बाधक बना हुआ है।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद ही कांग्रेस आलाकमान से सीधे संपर्क में हैं। वह लगातार दिल्ली आ-जा रहे हैं। पूर्ण मंत्रिमंडल का गठन न होने से अब गठबंधन में भी बेचैनी महसूस की जा रही है। जनता में भी गलत संदेश जा रहा है। खैर, मुख्यमंत्री यह कह रहे हैं कि 19 जनवरी तक सबकुछ स्पष्ट हो जाएगा। आशंका यह भी जताई जा रही है कि मंत्रिपद और विभागों के बंटवारे के बाद झारखंड में भी महाराष्ट्र जैसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। महाराष्ट्र में मंत्रिपद और विभागों को लेकर गठबंधन के तीनों दलों- शिवसेना, कांग्रेस और राकांपा में विरोध के स्वर उठ चुके हैं। झारखंड में गठबंधन सरकारों के इतिहास से तो सभी भलीभांति वाकिफ हैं ही।

शिबू सोरेन। फाइल फोटो।

**बाबूलाल की घरवापसी**: पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड विकास मोर्चा प्रमुख बाबूलाल मरांडी की भाजपा में वापसी तय हो चुकी है। करीब एक सप्ताह विदेश में बिताकर वह लौट आए हैं। भाजपा ने भी खरमास के बाद ही नेता प्रतिपक्ष चुनने का एलान किया था। रघुवर दास के हारने, आदिवासियों में भाजपा के प्रति नाराजगी सहित कई अन्य ऐसे कारण हैं जिनके चलते भाजपा और बाबूलाल मरांडी एक-दूसरे के करीब आने को मजबूर हुए हैं। पूरी झाविमो, भाजपा में विलय को तैयार है, लेकिन पार्टी के विधायक प्रदीप यादव और बंधु तिर्की के सुर इससे इतर हैं। विलय में कोई कानूनी अड़चन न आए, इन्हें दूर करने में ही बाबूलाल मरांडी लगे हुए हैं। बाबूलाल मरांडी के आने से जहां झारखंड में भाजपा को एक मजबूत आदिवासी चेहरा मिल जाएगा, वहीं उन्हें सही ठिकाना। भाजपा से अलग होने के बाद उनका कद बढ़ा तो कतई नहीं। झाविमो की ताकत भी लगातार कम होती जा रही है। ऐसे में घरवापसी उन्हें नई ताकत दे सकती है। वह लगातार कह रहे हैं कि उन्हें किसी पद की चाहत नहीं है। इससे यह भी संकेत मिल रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष अथवा प्रदेश अध्यक्ष से इतर उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर कोई जिम्मेदारी मिल सकती है। आदिवासियों के बीच उनकी काफी स्वीकार्यता है और भाजपा इसे देश भर में भुना सकती है।

**स्थानीय नीति का निकला जिन्न**: राज्य बनने के बाद से ही स्थानीय नीति को लेकर राज्य में कई बार बखेड़ा हो चुका है। रघुवर दास सरकार ने वर्ष 2014 में पहली बार स्थानीय नीति को परिभाषित किया। इसमें 1985 से झारखंड में रहने वालों को स्थानीय माना गया, लेकिन अब झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन ने 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बनाने की बात कहकर नया विवाद शुरू कर दिया है। झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन फिलहाल इस पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन यह मुद्दा राज्य की राजनीति में बड़ी हलचल पैदा करेगा।

झामुमो और कांग्रेस यह कहते रहे हैं कि रघुवर दास की स्थानीय नीति से राज्य के लोगों के अवसर कम हुए हैं और वह इसमें बदलाव करेंगे। बदलाव क्या होंगे? क्या 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बनेगी? इस पर अभी सब मौन हैं। झामुमो सुप्रीमो के बयान के बाद कांग्रेस में हलचल है। स्थानीय बनाम बाहरी में उन्हें बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इससे राज्य में नए तरीके की समस्याएं भी खड़ी हो सकती हैं। फिलहाल कांग्रेस नेता कह रहे हैं मंत्रिमंडल के गठन के बाद सहयोगी दल न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाकर उस पर काम करेंगे। यह देखना दिलचस्प होगा, झामुमो का क्या रुख रहता है। हेमंत सरकार पार्टी सुप्रीमो के साथ रहती है अथवा कोई बीच का रास्ता निकालती है।

समस्या

# चिंता का विषय है बढ़ता मनोरोग

नरपतदान चारण
स्वतंत्र टिप्पणीकार

**शारीरिक बीमारी की तरह भारत में मानसिक बीमारी को गंभीरता से नहीं लिया जाता है। बदलते परिवेश में यह बीमारी बड़ी आबादी को चपेट में ले रही है जिसे हमें समझना होगा**

देश भर में मनोरोगियों की संख्या में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। प्रसिद्ध विज्ञान शोध पत्रिका 'द लांसेट' की एक हालिया रिपोर्ट का विश्लेषण यह बताता है कि समूचे देश में मनोरोगियों की तादाद में वृद्धि हुई है। वर्ष 2017 तक देश में लगभग 19.7 करोड़ व्यक्ति (जिनमें बच्चे एवं किशोर भी शामिल हैं) गंभीर मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से प्रभावित हैं। रिपोर्ट के अनुसार बीते 27 वर्षों में मनोरोगियों की संख्या दोगुनी हो गई है। मुख्य रूप से डिप्रेशन, एंग्जाइटी और सिजोफ्रेनिया से लोग ज्यादा प्रभावित हैं। डिप्रेशन पीड़ितों में बुजुर्गों और महिलाओं की संख्या अधिक है। डिप्रेशन की वजह से होने वाली आत्महत्याओं में भी वृद्धि हुई है।

देश में दक्षिण भारतीय राज्यों खासकर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लोग इससे सर्वाधिक प्रभावित हैं। गौरतलब है कि मानसिक बीमारी किसी व्यक्ति के महसूस करने, सोचने एवं काम करने के तरीकों को प्रभावित करती है।

यह रोग व्यक्ति के मनोयोग, स्वभाव, ध्यान और संयोजन एवं बातचीत करने की क्षमता में समस्या पैदा करता है। अंततः व्यक्ति असामान्य व्यवहार का शिकार हो जाता है। उसे दैनिक जीवन के कार्यकलापों के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के लिए कई कारक उत्तरदायी हैं। जैसे परिवेश संबंधी तनाव (जैसे चिंता, अकेलापन, साथियों का दबाव आदि), आत्म-सम्मान में कमी, परिवार में मृत्यु या तलाक, दुर्घटना, हिंसा एवं दुष्कर्म आदि से मनोवैज्ञानिक आघात होना, आनुवंशिक असामान्यताएं, मस्तिष्क की चोट/ दोष, अल्कोहल एवं ड्रग्स जैसे मादक पदार्थों का सेवन और संक्रमण के कारण मस्तिष्क की क्षति आदि।

विशेषज्ञों का इस संबंध में कहना है कि जब एक व्यक्ति ठीक से सोच नहीं पाता, उसका अपनी भावनाओं और व्यवहार पर काबू नहीं रहता, तो ऐसी हालत को मानसिक रोग कहते हैं। मानसिक रोगी आसानी से दूसरों को समझ नहीं पाता और उसे रोजमर्रा के काम ठीक से करने में मुश्किल होती है। मानसिक रोग के लक्षण, हर व्यक्ति में अलग-अलग हो सकते हैं। ये इस बात पर निर्भर करते हैं कि उसके हालात कैसे हैं और उसे कौन-सी मानसिक बीमारी है। कुछ लोगों में इसके लक्षण लंबे समय तक रहते हैं और साफ नजर आते हैं, जबकि कुछ लोगों में शायद थोड़े समय के लिए हों और साफ नजर न आएं। मानसिक रोग किसी को भी हो सकता है, फिर चाहे वह आदमी हो या औरत, जवान हो या बुजुर्ग। हालांकि किसी को मानसिक रोग होने का कारण यह नहीं कि उसमें कोई दोष है। मानसिक रोग पीड़ित व्यक्ति समाज में एक कमजोर वर्ग का गठन करता है तथा जिसे हमारे समाज में भेदभाव की तरह जाना जाता है। जो लोग मानसिक रोग के शिकार होते हैं, उसका असर उनके नजदीकी लोगों पर भी पड़ता है।

देखा गया है कि हर चौथे इंसान को कभी-न-कभी मानसिक रोग होता है। दुनिया भर में इस रोग की सबसे बड़ी वजह निराशा है। बायपोलर डिसऑर्डर या सिजोफ्रेनिया बहुत गंभीर और खतरनाक मानसिक बीमारियां हैं। हालांकि दुखद बात यह है कि इतनी भारी तादाद में लोग मानसिक रोग की गिरफ्त में आ रहे हैं, फिर भी लोग इसे छिपाए रखते हैं या इसे नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि अक्सर इस तरह की बीमारी के शिकार लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता।

बहुत-से लोगों ने जब अपनी हालत के बारे में अच्छी तरह जाना और फिर डॉक्टरों की सलाह के मुताबिक इलाज करवाया, तो उन्हें अपनी बीमारी से लड़ने में काफी मदद मिली। परिवार को मानसिक रोग से पीड़ित व्यक्तियों और रिश्तेदारों की देखभाल और उपचार के लिए वित्तीय, शारीरिक, भावनात्मक, मानसिक और सामाजिक बोझ को सहन करना पड़ता है। इन तमाम दुश्वारियों को देखते हुए, मानसिक रोग से पीड़ित व्यक्तियों को अन्य स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित लोगों की तरह माना जाना चाहिए और उनके आसपास के वातावरण, समुचित उपचार तथा समाज में उनकी पूर्ण भागीदारी के अनुकूल बनाया जाना चाहिए। इस तथ्य को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि अगर मानसिक रोगी अच्छी तरह अपना इलाज करवाए, तो वह ठीक हो सकता है। लेकिन दुर्भाग्यवश 80 से 90 प्रतिशत मानसिक रोगी कई कारणों इलाज नहीं करवा रहे हैं और अंधविश्वासों में जकड़े हुए हैं। इसकी वजह से ना केवल उनकी बड़ी रकम खर्च होती है, बल्कि काफी सारा वक्त भी बर्बाद हो जाता है। इन सभी कारणों से धीरे-धीरे पीड़ित व्यक्ति की मानसिक दशा और भी बिगड़ती जाती है।

प्रतीकात्मक फोटो।

**सही उपचार से मुमकिन बीमारी का इलाज** : मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति समय पर उपचार ले तो उसका पूर्ण रूप से स्वस्थ होना बिल्कुल संभव है। मानसिक रोगों के कारण होने वाली शारीरिक अशक्तता को भी काफी हद तक रोका जा सकता है, जिससे पीड़ित व्यक्ति समाज और परिवार में अपने दायित्व का समग्रता से निर्वहन कर सकता है। समाज और परिवार को भी मानसिक रोगी के प्रति संवेदना और सहानुभूति पूर्ण व्यवहार करना चाहिए। वह एक अच्छी और खुशहाल जिंदगी जी सकता है। आमतौर पर एक गलतफहमी यह भी होती है कि कोई मानसिक स्वास्थ्य विकार न होने का मतलब है कि व्यक्ति मानसिक और भावनात्मक रूप से स्वस्थ है।

विशेषज्ञों का कहना है कि केवल अवसाद, व्यग्रता या अन्य विकार नहीं होने पर भी जरूरी नहीं है कि व्यक्ति मानसिक या भावनात्मक रूप से स्वस्थ है, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य को कई तत्व प्रभावित करते हैं और इन सभी तत्वों को जान-समझकर ही इस बीमारी से छुटकारा पाया जा सकता है।

**17500** क्विंटल रक्त चंदन लकड़ी भारत को वापस करेगा नेपाल। नेपाल मंत्रिपरिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। दरअसल, तस्कर रक्त चंदन कर्नाटक के जंगलों से नेपाल के रास्ते चीन में पहुंचाते रहे हैं। इसकी तस्करी रोकने के लिए भारत सरकार ने नेपाल सरकार को पत्र लिखा था।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शुक्रवार 17 जनवरी 2020

बंगाल

# तेजाबी हमलों पर लगे अंकुश

महानगर से सटे उत्तर 24 परगना जिले के बैरकपुर इलाके में तीन महिलाओं के ऊपर तेजाब फेंके जाने की ताजा घटना ने एक बार फिर सिहरन पैदा कर दी है। यह उन महिलाओं का सौभाग्य था कि उन पर फेंका गया तेजाब म्यूरेटिक एसिड था जिसकी वजह से कोई विशेष क्षति नहीं हुई। पर उन तीनों के साथ ही पूरा इलाका दहशत की चपेट में है। बैरकपुर के बीजपुर थाना क्षेत्र के कांचरापाड़ा के पाल्लादह अंचल में खरीदे गए मकान पर कब्जा जमाए बैठी महिला से तीनों महिलाएं मकान खाली कराने गई थीं। उस महिला ने ही तेजाब फेंक दिया। इस घटना ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। इसकी एक बड़ी वजह गुजरे शुक्रवार को रिलीज हुई दीपिका पादुकोण की फिल्म 'छपाक' भी है।

छपाक तेजाब पीड़ित महिलाओं की कहानी है। इस फिल्म के रिलीज होने के साथ ही एसिड पीड़ितों की व्यथा को लेकर देश भर में बहस चल रही है। पश्चिम बंगाल में तीनों महिलाओं पर तेजाब फेंके जाने की घटना पहली घटना नहीं है। ऐसी घटनाओं की बेशुमार कहानियां हैं और तेजाब के जख्मों की टीस भुगत रहीं अनगिनत महिलाएं हैं। कड़े मानकों के बावजूद खुलेआम हो रही तेजाब की बिक्री बेहद चिंताजनक है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने अभी ताजा आंकड़ा जारी किया जिसमें एक वर्ष में देश भर में एसिड के हमले में 240 लोगों का चेहरा बदरंग हो गया। इस हमले में कुल 57 फीसद महिलाएं शिकार हुईं। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक एसिड हमले के सर्वाधिक मामले पश्चिम बंगाल में दर्ज हुए जिनमें 53 लोगों को इसका शिकार बनाया गया। इस वर्ष तेजाबी हमले में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर चला गया है, जबकि पिछली बार वह पहले स्थान पर था। पश्चिम बंगाल दूसरे स्थान से उठकर पहले स्थान पर आ गया है। ये आंकड़े यह बताने के लिए काफी हैं कि तेजाबी हमले पर रोक लगाने की दिशा में पश्चिम बंगाल में कारगर कदम नहीं उठाए गए। छपाक से किसी चेहरे पर तेजाब उड़ेल कर ताजिंदगी जख्म देने वाले क्रूर अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए कोई ऐसी पहल नहीं हो सकी कि उनमें दहशत हो। ताकि कोई और फिर ऐसा कदम न उठा सके। बैरकपुर की घटना में तो महिला ने ही तीनों महिलाओं पर तेजाब फेंका है। इस घटना के बाद एक युवा अधिवक्ता ने तो टिप्पणी की कि बहुत कुछ गलत करना फिल्में भी सिखाती हैं। उनकी दलील थी कि छपाक में भी तेजाब महिला ही फेंकती है। बहरहाल इन दलीलों से ऊपर सोचने की बात यह है कि ऐसे अपराध पर कैसे अंकुश लगे।

**छपाक से किसी चेहरे पर तेजाब उड़ेल कर ताजिंदगी जख्म देने वाले क्रूर अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए कोई ऐसी पहल नहीं हो सकी कि उनमें दहशत हो**

सरकार को इस दिशा में ठोस कदम उठाना चाहिए। कारण यह कि तेजाब के हमले से पीड़ितों की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। पीड़ितों को मात्र आर्थिक सहायता देकर उनके जख्मों पर मरहम नहीं लगाया जा सकता। सरकार को तेजाब की बिक्री नियंत्रित करने के लिए कड़े कदम उठाने होंगे। सरकार को स्वयं भी समय-समय पर इसके लिए जिलों से जानकारी लेनी होगी।

पंजाब

# सभ्याचार पर प्रहार

श्री दरबार साहिब के रास्ते में हेरिटेज स्ट्रीट में लगे विरासती बुतों को गर्म ख्याली संगठनों के सदस्यों ने बुधवार तड़के तोड़ने का प्रयास किया। आरोपितों ने लोहे के बुतों पर हथौड़ों से कई वार किए, लेकिन वह उन्हें ढहा नहीं पाए। पुलिस के घटनास्थल पर पहुंचने तक गर्म ख्याली बुतों के नीचे बने आधार (चबूतरे) को तोड़ चुके थे। पुलिस के मुताबिक जब उसने आरोपितों को रोकने का प्रयास किया तो कुछ युवकों ने पुलिस दल पर ही हमला कर मुलाजिमों को खदेड़ दिया। कोतवाली थाने की पुलिस ने आठ आरोपितों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ पुलिस पार्टी पर हमला करने और सरकारी सपंत्ति को तोड़ने के आरोप में केस दर्ज किया है। दरअसल गर्म ख्याली संगठनों हिम्मत-ए-खालसा, सतकार कमेटी एवं जत्था सिर लत्थ खालसा के सदस्य इन बुतों को हटाने की मांग उठाते रहे हैं। उनकी मांग थी कि नाच-गाना पेश करते कलाकारों की प्रतिमाओं के स्थान पर सिख योद्धाओं के बुत लगाए जाएं। जो सिख विरासत व इतिहास को प्रदर्शित करते हों।

अमृतसर स्थित श्री दरबार साहिब के मार्ग में निर्मित हेरिटेज स्ट्रीट में जो विरासती बुत लगाए गए हैं, उस पर शायद ही किसी पंजाबी को गर्व न हो। सभी को इस पर गर्व होना भी चाहिए, क्योंकि कभी इस जगह पर तंग गलियां और भीड़-भाड़ ही होती थी, लेकिन आज यहां देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालु पंजाब की समृद्ध विरासत देख फूले नहीं समाते। यह हैरानी की बात है कि जिन बुतों से और जिस गलियारे से पंजाब के सभ्याचार और संस्कृति की झलक मिलती है, उस पर भी विरोध जताया जाए और तोड़फोड़ की जाए। यदि इन बुतों के साथ सेल्फी ली जाती है और इनके सामने गिद्दा अथवा भंगड़ा जैसे नृत्य किए भी जाते हैं तो इसमें आपत्तिजनक क्या है? इसमें कहां फूहड़ता है? इससे किस तरह पंजाबी सभ्याचार को क्षति पहुंच रही है? इसके विपरीत यह जगह तो अब धार्मिक पर्यटन के लिए चर्चा में है। यहां आने वाले पर्यटक इस गलियारे और इन बुतों को देखकर पंजाब की सभ्यता और संस्कृति से परिचित और प्रभावित होते हैं। इससे तो प्रदेश के सभ्याचार का यश ही बढ़ेगा। जिन बुतों से सभ्याचार और संस्कृति की झलक मिलती है, उन्हें तोड़ने की कोशिश संकुचित मानसिकता का ही परिचायक है और इसका कड़ा प्रतिकार किया जाना चाहिए। चंद लोगों ने जो कृत्य किया उसे अराजक ही कहा जाएगा। यदि यहां हो रही कोई गतिविधि किसी को आपत्तिजनक लग रही थी तो उचित मंच पर इसका विरोध जताया जाना चाहिए था।

प्रतीकात्मक फोटो।

**जिन बुतों से पंजाब के सभ्याचार और संस्कृति की झलक मिलती है, उन्हें तोड़ने की कोशिश संकुचित मानसिकता का ही परिचायक है जिसका प्रतिकार होना चाहिए**

अंधविरोध में सभ्याचार के प्रतीकों पर प्रहार की अनुमति किसी को नहीं दी जा सकती। कानून और संपत्ति तोड़कर विरोध करने का यह चलन ही अस्वीकार्य है। पुलिस और प्रशासन को ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। अन्यथा आज हेरिटेज स्ट्रीट में तोड़फोड़ की गई है, कल किसी और ऐतिहासिक अथवा धार्मिक प्रतीक को क्षति पहुंचाने की कोशिश की जा सकती है। यह सुनिश्चित किया ही जाना चाहिए कि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, क्योंकि इससे सिर्फ और सिर्फ प्रदेश की समृद्ध संस्कृति को आघात ही पहुंचेगा।

बिहार

# मानव शृंखला से जागरूकता

सियासी गर्माहट के बीच राज्य सरकार का ध्यान अभी जल-जीवन-हरियाली को लेकर 19 जनवरी को बनने वाली मानव शृंखला पर है। सरकार से लेकर पूरा प्रशासनिक महकमा इस अभियान की तैयारी में लगा है। मुख्यमंत्री राज्य का दौरा कर लोगों को जागरूक करने का अभियान पूरा कर चुके हैं। अब जिला और प्रखंड स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम चल रहा है। जिलाधिकारी से लेकर तमाम अधिकारी रात-दिन मानव शृंखला को सफल बनाने में लगे हुए हैं। रंगोली बनाने से लेकर तरह-तरह के आयोजनों से लोगों को इसकी महत्ता बताने के साथ ही इसमें शामिल होने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। कार्यक्रम में 11 अवयवों को शामिल किया गया है। कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। अगले तीन वर्षों में इस पर 24,500 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। शहरीकरण और विकास की शर्त पर जिस तरह से प्रकृति का दोहन किया जा रहा है, उससे भविष्य में जीवन पर खतरा उत्पन्न हो सकता है। इस लिहाज से इस अभियान की सार्थकता बढ़ जाती है।

प्रतीकात्मक फोटो।

जल-जीवन -हरियाली पर बनने वाली मानव शृंखला लोगों को भविष्य के प्रति सचेत करेगी। जीवन के लिए जल और हरियाली के महत्व को देखते हुए इस अभियान को महज एक दिन के दायरे में बांधना उचित नहीं होगा। इस पर लगातार नजर रखने की जरूरत है। अतिक्रमण और प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन के कारण जल स्रोतों पर संकट सामने दिख रहा है। ताल-तलैया या तो सूख गए या समय के साथ लापता हो गए। कई नदियां पानी की कमी के कारण मृतप्राय हो चुकी हैं और वन क्षेत्र सिमटते जा रहे हैं। विकास के क्रम में हजारों पेड़ काट दिए गए। बढ़ती आबादी का बोझ उठाने के लिए रोज बन रहीं बहुमंजिला इमारतों की निर्माण सामग्री जमीन को कंक्रीट में बदलती जा रही हैं। इससे कई तरह की समस्याएं पैदा हो रही हैं। जलस्तर लगातार नीचे जा रहा है। पटना में पिछले साल आई बाढ़ से लोगों को काफी परेशानी हुई।

कोसी-सीमांचल समेत राज्य की बड़ी आबादी बाढ़ और सुखाड़ की समस्या से हर साल दो-चार होती है। समाधान हमारी परंपराओं में छिपा है। जल और हरियाली हमारी संस्कृति का अहम हिस्सा रही है। इससे छेड़छाड़ का परिणाम हम सब देख रहे हैं। नई पीढ़ी को बेहतर भविष्य देने के लिए जागरूकता जरूरी है। सरकार इसे अभियान के रूप में लेकर सामने आई है। कई योजनाएं भी इसके साथ चल रहीं हैं। जागरूकता के लिए मानव शृंखला बनाई जाएगी। लेकिन अभियान का दूरगामी प्रभाव रह सके, इसके लिए लोगों को भी अपने नागरिक होने का कर्तव्य पूरा करना होगा।

हिमाचल प्रदेश

# शिक्षा और स्वास्थ्य की करनी होगी चिंता

शिक्षा और स्वस्थ समाज से ही सशक्त राष्ट्र की परिकल्पना साकार होती है। इसके लिए सरकार को इस तरह की व्यवस्थाएं बनाई जानी चाहिए कि कहीं पर किसी तरह की बाधा न उत्पन्न हो। अधिकांश राज्यों में पिछले कुछ दशक से देखने में आ रहा है कि सरकार सभी को शिक्षा मुहैया कराने के मामले में आंकड़ों में भले ही अधिक से अधिक बच्चों को स्कूल तक लाने में कामयाब हुई है, लेकिन इसका एक दूसरा और महत्वपूर्ण पहलू यह भी उभर कर सामने आया है कि शिक्षा की गुणवत्ता में बढ़ोतरी उस लिहाज से नहीं हो पा रही है, जितनी होनी चाहिए। यही दशा स्वास्थ्य सेवाओं में भी है। दूरदराज ग्रामीण इलाकों तक देश के कई राज्यों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं नहीं पहुंच पाई हैं जिन्हें दूर करने इन राज्यों के लिए बड़ी चुनौती है। शिक्षा और बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने में हिमाचल प्रदेश वैसे तो अव्वल राज्यों की श्रेणी में है। हकीकत यह है कि प्रदेश के कई शिक्षण संस्थानों में अनेक खामियां हैं। कहीं अध्यापकों के पद रिक्त हैं तो कई जगह अन्य स्टाफ की कमी है। कई स्कूलों के भवन भी संतोषजनक नहीं हैं।

**शिक्षकों की कमी दूर करने के प्रयास में तेजी लाने की आवश्यकता है। खाली पदों का डाटा तैयार होने से विद्यालयों के रिक्त पदों को भरना आसान होगा**

यह बात सही है कि सरकार सभी को शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए गंभीर है, लेकिन अभी इस दिशा में और प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। पिछले दिनों हिमाचल प्रदेश में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में शिक्षकों के हजारों पद भरने को मंजूरी दे दी गई है, लेकिन इस संबंध में अभी तक प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। इस विषय की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए इस संबंध में जल्द कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए। उधर शिक्षा विभाग का यह प्रयास सराहनीय है, जिसके तहत स्कूलों में रिक्त होने वाले पदों को तुरंत भरा जाएगा। शिक्षा विभाग सत्र शुरू होने से पूर्व ही एक डाटा तैयार करेगा, जिसके तहत किसी पद के रिक्त होने से पूर्व ही सभी औपचारिकताएं पूरी कर दी जाएंगी। इस डाटा में इस तरह का सारा ब्योरा होगा, जिसमें यह जानकारी होगी कि कौन शिक्षक कब सेवानिवृत्त हो रहा है और कौन सा शिक्षक कब पदोन्नत होगा। इसके बाद कितने पद खाली होंगे। इस तरह की जानकारी पहले ही होने के कारण विभाग रिक्त पदों को समय पर भर देगा और लंबे समय तक कोई पद खाली नहीं रहेगा। अभी तक किसी शिक्षक के सेवानिवृत्त या पदोन्नत होने के बाद रिक्त होने वाले पद को भरने में कई तरह की औपचारिकताएं पूरी करने में काफी समय लग जाता था। इससे स्कूलों में विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित होती थी। विभाग की इस योजना से जहां अधिक देर तक पद रिक्त नहीं रहेगा, वहीं बच्चों की पढ़ाई भी बाधित नहीं होगी। शिक्षा विभाग को इस तरह के भी प्रयास करने होंगे कि शिक्षकों की ड्यूटी गैर शैक्षिक कार्यों में न लगाई जाए। इससे भी बच्चों की पढ़ाई बाधित होती रही है। सरकार को भी चाहिए कि शिक्षित समाज की परिकल्पना को साकार करने के लिए शिक्षण संस्थानों में तमाम सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं। दूरदराज के क्षेत्रों में जहां भवनों की कमी है या शिक्षकों को पद रिक्त हैं उन्हें जल्द भरा जाए।

# मध्य प्रदेश सरकार ने एसिड की बिक्री पर लगाई रोक

राज्य ब्यूरो, भोपाल

अभिनेत्री दीपिका पादुकोण अभिनीत फिल्म 'छपाक' को टैक्स फ्री करने के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश में खुलेतौर पर एसिड (तेजाब) की बिक्री पर रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा है कि एसिड अटैक सर्वाइवर पर बनी फिल्म को टैक्स फ्री करना ही काफी नहीं है। इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए जागरूकता के साथ कड़े कदम उठाने की जरूरत है। उन्होंने पूरे प्रदेश में एसिड की खुले में बिक्री को लेकर अभियान चलाने के निर्देश भी दिए हैं।

मुख्यमंत्री नाथ ने ट्विटर पर लिखा है कि प्रदेश में किसी भी बहन-बेटी पर एसिड अटैक की घटनाओं की रोकथाम के लिए खुले में एसिड की बिक्री पर नियंत्रण और अंकुश बेहद जरूरी है। उन्होंने लिखा है कि ऐसी घटनाएं कतई बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। ऐसी घटना सामने आने पर जिम्मेदारी भी तय होगी और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा भी मिलेगी। मप्र में एसिड की खुले आम बिक्री का मामला गुरुवार को मप्र हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में भी उठा। हाई कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर पूछा कि बाजार में खुलेआम एसिड कैसे बिक रहा है? एसिड बेचने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? जिम्मेदारों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई? इस बारे में सरकार से 16 मार्च तक जवाब मांगा गया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को यह नोटिस एसिड अटैक पीड़िता की ओर से दायर जनहित याचिका पर दिया। याचिकाकर्ता की तरफ से एडवोकेट शन्नो शगुफ्ता खान पैरवी कर रही हैं।

**यह हैं एसिड बिक्री के नियम**

- 18 साल से कम उम्र के किसी व्यक्ति को एसिड नहीं बेचा जा सकता।
- एसिड व्यापारी खरीदने आए हर ग्राहक से पूछें कि उसे यह क्यों चाहिए?
- व्यापारी हर ग्राहक का पहचान पत्र भी अनिवार्य रूप से लें।
- जो विक्रेता नियमों का पालन नहीं करें उस पर 50 हजार रुपये जुर्माना लगाएं।

**फिर भी 30 रुपए लीटर में खुले आम हो रही बिक्री**

उक्त नियमों के बाद भी मप्र के बाजारों में खुलेआम 30 रुपए लीटर में एसिड बिक रहा है। याचिकाकर्ता के वकील ने खुद बाजार का सर्वे किया। 50 से ज्यादा दुकानदार बिना किसी पहचान पत्र और पूछताछ के एसिड देने को तैयार हो गए।

**पीड़िता की दोनों आंखों की चली गई थी रोशनी**

एडवोकेट खान ने बताया कि याचिकाकर्ता खुद इंदौर की एक युवती पर नवंबर 2018 में एक युवक ने एसिड फेंका था। इससे उसकी दोनों आंखों की रोशनी चली गई। वह पीड़िता पर शादी के लिए दबाव बना रहा था। पीड़िता का अभी हैदराबाद में इलाज चल रहा है। आरोपित जेल में है।

# बैंकों के भरोसे मत बैठिए, सतर्कता बढ़ाकर साइबर अपराधियों को कर सकते हैं फेल

**किस्त पांच**

ज्ञान बिहारी मिश्र, लखनऊ

बैंकों में आपकी मेहनत की कमाई जमा है। रुपये आपके हैं तो इसके प्रति जिम्मेदारी भी आपको ही उठानी पड़ेगी। बैंकों के भरोसे बैठकर आप अपनी रकम सुरक्षित नहीं रख सकते। साइबर अपराधियों से बचने के लिए सतर्कता सबसे बड़ा हथियार है। आपको समझना होगा कि बैंक की ओर से कभी भी फोन, ई-मेल अथवा मैसेज से खातों के बारे में जानकारी नहीं मांगी जाती।

**कैसे होता कार्ड का डाटा चोरी** : जालसाज स्कीमर (डाटा चोरी करने की डिवाइस) एक तरह की चिप का प्रयोग करते हैं, इसे एटीएम के कार्ड रीडर स्लॉट में लगाकर डाटा चोरी कर ली जाती है। कार्ड ट्रेपिंग के जरिए कार्ड की जानकारी कॉपी कर ली जाती है। शोल्डर सर्फिंग के जरिए ठग आपके एटीएम कार्ड का नंबर पढ़ लेते हैं। वहीं मदद का झांसा देकर कार्ड बदल देते हैं। एटीएम में हिडेन कैमरे लगाए जाते हैं। इससे पिन कोड चोरी कर लिया जाता है।

**ऐसे करते ऑनलाइन ठगी** : ठग किसी वास्तविक वेबसाइट से मिलती जुलती फर्जी वेबसाइट बना लेते हैं। एटीएम के जरिए अगर वेबसाइट से कोई लेनदेन की जाती है तो कार्ड का डाटा चोरी कर लेते हैं। की-स्ट्रोक लॉजिंग तकनीक के जरिए जालसाज लोगों को की-लॉगर साफ्टवेयर का लिंक भेजते हैं। इसे डाउनलोड करने वाले व्यक्ति से ठग की-स्ट्रोक के जरिए नेट बैंकिंग पासवर्ड चोरी कर लेते हैं। वहीं पब्लिक वाई-फाई का प्रयोग कर स्मार्ट फोन से लेनदेन करते समय भी डाटा चोरी कर लिया जाता है।

मालवेयर साफ्टवेयर के जरिए कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाकर बैंक व एटीएम के सर्वर हैक कर लेते हैं। इसके बाद डाटा चोरी कर लिया जाता है। जिसके बाद साइबर ठगी को अंजाम दिया जाता है।

- बैंकों में जमा रुपयों के सुरक्षा की जिम्मेदारी भी आपकी
- एटीएम से रुपये निकालते व फोन पर बात के समय रहें सतर्क

प्रतीकात्मक

**समझें, कैसे बचाएं खुद को**

बिना गार्ड या खराब कैमरे वाले जीर्ण स्थिति के एटीएम बूथ का इस्तेमाल न करें। दो बार पिन कोड मांगने वाले एटीएम में न जाएं। पिन नंबर डालते समय की बोर्ड ढक लें, ताकि वह कैमरे में कैद न हो पाए। किसी अपरिचित से एटीएम का प्रयोग करने के लिए मदद न मांगें।

**ऐसे होगा ऑनलाइन बचाव**

ऐसे वेबसाइट का ही प्रयोग करें जो एसएसएल सर्टिफाइड हों। यह ब्राउजर बॉक्स में लॉक साइन से दिखता है। एचटीटीपीएस प्रोटोकॉल वेबसाइट का ही प्रयोग करें। एंटी-वायरस साफ्टवेयर आपके कंप्यूटर को सुरक्षित रखेगा। आप मोबाइल में आइडेंटिटी थेप्ट डिटेक्शन एप इंस्टाल कर सकते हैं, इससे मोबाइल खोने की दशा में आपको डाटा वापस मिल जाएगा। डेबिट कार्ड से ई-कामर्स ट्रांजेक्शन न करें। कार्ड वेरीफिकेशन वेल्यू ( सीवीवी) नंबर को छिपाकर रखें। सोशल साइट्स पर ऑनलाइन एकाउंट का प्रयोग करने के बाद फौरन लॉग आउट कर दें। पासवर्ड बदलते रहें। गोपनीय जानकारी किसी से साझा न करें। बैंक स्टेटमेंट चेक करते रहें। किसी भी सादी रसीद पर हस्ताक्षर न करें।

# हरियाणा में चूल्हे से कमजोर हो रहे महिलाओं के फेफड़े

पुनीत शर्मा, रोहतक

- पीजीआइ के फिजियोलॉजी विभाग के चिकित्सकों की रिसर्च में सामने आए चौंकाने वाले तथ्य
- रिसर्च में 30 गैस पर और 30 चूल्हे पर खाना बनाने वाली 30 से 45 आयु वर्ग की महिलाओं को किया गया शामिल

चूल्हे पर खाना बनाने वाली महिलाओं को धुएं के कारण विभिन्न बीमारियों से जूझना पड़ता है। चूल्हे पर खाना बनाने वाली 92 फीसद महिलाओं को फेफड़े संबंधी बीमारी व सांस फूलने की शिकायत रहती है। यह बात पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के चिकित्सकों की रिसर्च में सामने आई है। रिसर्च में शामिल की गई महिलाएं ऐसी थीं जो अपने किसी रिश्तेदार मरीज को पीजीआइ लेकर पहुंचीं थीं।

पीजीआइएमएस के फिजियोलॉजी विभाग के चिकित्सक डा. राजेश गुप्ता के निर्देशन में विद्यार्थियों ने चूल्हे पर खाना बनाने वाली और गैस पर खाना बनाने वाली 30 से 45 आयु वर्ग की 60 महिलाओं को अपनी रिसर्च में शामिल किया। रिसर्च में सामने आया कि गैस पर खाना बनाने वाली महिलाओं की (1.5) फेफड़ों की क्षमता (फोर्स विटाल केपेसिटी) चूल्हे पर खाना बनाने वाली महिलाओं की अपेक्षा (2+) अधिक थी। चूल्हे पर खाना बनाने वाली 30 फीसद महिलाओं में फेफड़े संबंधी बीमारी की शुरुआत हो चुकी थी, जबकि 62 फीसद महिलाओं में मध्यम स्तर की बीमारी थी।

**दिल की धड़कन भी अधिक** : चिकित्सकों ने बताया कि जो महिलाएं चूल्हे पर खाना बनातीं हैं, उन्हें गैस पर खाना बनाने वाली महिलाओं की अपेक्षा व्यायाम करने पर जल्द थकावट होती है। गैस पर खाना बनाने वाली महिलाओं की क्षमता 92 फीसद पाई गई तो चूल्हे पर खाना बनाने वाली महिलाओं में यह 60 फीसद ही पाई गई। चूल्हे पर खाना बनाने वाली महिलाओं की दिल की धड़कन 86.26 और गैस पर खाना बनाने वाली महिलाओं की 82.81 पाई गई। दिल की धड़कन पर नब्ज का प्रभाव चूल्हे पर खाना बनाने वाली महिलाओं में 140 और गैस पर खाना बनाने वाली महिलाओं में 88 फीसद पाया गया।

**बढ़ती बीमारी से राहत दिला रही उज्जवला योजना**

1 मई 2016 को केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री उज्जवला योजना चूल्हे पर कार्य करने वाली महिलाओं के लिए राहत लेकर आई। योजना के तहत करोड़ों महिलाओं को फ्री गैस कनेक्शन बांटे गए, जिसके कारण उन्हें न केवल धुंए से आजादी मिली, बल्कि फेफड़े, सांस व दिल संबंधी विभिन्न बीमारियों से निजात भी मिली।

# जम्मू- कश्मीर में मौजूद ऐसे 'मददगार' जो किसी की उम्मीद नहीं तोड़ते

राज्य ब्यूरो, जम्मू

- सीआरपीएफ की हेल्पलाइन 'मददगार' फिर मदद के लिए आगे आई, मरीज को दिया खून

केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की हेल्पलाइन 'मददगार' अब कश्मीर के लाखों लोगों की उम्मीद बन गई है। इस उम्मीद ने आज तक किसी की उम्मीद को नहीं तोड़ा है।

बर्फबारी के बीच रात में दम तोड़ रही जिंदगी हो या विपरीत हालात में किसी को जरूरत हो या अस्पतालों में खून के लिए दरबदर हो रहे लोग हों, जिंदगी के यह 'मददगार' हमेशा मदद के लिए आगे रहते हैं। कश्मीर के अस्पतालों में यह 'मददगार' अभी तक एक हजार यूनिट से ज्यादा खून जरूरतमंदों को दे चुके हैं। आम लोगों से लेकर अधिकारी तक इनकी सेवाओं को पसंद करते हैं। कश्मीर के लोगों के लिए यह हेल्पलाइन सबसे अधिक मददगार साबित हो रही है।

हाल ही में श्रीनगर के शेर-ए-कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में भर्ती एक मरीज को खून की जरूरत पड़ी तो एसएसपी इम्तियाज हुसैन ने ट्वीट कर पीड़ित के लिए खून मांगा। उन्होंने सीआरपीएफ की हेल्पलाइन 'मददगार' को भी ट्वीट किया। उनके ट्वीट के कुछ घंटों में ही जवान शेर-ए-कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में पहुंचे और मरीज को चार यूनिट ब्लड दिया। जवानों की इस तत्परता ने एसएसपी का दिल जीत लिया। उन्होंने ट्वीट कर सीआरपीएफ के जवानों की सराहना करते हुए कहा कि उनकी इस निःस्वार्थ सेवा के लिए धन्यवाद।

पिछले तीस महीनों में सीआरपीएफ के ये 'मददगार' कश्मीर के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती मरीजों को एक हजार से अधिक यूनिट खून दे चुकी हैं। यह रक्तदान करने वाले कई गैर सरकारी संगठनों से कहीं अधिक हैं। इस सेवा के लिए जवानों की पहले भी सराहना हो चुकी है। कुछ दिन पहले ही 'मददगार' की टीम ने रामबन में तीन बच्चों व अन्य परिजनों के साथ फंसे एक परिजन की कॉल पर बर्फीली रात में 12 किलोमीटर पैदल चलकर उन्हें खाने पीने का सामान उपलब्ध करवाया था।

# मप्र सिंगरौली के तालाबों में फ्लाई ऐश की डंपिंग बंद करने की मांग

**नई दिल्ली, प्रेट्र** : नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में याचिका दायर कर मध्य प्रदेश के सिंगरौली और उत्तर प्रदेश के सोनभद्र थर्मल पावर प्लांटों की फ्लाई ऐश (उड़ने वाली राख), विषाक्त अवशेष और औद्योगिक कचरे को रिहंद जलाशय एवं अन्य तालाबों में हो रही डंपिंग पर रोक लगाने का निर्देश देने की मांग की गई है। वकील अश्वनी कुमार दुबे ने गुरुवार को यह याचिका दायर की।

याचिका में छह अक्टूबर 2019 की एक घटना का उल्लेख है। सिंगरौली में एनटीपीसी विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन की राख से बना बांध लापरवाही के कारण टूट गया था। इससे 35 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा फ्लाई ऐश गोविंद वल्लभ पंत सागर 'रिहंद जलाशय' में चली गई। इससे जलाशय का पानी दूषित हो गया। बांध टूटने के कारण फ्लाई ऐश ने खेती की भूमि तबाह कर दी और कई पशु भी लापता हो गए।

# कॉमन सर्विस सेंटर से वापस लिया काम पंजाब में नए कार्ड बनाने पर भी रोक

धरमिंदर सिंह, फतेहगढ़ साहिब

आयुष्मान भारत योजना (सरबत सेहत बीमा योजना) में फर्जी कार्ड बनने के लगातार सामने आए केसों के बाद स्टेट हेल्थ एजेंसी ने सूबे में एक हजार से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर बंद कर दिए हैं।

यह फैसला सेहत मंत्री बलबीर सिद्धू के आदेश के बाद लिया गया है। नए आदेशों तक पंजाब में कोई भी नया कार्ड बनाने पर भी रोक लगा दी गई है। विशेष परिस्थिति में अब कार्ड केवल प्रदेश के सिविल अस्पतालों या पैनल में शामिल निजी अस्पतालों में ही बनेंगे। वो भी उन लाभार्थियों के ही बनेंगे, जिन्हें इलाज के लिए तुरंत कार्ड की जरूरत होगी। रूटीन में कोई भी कार्ड नहीं बनेगा।

एजेंसी ने भी जांच के बाद माना था कि

**आयुष्मान में फर्जीवाड़ा**

फर्जीवाड़ा का मुख्य कारण कॉमन सर्विस सेंटर ही थे। इसको लेकर चंडीगढ़ में एजेंसी के सीनियर अधिकारियों की बैठक भी हुई। इसमें फैसला लिया गया कि स्टेट हेल्थ एजेंसी अब इन कॉमन सर्विस सेंटरों से काम नहीं करवाएगी। सेहत मंत्री बलबीर सिद्धू ने कहा कि एजेंसी नए टेंडर निकालेगी और अगले हफ्ते तक नई कंपनी कार्ड बनाने का काम भी शुरू कर देगी। उन्होंने एजेंसी को निर्देश हैं कि सिविल सर्जनों की निगरानी में ही कार्ड बनने चाहिए।

**अब तक पांच लाख कार्डों का ऑडिट** : फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद अब तक स्टेट हेल्थ एजेंसी के मोहाली स्थित मुख्यालय पर एक टीम प्रदेशभर के करीब पांच लाख कार्डों का ऑडिट कर चुकी है। इनमें फतेहगढ़ साहिब के करीब सवा लाख कार्ड शामिल हैं।

जिस कार्ड में गड़बड़ी पाई जाती है तो उसे साथ ही रद कर दिया जाता है। स्टेट हेल्थ एजेंसी के अधिकारी डॉ. संजीव जैन ने कॉमन सर्विस सेंटर बंद करने की पुष्टि की है। कहा कि आने वाले दिनों में बेहतर सुधार देखने को मिलेंगे।

**दैनिक जागरण ने उठाया था मुद्दा** : गौरतलब है कि दैनिक जागरण ने सबसे पहले फतेहगढ़ साहिब में आयुष्मान कार्डों में फर्जीवाड़े को उजागर किया था। इसके बाद पंजाबभर में ऐसे हजारों फर्जी कार्ड बनने का राजफाश हुआ। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी कड़ा संज्ञान लिया। स्वास्थ्य मंत्री ने खुद कई कार्ड रद किए थे। अब पूरे प्रदेश में कार्ड बनाने पर रोक लगा दी गई है।

दैनिक जागरण
# सबरंग
प्लान वीकेंड के
नई दिल्ली, शुक्रवार, 17 जनवरी, 2020
सुझाव व प्रतिक्रिया के लिए लिखें :sabrang@nda.jagran.com
https://www.facebook.com/jagransabrang/

देखो, हां, कैद करो इसे मोबाइल में...बिलकुल ऐसे ही दृश्य तो दिखते हैं नदियों के किनारे।

'लक्ष्मी' हर घर की...यही संदेश दे रही है विजय वंश की यह कलाकृति, भले सब्जी बेच रही महिला हो उसके सौभाग्य में भी 'लक्ष्मी' है।

प्रदर्शनी

# आंखों ने देखी...मन ने सुनी रंगों की बोली

पेंसिल से खींची गईं बारीक लकीरें भी जब एक कलाकार का नजरिया लेती हैं तो समाज पर कटाक्ष बन जाती हैं। एक सीख...एक सबक... एक संदेश दे जाती हैं। यहां तो सैकड़ों संदेशों का समावेश है...कहते हैं न हर रंग कुछ कहता है...यहां हर रंग बेहद बातूनी है। आपकी ही बात कहेगा। एक बार देखने आएं तो सही...। सबरंग के इस अंक में एक साथ सजी 200 कलाकृतियों से रूबरू करा रहे हैं संजीव कुमार मिश्र :

डॉ सूर्यस्नाता महांती, इनकी कलाकृतियां आस्था के द्वार...विश्वास के द्वार...जीवन की कहानी को दर्शाते वक्त के द्वार...सब दिखाती हैं।

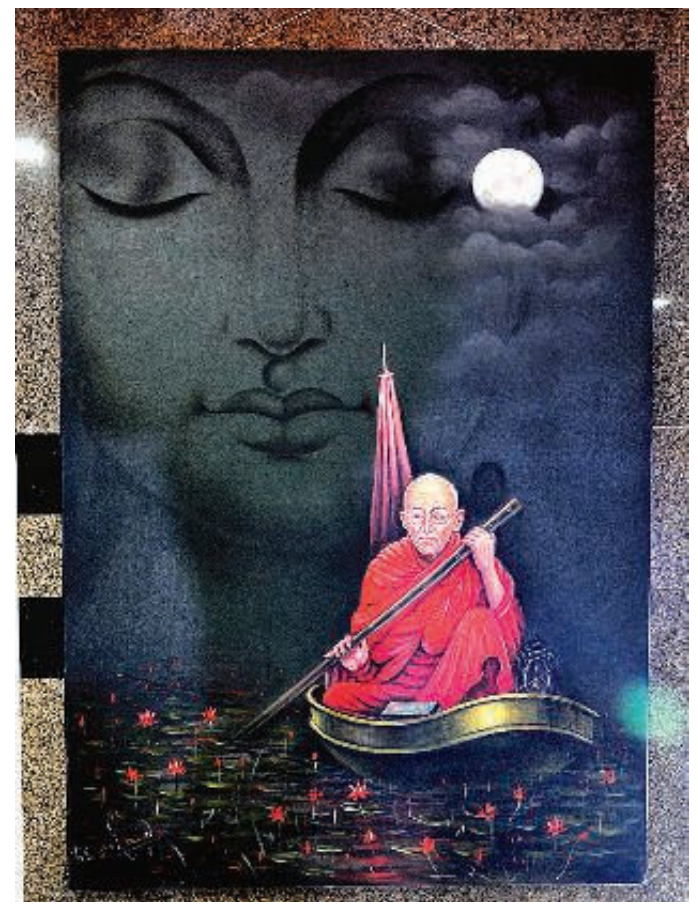
जनपथ सब-वे में कलाकार प्रिंस चांद की यह पेंटिंग दर्शकों को खासा प्रभावित कर रही है। सभी फोटो-ध्रुव कुमार

एक खास बात देखेंगे इस प्रदर्शनी में, यहां आपको हर कलाकृति में भारत की आत्मा बसी नजर आएगी। ऐसे विषय नजर आएंगे जो या तो आपके हैं या आपके आसपास के। मजहब, जाति, व्यक्ति विशेष की बेड़ियों में लिपटी...पर्यावरण अलख जगाती...बेजुबानों की कहानी सुनाती रंगों की अद्भुत दुनिया बना हुआ है जनपथ स्थित सब-वे। आर्ट गैलरी की दहलीज लांघ सब-वे में आयोजित कलाकृतियों की प्रदर्शनी दर्शकों को हैरत में डालती है, रोमांचित करती है और फोटो खिंचवाने को आकर्षित भी करती है।

**आस्था का रंग** : सब-वे में जैसे ही प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले आपको डॉ सूर्यस्नाता महांती की कलाकृतियों के जरिये आस्था के चटख रंग दिखाई देंगे। महांती की यहां पांच कलाकृतियां कलर ऑफ फेथ, कॉलिंग बेल, ए जर्नी इन ड्रीम, हाउस ऑफ शिवा और बलीश...प्रदर्शित हैं। कलर ऑफ फेथ...गंगा जमुनी तहजीब की डोर को मजबूत करता है। इसमें मंदिर और मस्जिद का समावेश है। बकौल महांती कलर ऑफ फेथ का कांसेप्ट बाइबिल में मिलता है। हम किसी भी धर्म से हों लेकिन जुड़े तो विश्वास से ही होते हैं। वहीं कॉलिंग बेल सही समय का बोध कराती है। हम मंदिर की चौखट पर खड़े रहते हैं लेकिन जब तक भगवान का बुलावा नहीं आता दर्शन करने नहीं जाते। हर व्यक्ति के जीवन में कॉलिंग टाइम आता है। जब हमें जिंदगी जीने का मकसद मिलता है। स्वप्न दृष्टि पेंटिंग दर्शकों को रुकने पर मजबूर करती है। कारण, पेंटिंग में कई मंदिर दिखते हैं लेकिन उनके दरवाजे नहीं दिखते, है न अद्भुत, ये जिंदगी के विभिन्न पड़ाव को दर्शाती है। जिंदगी का लक्ष्य व्यक्ति को तय करना है। यह आपको तय करना है कि कहां शांति मिलती है। सपनों का द्वार खुद ढूंढना होगा। वहीं हाउस ऑफ शिवा-सत्व, रज और तम गुणों से परे शिव से दर्शकों को रूबरू कराता है।

**आंतरिक खूबसूरती की तलाश** : लोग खूबसूरत दिखने के लिए ना जाने क्या-क्या जतन करते हैं। यह जानते हुए भी कि असल खूबसूरती तो हमारे मन के भीतर है। इसी कांसेप्ट को कैनवस पर उकेरती है दर्शन शर्मा की कलाकृति। कलाकृति बताती है कि जैसे खुशबू चारो तरफ फैलती है वैसे ही आंतरिक सुंदरता भी तो चारो तरफ फैलती है। उसे रोका नहीं जा सकता है। मोनिका सिंह की कलाकृति राधा कृष्ण को मधुबनी परंपरा में संयोजित कर कैनवस पर उकेरती है। मधुबनी को नए सिरे से क्रिएट करती हैं। छाया दुबे की कलाकृति एब्सट्रैक्ट विधा से पर्यावरण को दर्शकों के सम्मुख प्रस्तुत करती है।

**हिंसक होता आदमी** : प्रदर्शनी में कलाकृतियों के साथ साथ गुरुदीप सिंह के स्कल्पचर भी हैं। इन स्कल्पचर की खासियत बताते हुए क्यूरेटर किशोर कहते हैं कि ये सभी लकड़ी का काम है। जिस पर वर्तमान मानवीय दशा को दर्शाया गया है। स्कल्पचर में आदमी को जानवर के रूप में दिखाया गया है। आज के समय में आदमी जानवर की तरह बर्ताव कर रहा है। इसलिए आदमी को लोहे की सींग उग आए हैं। यह कलाकृति दर्शकों का ध्यान आकर्षित कर रही है।

**सब्जी बेचने वाली भी लक्ष्मी** : वेदों में कहा गया है कि जहां नारी की पूजा होती है वहां भगवान का वास होता है। लेकिन घर और समाज में नारी का महत्व वर्तमान में पैसे से तौला जाने लगा है। यदि वो सूट बूट पहन ऑफिस काम करने जाती है तो घर में उसकी पूछ होती है। लेकिन ऐसा नहीं है। सब्जी बेचने जाने वाली, या किसी भी तरह मेहनत कर परिवार का खर्च चलाने वाली महिला भी लक्ष्मी का रूप है। पेंटिंग में लक्ष्मी की जगह महिला को दिखाया गया है। हाथों में धन का अकूत भंडार लिए। नारी शक्ति पर ही आधारित अनिल टाटो की कलाकृति भी शानदार है। जिसमें एब्सट्रैक्ट फार्म में नारी के चेहरे को दिखाया गया है।

**जिंदगी का सफर** : अशोक पिल्लई की कलाकृति आदमी की यात्रा पर आधारित है। कलाकृति में समुद्र किनारे एक सूखा पेड़ दिखता है। अशोक कहते हैं कि यह सूखा पेड़, जो समुद्र में बहकर किनारे तक आया है। लेकिन जरा देखिए, किस तरह दोबारा सफर पर जाने के लिए तैयार खड़ा है। ना पत्तियां हैं ना हरी भरी शाखाएं। सूख चुका है लेकिन फिर भी सफर पर जाने के लिए तत्पर है। यही जिंदगी का फलसफा है।

**ब्रह्मा नहीं कंप्यूटर कर रहा नियंत्रित** : सुनील के सूर्यवंशी की कलाकृति बहुत ही गंभीर संदेश देती है। कलाकृति को पहली नजर में देखने पर सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा ही परिलक्षित होते हैं। लेकिन यहीं फूलों से कंप्यूटर का माउस निकलता दिखता है। सुनील कहते हैं कि सृष्टि ब्रह्मा ने रची। लेकिन अब जिस तरह डिजिटल हावी हो रहा है उससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे धीरे धीरे हम भी मशीन बनते जा रहे हैं। इसलिए अब कंप्यूटर ही हम पर नियंत्रण कर रहा है।

**शिव की महिमा** : शिव की अपार महिमा को दर्शाती अनीता दिनेश की कलाकृति आकर्षक है। उनकी यहां तीन कलाकृतियां लगी हैं। कहतीं हैं शिव, बनारस के कण-कण में हैं। वहां की जिंदगी शिवत्व में रमी बसी है। पेंटिंग में बनारस के शिव मंदिरों को एब्सट्रैक्ट रूप में दिखाया गया है। कलाकृति की खासियत ही...उसका रहस्यवाद की चादर में लिपटा होना है। पेंटिंग देखने से कहीं यह शिव मंदिर या बनारस की प्रतीत नहीं होती है। पहचान के नाम पर मंदिरों की छतरियां और कुछ प्रतीक चिन्ह दिखते हैं। जबकि एक अन्य कलाकृति नीले रंग में रंगी है। कहती हैं पेंटिंग में बनारस की आत्मा में शिव के वास को दिखाने की कोशिश की गई है। नीला रंग शिव का प्रतीक है, तभी तो नीलकंठ कहते हैं।

> दिल्ली में आर्ट गैलरी की कमी नहीं है। लेकिन आम लोग इन गैलरियों की दीवारों के अंदर क्या चल रहा है, इससे अनजान रहते हैं। किसी देश का विकास सिर्फ आर्थिक नहीं होता है, उसकी संस्कृति समृद्धता भी मायने रखती है। हमारी कोशिश है कि लोग कला को समझें, कलाकारों को जाने। यूरोप में इस तरह का प्रचलन है, वहां सब-वे में कलाकृतियों की प्रदर्शनी लगती हैं।
>
> - किशोर लाबर, आर्ट क्यूरेटर

## इस बार यहां चलें

### गांधी के आदर्शों पर प्रस्तुति

आप अगर अस्ताद देबू के मुरीद हैं तो इस सप्ताहांत उनकी प्रस्तुति देखने का बेहतरीन मौका है। चिन्मय ऑडिटोरियम में अस्ताद देबू, महात्मा गांधी के आदर्शों पर प्रस्तुति देंगे। जो, रिश्ते चार सिद्धांत–सम्मान, समझ, स्वीकृति और प्रशंसा पर आधारित होते हैं। ताकत शारीरिक क्षमता से नहीं आती, यह अदम्य इच्छाशक्ति से आती है, सरीखे प्रेरक वाक्यों पर आधारित होगी।
- **कहां** : चिन्मय आडिटोरियम, लोदी रोड।
- **कब** : 18 जनवरी, शाम साढ़े छह बजे।
- **प्रवेश** : निश्शुल्क।

### मसखरे करेंगे लोटपोट

शाकुंतलम अगर पूरा कर पाए तो क्या हो यदि मसखरे, कालिदास की महान रचना की पुनर्व्याख्या करने लगें? क्या मसखरे संभाल पाएंगे 2500 साल पुराने पाठ का दबाव? या वे चारों बस मूर्ख बनकर रह जाएंगे? तीन मसखरे जब नाटक की व्याख्या करने हैं तो परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि दर्शक हंसकर लोटपोट हो जाते हैं।
- **कहां** : चिन्मय आडिटोरियम, लोदी रोड।
- **कब** : 18 जनवरी, शाम साढ़े छह बजे।
- **प्रवेश** : ऑनलाइन बुकिंग, 400, 499 रुपये टिकट।

### ए बॉय नेम थियेटर

ए बॉय नेम थियेटर, हास्य नाटक है। जो नाटक के गॉडफादर, विलियम के लिए एक अनूठी श्रद्धांजलि है। कहानी, दिल्ली के विभिन्न थियेटरों के पीछे की कहानी से दर्शकों को रूबरू कराती है। थियेटर में नाटक होते हैं, दर्शक आते हैं। लेकिन एक थियेटर में पर्दे के पीछे की कहानी से दर्शक अंजान रहते हैं। बस दर्शकों को यही पर्दे के पीछे की कहानी से परिचित कराना है। कहानी, दर्शकों को खूब हंसाती है।
- **कहां** : अलायंस फ्रांसिस डे, दिल्ली।
- **कब** : 18 जनवरी, रात आठ बजे।
- **प्रवेश** : ऑनलाइन बुकिंग, 400, 499 रुपये टिकट।

### कैदी...सस्पेंस

डेबी चौटियाल पर अपने पति की हत्या का आरोप है। बचाव पक्ष के वकील राधिका गौतम डेबी की मासूमियत में विश्वास करते हैं और उसे बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन डेबी उस भयावह रात के विवरण पर चुप रहती है। हत्या के पीछे का सच क्या है? इसकी कहानी करीब नब्बे मिनट तक दर्शकों को बांधे रखती है।
- **कहां** : स्टेन आडिटोरियम, लोदी रोड।
- **कब** : 19 जनवरी, शाम सात बजे।
- **प्रवेश** : ऑनलाइन बुकिंग द्वारा प्रवेश।

जायका

# घर के खाने की याद ने बनाया शेफ

अनुभव...जिंदगी का ऐसा फार्मूला जो हर जगह फिट बैठता है अपनी जरूरत का फील भी देता है। अब आपको खाने का ही शौक हो या खाना बनाने का? सोचो आपको उसकी वैरायटी का कैसे पता लगेगा? स्वाभाविक है जब आप वहां जाएंगे...खाएंगे और यदि शौक रखते हैं तो फिर वैसा ही खुद भी बनाएंगे। अब रोहिणी को भी शौक था सो उन्होंने भी फूडी सफर किए, पढ़ाई के लिए घर से बाहर रहीं और उसी अनुभव से अच्छी शेफ की मिसाल बन सकीं।

शेफ रोहिणी

मास्टरशेफ तक की मंजिल तक पहुंच सकीं। एक होमशेफ से मास्टरशेफ के सर्वश्रेष्ठ प्रतिभागियों में पहुंची रोहिणी वैसे तो भारतीय व्यंजनों को खासा पसंद करती हैं लेकिन उनकी विशेषताओं में इंडियन व एशियन रेसिपीज के अलावा मिडल ईस्ट, इटालियन व स्पैनिश डिशेज शामिल हैं। 16 वर्षों तक अमेरिका में रहीं रोहिणी ने देश-विदेश के भोजन को चखा...उस स्वाद का अनुभव लिया। प्रयोगों के जरिये लोगों को सुस्वाद देने वाली रोहिणी कुकिंग व बेकिंग करती हैं। मिठाइयों और केक्स में भी रोहिणी को महारथ हासिल है। रोहिणी के मुताबिक वे जब घर पर थीं तो उन्हें, दाल-चावल, तोरी, टिंडा और लौकी जैसी सब्जियां खाना पसंद नहीं करती थीं। लेकिन जब वे अमेरिका में पढ़ने गईं तो बाहर के खाने से बोर हो गईं और उन्हें मम्मी-पापा के बनाए उसी खाने की याद आने लगी। उस समय कॉल्स बहुत महंगी होती थीं तो वे पिता जी से इन डिशेज की रेसिपीज खत के द्वारा मंगवाने लगीं। धीरे-धीरे खाना बनाना उनका शौक और फिर पैशन बन गया। यूएस में रहते हुए कई तरह की फूड कल्चर से रूबरू हो रहीं थीं तो उनकी पाक कला भी विस्तृत होने लगी। शादी के बाद ससुराल में फूडी माहौल मिल गया...बस फिर क्या था। अब वे अपने इंस्टाग्राम पेज पर रेसिपीज शेयर करती हैं ताकि लोग हर तरह के भोजन को बनाने में पारंगत हो सकें।

**सेहत से भरपूर एनर्जी बॉल्स** : ठंड के मौसम में लड्डू व गजक का विशेष स्वाद पाना है तो रोहिणी की रेसिपीज को फॉलो करना होगा। रोहिणी के मुताबिक लोगों को अनूठा स्वाद देने के लिए उन्होंने मिठाइयों के साथ प्रयोग किया है। ऐसे में वे गजक व लड्डू नट्स, चॉकलेट व ड्राइफ्रूट के साथ ओट्स से बनाए जा रहे हैं। उनके मुताबिक एक वर्ग है जो कि परंपरागत डिशेज चाहता है लेकिन अपने टेस्ट के अनुरूप उन्हें ढालकर। ऐसे में लोगों के लिए यह फ्यूजन मिठाइयां भी बनाती हूं जोकि लोगों को खूबस पसंद आती है।

**प्रियंका दुबे मेहता**

### भाजा पीठा का गजब स्वाद

नाम शायद पहली बार सुना हो लेकिन इसका स्वाद व आकार कहीं न कहीं गुझिए जैसे होता है। गुड़, दो बारीक कटे नारियल, किशमिश,

दो चम्मच हरी इलायची का पाउडर, ढाई कप आटा, दो चम्मच घी, नमक व तेल से इसे आप रोहिणी के अंदाज में बना सकते हैं। एक बड़े बाउल में गेहूं के आटे को लें और उसमें नमक व तीन चम्मच तेल मिलाएं। इसे गुनगुने पानी से गूंथ लें। आधे घंटे के लिए ढक कर रख लें। अब एक भारी तली वाले बर्तन में दो चम्मच घी डालकर उसमें घिसा हुआ नारियल डालें इसमें थोड़ा सा नमक भी डालें। गुड़ को छोटे टुकड़ों में काट लें। अब इसे नारियल के मिक्सचर में डालें। धीमी आंच पर हिलाते हुए पकाएं ताकि उसका पानी सूख जाए। अब आटे की छोटी लोइयां बनाकर उसमें इस मिक्सचर को भरें और इसे तल लें। आपका भाजा पीठा तैयार है।

### ओट्स वाले लड्डू

एक कप क्विक कुकिंग ओट्स, छह से आठ खजूर, दो चम्मच फ्लेक्स सीड, एक मुट्ठी बादाम, एक से दो चम्मच कद्दू के बीज, एक से दो चम्मच नारियल तेल व नमक के साथ आप इस हेल्दी लड्डू को अपने घर पर भी तैयार कर सकते हैं। मिक्सर में बादाम, खजूर और नारियल तेल को पीस लें। अब इस पेस्ट में ओट्स मिला लें। इसे बड़े कटोरे में निकाल कर इसमें सभी प्रकार के बीज, क्रैनबेरी और नमक मिला लें। इसके लड्डू बनाकर फ्रीज करें।

सभी फोटो सौजन्य : शेफ रोहिणी

संगीत-नृत्य उत्सव

# घुंघरुओं ने बांधी तहजीब की डोर

श्रीराम सेंटर के सभागार में आयोजित रंग-ए-सुखन कार्यक्रम में प्रस्तुति देती कलाकार। जागरण

ज्यों ज्यों समारोह शुरू होने का पल नजदीक आ रहा था दर्शकों की बेताबी बढ़ती जा रही थी। कारण, काव्य पर कथक प्रस्तुति थी। रंग-ए-सुखन की प्रस्तुति एक बार जो शुरू हुई तो करीब डेढ़ घंटे तक दर्शक सुरों की बारिश में भीगते रहे।

आमद कथक डांस सेंटर द्वारा आयोजित कार्यक्रम में कथक गुरु रानी खानम द्वारा प्रशिक्षित 100 से अधिक कलाकारों ने प्रस्तुति दी। युवा कथक नर्तकों ने नृत्य कला का बेजोड़ प्रदर्शन किया। उनके घुंघरुओं की खनक से हॉल गूंज रहा था। कविताओं पर थिरकते कदमों को देखना दर्शकों के लिए एक अनूठा अनुभव था। शुरुआत दाग-देहलवी की नज्म 'क्यों चुराते हो देखकर आंखें, कर चुकी मेरे दिल में घर आंखें' से हुई। गजल की यह प्रस्तुति 19वीं शताब्दी के महफिल-ए-अंदाज विधा को जीवंत कर गई। इस नज्म पर कथक प्रस्तुति बेमिसाल थी। दर्शकों ने तालियां बजाकर प्रस्तुति का सम्मान किया। सुरमयी शाम का अगला पड़ाव सिंध प्रांत के लब्ध-प्रतिष्ठित सूफी संत लाल शाहबाज कलंदर के सम्मान में लिखित आध्यात्मिक सूफी गीत दमा-दम मस्त कलंदर की संगीतमय प्रस्तुति थी। इस नज्म पर कथक प्रस्तुति के दौरान हॉल में दर्शक अपनी सीट से खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। सूफी संत लाल शाहबाज कलंदर ने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच धार्मिक सहिष्णुता का प्रचार करते हुए अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है। संगीतमय सफर में तीन ताल और 16 बीट्स में संगीतबद्ध व राग केदार पर आधारित केदार सरगम ने श्रोताओं के दिल को झंकृत कर दिया। इसके बाद युवा कलाकारों ने राग मालगुंजी पर मालगुंजी सरगम प्रस्तुत की। 16 बीट्स संगीत की खासियत है कि इसमें गीत के बोल में तेजी के साथ नर्तकियां मेलोडी, सुर-ताल के सार के अपने खूबसूरत फुटवर्क और भावभंगिमाओं के साथ थिरकन श्रोताओं को झूमने पर मजबूर कर देती हैं। इसमें जटिल स्टेप्स और नृत्य-संगीत की लय जानदार होती है।

इस प्रस्तुति के उपरांत, स्वास्तिक डांस-24 संस्था से जुड़े युवा कलाकारों ने गीत प्रस्तुत किया। आमद डांस सेंटर और स्वस्तिक डांस-24 संस्था के प्रशिक्षित युवा छात्रों ने पारंपरिक कथक नृत्य की जोरदार प्रस्तुति दी, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा। देर शाम विश्व प्रसिद्ध सूफी संत बुल्ले शाह की सुपरिचित सूफी काव्य रचना तेरे इश्क ने नचाया करके थैया-थैया के सामूहिक प्रदर्शन के साथ कार्यक्रम समाप्त हुआ।

रानी खानम कहती हैं कि कार्यक्रम की खासियत भारत-फारस की सभ्यता और संस्कृति को दर्शाती, उर्दू और फारसी कलाम पर आधारित गीतों की सुंदर प्रस्तुति थी। जिसे दर्शक गंगा-जमुनी तहजीब के नाम से जानते है। हमारा मुख्य उद्देश्य युवा कलाकारों को मंच प्रदान करने के साथ-साथ भारत की इस समृद्ध गीत-संगीत-नृत्य परंपरा को दर्शकों के बीच ले जाना है।

**संजीव कुमार मिश्र**

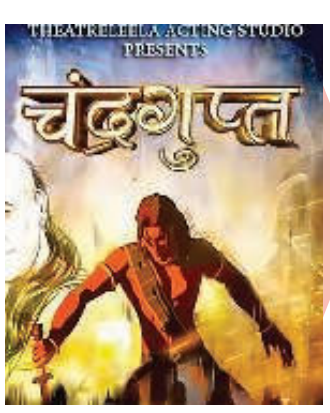


### चंद्रगुप्त, ऐतिहासिक नाटक

एक ऐतिहासिक नाटक, जो चंद्रगुप्त मौर्य की एक सामान्य से मगध के राजा तक की यात्रा को दर्शाता है। इसमें यह भी दिखाया गया है कि कैसे चाणक्य ने यूनानियों को हराने के लिए अपने मन और चंद्रगुप्त की ताकत का इस्तेमाल किया और भारत को एक एकजुट राष्ट्र बनाने की अपनी इच्छा को पूरा किया।
- **कहां** : श्रीराम सेंटर फॉर परफार्मिंग आर्ट, मंडी हाउस।
- **कब** : 19 जनवरी, रात साढ़े सात एवं आठ बजकर पचास मिनट पर।
- **प्रवेश** : ऑनलाइन बुकिंग, 200 से 500 रुपये तक।

### एयरपोर्ट पर लोहड़ी विशेष

आइजीआइ एयरपोर्ट यात्रियों को लोहड़ी पर विशेष जायके का प्रबंध किया है टीएमएफ यानी ट्रैवल फूड सर्विसेज ने। यहां विशेष लोहड़ी थाली उपलब्ध है। वेज और नॉनवेज थाली में प्रामाणिक पंजाबी भोजन जैसे मसटर्ड ग्रीन एवं अदरक व लहसुन मसालों से तैयार सरसों का साग, मक्के की रोटी के साथ परोसा जा रहा है।
- **कहां** : दिल्ली स्ट्रीट आउटलेट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट।
- **कब** : 17 जनवरी तक
- **प्रवेश** : उपयोग पर आधारित

### खास है बैंटर का पिजा

नार्थ इंडियन, कांटिनेंटल, इटैलियन और कैजुअल डाइनिंग के लिए यहां दिल्ली–एनसीआर से लोग आते हैं। यहां का पिजा उतना ही प्रसिद्ध है जितना की दाल मखनी, मॉकटेल, वाटरमेलन मॉकटेल, बटर चिकन और बिरयानी। यहां का बेहतरीन माहौल जायके की लज्जत और बढ़ा देता है।
- **कहां** : 31–बी, पूसा रोड, राजिंदर नगर।
- **कब** : दोपहर 12 से रात 12 बजे तक।
- **प्रवेश** : प्रति दो व्यक्ति लगभग 1500 रुपये।

## रिलायंस जियो सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बनी

**नई दिल्ली :** एशिया के सबसे बड़े धनकुबेर मुकेश अंबानी नियंत्रित रिलायंस जियो देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम सेवा प्रदाता कंपनी बन गई है। टेलीकॉम नियामक ट्राई के मुताबिक कंपनी ने पिछले वर्ष नवंबर में 56 लाख ग्राहक जोड़े। इसके साथ देशभर में कंपनी के सब्सक्राइबर्स की तादाद 36.99 लाख पर पहुंच गई है। इस सब्सक्राइबर आधार के साथ मोबाइल सर्विसेज बाजार में कंपनी की हिस्सेदारी 32.04 प्रतिशत पर पहुंच गई है। (प्रेट्र)

फिजिकल रिटेल की अपनी खूबी और खामी है। वहीं डिजिटल की अपनी अलग खूबियां हैं। भविष्य में इन दोनों का मिलाजुला रूप यानी फिजिटल देखने को मिल सकता है।
— किशोर बियानी, एमडी एवं सीईओ, फ्यूचर ग्रुप

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सेंसेक्स | 41,932.56 | ▲ 59.83 | निफ्टी | 12,355.50 | ▲ 12.20 | सोना प्रति दस ग्राम | ₹ 40,458 | ▲ ₹43 | चांदी प्रति किलोग्राम | ₹ 47,406 | ▲ ₹209 |
| $ डॉलर | ₹ 70.93 | ▲ ₹0.11 | क्रूड (ब्रेंट) प्रति बैरल | $ 64.33 | | | | | | | |

**आसार** ▸ लाइसेंस शुल्क में कमी व इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक की स्थापना का एलान संभव

# टेलीकॉम को अब बजट से ही उम्मीद

### 1.47 लाख के बकायों के अलावा उद्योग पर है आठ लाख करोड़ रुपये का कर्ज

**जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली**

सुप्रीम कोर्ट से पुनर्विचार याचिका खारिज होने के बाद अब टेलीकॉम कंपनियों की सारी आस सरकार पर टिक गई है। उन्हें उम्मीद है कि सरकार आगामी बजट के जरिये उन्हें 1.47 लाख करोड़ रुपये के बकायों की अदायगी के साथ भारी कर्जों के दंश से राहत प्रदान कर सकती है। स्पेक्ट्रम लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज (एसयूसी) में कमी के जरिये ऐसा किया जा सकता है।

पिछले दिनो बजट से संबंधित बैठकों में टेलीकॉम उद्योग ने दूरसंचार विभाग के अधिकारियों के समक्ष अपनी समस्याएं रखी थीं। इसमें उन्होंने कर्जों के भारी बोझ के अलावा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के चलते 1.47 लाख करोड़ रुपये की तात्कालिक देनदारी से उद्योग पर टूटी मुसीबत का हवाला दिया था। कंपनियों ने कहा था कि यदि बजट में लाइसेंस फीस और एसयूसी की दरों से राहत नहीं दी गई तो उनके लिए आगामी स्पेक्ट्रम नीलामी में भाग लेना मुश्किल हो जाएगा। कंपनियां यदि भाग लेंगी भी तो बहुत कम स्पेक्ट्रम की खरीदारी करेंगी। इससे देश में टेलीकॉम सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण के साथ 5-जी सेवाओं की लांचिंग में विलंब हो सकता है।

टेलीकॉम उद्योग की प्रतिनिधि संस्था सीओएआइ के महानिदेशक मैथ्यू राजन के अनुसार 'उद्योग ने लाइसेंस फीस को मौजूदा आठ फीसद से घटाकर तीन फीसद करने तथा स्पेक्ट्रम यूजेज चार्ज एसयूसी को छह फीसद से घटाकर एक फीसद करने की मांग की है। हमें उम्मीद है कि बजट में लाइसेंस फीस में कमी की जाएगी।' सीओएआइ ने जीएसटी इनपुट टैक्स के 36 हजार करोड़ रुपये के बकायों का भुगतान करने के साथ टेलीकॉम उपकरणों पर ऊंची कर दरों को घटाने की भी सरकार से मांग की है।

दूरसंचार विभाग के साथ बैठक में टेलीकॉम कंपनियों ने सरकार ने टेलीकॉम उद्योग को कम ब्याज पर कर्ज की सुविधा के लिए एक इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक की स्थापना करने का सुझाव भी दिया है। यह बैंक टैक्स फ्री बांड जारी कर कर्ज के लिए धन जुटाएगा। माना जाता है कि वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण पहली फरवरी को बजट पेश करते वक्त इस संबंध में एलान कर सकती हैं।

टेलीकॉम कंपनियों पर इस समय संयुक्त रूप से लगभग आठ लाख करोड़ रुपये का कर्ज है। दिसंबर में दरों में बढ़ोतरी के बावजूद भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया को पिछली छमाही में भारी घाटा हुआ है। इस बीच बकायों के भुगतान के लिए भारती एयरटेल ने विभिन्न तरीकों से 21 हजार करोड़ रुपये की राशि जुटाने की प्रक्रिया पूरी कर ली है।

इस क्षेत्र में इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करने और उसका प्रबंध संभालने वाली कंपनियों ने भी दूरसंचार विभाग से बजट में राहत के बारे में अपनी मांगें साझा की हैं। टावर एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन ने कॉल ड्रॉप की समस्या से निपटने के लिए मोबाइल टावर में इस्तेमाल होने वाले उपस्करों पर शुल्कों में कमी किए जाने का सुझाव दिया है।

प्रतीकात्मक फोटो

### इंटरनेट कंपनियों पर मंडरा रहा बड़ा खतरा

**नई दिल्ली, प्रेट्र :** इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनियों ने सरकार से आग्रह किया है कि वह एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (एजीआर) को यथाशीघ्र दोबारा परिभाषित करे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मामले में टेलीकॉम कंपनियों की याचिका खारिज किए जाने के बाद इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनियों में भी खलबली मची है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (आइएसपीएआइ) के प्रेसिडेंट राजेश छड़िया ने कहा कि अगर सरकार ने एजीआर की परिभाषा तय नहीं की, तो छोटी इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनियां खत्म हो जाएंगी। यह टेलीकॉम उद्योग के लिए भयावह होगा, क्योंकि बाजार में सिर्फ दो कंपनियों का प्रभुत्व अच्छी बात नहीं है।

## तीन प्रतिशत की विकास दर को भी पार करेगा कृषि क्षेत्र

**जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली :** कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर को लेकर लगाई जा रही अटकलों के विपरीत यह क्षेत्र पिछले साल के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। नीति आयोग के सदस्य डॉ. रमेश चंद ने कहा, 'चालू वित्त वर्ष (2019-20) के दौरान कृषि क्षेत्र की विकास दर 3.1 फीसद पर पहुंच सकती है, जो पिछले साल के 2.9 फीसद से अधिक होगी।' डॉ. रमेश चंद गुरुवार को एसोचैम के एक कार्यक्रम में बोल रहे थे।

उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में इस क्षेत्र की विकास दर दो फीसद थी, जो 2018-19 में बढ़कर 2.9 फीसद हो गई। मौजूदा समय में कृषि क्षेत्र में निजी निवेश और प्रतिस्पर्धा की सख्त जरूरत है, जिससे इसका भला हो सकता है। कृषि क्षेत्र में निजी निवेश की आवश्यकता पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि देश का कृषि क्षेत्र आधुनिक खेती की ओर बढ़ रहा है। इसमें विकास तभी संभव है, जब निजी निवेश और प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। चंद ने निजी निवेश पर जोर देते हुए कहा, 'जब तक कृषि में बीज से लेकर बिक्री तक कॉरपोरेट सेक्टर की सहभागिता नहीं बढ़ेगी, तब तक क्रांति और किसानों की आमदनी को दोगुना करने का लक्ष्य प्राप्त करना कठिन होगा।' नीति आयोग इसके लिए केंद्र सरकार पर लगातार दबाव बना रहा है कि वह जल्दी से जल्दी भूमि पट्टेदारी का मॉडल कानून राज्यों को अपनाने के लिए तैयार करे।

## तकनीक पर ही साइकिल उद्योग की रफ्तार संभव

- बजट में साइकिल उद्योग ने मांगा बराबरी की स्पर्धा का माहौल
- जीएसटी की अनियमितताओं को दूर किए बिना करोबार संभव नहीं

**राजीव शर्मा, लुधियाना**

तकनीक के अभाव में साइकिल उद्योग की रफ्तार लगातार धीमी हो रही है। इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि 2001 में देश में 1.31 करोड़ और चीन में 5.5 करोड़ साइकिल का उत्पादन होता था। आज चीन में उत्पादन 17 करोड़ यूनिट सालाना के पार हो गया है। जबकि 19 साल के लंबे अंतराल के बाद देश में यह आंकड़ा केवल 1.75 करोड़ तक ही पहुंच पाया है। इसमें भी 50 लाख से अधिक साइकिलें विभिन्न राज्य सरकारें स्कूली छात्राओं को देने के लिए टेंडरों के जरिये खरीद रही हैं।

इसके अलावा साइकिल एवं पार्ट्स का विदेश से आयात बढ़ रहा है। 2018-19 में साइकिल एवं पार्ट्स का आयात करीब 2,200 करोड़ रुपये के आसपास रहा। आंकड़े जाहिर करते हैं कि घरेलू साइकिल मार्केट की ग्रोथ को आयात खा रहा है। नतीजतन साइकिल उद्योग के लिए घरेलू बाजार भी मुट्ठी से रेत की तरह फिसल रहा है। साइकिल उद्यमियों ने मांग की है कि बजट में साइकिल को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष पैकेज दिया जाए। इसके अलावा टेक्नोलॉजी बढ़ाने के उपाय किए जाएं। इंडस्ट्री के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड उपलब्ध कराई जाए, ताकि बाजार की चुनौतियों का डट कर मुकाबला कर सकें। उद्यमियों का तर्क है कि लुधियाना साइकिल उद्योग का गढ़ है। यहां पर साइकिल एवं पार्ट्स के करीब 4,500 यूनिट्स हैं। साइकिल उद्योग का सालाना कारोबार 7000 करोड़ से अधिक का है। 95 फीसद से अधिक इकाईयां सुक्ष्म, लघु व मध्यम सेक्टर में स्थापित हैं। संसाधनों की कमी के कारण छोटी इकाईयां बाजार के साथ कदमताल नहीं मिला पा रही हैं।

फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशंस (फियो) के आंकड़ों के मुताबिक देश में साइकिल एवं पार्ट्स का आयात वर्ष 2017-18 में 21.7 करोड़ डॉलर (करीब 1,541 करोड़ रुपये) मूल्य का था, जो वर्ष 2018-19 में बढ़कर 21.99 करोड़ डॉलर (करीब 1,562 करोड़ रुपये) पर पहुंच गया। इसी तरह साइकिल एवं पार्ट्स का निर्यात वर्ष 2017-18 में 25.38 करोड़ डॉलर (करीब 1,802 करोड़ रुपये) था, जो वर्ष 2018-19 में बढ़कर 30.14 करोड़ डॉलर (2,140 करोड़ रुपये) पर पहुंच गया। साइकिल के अलावा व्हील, रिम, स्पोक, हब, ब्रेक, पैडल एवं सेडल का ज्यादा आयात किया जा रहा है।

**तकनीक के अभाव में हाई-एंड साइकिलों के पुर्जे हो रहे आयात : आरडी शर्मा :** इंडियन बाईसाइकिल मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन के प्रधान एवं हाईबर्ड साइकिल्स के सीएमडी आरडी शर्मा का कहना है कि बदलते दौर में हाई-एंड साइकिलों का मार्केट बढ़ रहा है। मगर, तकनीक की कमी के कारण ज्यादातर हाई-एंड साइकिल एवं पुर्जे आयात किए जा रहे हैं। इसके लिए उद्योग को विश्व स्तरीय तकनीक की जरूरत है। ऐसे में सरकार तकनीक को प्रोत्साहित करने के लिए सहूलियतें एवं सब्सिडी दे। एमएसएमई सेक्टर में फंड की किल्लत को दूर करने के लिए बैंकों को निर्देश दिए जाएं कि वे आसान शर्तों पर इंडस्ट्री को ऋण मुहैया कराएं। इसके अलावा निर्यात को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त इनसेंटिव दिए जाएं।

### उद्योग को सस्ते दाम पर स्टील मुहैया हो : केके सेठ

फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल आर्गनाइजेशन के चेयरमैन एवं नीलम साइकिल्स के एमडी केके सेठ का कहना है कि कच्चे माल स्टील के दामों में अस्थिरता में छोटी इंडस्ट्री संभल नहीं कर पाती। छोटे उद्योगों के लिए सरकार एक प्लेटफॉर्म तैयार करे और सस्ते दाम पर स्टील मुहैया कराया जाए। इसके अलावा सस्ते आयात को नियंत्रित करने के ठोस उपाय किए जाएं।

### जीएसटी की विसंगतियां दूर की जाएं : चावला

यूनाइटेड साइकिल एंड पार्ट्स मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डीएस चावला का कहना है कि बजट में जीएसटी से संबंधित विसंगतियों को दूर किया जाए। साइकिल एवं पार्ट्स पर जीएसटी की दर पांच फीसद की जाए। कॉरपोरेट की तर्ज पर पार्टनरशिप एवं प्रोपराइटर इकाइयों को भी राहत दी जाए। अपग्रेडेशन के लिए टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड का लाभ दिया जाए।

## न्यूज गैलरी

### बाथरूम एसेसरीज सेग्मेंट में वेक्टस इंडस्ट्रीज के कदम

**नई दिल्ली :** वाटर स्टोरेज टैंक और पाइपिंग सिस्टम क्षेत्र की अग्रणी कंपनी वेक्टस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने बाथरूम एसेसरीज सेग्मेंट में कदम रखा है। कंपनी ने इसकी शुरुआत सिस्टर्न टैंक और टॉयलेट सीट कवर के साथ की है। इसके तहत कंपनी ने चार प्रकार के सिस्टर्न टैंक और तीन प्रकार के टॉयलेट सीट कवर लांच किए हैं। इस बारे में कंपनी के डायरेक्टर आशीष बाहेती ने कहा कि वाटर स्टोरेज टैंक और पाइपिंग सिस्टम में हमारा वर्षों का अनुभव है। हमें उम्मीद है कि नए सेग्मेंट में भी हम ग्राहकों को कई विकल्प उपलब्ध कराने और उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने में पूरी तरह सफल होंगे। कंपनी के पास देशभर में 4,300 से अधिक डीलरों और वितरकों का नेटवर्क है। (वि.)

### पिछले वर्ष कंपनियों ने आइपीओ से जुटाए करीब 17,900 करोड़ रुपये

**नई दिल्ली :** पिछले वर्ष भारतीय कंपनियों ने प्रारंभिक पब्लिक ऑफर (आइपीओ) के माध्यम से करीब 17,900 करोड़ रुपये जुटाए हैं। इनमें से पिछले वर्ष की चौथी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर, 2019) में 12 आइपीओ से 34 करोड़ डॉलर यानी 2,400 करोड़ रुपये जुटाए गए। ईवाई की एक रिपोर्ट के अनुसार आइपीओ की संख्या के हिसाब से घरेलू शेयर बाजारों का दुनियाभर में सातवां स्थान रहा। 'ईवाई इंडिया आइपीओ ट्रेंड्स रिपोर्ट : क्यू-4 2019' में कहा गया है कि पिछले वर्ष कुल 62 आइपीओ आए। (प्रेट्र)

## ऑफिस स्पेस लीजिंग में नरमी का संकेत

**नई दिल्ली, प्रेट्र :** देश के छह प्रमुख शहरों में ऑफिस किराए पर लेने की गतिविधियों में इस साल नरमी रह सकती है। 2019 में इस क्षेत्र में 22 फीसद की वृद्धि दर्ज की गई थी। इस दौरान ऑफिस स्पेस मार्केट 5.77 करोड़ वर्ग फीट के स्तर को पार कर गया। 2020 में यह वृद्धि दर सात से आठ फीसद पर ठहर सकती है।

ब्रिटेन की प्रॉपर्टी कंसल्टेंट सेविल्स ने इस संबंध में रिपोर्ट जारी की है। सेविल्स इंडिया के सीईओ अनुराग माथुर ने कहा कि 2020 में ऑफिस स्पेस लीजिंग 6.1 करोड़ वर्ग फीट तक पहुंच सकती है। रिपोर्ट में पाया गया कि किराए पर लिए गए ऑफिस स्पेस में 40 फीसद हिस्सेदारी अमेरिकी कंपनियों की रही। यूरोपीय व स्थानीय कंपनियों की हिस्सेदारी 30-30 फीसद रही।

2019 में हैदराबाद में ऑफिस स्पेस लीजिंग 53 फीसद बढ़कर 95 लाख वर्ग फीट पर पहुंच गई। चेन्नई में यह 60 फीसद बढ़कर 80 लाख वर्ग फीट रही। दिल्ली-एनसीआर में ऑफिस स्पेस लीजिंग 14 फीसद बढ़कर 1.09 करोड़ वर्ग फीट रही। बेंगलुरु में 15 फीसद बढ़कर यह 1.56 करोड़ वर्ग फीट रही।

## लुक ईस्ट नहीं, एक्ट ईस्ट पर दिया जोर : अनुराग ठाकुर

**जागरण संवाददाता, कोलकाता**

- बोले केंद्रीय मंत्री - ईमानदारी से बैर नहीं और बेईमानों की खैर नहीं
- ठाकुर ने कहा - हमने लिए कई बड़े और कड़े निर्णय

आम बजट पेश होने से पहले केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने मौजूदा वित्तीय संकट व व्यापारी वर्ग को पेश आ रही तमाम समस्याओं के समाधान पर उनसे राय मांगी। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारें 'लुक ईस्ट' नीति पर केवल चर्चा करती थीं, लेकिन हम 'एक्ट ईस्ट' नीति के साथ पूर्वी भारत के विकास को अग्रसर हैं। इसके लिए हमने कई बड़े और कड़े निर्णय भी लिए हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्योगपतियों से मुलाकात कर मौजूदा आर्थिक समस्याओं को लेकर उनके सुझावों पर गौर किया है। हम देश की जनता से सुझाव ले भविष्य की बेहतरी को काम करने में विश्वास करते हैं। ठाकुर कोलकाता में मर्चेंट्स चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, भारत चैंबर ऑफ कॉमर्स, कलकत्ता चैंबर ऑफ कॉमर्स, डीटीपीए और एसीएई के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित एक विशेष परिचर्चा सत्र को संबोधित कर रहे थे।

राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि नोटबंदी के बाद बाद आज 11.5 करोड़ लोग नियमित रूप से टैक्स का भुगतान कर देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। यह हमारी उपलब्धि है, क्योंकि हमने लोगों को ईमानदार बनाया है। हम 'ईमानदारी से बैर नहीं और बेईमानों की खैर नहीं' में यकीन रखते हैं।

वित्त राज्यमंत्री ने कहा कि अगले पांच वर्षों में पांच लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल करने के लिए हर नागरिक को अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। हमारी सरकार आने से पहले बैंकों ने करीब 58 लाख करोड़ रुपये के कर्ज बांट दिए थे, लेकिन हमने एनपीए को स्वच्छ करने के साथ ही 10 सरकारी बैंकों का विलय कर चार बड़े बैंक बनाने का फैसला किया, ताकि आर्थिक मोर्चे पर देश को मजबूत बनाया जा सके।

## आइएलएफएस मामले में आय के बंटवारे का फॉर्मूला देगा एनक्लैट

**नई दिल्ली, प्रेट्र :** कर्ज में डूबे आइएलएंडएफएस समूह की कंपनियों के कर्जदाताओं के बीच आय के बंटवारे को लेकर नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (एनक्लैट) फॉर्मूला सुझाएगा। ट्रिब्यूनल ने गुरुवार को यह बात कही। एनक्लैट के चेयरपर्सन जस्टिस एसजे मुखोपाध्याय की पीठ ने कहा कि इस फॉर्मूले में कर्जदाताओं समेत सभी हिस्सेदारों के हितों का ध्यान रखा जाएगा। आइएलएंडएफएस समूह पर कुल कर्ज 90,000 करोड़ रुपये से ज्यादा है। ट्रिब्यूनल ने कुछ कर्जदाताओं को कंपनी के रिजॉल्यूशन में अपनी स्थिति बताते हुए कॉरपोरेट मामले मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित नए फ्रेमवर्क में हफ्तेभर के भीतर जानकारी देने को कहा है।

**जेएसडब्ल्यू स्टील मामले में एनक्लैट ने मांगी जानकारी :** एनक्लैट ने भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड (बीपीएसएल) मामले में सफल बोलीकर्ता जेएसडब्ल्यू स्टील के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), एसएफआइओ और सीबीआइ जैसी जांच एजेंसियों से जानकारी मांगी है।

## भारत के ई-कॉमर्स मार्केट में विक्रेता और खरीदार पूरी तरह स्वतंत्र

▸ प्रथम पृष्ठ से आगे

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस में विदेशी निवेश की अनुमति देता है और इस मॉडल में विक्रेता व खरीदार पूरी तरह स्वतंत्र होते हैं। मार्केट प्लेस कंपनियां अपनी इन्वेंटरी नहीं बना सकती हैं, न ही उन्हें कीमतें निर्धारित करने का अधिकार है। गोयल ने कहा, 'भारत में ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस बिजनेस के लिए स्थापित नियम हैं। जब तक लोग इन नियमों का पालन करते हैं, हम इनका स्वागत करते रहेंगे।' हालांकि गोयल ने यह स्पष्ट किया कि ई-कॉमर्स कंपनियां कारोबार के गलत तरीके अपना रही हैं या नहीं, यह जांच अधिकारी ही तय करेंगे। जांच के नतीजों का सबको सम्मान करना चाहिए।

**सीसीआइ कर रहा जांच :** फेयर ट्रेड नियामक भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआइ) ने हाल ही में बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियों फ्लिपकार्ट और अमेजन पर कारोबार के गलत तरीके अपनाने, बहुत ज्यादा डिस्काउंट देने और कुछ विक्रेताओं को बढ़ावा देने के आरोपों पर जांच का आदेश दिया है। भारत में मल्टी ब्रांड रिटेल में 49 फीसद प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ) की अनुमति है।

**कारोबारी मसले सुलझा लेंगे भारत-अमेरिका :** वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि अमेरिका के साथ कारोबारी मसलों को सुलझाने पर बातचीत अगले चरण में है। दोनों देश अपने कारोबारी संबंधों को विस्तार दे सकते हैं, जिससे आगे चलकर मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) का रास्ता बनने की उम्मीद है। गोयल ने कहा कि दोनों देश बड़े कारोबारी साझेदार हैं और द्विपक्षीय व्यापार को और बढ़ा सकते हैं।

## पहली बार 42,000 को पार कर लौटा सेंसेक्स

- अमेरिका और चीन के बीच कारोबारी समझौते पर हस्ताक्षर से दुनियाभर के बाजारों में दिखी राहत
- सेंसेक्स 59.83, निफ्टी 12.20 अंकों की मजबूती के साथ हुए बंद

**मुंबई, प्रेट्र :** अमेरिका-चीन में पहले चरण की कारोबारी सहमति पर हस्ताक्षर के चलते घरेलू शेयर बाजारों में निवेशकों ने खुलकर दांव लगाया। दुनियाभर के बाजारों में दिख रही राहत का इशारा पाकर बीएसई का 30-शेयरों वाला प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स पहली बार इंट्रा-डे में 42,000 का मनोवैज्ञानिक स्तर पार कर 42,059.45 अंक तक गया। हालांकि कारोबार के आखिर में यह थोड़ा फिसलकर 59.83 अंकों यानी 0.14 प्रतिशत की बढ़त के साथ 41,932.56 अंक पर स्थिर हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का 50-शेयरों वाला प्रमुख सूचकांक निफ्टी भी गुरुवार को इंट्रा-डे में 12,389.05 अंकों के सर्वकालिक उच्च स्तर तक गया। कारोबार के आखिर में निफ्टी 12.20 अंकों यानी 0.10 प्रतिशत की मजबूती के साथ 12,355.50 अंक पर बंद हुआ।

सेंसेक्स पैक में गुरुवार को सबसे ज्यादा 3.23 प्रतिशत का उछाल नेस्ले इंडिया के शेयरों में दर्ज किया गया। कोटक महिंद्रा बैंक, एचयूएल, भारती एयरटेल, आरआइएल, टीसीएस, पावरग्रिड और टाइटन के शेयर भी मजबूती के साथ बंद हुए। हालांकि सेंसेक्स पैक के 18 स्टॉक्स को गिरावट का सामना करना पड़ा, लेकिन 12 स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी के चलते यह चढ़कर बंद हुआ। सेक्टोरल इंडेक्स के मामले में बीएसई के रियल्टी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, हेल्थकेयर, टेलीकॉम, एफएमसीजी, एनर्जी और ऑटो इंडेक्स बढ़त के साथ बंद हुए। बीएसई मिडकैप और स्मॉलकैप इंडेक्स में भी 0.78 प्रतिशत तक की मजबूती देखी गई।

दिन के कारोबार के बारे में जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के रिसर्च प्रमुख विनोद नायर का कहना था कि पिछले करीब एक महीने के दमदार प्रदर्शन के बाद घरेलू शेयर बाजार थोड़े सुस्ताते दिख रहे हैं। प्रमुख सूचकांकों को बड़ी कंपनियों के तिमाही नतीजों का इंतजार करते देखा जा सकता है। विदेशी मोर्चे पर अमेरिका-चीन में पहले चरण के कारोबारी समझौते पर हस्ताक्षर होने और भारतीय बाजार में महंगाई दर के एकदम से बढ़ जाने का असर घरेलू बाजारों पर दिखेगा। एशिया के अन्य प्रमुख बाजारों में शंघाई को छोड़कर सभी प्रमुख बाजार हरे निशान पर बंद हुए।

### सोना 43 रुपये संभला, चांदी 209 रुपये उछली

**नई दिल्ली, प्रेट्र :** डॉलर के मुकाबले रुपये के टूटने के चलते घरेलू सराफा बाजारों में गुरुवार को सोना 43 रुपये संभलकर 40,458 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। चांदी भी 209 रुपये के उछाल के साथ 47,406 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। एचडीएफसी सिक्युरिटीज के सीनियर एनालिस्ट (कमोडिटीज) तपन पटेल ने कहा कि मकर संक्रांति के बाद खरीदारी बढ़ने और रुपये के अवमूल्यन के चलते निवेशकों ने बहुमूल्य धातुओं की खरीद बढ़ाई। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में सोना 1,553 डॉलर और चांदी 17.87 डॉलर प्रति औंस (28.35 ग्राम) के लगभग सपाट स्तर पर बिक रहे थे। इस बीच, सरकार ने सोने की ज्वैलरी और कलाकृतियों की अनिवार्य हॉलमार्किंग की अधिसूचना बुधवार को जारी कर दी। यह नियम अगले वर्ष 15 जनवरी से लागू होगा। इसके उल्लंघन पर ज्वैलर्स को सजा मिलेगी। नए नियमों के मुताबिक ज्वैलर्स को अब 14, 18 और 22 कैरेट के हॉलमार्किंग वाले स्वर्ण आभूषण और कलाकृतियां बेचने की इजाजत होगी। इससे पहले ज्वैलर्स 10 ग्रेड के स्वर्ण आभूषणों की बिक्री कर सकते थे।

## जनमत मुद्दा

**क्या सभी आर्थिक-सामाजिक हैसियत वाले लोगों को खुश करने वाला बजट पेश करना संभव है?**

mudda@jagran.com पर आप अपनी राय हमें भेज सकते हैं। मोबाइल से मैसेज भी कर सकते हैं।

**बड़ा कदम**

कार्ड के इस्तेमाल को ज्यादा सुरक्षित व सुविधाजनक बनाने के लिए रिजर्व बैंक का निर्देश, बैंकों को अपने कार्ड के इस्तेमाल से संबंधित पूरा नियंत्रण यूजर्स के हाथ में देने को कहा

## ग्राहकों को क्रेडिट, डेबिट कार्ड स्विच ऑफ करने की सुविधा दें बैंक

**नई दिल्ली, आइएएनएस :** आने वाले दिनों में आप अपनी जरूरत के हिसाब से अपने डेबिट और क्रेडिट कार्ड को डिसेबल और इनेबल कर पाएंगे। रिजर्व ने इस संबंध में सभी बैंकों को निर्देश दिया है। इससे कार्ड का इस्तेमाल सुविधाजनक और ज्यादा सुरक्षित होगा।

पिछले कुछ साल में देश में डिजिटल लेनदेन तेजी से बढ़ा है। लोग नकदी के स्थान पर क्रेडिट या डेबिट कार्ड के इस्तेमाल को लेकर जागरूक हो रहे हैं। इस बढ़ते कैशलेस लेनदेन के साथ ही डिजिटल फ्रॉड के मामले भी बढ़े हैं। इस तरह के फ्रॉड पर लगाम लगाने की दिशा में रिजर्व बैंक का यह निर्देश बेहद कारगर साबित हो सकता है। इस निर्देश के तहत सभी नए कार्ड में केवल देश के भीतर किसी पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) या एटीएम पर स्वाइप करते हुए इस्तेमाल की सुविधा ही इनेबल रहेगी। नया कार्ड ऑनलाइन या कॉन्टेक्टलेस लेनदेन में प्रयोग नहीं किया जा सकेगा। लेनदेन के अन्य तरीकों में इस्तेमाल के लिए बाद में ग्राहक खुद ही कार्ड को इनेबल कर सकेंगे। ग्राहक अपनी जरूरत को देखते हुए यह भी तय कर सकेगा कि कब किस माध्यम से कार्ड की कितनी लिमिट का इस्तेमाल किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर किसी क्रेडिट कार्ड की लिमिट चाहे जितनी हो, ग्राहक अपने हिसाब से यह तय कर सकेगा कि लिमिट का कितना हिस्सा ऑनलाइन या किसी अन्य माध्यम से लेनदेन में इस्तेमाल हो। देश या देश के बाहर लेनदेन के सभी माध्यमों के लिए लेनदेन की अलग-अलग लिमिट तय करने की सुविधा रहेगी। रिजर्व बैंक की ओर से जारी इस सर्कुलर के निर्देश प्रीपेड गिफ्ट कार्ड या मास ट्रांजिट सिस्टम पर इस्तेमाल होने वाले कार्ड के मामले में बाध्यकारी नहीं होंगे।

कार्ड की लिमिट का कितना हिस्सा लेनदेन में इस्तेमाल हो, ग्राहक यह भी तय कर सकेगा। प्रतीकात्मक फोटो

**आसानी से उपलब्ध होगी सुविधा :** रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि कार्ड के इस्तेमाल की लिमिट तय करने से लेकर उसे इनेबल या डिसेबल करने तक की सभी सुविधाएं ग्राहक को मोबाइल एप्लीकेशन, इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम या आइवीआर के जरिये उपलब्ध कराई जाएं। यहां तक कि ग्राहकों को बैंक शाखाओं में जाकर भी अपना कार्ड इनेबल या डिसेबल कराने की सुविधा मिलेगी। कार्ड के स्टेटस में किसी भी बदलाव के तुरंत बाद ग्राहक को एसएमएस या ईमेल से अलर्ट देना भी बैंकों की जिम्मेदारी रहेगी।

**तीन श्रेणियों में बांटा गया है लेनदेन का तरीका :** कार्ड को इनेबल या डिसेबल करने के मामले में लेनदेन के तरीकों को तीन श्रेणियों में बांटा गया है। पहला, कार्ड नॉट प्रजेंट यानी ऑनलाइन लेनदेन, दूसरा, कार्ड प्रजेंट यानी कार्ड को स्वाइप करते हुए इस्तेमाल करना और तीसरा, कॉन्टेक्टलेस यानी कार्ड को स्वाइप किए बिना होने वाला लेनदेन। कार्ड नॉट प्रजेंट के मामले में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों तरह के लेनदेन को इनेबल या डिसेबल करने का विकल्प मिलेगा। कार्ड प्रजेंट के मामले में घरेलू लेनदेन एक्टिव रहेगा लेकिन अंतरराष्ट्रीय लेनदेन को इनेबल या डिसेबल करने की सुविधा रहेगी। कॉन्टेक्टलेस लेनदेन भी इनेबल या डिसेबल किया जा सकेगा, जो एक साथ घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों जगहों पर लेनदेन के मामले में प्रभावी रहेगा।

**मौजूदा कार्ड भी होंगे डिसेबल**

अभी जिस कार्ड को कभी ऑनलाइन (कार्ड नॉट प्रजेंट), अंतरराष्ट्रीय या कॉन्टेक्टलेस लेनदेन में इस्तेमाल नहीं किया है, उस मौजूदा कार्ड को भी बैंकों को अनिवार्य रूप से डिसेबल करना होगा। जरूरत होने पर यूजर इन सुविधाओं को इनेबल करा सकेंगे।

**कुछ बैंक दे रहे हैं सुविधा**

एक्सिस बैंक, आइसीआइसीआइ और आरबीएल जैसे कुछ बैंक अपने ग्राहकों को इस तरह की सुविधा दे रहे हैं। ग्राहक इन बैंकों के मोबाइल एप का इस्तेमाल करते हुए कार्ड के उपयोग को नियंत्रित कर सकते हैं।

## होंडा ने बीएस-6 उत्सर्जन मानक वाली एक्टिवा-6जी लांच की

**नई दिल्ली, (वि.) :** होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया लिमिटेड (एचएमएसआइ) ने बीएस-6 उत्सर्जन मानक वाली नई एक्टिवा-6जी लांच की है। इसकी शुरुआती कीमत 63,912 रुपये (एक्स-शोरूम दिल्ली) तय की गई है। ग्राहकों के लिए एक्टिवा-6जी अगले कुछ हफ्ते में उपलब्ध हो जाएगी।

एचएमएसआइ प्रेसिडेंट और सीईओ मिनोरू कातो ने कहा, 'नए उत्सर्जन मानक अनिवार्य किए जाने के नियमन से काफी पहले ही होंडा ने एक्

**05** हजार ऊंटों को मौत के घाट उतार दिया गया है ऑस्ट्रेलिया में। दरअसल, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया सूखे की समस्या से गुजर रहा है। बड़ी संख्या में ऊंट गांवों की तरफ आ रहे हैं, जिससे गांवों में मौजूद सीमित भोजन और जल संसाधनों पर खतरा मंडरा रहा था।



# मुशर्रफ ने मौत की सजा को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

- देशद्रोह मामले में विशेष अदालत का फैसला रद करने की अपील की

**इस्लामाबाद, प्रेट्र :** पाकिस्तान के पूर्व सैन्य शासक परवेज मुशर्रफ ने देशद्रोह मामले में विशेष अदालत के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उन्होंने गुरुवार को दाखिल अपनी अर्जी में विशेष अदालत के फैसले को रद करने की अपील की है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गठित विशेष अदालत की तीन जजों वाली पीठ ने गत 17 दिसंबर को मुशर्रफ को देशद्रोह का दोषी करार देते हुए मौत की सजा सुनाई थी।

डॉन अखबार के अनुसार, 74 वर्षीय पूर्व सेना प्रमुख मुशर्रफ के वकील की ओर से सुप्रीम कोर्ट में 90 पेज की अर्जी दाखिल की गई है। इसमें बताया गया है कि विशेष अदालत में मुशर्रफ की अनुपस्थिति इरादतन नहीं थी। वह खराब सेहत के कारण अदालत में पेश नहीं हो पा रहे थे। मुशर्रफ को बीमार मानने के बावजूद विशेष अदालत ने उनकी अनुपस्थिति में फैसला सुना दिया। इसके पहले बीते सोमवार को लाहौर हाई कोर्ट ने मुशर्रफ की अपील पर विशेष अदालत के फैसले को असंवैधानिक करार दिया था। कोर्ट ने कहा था कि मुशर्रफ के खिलाफ देशद्रोह का मामला कानून के नजरिए से सही तरीके से नहीं तैयार किया गया था। बीते दिनों उनकी एक फोटो वायरल हुई थी जिसमें वे दुर्बल नजर आ रहे थे।

### यह है मामला

वर्ष 2007 में पाकिस्तान पर आपातकाल थोपने, संविधान को निलंबित करने और जजों को हिरासत में रखने के आरोप में मुशर्रफ के खिलाफ 2013 में मुकदमा दर्ज किया गया था। यह मुकदमा तत्कालीन नवाज शरीफ सरकार की ओर से दर्ज कराया गया था। मामले में खुद को घिरते देख मुशर्रफ इलाज के बहाने 18 मार्च, 2016 को दुबई चले गए थे। तब से वह अपने मुल्क नहीं लौटे।

# प्रिंस हैरी ने शाही हैसियत से निभाई आखिरी जिम्मेदारी

- शाही दर्जा खत्म होने की घोषणा के बाद पहली बार आए लोगों के बीच
- बकिंघम पैलेस के पार्क में बच्चों के रग्बी लीग मैच में बतौर अतिथि पहुंचे

**लंदन, रायटर :** ब्रिटेन में प्रिंस हैरी अपना शाही दर्जा छोड़ने की घोषणा के बाद गुरुवार को पहली बार लोगों के बीच आए। पौत्र प्रिंस हैरी और उनकी अमेरिकी पत्नी मेगन की इच्छानुसार महारानी एलिजाबेथ ने वरिष्ठ शाही सदस्य का दर्जा छोड़ने का उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। शाही दंपती अब अपने लिए स्वतंत्र भूमिका की तलाश में हैं।

ब्रिटेन के सिंहासन के छठे नंबर के दावेदार प्रिंस हैरी ने गुरुवार को बकिंघम पैलेस के गार्डेन में बच्चों को रग्बी का लीग मैच खेलते देखा। ये बच्चे अगले साल होने वाले विश्व कप के लिए तैयारी कर रहे थे। प्रिंस हैरी के लिए शाही अतिथि के रूप में जिम्मेदारी निभाने का यह आखिरी मौका था। पिछले हफ्ते प्रिंस हैरी (35) और उनकी पत्नी मेगन (38) ने अपनी शाही जिम्मेदारी को छोड़ने की इच्छा जताई थी। वे अपना ज्यादा समय अमेरिका में गुजारना चाहते हैं, जहां वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने के लिए कुछ काम करना चाहते हैं। शाही दंपती की यह इच्छा महारानी और बाकी के शाही परिवार के लिए झटके जैसी थी। सोमवार को सैंड्रिंघम एस्टेट में परिवार ने बैठकर हालात पर विचार किया। इस बैठक में महारानी एलिजाबेथ के अलावा प्रिंस हैरी, उनके बड़े भाई प्रिंस विलियम और उनके पिता प्रिंस चार्ल्स शामिल हुए थे। बैठक में तय हुआ कि प्रिंस हैरी और उनकी पत्नी ब्रिटेन, कनाडा और अमेरिका में इच्छानुसार अपना समय व्यतीत कर सकते हैं।

ब्रिटेन के प्रिंस हैरी शाही पद छोड़ने की घोषणा के बाद गुरुवार को पहली बार सार्वजनिक तौर पर नजर आए। उन्होंने बकिंघम पैलेस के एक पार्क में आयोजित रग्बी लीग मैच में शाही अतिथि के रूप में आखिरी बार जिम्मेदारी निभाई। इस मौके पर उन्होंने टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले 21 देशों के प्रतिनिधियों और स्कूली बच्चों से मुलाकात भी की। रायटर

बैठक के बाद 93 वर्षीय महारानी ने गैर परंपरागत दुर्लभ बयान जारी कर कहा, हम चाहते थे कि दंपती शाही परिवार का हिस्सा बने रहें। लेकिन हम उनकी ज्यादा स्वतंत्र जीवन जीने की इच्छा का भी सम्मान करते हैं। इसलिए उन्हें शाही परंपराओं से बाहर जाने की अनुमति देते हैं। जबकि शाही दंपती ने कहा, वे जीवन में प्रगतिवादी नई भूमिका अपनाना चाहते हैं। नई भूमिका में वह अपने लिए धन भी कमाना चाहते हैं और हैसियत भी बनाना चाहते हैं। मेगन इस समय अपने बेटे आर्ची के साथ कनाडा में हैं जबकि हैरी कुछ औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए फिलहाल ब्रिटेन में हैं। कनाडा में मेगन मर्केल ने वैंकुवर शहर के डाउन टाउन ईस्ट साइड वीमेंस सेंटर में जाकर समस्याओं से जूझ रही महिलाओं का हौसला बढ़ाया, उन्हें समर्थन दिया।

## मेगन मर्केल के पिता की कोर्ट में हो सकती है पेशी

**लंदन, प्रेट्र :** ब्रिटेन में डचेज ऑफ ससेक्स मेगन मर्केल से जुड़े एक कानूनी मामले में उनके पिता को कोर्ट में पेश होना पड़ सकता है। मेगन ने पिता को लिखे पत्र को सार्वजनिक करने पर मेल ऑन सनडे अखबार के खिलाफ निजता के उल्लंघन, निजी सूचना को सार्वजनिक करने आदि का मुकदमा किया है।

ब्रिटेन के प्रिंस हैरी की पत्नी व पूर्व टेलीविजन स्टार मेगन ने शादी के तीन महीने बाद अपने पिता को ये पत्र लिखे थे। इन पत्रों के अखबार में प्रकाशित होने के बाद अक्टूबर 2019 में मेगन के वकीलों ने लंदन की कोर्ट में मुकदमा दायर कर प्रकाशक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। याचिका में यह भी कहा गया है कि अखबार समूह डचेज ऑफ ससेक्स मेगन और उनके पति प्रिंस हैरी के खिलाफ अमर्यादित खबरें प्रकाशित करता रहा है और शाही दंपती को बेवजह निशाना बनाता रहा है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान अखबार के अधिवक्ता ने मेगन के पिता को तलब करने का अनुरोध किया है।

## न्यूज गैलरी

### गुलाम कश्मीर में 18 घंटे से बर्फ में दबी लड़की जिंदा मिली

नीलम वैली में हुए हिमस्खन के घायलों को मुजफ्फराबाद के अस्पताल की ओर ले जाते बचवादल की सदस्य। एएफपी

**मुजफ्फराबाद :** पाकिस्तान के कब्जे वाले गुलाम कश्मीर के नीलम घाटी इलाके में हिमस्खलन के कारण भारी बर्फ के नीचे दबी 12 साल की लड़की को जिंदा बचा लिया गया है। समीना बीबी नाम की यह लड़की हिमस्खलन में तबाह हो चुके अपने घर में 18 घंटे से दबी पड़ी थी। बचावकर्मियों ने जब उसे बाहर निकाला उसके मुंह से खून निकल रहा था और उसका एक पैर भी टूट गया था। मुश्किल हालात में उसका बचना किसी चमत्कार से कम नहीं है। समीना का फिलहाल मुजफ्फराबाद के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है। डॉक्टरों ने अब उसे खतरे से बाहर बताया है। समीना की मां शहनाज बीबी ने बताया कि हिमस्खलन की इस घटना में उनके दो बच्चों की मौत हो गई है। समीना के बारे में भी उन्हें आशंकाओं ने घेर रखा था। मंगलवार को हिमस्खलन के वक्त शहनाज के तीन मंजिले मकान में कई लोग सर्दी से बचने को अलाव जलाकर बैठे थे तभी अचानक हादसा हो गया। पाकिस्तान में भीषण बर्फबारी के कारण 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अकेले गुलाम कश्मीर में 76 लोगों की जान जा चुकी है। (एएनआइ)

### गफूर को हटा बाबर को बनाया पाकिस्तानी सेना का प्रवक्ता

**नई दिल्ली :** पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता के रूप विवादित छवि बनाने वाले मेजर जनरल आसिफ गफूर को गुरुवार को उनके पद से हटा दिया गया। उनके स्थान पर मेजर बाबर इफ्तिखार को प्रवक्ता बनाया गया है। गफूर ने अपने तीन साल के कार्यकाल में जारी ट्वीट डिलीट करने और गलत जानकारियां देने के चलते कई बार हास्यास्पद स्थिति झेली। सोशल मीडिया पर उनकी खिंचाई भी हुई। सेना के प्रवक्ता के रूप में उन्होंने भारतीय अभिनेत्री दीपिका पादुकोण के दिल्ली में नकाबपोशों के हमले के बाद जेएनयू जाने के कदम का समर्थन किया। इस राजनीतिक बयान के लिए उनकी काफी खिंचाई भी हुई। आशिफ गफूर को पाकिस्तानी सेना की 40 वीं इन्फेंट्री डिवीजन का कमांडिंग ऑफिसर बनाया गया है। यह डिवीजन पंजाब के ओकरा में तैनात है, जो भारतीय सीमा के नजदीक का इलाका है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा इस आशय की घोषणा की। गफूर अब जल्द ही अपनी नई जिम्मेदारी संभालेंगे। (एएनआइ)

# पुतिन की पसंद के मिशस्टीन बने रूस के नए प्रधानमंत्री

**बड़ा बदलाव** ▸ पूर्व राजस्व अधिकारी के नाम पर पार्टी की मुहर

## रूसी राष्ट्रपति ने फिर साबित की सत्ता पर मजबूत पकड़

**मॉस्को, रायटर :** रूस में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी मजबूत राजनीतिक पकड़ साबित करते हुए गुरुवार को प्रधानमंत्री पद के लिए मिखाइल मिशस्टीन का नाम प्रस्तावित किया। चंद मिनटों में ही उनके नाम पर पार्टी ने सर्वसम्मति की मुहर लगा दी। पुतिन की इच्छा पर बुधवार को ही प्रधानमंत्री दिमित्री मेदवेदेव ने मंत्रिपरिषद के साथ इस्तीफा दे दिया था। इस राजनीतिक घटनाक्रम से 2024 में राष्ट्रपति पद छोड़ने के इच्छुक पुतिन की सत्ता पर पकड़ एक बार फिर साबित हो गई है। पुतिन रूस की सत्ता पर पिछले 20 साल से काबिज हैं।

रूसी संसद के निचले सदन ड्यूमा में मिशस्टीन के पहले भाषण के बाद मतदान होगा। इसके जरिये प्रधानमंत्री के तौर पर उनके नाम को संसद की भी स्वीकृति मिल जाएगी। पुतिन की यूनाइटेड रसिया पार्टी को ड्यूमा में बहुमत प्राप्त है। मिशस्टीन (53) रूस में राजस्व सेवा के अधिकारी थे। जब उन्होंने अप्रत्याशित तरीके से देश का कर संग्रह बढ़ाया तो वह चर्चा में आए और उन्हें लोगों से तारीफ मिली। यही बात उन्हें पुतिन की नजरों में लाई। नतीजा, पुतिन ने मिशस्टीन को क्षेत्रफल के लिहाज से दुनिया के सबसे बड़े देश का प्रधानमंत्री बना दिया।

**मेदवेदेव को यूएन का उप प्रमुख बनाया :** बता दें कि बुधवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने संवैधानिक सुधार की घोषणा करने के बाद प्रधानमंत्री मिमित्री मेदवेदेव ने इस्तीफा दे दिया था, जिसे पुतिन ने स्वीकार कर उन्हें सुरक्षा परिषद का उप प्रमुख नियुक्त कर दिया था।

**क्या हैं नए नियम :** पुतिन ने बुधवार को राष्ट्र के नाम अपने संदेश में कहा था कि वह संसद के निचले सदन डुमा को देश का प्रधानमंत्री तय करने की शक्ति देने का प्रस्ताव करते हैं। प्रधानमंत्री ही देश के उप प्रधानमंत्रियों और सरकार के मंत्रियों के नाम संसद के समक्ष पेश करेगा। संसद द्वारा इन नामों को मंजूरी दिए जाने के बाद राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करने के लिए बाध्य होंगे। राष्ट्रपति को किसी भी कीमत पर संसद द्वारा मंजूर नामों को अस्वीकार करने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने स्टेट काउंसिल को भी मजबूत बनाने का प्रस्ताव किया है। माना जा रहा है कि राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद पुतिन स्टेट काउंसिल का प्रमुख बन सकते हैं।

केंद्रीय टैक्स सेवा के प्रमुख रहे मिखाइल मिशस्टीन। रायटर

### द जनवरी रिवोल्यूशन की दी संज्ञा

आलोचकों के अनुसार खुफिया अधिकारी रह चुके पुतिन राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद भी सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने मेदवेदेव की जगह राजनीतिक तौर पर कमजोर मिशस्टीन को प्रधानमंत्री बनाया है। संविधान में बदलाव कर पुतिन 2024 के बाद भी सत्ता में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का प्रावधान कर सकते हैं। विपक्ष के नेता लियोनिद वोलकोव ने कहा है कि पुतिन को जीवन भर सत्ता में बनाए रखने के लिए सब कुछ करीने से सजाया जा रहा है। 'द कोमरसेंट' ने पुतिन के इस कदम को 'द जनवरी रिवोल्यूशन' की संज्ञा दी है।

## चीन की बेल्ट एंड रोड परियोजना में पारदर्शिता का अभाव

**बीजिंग, एएफपी :** चीन को विश्व के दूसरे देशों से जोड़ने वाली महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड परियोजनाओं से यूरोपीय कंपनियों ने किनारा कर लिया है। इसके लिए कंपनियों ने चीन द्वारा दी गई जानकारियों में अभाव व जारी निविदाओं में पारदर्शिता की कमी को मुख्य वजहें बताईं। कंपनियों का यह आकलन चीन में कार्यरत 132 यूरोपीय फर्मों के मध्य हुए सर्वे से सामने आया है। पोल को चीन में यूरोपियन यूनियन चैंबर ऑफ कॉमर्स ने कराया था, जिसकी रिपोर्ट गुरुवार को प्रकाशित हुई।

सर्वे के प्रकाशन के बाद चैंबर के अध्यक्ष जोर्ग वुटके ने कहा कि निविदाओं के आवंटन में चीन की सरकार ने अनियमितताएं भी बरती हैं। सूचना प्रदान किए बिना अधिकतर निविदाएं चीन की स्थानीय कंपनियों को दे दी गईं। दूसरी तरफ 132 यूरोपीय कंपनियों में केवल 20 फर्मों को ही काम करने का मौका मिला। पारदर्शिता के अभाव के कारण विश्व बैंक और एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इंवेस्टमेंट बैंक जैसे बड़े संस्थानों ने कोई खास रूचि नहीं दिखाई। बता दें कि चीन पाकिस्तान में चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (सीपीईसी) को विकसित कर रहा है। इसके लिए चीन ने पाकिस्तान को 46 हजार करोड़ डॉलर की आर्थिक मदद मुहैया कराई है। सीपीईसी में चीन ग्वादर पोर्ट से एक मार्ग पाकिस्तान के भीतर होकर अपने सीमा तक लेकर जाएगा। चीन के इस प्रोजेक्ट को लेकर भारत की ओर से आपत्ति दर्ज कराई गई है।

# चुनाव के तुरंत बाद ताइवान ने शुरू किया सैन्य अभ्यास

**ताइपे, एपी :** ताइवान में राष्ट्रपति और संसदीय चुनाव के तुरंत बाद सैन्य अभ्यास शुरू हो गया है। ताइवान की नौसेना ने गुरुवार को छोटे हथियारों के साथ आमने-सामने की लड़ाई का अभ्यास किया। इससे पहले वायुसेना ने अपनी युद्ध कला का प्रदर्शन किया था। अमेरिका से आधुनिक एफ-16 लड़ाकू विमानों की खरीदारी कर रहा ताइवान पड़ोसी चीन से रक्षा को लेकर मजबूती से कदम आगे बढ़ा रहा है।

हालिया चुनाव में ताइवान की स्वतंत्रता की बात करने वाली राष्ट्रपति साई इंग-वेन ने फिर जीत दर्ज की है। साई की जीत को चीन की ताइवान से संबंधित रणनीति की हार माना जा रहा है। ताइवान को अपना हिस्सा मानने वाला चीन उसे अपने भूभाग में शामिल करने के लिए सैन्य कार्रवाई की धमकी देता रहा है। इसे देखते हुए लोकतांत्रिक ताइवान अपनी सैन्य क्षमता मजबूत करने में लगा है। इसी के मद्देनजर वह अमेरिका से एफ-16 लड़ाकू विमान खरीद रहा है।

ताइवान में गुरुवार को सैन्य अभ्यास के दौरान खड़े सेना के जवान। रायटर

# ... जब मोदी पर जाहिर हुआ राष्ट्रपति ट्रंप का अल्प ज्ञान!

- अमेरिकी राष्ट्रपति बोले-चीनी सीमा भारत से लगी हुई नहीं
- यह सुनकर हतप्रभ रह गए मोदी, माना ट्रंप भरोसे के लायक नहीं

**वाशिंगटन, प्रेट्र :** अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भारत और चीन को लेकर कुछ ऐसा कह दिया कि मोदी चौंक गए। साथ ही ट्रंप का भूगोल को लेकर अल्पज्ञान भी उजागर हो गया। ट्रंप ने मोदी से कहा था कि चीन की सीमा भारत से लगी हुई नहीं है। ऐसा दावा पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले दो अमेरिकी पत्रकारों की नई किताब में किया गया है।

वाशिंगटन पोस्ट में बुधवार को प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार वाशिंगटन पोस्ट के रिपोर्टर फिलिप रुकर और कैरोल डी.लीओनिंग की 417 पेज की किताब 'ए वेरी स्टेबल जीनियस' में ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के शुरुआती तीन सालों का लेखा-जोखा है। यह किताब ट्रंप की ऐसी ही बहुत सी गफलतों के किस्सों से भरी पड़ी है। सफल उद्योगपति से राजनेता बने ट्रंप ने 2016 में अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव जीता और 20 जनवरी, 2017 को पदभार संभाला था।

किताब में दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के दौरान ट्रंप ने कहा, 'चीन की सीमा भारत से लगी हुई नहीं है' (इट्स नॉट लाइक यू हैव गॉट चाइना ऑन यौर बार्डर)। हालांकि वाशिंगटन पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में यह नहीं बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप ने यह गफलत कौन से साल में की।

भारत-चीन भूगोल पर ट्रंप के इस बयान का दावा करते हुए वाशिंगटन पोस्ट के दोनों रिपोर्टर ने बताया कि इतना सुनते ही पीएम मोदी की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। फिर उनके चेहरे के भाव स्तब्ध होने से लेकर चिंता में बदल गए। बैठक के बाद राष्ट्राध्यक्ष के सहायक ने लेखकों को बताया कि इतना सुनने के बाद ही पीएम मोदी उस बैठक से ही चले गए।

ध्यान रहे कि मोदी वर्ष 2019 में ही ट्रंप से चार बार मिल चुके हैं। इन दोनों रिपोर्टरों को ट्रंप और रूस की रिपोर्टिंग करने पर 2018 का पुलित्जर पुरस्कार मिल चुका है। उल्लेखनीय है कि भारत और चीन के बीच 3,488 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) है।

# यूक्रेन पर दबाव डालने को ट्रंप प्रशासन ने रोकी सहायता

- महाभियोग प्रस्ताव पर चर्चा से पूर्व निगरानी समिति ने किया रहस्योद्घाटन
- संसद की स्वीकृति के बाद यह रोक कानून का उल्लंघन : वाच डॉग
- प्रतिनिधि सभा द्वारा सीनेट को भेजे गए मसौदे पर अब 21 जनवरी को हो सकती है चर्चा

**वाशिंगटन, रायटर :** सीनेट में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर चर्चा से पूर्व संसद की निगरानी समिति ने यूक्रेन की सैन्य सहायता पर नया रहस्योद्घाटन किया है। समिति ने कहा है कि व्हाइट हाउस ने संसद की स्वीकृति के बावजूद यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य सहायता पर रोक लगा रखी है। यह कानून का उल्लंघन है।

ट्रंप को राष्ट्रपति पद से हटाने के लिए सीनेट में पेश होने वाले महाभियोग प्रस्ताव के पीछे भी यूक्रेन से जुड़ा मामला है। संसदीय जांच में पता चला है कि ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदोमीर जेलेंस्की को फोन वार्ता में दबाव डालकर अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता जो बिडेन के खिलाफ जांच कराने के लिए कहा था। संभावना है कि बिडेन इस साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप के सामने डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार होंगे। इसी के आधार पर ट्रंप के खिलाफ निजी हित के लिए पद के दुरुपयोग का आरोप तय हुआ है। दूसरा आरोप संसदीय जांच में बाधा डालने का है। प्रतिनिधि सभा ने बुधवार को दोनों आरोपों पर अपने पारित प्रस्ताव का मसौदा सीनेट को भेज दिया है। माना जा रहा है कि 21 जनवरी को उस पर सीनेट में चर्चा हो सकती है। अमेरिका के इतिहास में यह तीसरे राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग चर्चा होगी।

संसद की निगरानी समिति के अनुसार संसद की स्वीकृति के बावजूद ट्रंप प्रशासन ने 391 मिलियन डॉलर (2,775 करोड़ रुपये) की सैन्य सहायता यूक्रेन को नहीं दी। इसका उद्देश्य यूक्रेन को दबाव में लेना था कि वह ट्रंप के खिलाफ महाभियोग के लिए चल रही जांच में सहयोग न दे। गवर्नमेंट अकाउंटबिलिटी ऑफिस ने कहा है कि कानूनी के तहत सरकार के प्रस्ताव को संसद की स्वीकृति के बाद रोका जाना कानून का उल्लंघन है। इससे ट्रंप प्रशासन की कार्यप्रणाली का पता चलता है। इसको लेकर संसद को सरकार से सवाल पूछना चाहिए।

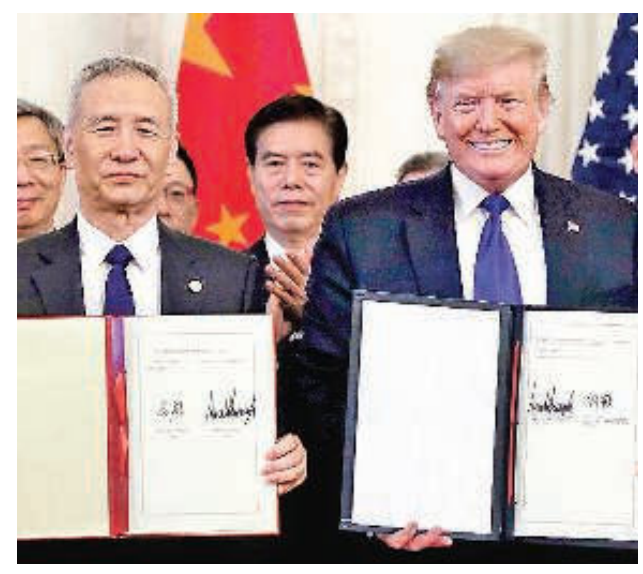

### अमेरिका-चीन के बीच व्यापार समझौता

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के वाइस प्रीमियर लियू हे के बीच हुए पहले चरण के व्यापार समझौते से वैश्विक अर्थव्यवस्था को उम्मीद की किरण नजर आई है। समझौते पर हस्ताक्षर के बाद अंतरराष्ट्रीय शेयर बाजारों में जोरदार उछाल देखने को मिला। बता दें कि विश्व की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच बीते 18 महीने से ट्रेड वार जारी था। एपी

**मिली राहत**

एक करोड़ हेक्टेयर इलाके में खाक हो चुके हैं पेड़-पौधे, कई प्रजातियों के अस्तित्व पर मंडरा रहा खतरा, भारी बारिश के कारण से अब बाढ़ की चुनौती हो रही पेश

# जंगलों की आग से जूझ रहे ऑस्ट्रेलिया में भारी बारिश

**मेलबर्न, प्रेट्र :** जंगलों की आग से जूझ रहे ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी हिस्से में बारिश राहत बनकर आई है। लेकिन भारी बारिश के कारण लोगों के सामने बाढ़ के रूप में दूसरी चुनौती भी खड़ी हो गई है।

पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग से एक करोड़ हेक्टेयर से ज्यादा इलाके के पेड़-पौधे खाक हो गए। दो हजार से ज्यादा घर भी आग की भेंट चढ़ गए। अब तक 28 लोग जान गंवा चुके हैं। जबकि कई जीव-जंतुओं की प्रजातियां खतरे में पड़ गई हैं। जंगलों में लगी आग से उठ रहे धुएं से ऑस्ट्रेलिया की आबोहवा भी खराब हो गई है। मेलबर्न शहर में बीते मंगलवार को वायु गुणवत्ता दुनिया में सबसे बदतर दर्ज की गई थी। स्थानीय मौसम ब्यूरो के अनुसार, बुधवार को हुई भारी बारिश से आबोहवा कुछ साफ हुई, लेकिन विक्टोरिया प्रांत के जंगलों में अब भी 16 जगहों पर आग सुलग रही है। जबकि सबसे प्रभावित न्यू साउथ वेल्स प्रांत में बारिश से कुछ जगहों पर आग बुझने की खबर है। मौसम ब्यूरो की प्रवक्ता ने बताया कि भारी बारिश से उत्तर-पश्चिम मेलबर्न में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। महज आधे घंटे में 44 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई।

**पर्यटन उद्योग को पांच हजार करोड़ का नुकसान :** समाचार एजेंसी आइएएनएस के अनुसार, जंगलों में लगी आग के कारण ऑस्ट्रेलिया के पर्यटन उद्योग को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। ऑस्ट्रेलिया टूरिज्म इंडस्ट्री काउंसिल के अनुसार, पर्यटन उद्योग को करीब पांच हजार करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचा है। इससे उभरने के लिए ऑस्ट्रेलिया को काफी समय लग सकता है।

ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आगजनी के कारण लोगों के साथ-साथ वन्य जीवों के लिए भी संकट पैदा हो गया था। फाइल

### आग से बचाए गए 'डायनासोर ट्री'

जंगलों की आग से जूझ रहे दमकलकर्मी एक ऐसी प्राचीन प्रजाति के पेड़ों को बचाने में सफल रहे, जिन्हें 'डायनासोर ट्री' कहा जाता है। वोललेमी पाइन पेड़ दुनिया में सिर्फ न्यू साउथ वेल्स के ब्लू माउंटेन पर पाए जाते हैं। इन पेड़ों की प्रागैतिहासिक उत्पत्ति के कारण इन्हें 'डायनासोर ट्री' कहा जाता है। इन पेड़ों की ऊंचाई 200 फीट से कम होती है।

# ब्रिटिश महिला का हत्यारा 15 साल बाद पाक में गिरफ्तार

**इस्लामाबाद, एपी :** ब्रिटेन में करीब 15 साल पहले एक महिला पुलिस अधिकारी की हत्या कर भागे पाकिस्तानी नागरिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। ब्रिटिश पुलिस अधिकारी शेरोन बेशेनिवस्की (38) की 2005 में ब्रैडफोर्ड शहर में तब गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जब वह लूट की सूचना मिलने पर घटनास्थल पर पहुंची थीं। इस वारदात में लिप्त छह लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन पाकिस्तानी नागरिक पिरान डिट्टा खान बचकर ब्रिटेन से भाग निकला था।

पिरान (71) को बुधवार को इस्लामाबाद की अदालत में पेश किया गया। पुलिस ने बताया कि पाकिस्तान और ब्रिटेन के अधिकारियों के सहयोग से यह गिरफ्तारी हुई। यह मामला ब्रिटिश ट्रेवल एजेंसी में लूट से जुड़ा था। लूट की सूचना पर मौके पर पहुंचीं शेरोन की सशस्त्र गिरोह के सदस्यों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी।

### टीवी शो में मंत्री ने दिखाया फौजी बूट, एंकर पर पाबंदी

**इस्लामाबाद, प्रेट्र :** टीवी शो के दौरान फौजी बूट दिखाए जाने पर पाकिस्तान के एक न्यूज चैनल के एंकर और उसके कार्यक्रम पर 60 दिन की पाबंदी लगा दी गई है। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी (पीईएमआरए) ने यह पाबंदी एआरवाई न्यूज के एंकर कासिफ अब्बासी और उनके शो 'ऑफ द रिकॉर्ड' पर लगाई है।

अब्बासी के शो में पाकिस्तान की इमरान सरकार के मंत्री फैसल वावदा और विपक्षी दल पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज व पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नेताओं के बीच बहस के दौरान यह वाकया हुआ था।

# बराबरी का मुकाबला



**ये भी जानिए**

भारतीय टीम को पिछले पांच वनडे मैचों में तीन जीत और दो हार मिली हैं जबकि ऑस्ट्रेलिया को भी इतने मैचों में ही तीन जीत और दो हार मिली हैं।

# कंगारुओं को दबोचना चाहेंगे जख्मी शेर

## भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा वनडे आज, पिछले मैच में शर्मसार करने वाली हार के बाद टीम इंडिया जीत को बेताब

**राजकोट, प्रेट्र:** मुंबई में खेले गए पहले वनडे में 10 विकेट से मिली शर्मसार करने वाली हार के बाद भारतीय टीम के लिए चुनौतियां बढ़ गईं हैं। ऑस्ट्रेलिया ने वानखेड़े में जिस तरह का प्रदर्शन किया था उसने एक तरह से मेजबान टीम की कई कमियों को उजागर किया था और अब विराट कोहली की कप्तानी वाली भारतीय टीम शुक्रवार को खेले जाने वाले दूसरे वनडे में चुनौतीपूर्ण वापसी की कोशिश में होगी। पहले मैच के बाद कोहली ने भी माना था कि यह ऑस्ट्रेलियाई टीम बेहद मजबूत है और इसके खिलाफ वापसी करना कठिन चुनौती होगा। सौराष्ट्र क्रिकेट संघ स्टेडियम में भारतीय टीम इस चुनौती को कैसे पार करती है यह देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है।

**मुश्किल हुई चुनौतियां:** वानखेड़े स्टेडियम में हुए पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया ने ना तो भारत को बड़ा स्कोर खड़ा करने दिया और ना ही एक भी विकेट लेने दिया। जसप्रीत बुमराह, मुहम्मद शमी जैसे गेंदबाजों के रहते डेविड वार्नर और आरोन फिंच की सलामी जोड़ी आसानी से रन बनाती रही और भारतीय गेंदबाजों को विकेट के लिए तरसाती रही।

**नंबर तीन पर खेलेंगे कोहली:** राजकोट में कोहली के सामने सबसे बड़ी चुनौती बल्लेबाजी क्रम है। सही मायनों में देखा जाए तो यह नई परेशानी नहीं है विश्व कप के पहले ही भारत के मध्य क्रम और निचले क्रम की कलई कई बार खुलती रही है। मुंबई वनडे उस संख्या में इजाफा था जिसने बता दिया था कि भारतीय मध्य क्रम और निचले क्रम में शीर्ष गेंदबाजों से निपटने का दम अभी तक नहीं आया है। इसके अलावा शीर्ष क्रम में बल्लेबाजों के स्थानों को लेकर भी माथापच्ची होनी है। रोहित शर्मा, शिखर धवन और लोकेश राहुल के रूप में तीन सलामी बल्लेबाजों के रहते हुए कौन कहां खेलेगा यह सिरदर्द बना है। मुंबई में रोहित और धवन ने ओपनिंग की थी तो राहुल नंबर-3 खेले थे। कोहली को इस कारण चौथे नंबर पर आना पड़ा था। कोहली के इस नंबर पर आने की कई पूर्व खिलाड़ियों ने आलोचना की थी और यह तक कहा था कि कोहली को नंबर-3 पर ही खेलना चाहिए। मुमकिन है कि कोहली अपने पुराने स्थान पर खेलें। अब देखना यह है कि सलामी बल्लेबाजी कौन करता है।

**राहुल खेलेंगे नंबर-4 पर:** संभावना है कि रोहित और धवन सलामी जोड़ी के रूप में रहेंगे और राहुल नंबर-4 पर खेलें। राहुल का खेलना तय है इसका एक कारण यह है कि उन्हें दूसरे मैच में बतौर विकेटकीपर के तौर पर खिलाया जाएगा क्योंकि रिषभ पंत चोट के कारण दूसरे मैच में नहीं खेलेंगे। पहले मैच में उन्हें सिर में चोट लगी थी और इसी कारण वह पहले मैच में क्षेत्ररक्षण करने नहीं उतरे थे। वानखेड़े में भी राहुल ने विकेटकीपिंग की थी।

**पंत की जगह कौन:** अब देखना होगा कि पंत के स्थान पर टीम में कौन आता है। कोहली किसी बल्लेबाज को अंतिम-11 में लाते हैं या ऑलराउंडर शिवम दुबे को मौका देते हैं। कोहली अगर दुबे को मौका दें तो हैरानी वाली बात नहीं होगी क्योंकि इससे उन्हें गेंदबाजी में भी विकल्प मिलेगा। कुल मिलाकर दूसरे मैच से पहले टीम प्रबंधन के सामने बल्लेबाजी क्रम को व्यवस्थित करने की चुनौती है। यही हाल गेंदबाजी का भी है। बुमराह और शमी पहले वनडे में बेअसर रहे थे, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि यह दोनों प्रभाव नहीं छोड़ पाए। हां स्पिन विभाग में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। युजवेंद्रा सिंह चहल के अंतिम-11 में आने की संभावनाओं से भी इन्कार नहीं किया जा सकता।

**ऑस्ट्रेलिया से बचकर रहना:** ऑस्ट्रेलिया पहले मैच में मिली जीत के बाद आत्मविश्वास से लबरेज होगी, लेकिन वह जानती है कि भारत जख्मी शेर है जो वापसी को बेताब है। ऑस्ट्रेलियाई लिहाज से उसकी गेंदबाजी सही जा रही है। पहले मैच में वार्नर और फिंच के कारण बाकी बल्लेबाजों को मौका नहीं मिला था। स्टीव स्मिथ कितने खतरनाक हैं यह कोहली एंड कंपनी जानती है। मार्नस लाबुशाने को अपने पहले वनडे में बल्लेबाजी करने को नहीं मिला था।

### भारत के लिए भाग्यशाली नहीं रहा है एससीए स्टेडियम

**राजकोट :** मेजबान भारत का सौराष्ट्र क्रिकेट संघ स्टेडियम पर वनडे क्रिकेट में रिकॉर्ड बेहद खराब है क्योंकि इस मैदान पर उसे दोनों मौकों पर पराजय झेलनी पड़ी। भारत ने 11 जनवरी 2013 को एससीए स्टेडियम पर इंग्लैंड के खिलाफ पहला वनडे खेला था जिसमें उसे नौ रन से पराजय झेलनी पड़ी थी। उसके बाद 18 अक्टूबर 2015 को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ इसी मैदान पर टीम इंडिया 18 रन से हारी। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने यहां भारत के खिलाफ 10 अक्टूबर 2013 को एक टी-20 मैच खेला जिसमें उसे शिकस्त मिली। राजकोट में पहले मैच एससीए की जगह पुराने स्टेडियम में मैच होते थे। उस स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया ने पहला वनडे अक्टूबर 1986 को खेला था जिसमें उसने सात विकेट से जीत दर्ज की।

**संभावित टीम भारत:** विराट कोहली (कप्तान), रोहित शर्मा (उपकप्तान), जसप्रीत बुमराह, युजवेंद्रा सिंह चहल, शिखर धवन, शिवम दुबे, श्रेयस अय्यर, रवींद्र जडेजा, केदार जाधव, कुलदीप यादव, मुहम्मद शमी, मनीष पांडे, लोकेश राहुल, नवदीप सैनी, शार्दुल ठाकुर।

**संभावित टीम ऑस्ट्रेलिया:** आरोन फिंच (कप्तान), एलेक्स कैरी, पैट कमिंस, एश्टन एगर, हैंड्सकोंब, जोश हेजलवुड, मार्नस लाबुशाने, केन रिचर्डसन, डी आर्ची शॉर्ट, स्टीव स्मिथ, मिशेल स्टार्क, एश्टन टर्नर, डेविड वार्नर, एडम जांपा।

**04** वनडे में लगातार हार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय टीम को घर में मिली हैं। भारतीय टीम 1999 और 2004 में पाकिस्तान के खिलाफ घर में लगातार पांच वनडे हारी थी, जबकि 1980 से 1989 तक भारत वेस्टइंडीज के खिलाफ लगातार 15 वनडे हारी थी

**76.26** का बल्लेबाजी औसत है विराट कोहली का वनडे में लेग स्पिनरों के खिलाफ। लेग स्पिनरों के खिलाफ विराट ने प्रति ओवर 6.3 रन बनाए हैं। ऐसे में एडम जांपा का यह कहना कि कोहली शुरुआत में लेग स्पिनरों को नहीं खेल पाते हैं गलत है

**01** विकेट दूर हैं वनडे में 100 विकेट पूरे करने से भारतीय चाइनामैन स्पिनर कुलदीप यादव

» अभ्यास सत्र के दौरान कुछ इस अंदाज में दिखे भारतीय कप्तान विराट कोहली ● एपी

## अंडर-19 विश्व कप का आगाज आज से, रविवार को भारत का पहला मुकाबला श्रीलंका से होगा

# फिर कर लो दुनिया मुट्ठी में

मैंने हमेशा कहा है कि अंडर-19 विश्व कप एक खिलाड़ी के रूप में मेरे विकास के लिहाज से मेरे करियर का सबसे अहम दौर था। यह दूसरा मौका था जब अंडर-19 विश्व कप का प्रसारण टीवी पर हो रहा था। कई लोग रन बनाते हैं और अच्छा करते हैं, लेकिन जब आपको लोग खेलते हुए देख रहे होते हैं तो फिर बात कुछ और होती है। मेरी ओर से युवा भारतीय टीम को शुभकामनाएं।

**विराट कोहली**, भारतीय कप्तान

अंडर-19 विश्व कप के लिए शुभकामनाएं लड़कों। अपने देश के लिए खेलना हमेशा ही गर्व का विषय होता है। कप को घर लाओ। शुभकामनाएं। मजबूती से खेलना। **हरमनप्रीत कौर**, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान

**केपटाउन, प्रेट्र :** अपने भविष्य के सपनों को संजोने के लिए दुनिया की 16 टीमों के युवा खिलाड़ी शुक्रवार से दक्षिण अफ्रीका में शुरू हो रहे अंडर-19 विश्व कप में खेलने उतरेंगे। भारत ने 2018 में पृथ्वी शॉ की कप्तानी में पिछला विश्व कप जीता था।

मौजूदा चैंपियन भारत पांचवीं बार खिताब जीतने का दावेदार है, जिसके पास कप्तान प्रियम गर्ग समेत छह ऐसे खिलाड़ी हैं, जो सीनियर क्रिकेट में खेल चुके हैं। भारतीय टीम में शामिल यशस्वी जायसवाल, गर्ग, रवि बिश्नोई और कार्तिक त्यागी को नहीं भूलना चाहिए, जिन्हें आइपीएल में बड़ी रकम में खरीदा गया था। 2008 में विराट कोहली की कप्तानी में खिताब जीतने के बाद से भारतीय टीम का अंडर-19 विश्व कप में दबदबा रहा है।

पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीम में शामिल भविष्य के सितारे भी चमक बिखेरेंगे, तो वहीं जापान और नाइजीरिया जैसी टीमों के पास पहली बार विश्व क्रिकेट में अपनी छाप छोड़ने का मौका होगा। जापान को ग्रुप-ए में भारत, न्यूजीलैंड और श्रीलंका के साथ रखा गया है। हालांकि, जापानी टीम में तुषार चतुर्वेदी, युगांधर रेथारेकर, इशान फर्टयाल, देबाशीष साहू जैसे दक्षिण एशियाई खिलाड़ी हैं, तो काजूमाशा ताकाहाशी, मासातो मोरिता और शू नोगुची जैसे जापानी खिलाड़ी भी शामिल हैं। नाइजीरियाई टीम को ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के साथ मुश्किल ग्रुप में रखा गया है। उनके पास स्लिवेस्टर ओक्पे, ओच्हे बोनीफेस, इफेआनयीचुक्वू उबोह और ओलाइंका ओलालेये जैसे खिलाड़ी हैं। टूर्नामेंट की शुरुआत मेजबान दक्षिण अफ्रीका और अफगानिस्तान के बीच किंबर्ले में शुक्रवार को खेले जाने वाले मुकाबले से होगी। इसके अगले ही दिन ऑस्ट्रेलिया का सामना वेस्टइंडीज से होगा। भारत की ही तरह ऑस्ट्रेलियाई टीम में कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो सीनियर स्तर पर क्रिकेट खेल चुके हैं। इनमें ऑस्ट्रेलिया के पूर्व डेथ ओवर विशेषज्ञ गेंदबाज इयान हार्वे के भतीजे मैकेंजी हार्वे शामिल हैं, जो दो लिस्ट-ए और 13 टी-20 मुकाबले खेल चुके हैं। ऐसे ही इंग्लैंड की टीम में बेन चार्ल्सवर्थ जैसे अनुभवी खिलाड़ी हैं।

भारतीय अंडर-19 क्रिकेट टीम ● ट्विटर

**भारतीय टीम :** प्रियम गर्ग (कप्तान), ध्रुव चंद जुरेल (उप कप्तान और विकेटकीपर), यशस्वी जायसवाल, तिलक वर्मा, दिव्यांश सक्सेना, शाश्वत रावत, दिव्यांश जोशी, शुभांग हेगडे, रवि बिश्नोई, आकाश सिंह, कार्तिक त्यागी, अथर्व अंकोलेकर, कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), सुशांत मिश्रा और विद्याधर पाटिल।

**विश्व कप ग्रुप**

| | |
|---|---|
| ग्रुप-ए | भारत, जापान, न्यूजीलैंड और श्रीलंका |
| ग्रुप-बी | ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, नाइजीरिया और वेस्टइंडीज |
| ग्रुप-सी | बांग्लादेश, पाकिस्तान स्कॉटलैंड और जिंबाब्वे |
| ग्रुप-डी | अफगानिस्तान, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका और यूएई |

**अंडर-19 विश्व विजेता कप्तान**

| वर्ष | कप्तान | देश |
|---|---|---|
| 1998 | ओवेश शाह | इंग्लैंड |
| 2000 | मुहम्मद कैफ | भारत |
| 2002 | कैमरून व्हाइट | ऑस्ट्रेलिया |
| 2004 | खालिद लतीफ | पाकिस्तान |
| 2006 | सरफराज | पाकिस्तान |
| 2008 | विराट कोहली | भारत |
| 2010 | मिशेल मार्श | ऑस्ट्रेलिया |
| 2012 | उन्मुक्त चंद | भारत |
| 2014 | एडेन मार्करैम | द. अफ्रीका |
| 2016 | हेटमायर | वेस्टइंडीज |
| 2018 | पृथ्वी शॉ | भारत |

### भारत के खिलाफ नहीं दिखेंगे बोल्ट-फर्ग्यूसन

**वेलिंगटन प्रेट्र:** न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने भारत के खिलाफ इसी महीने खेली जाने वाली टी-20 सीरीज के लिए टीम का एलान कर दिया है। भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली जा रही वनडे सीरीज खत्म करने के साथ ही न्यूजीलैंड दौरे के लिए रवाना होगी। इस टीम में चोटिल तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट और लॉकी फर्ग्यूसन को जगह नहीं मिली है। भारत के खिलाफ जनवरी के आखिर में खेली जाने वाली टी-20 सीरीज टीम में कप्तान केन विलियमसन की वापसी हुई है, जबकि दो साल से बाहर चल रहे हैमिश बेनेट को भी जगह दी गई है।

भारत के खिलाफ चुनी गई इस टीम में पहले मैच के लिए कोलिन डि ग्रैंडहोम को शामिल किया गया है, जबकि टॉम ब्रूस को आखिरी के दो मुकाबलों के लिए टीम में चुना गया है। वह डि ग्रैंडहोम की जगह भारत के खिलाफ चौथा और पांचवां टी-20 मुकाबला खेलेंगे। पहला टी-20 मैच 24 जनवरी को खेला जाएगा।

**न्यूजीलैंड की टी-20 टीम :** केन विलियमसन (कप्तान), हैमिश बेनेट, टॉम ब्रूस, कोलिन डि ग्रैंडहोम, मार्टिन गुप्टिल, स्कॉट कुग्गेलिन, डेरेल मिशेल, कोलिन मुनरो, रॉस टेलर, ब्लेयर टिकनर, मिशेल सेंटनर, टिम सेफर्ट (विकेटकीपर), ईश सोढ़ी, टिम साउथी।

# कोहली के बल्लेबाजी क्रम को हार का कारण बताना बेवकूफी

**गौतम गंभीर**

**फ्लिक**

मैंने सुना है कि फिल्म इंडस्ट्री में कुछ स्टार इसको लेकर बहुत सचेत होते हैं कि वह कितने समय स्क्रीन पर दिखेंगे। अगर उन्हें कोई फिल्म मिल रही है तो उसमें अच्छी लाइन उन्हें मिलनी चाहिए, प्रोमो या ट्रेलर में उन्हें कितनी जगह मिली। तो यह सब क्या असुरक्षा, प्रतिद्वंदिता, बाजार की वजह से है? मुझे नहीं पता इसे क्या कहना चाहिए। मैं इसको लेकर भी पक्का नहीं हूं कि इसे तथ्य कहूं या निडरता, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि मेरे करियर में असुरक्षा ने कितना प्रभाव डाला।

मेरे पास ऐसे कई मामले हैं जिसमें बल्लेबाज को अपना स्थान गंवाने का डर होता है। यह खुद के करियर को बचाने के लिए होता है, ना कि कुल मिलाकर टीम के बेहतरी के लिए। ये बल्लेबाज बल्लेबाजी क्रम में अपने स्थान को बचाए रखते हैं, क्योंकि वह टीम से बाहर जाने का रिस्क नहीं लेना चाहते। ऐसे में विराट कोहली बधाई के पात्र हैं जो मुंबई में रोहित शर्मा, शिखर धवन और केएल राहुल के लिए अपना नंबर तीन का स्थान गंवाने को तैयार हो गए।

कह सकते हैं कि सिनेमा और क्रिकेट में कोई मेल नहीं। आलोचक यह भी कह सकते हैं कि एक बल्लेबाज को हर जगह खेलने का आदी होना चाहिए, जिससे वह अपनी बल्लेबाजी को आंक सके। निचले क्रम पर खेलना चुनौती होता है। तब विफलता और टीम से बाहर जाने का डर भी होता है। मैं इस हिस्से के पक्ष में नहीं हूं। यह सब खुद को फिट बैठाने पर निर्भर करता है। अगर कोई ओपनिंग बल्लेबाज नंबर तीन पर आता है तो वह महसूस कर सकता है कि गेंद उसके बल्ले पर नहीं आ रही है। किसी भी केस में कोहली और टीम प्रबंधन प्रयोग कर सकते हैं। मुझे लगता है कि यह भारत का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजी क्रम था और यह कहना बेवकूफी है कि भारत यह मैच इसीलिए हारा क्योंकि कोहली ने अपना स्थान बदला। भारत के पास राजकोट और बेंगलुरु में अपना खेल दिखाने का मौका है।

#WhatDrivesYou
EXIDE

### भारत के ग्रुप मुकाबले

| | | | |
|---|---|---|---|
| 19 जनवरी | VS | श्रीलंका | दोपहर 1:30 |
| 21 जनवरी | VS | जापान | दोपहर 1:30 |
| 24 जनवरी | VS | न्यूजीलैंड | दोपहर 1:30 |

### नहीं रहीं टीम इंडिया की सुपरफैन चारुलता

भारतीय क्रिकेट टीम की प्रशंसक चारुलता पटेल ● फाइल फोटो, प्रेट्र

**जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली:** व्हीलचेयर पर वुवुजेला बजाती 87 साल की बुजुर्ग भारतीय महिला प्रशंसक चारुलता पटेल ने पिछले साल दो जुलाई को बर्मिंघम के एजबेस्टन स्टेडियम में भारत और बांग्लादेश के बीच हुए विश्व कप मैच के दौरान इंटरनेट पर तूफान ला दिया था। तंजानिया में पैदा हुईं भारतीय मूल की चारुलता लंदन में रहती थीं। टीम इंडिया की बुजुर्ग सुपरफैन का सोमवार को निधन हो गया।

चारुलता के इंस्टाग्राम पर पोस्ट में उनके स्वजन की तरफ से लिखा गया है कि भारी मन से आपको जानकारी देता हूं कि हमारी प्यारी दादी ने 13 जनवरी की शाम 5.30 बजे अपनी अंतिम सांस ली। वह बेहद प्यारी महिला थीं, यह सच है कि अच्छी चीजें छोटे समय के लिए आती हैं। वह वास्तव में असाधारण थीं। वह हमारी दुनिया थीं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआइ) ने गुरुवार को सुपर दादी का विराट संग फोटो शेयर किया। बीसीसीआइ ने लिखा कि टीम इंडिया की सुपर फैन चारुलता हमेशा हमारे दिलों में रहेंगी। उनका खेल के प्रति जुनून हमें प्रोत्साहित करता रहेगा।

# आखिर धौनी के दिल में क्या है...

- बीसीसीआइ, टीम इंडिया के सदस्यों और सीएसके के दोस्तों को भी नहीं पता
- कप्तान रहते हुए टेस्ट से संन्यास लेने वाले धौनी नहीं छोड़ रहे वनडे और टी-20

अभिषेक त्रिपाठी ● नई दिल्ली

भारत को सभी आइसीसी खिताब दिलाने वाले इकलौते कप्तान महेंद्र सिंह धौनी ने दिसंबर 2014 में कप्तान रहते हुए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बीच सीरीज में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया था और इस कारण विराट कोहली को कप्तान बनने का मौका मिला। 33 साल की उम्र में उन्होंने अचानक ही टेस्ट क्रिकेट छोड़ दिया था और इसके बाद से उनकी छवि यह बन गई कि वह शीर्ष पर रहते हुए ही क्रिकेट छोड़ेंगे। 2016 में उन्होंने खुद ही वनडे और टी-20 की कप्तानी छोड़ दी। पिछले साल तक उनके करीबी कहते थे कि इंग्लैंड में 2019 विश्व कप के बाद वह सीमित ओवरों के क्रिकेट से संन्यास ले लेंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अब किसी को नहीं पता कि उनके दिल में क्या चल रहा है?

धौनी की सबसे फेवरिट टीम चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) में उनके साथी खिलाड़ी ने कहा कि किसी को भी इस बात का अनुमान नहीं है कि उनके दिल में क्या चल रहा है? जब किसी ने सोचा नहीं था तब उन्होंने टेस्ट से संन्यास लिया और सीमित ओवरों के क्रिकेट की कप्तानी छोड़ी। पिछले साल विश्व कप के बाद जब सबने सोचा कि वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लेंगे तो उन्होंने ऐसा नहीं किया। जब नियमों के कारण बीसीसीआइ को उन्हें केंद्रीय अनुबंध से बाहर करने को मजबूर होना पड़ा तो वह रांची में बल्ला थामे नजर आए। धौनी ऐसे ही हैं। अभी मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि वह अगले सत्र में आइपीएल में खेलेंगे। वहीं बीसीसीआइ के पदाधिकारी ने कहा कि धौनी ने भविष्य को लेकर किसी से बात नहीं की है। मुझे नहीं लगता किसी ने उनसे इस बारे में पूछा भी है और उन्होंने किसी को इस बारे में बताया भी है। यह वही जानते हैं कि उन्हें क्या करना है और इतने बड़े खिलाड़ी से संन्यास के बारे में किसी को पूछना भी नहीं चाहिए। उन्हें जब लगेगा तो वह अपने भविष्य पर फैसला लेंगे।

### ब्रांड वैल्यू या टी-20 विश्व कप

**नई दिल्ली:** जब क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने संन्यास लिया था तो उनकी ब्रांड वैल्यू भी धड़ाम हो गई थी। क्या इसी कारण धौनी अभी संन्यास की घोषणा नहीं कर रहे हैं। पिछले साल टी-20 विश्व कप से पहले धौनी बल्ले के लोगो के लिए लंबे समय का करार करना चाहते थे लेकिन कोई कंपनी इसके लिए तैयार नहीं हुई। इसके बाद वह विश्व कप में कई कंपनियों का लोगो लगाकर मैदान में उतरे। उनके प्रतिनिधि ने तब कहा था कि क्रिकेट के शुरुआती समय में जिन्होंने उनकी मदद की, उनके फ्री में उनके लोगो को बल्ले में लगाकर खेलकर धौनी उनको सम्मान दे रहे हैं। धौनी ने हाल ही में एक समारोह में वापसी के सवाल पर कहा था कि जनवरी तक मत पूछो। फिलहाल जनवरी चल रही है और धौनी ने अभ्यास करना शुरू कर दिया है। आइपीएल से जुड़े एक सदस्य ने कहा कि अगर धौनी आइपीएल से पहले संन्यास लेते हैं तो उनकी ही नहीं सीएसके की ब्रांड वैल्यू में भी गिरावट आएगी क्योंकि वह उसके कप्तान हैं। अब देखना है कि उनके दिमाग में आइपीएल है या ऑस्ट्रेलिया में होने वाला टी-20 विश्व कप?

एमएस धौनी ● फाइल फोटो, प्रेट्र

### मुझे नहीं लगता, अब धौनी भारत के लिए खेलेंगे: हरभजन

**नई दिल्ली, प्रेट्र:** पूर्व भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह ने कहा कि यह शायद धौनी के लिए रास्ते का अंत है। मैंने सुना था कि विश्व कप उनका आखिरी टूर्नामेंट होगा और वह उसके बाद नहीं खेलेंगे। उन्होंने इस बारे में बहुत पहले ही अपना मन बना लिया था और इसीलिए खुद को मैचों के लिए उपलब्ध नहीं कराया। भज्जी ने कहा कि अगर धौनी का आइपीएल में अच्छा प्रदर्शन रहता है और मुझे उम्मीद है कि ऐसा होगा क्योंकि वह कड़ी मेहनत करते हैं। इसके बावजूद भी वह खुद को टीम इंडिया के लिए उपलब्ध नहीं कराएंगे। मुझे नहीं लगता कि वह वापसी करेंगे।

**बीसीसीआइ पर भड़के धौनी प्रशंसक:** महेंद्र सिंह धौनी को अनुबंधित खिलाड़ियों की सूची से बाहर कर दिए जाने के बाद से उनके प्रशंसकों में काफी नाराजगी है। प्रशंसकों ने ट्विटर पर अपनी भड़ास निकाली। उन्होंने बोर्ड को निशाने पर लिया है और धौनी का नाम जोड़ने के लिए कहा है। यही कारण था कि ट्विटर पर थैंक्यू धौनी ट्रेंड करने लगा। एक प्रशंसक ने लिखा कि सूची में धौनी का नाम नहीं है। क्या यह टाइपिंग की गलती की वजह से है? एक अन्य प्रशंसक ने लिखा कि क्या यह धौनी के भविष्य को लेकर बड़ा फैसला है? एक अन्य प्रशंसक ने लिखा कि धन्यवाद धौनी, मेरा बचपन बेहतर बनाने के लिए। एक अन्य ने लिखा कि यह धौनी के लिए बुरी खबर है। धौनी को आपको लेना चाहिए था। उनके अंदर अभी दो साल तक खेलने की क्षमता है। यह बीसीसीआइ का गलत फैसला है। एक अन्य प्रशंसक ने लिखा कि धौनी केंद्रीय करार में शामिल नहीं।

### निशानेबाजी के बाद धौनी ने किया बल्लेबाजी का अभ्यास

**जागरण संवाददाता, रांची:** महेंद्र सिंह धौनी ने गुरुवार को रांची में पहले निशानेबाजी का अभ्यास किया और बाद में झारखंड रणजी टीम के साथ कुछ समय बिताया। क्रिकेट टीम के साथ अभ्यास के बाद वह मेंटर की भूमिका में आए और सौरभ तिवारी, नजीम सिद्दिकी, कुमार देवब्रत को बल्लेबाजी के टिप्स दिए। धौनी सुबह 11 बजे जेएससीए स्टेडियम पहुंचे थे। स्टेडियम में बनी दस मीटर की शूटिंग रेंज में उन्होंने निशानेबाजी का अभ्यास किया। लगभग एक घंटे तक अभ्यास करने के बाद धौनी ने झारखंड रणजी टीम के साथ अभ्यास किया। उन्होंने बल्लेबाजी के बाद थोड़ी देर कीपिंग में भी हाथ आजमाए। इस दौरान उनकी फिटनेस देखकर सभी दंग थे। माना जा रहा है कि धौनी आइपीएल की तैयारी में जुट गए हैं। यही नहीं धौनी ने अभ्यास सत्र के लिए एक बॉलिंग मशीन भी खरीदी है। झारखंड रणजी टीम लाल गेंद से अभ्यास कर रही है जबकि धौनी को आइपीएल में सफेद गेंद से खेलना है इसलिए रणजी टीम का अभ्यास सत्र खराब नहीं हो वह अगले कुछ दिनों तक यहां बॉलिंग मशीन से सफेद गेंद से बल्लेबाजी का अभ्यास कर सकते हैं।

### फिलहाल टीम इंडिया के दरवाजे बंद नहीं

**नई दिल्ली:** बीसीसीआइ के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि अनुबंध सूची से धौनी को बाहर करना तय था और उन्हें राष्ट्रीय चयन समिति ने सूची को अंतिम रूप देने से पहले इसकी जानकारी दे दी थी। पूर्व कप्तान अगर इस साल टी-20 टीम में शामिल होते हैं तो उन्हें सूची में फिर जगह मिल सकती है। हालांकि इसकी संभावना कम है। अधिकारी ने कहा कि मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि बीसीसीआइ के एक शीर्ष पदाधिकारी ने केंद्रीय अनुबंध के बारे में उनसे बात की थी। उन्हें बताया गया कि उन्होंने सितंबर 2019 से अब तक कोई मैच नहीं खेला है तो उन्हें सूची में नहीं रखा जा सकता। धौनी ऑस्ट्रेलिया में होने वाले टी-20 विश्व कप की टीम में जगह बनाते हैं तो उन्हें अनुबंध दिया जा सकता है। मौजूदा नियम के तहत उसी खिलाड़ी को केंद्रीय अनुबंध दिया जा सकता है जिसने कम से कम तीन टेस्ट, या आठ वनडे या आठ टी-20 खेले हों। केंद्रीय अनुबंध का देश के लिए खेलने से कोई कोई लेना-देना नहीं है। वह अच्छा प्रदर्शन कर भारतीय टीम में जगह बनाने की दावेदारी पेश कर सकते हैं। कोई इसे रास्ते बंद होने और चयनकर्ताओं से संकेत मिलने की तरह देखता है तो ऐसा नहीं है। पहले भी ऐसे खिलाड़ी रहे हैं जो बिना केंद्रीय अनुबंध के खेले हैं। टीम के मुख्य कोच रवि शास्त्री ने हाल ही में कहा था कि धौनी को लेकर आइपीएल तक इंतजार कीजिए। उनकी वापसी पर शास्त्री ने कहा था कि यह निर्भर करता है कि वह कब खेलना शुरू करते हैं और आइपीएल में कैसा खेलते हैं। वहीं दूसरे खिलाड़ी विकेटकीपिंग में क्या कर रहे हैं और धौनी के मुकाबले उनकी फॉर्म क्या है।

**ए ग्रेड में हरमनप्रीत:** बीसीसीआइ के सीनियर महिला टीम के वार्षिक अनुबंध में टी-20 कप्तान हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना और पूनम यादव को ए-ग्रेड में शामिल किया गया है। ए-ग्रेड में शामिल खिलाड़ियों को 50-50 लाख रुपये, बी-ग्रेड में शामिल खिलाड़ियों को 30-30 लाख रुपये और सी ग्रेड में शामिल खिलाड़ियों को 10-10 लाख रुपये मिलेंगे। मिताली राज, झूलन गोस्वामी, एकता बिष्ट, राधा यादव, शिखा पांडे, दीप्ति शर्मा, जेम्मिाह रोड्रिग्वेज और तानिया भाटिया को बी-ग्रेड में रखा गया है। वेदा कृष्णमूर्ति, पूनम राउत, अनुजा पाटिल, मानसी जोशी, डी हेमलता, अरुंधति रेड्डी, राजेश्वरी गायकवाड़, पूजा वस्त्राकर, हरलीन देओल, प्रिया पूनिया और शेफाली वर्मा को सी-ग्रेड में शामिल किया गया है।

बांग्लादेश क्रिकेट टीम के प्रत्येक खिलाड़ियों को भारतीय टीम से सीखने की जरूरत है।
– रसेल डोमिंगो, बांग्लादेश टीम के कोच

### गांगुली को भारतीय टीम से वापसी की उम्मीद

**मुंबई, आइएएनएस :** भारत को मंगलवार को यहां खेले गए पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया के हाथों 10 विकेट करारी हार झेलने पड़ी थी। लेकिन, अब बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने उम्मीद जताई है कि विराट कोहली की टीम इंडिया वापसी करेगी। उन्होंने इसके लिए कोहली को अपनी शुभकामनाएं भी दी हैं। गांगुली ने ट्विटर पर लिखा कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अगले दो वनडे अहम होंगे।

**टेनिस डायरी** ▶ ऑस्ट्रेलियन ओपन के पहले दौर में बोलिविया के डेलेन से भिड़ेंगे नंबर एक खिलाड़ी राफेल

# नडाल व सेरेना आसान आगाज को तैयार

## रूस की पोटापोवा के खिलाफ अभियान शुरू करेंगी विलियम्स

**मेलबर्न, एएफपी :** दुनिया के नंबर एक टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल अगले हफ्ते ऑस्ट्रेलियन ओपन के पहले दौर में बोलिविया के हुगो डेलेन से भिड़ेंगे, जबकि सेरेना विलियम्स शुरुआती मुकाबले में अनास्तासिया पोटापोवा के सामने होंगी और 24वां ग्रैंडस्लैम खिताब हासिल करने की कोशिश करेंगी।

स्पेन का यह स्टार अपने सबसे कम पसंदीदा कोर्ट पर रोजर फेडरर के रिकॉर्ड 20 ग्रैंडस्लैम सिंगल्स खिताब की बराबरी करने का प्रयास करेगा। नडाल ने मेलबर्न में महज एक ट्रॉफी 2009 में जीती है। गुरुवार को जारी ड्रॉ के अनुसार चौथे दौर में उनका सामना ऑस्ट्रेलिया के निक किर्गियोस से हो सकता है। गत चैंपियन नोवाक जोकोविक रिकॉर्ड आठवां ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब अपने नाम करने की कोशिश करेंगे और शुरुआत में जान-लेनार्ड स्ट्रफ के खिलाफ खेलेंगे। इस सर्बियाई खिलाड़ी के लिए 2019 शानदार रहा, जिसमें उन्होंने मेलबर्न पार्क और विंबलडन सहित पांच खिताब अपने नाम किए और साल का अंत दूसरे नंबर पर रहते हुए किया। जोकोविक अंतिम आठ में यूनान के युवा खिलाड़ी स्टेफानोस सितसिपास से भिड़ सकते हैं। सातवां ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब हासिल करने की कोशिश में जुटे फेडरर (38) पुरुषों के ड्रॉ में तीसरे क्वार्टर में अमेरिका के स्टीव जॉनसन के सामने हो सकते हैं, जिन्होंने यहां पिछला खिताब 2018 में जीता था।

महिलाओं के वर्ग में सेरेना की कोशिश मार्गरेट कोर्ट के रिकॉर्ड 24 ग्रैंडस्लैम सिंगल्स खिताब की बराबरी करने पर लगी होंगी, जिसके लिए वह अपने अभियान की शुरुआत 90वीं रैंकिंग की रूस की पोटापोवा के खिलाफ करेंगी। वह क्वार्टर फाइनल में गत चैंपियन नाओमी ओसाका के सामने हो सकती हैं। दूसरी वरीय कैरोलिना प्लिस्कोवा का सामना पहले दौर में क्रिस्टिना मलादेनोविच से होगा।

अमेरिका की दिग्गज महिला टेनिस खिलाड़ी सेरेनाविलियम्स। फाइल फोटो, एपी

**प्रजनेश फाइनल दौर में, नागल हारे**

**मेलबर्न, प्रेट्र :** भारत के शीर्ष रैंकिंग के सिंगल्स खिलाड़ी प्रजनेश गुणेश्वरन ऑस्ट्रेलियन ओपन के मुख्य ड्रॉ में जगह बनाने से केवल एक कदम दूर हैं। उन्होंने गुरुवार को क्वालीफायर के फाइनल दौर में जगह बनाई, जबकि हमवतन सुमित नागल का सफर यहां खत्म हो गया। विश्व रैंकिंग में 122वें पायदान पर काबिज प्रजनेश ने एक घंटे 22 मिनट तक चले मुकाबले में जर्मनी के यानिक हंफमैन को 1-6, 6-2, 6-1 से शिकस्त दी। क्वालीफायर में प्रजनेश को 17वीं वरीयता मिली थी। वह अंतिम दौर में लातविया के अर्नेस्ट गुलबिस से भिड़ेंगे, जिन्होंने अर्जेंटीना के फेडरिका कोरिया को हराया।

प्रजनेश ने शुरुआती दौर में स्थानीय वाइल्ड कार्डधारी हैरी बोरचियर को 6-2-6-4 से मात दी। इससे पहले नागल पुरुष सिंगल्स क्वालीफायर के पहले दौर में सीधे सेट में हारकर बाहर हो गए। क्वालीफायर में 21वीं वरीयता प्राप्त नागल को मिस्र के मुहम्मद सफवात ने 7-6, 6-2 से हराया। रामकुमार रामनाथन और महिला वर्ग में अंकिता रैना मंगलवार को ही हारकर बाहर हो गए थे।

**सानिया होबार्ट इंटरनेशनल के महिला डबल्स सेमीफाइनल में**

**होबार्ट, प्रेट्र :** मातृत्व अवकाश के बाद कोर्ट पर लौटीं भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने होबार्ट इंटरनेशनल के महिला डबल्स सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। यूक्रेन की नादिया किचेनोक के साथ सानिया ने अमेरिका की वानिया किंग और क्रिस्टिना मैकहेल की जोड़ी को एक घंटे 24 मिनट तक चले मुकाबले में 6-2, 4-6, 10-4 से मात दी। एक समय स्कोर 1-1 से बराबर था। पांचवीं वरीयता प्राप्त सानिया और किचेनोक ने टाईब्रेकर में शानदार प्रदर्शन किया। अब उनका सामना स्लोवेनिया की जमारा जिदांसेक और चेक गणराज्य की मारी बूजकोवा से होगा। सानिया मां बनने की वजह से दो साल से अधिक समय से टेनिस से दूर हैं।

**फ्रांस के क्वालीफायर हंबर्ट ने शापोवालोव को हराया**

**ऑकलैंड, एएफपी :** विश्व के 13वें नंबर के टेनिस खिलाड़ी डेनिस शापोवालोव गुरुवार को एटीपी ऑकलैंड क्लासिक टूर्नामेंट से बाहर हो गए। उन्हें 57वीं रैंकिंग पर काबिज फ्रांस के क्वालीफायर यूगो हंबर्ट के हाथों क्वार्टर फाइनल में सीधे सेटों में हार का सामना करना पड़ा। मुकाबले के दौरान दोनों सेटों में सिर्फ एक-एक ब्रेक था और हंबर्ट ने कनाडाई खिलाड़ी के छठे डबल फॉल्ट के साथ 7-5, 6-4 से अपने नाम कर लिया। हंबर्ट ने जीत के बाद कहा, 'मैं वाकई बहुत खुश हूं। यह मेरे करियर की सबसे बड़ी जीतों में से एक है।' हंबर्ट का सामना अब अमेरिका के जॉन इस्नर होगा। इस्नर ने एक अन्य रोमांचक क्वार्टर फाइनल मुकाबले में काइल एडमंड को 7-6, 7-6 से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। इस दौरान दोनों सेट टाईब्रेकर तक गए।

# चौथे नंबर के लिए टीम प्रयोग से गुजर रही : अय्यर

**रा8जकोट, प्रेट्र :** श्रेयस अय्यर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में अपने पसंदीदा चौथे नंबर पर खेलने का मौका नहीं मिला जिसके बाद उन्होंने गुरुवार को कहा कि भारतीय टीम में मौजूदा प्रतिस्पर्धा को देखते हुए एक खिलाड़ी को किसी भी नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अय्यर ने 2019 विश्व कप के बाद भारत की सीमित ओवरों की टीम में वापसी की है और उन्होंने चौथे नंबर पर अच्छा खेल दिखाया है।

मंगलवार को उन्हें चौथे के बजाय पांचवें नंबर पर कर दिया गया, क्योंकि कप्तान विराट कोहली खुद चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे ताकि विशेषज्ञ सलामी बल्लेबाज लोकेश राहुल और शिखर धवन को अंतिम एकादश में शामिल किया जा सके। हालांकि यह कदम कारगर नहीं रहा।

दूसरे वनडे से पहले 25 साल के अय्यर ने कहा कि इस स्थिति में आपको किसी भी नंबर पर बल्लेबाजी के लिए तैयार रहना चाहिए क्योंकि इस समय टीम में जो प्रतिस्पर्धा है, उसे देखते हुए टीम में खेलना अहम है। हम किसी विशेष नंबर पर बल्लेबाजी करने की वजह नहीं दे सकते। हमारे लिए सबसे अहम चीज ध्यान लगाए रखना है। हम इसके बारे में शिकायत नहीं कर सकते कि हमें उसी स्थान पर बल्लेबाजी करने को नहीं मिल रही। हम प्रयोग करने की कोशिश में हैं। उम्मीद है कि हम प्रत्येक बल्लेबाज को अच्छे स्थान पर खिलाएंगे।

**बौखलाया भारत करेगा पलटवार : फिंच**

**राजकोट :** ऑस्ट्रेलियाई कप्तान आरोन फिंच ने कहा कि पहले मैच में हमारा प्रदर्शन अच्छा रहा। क्षेत्ररक्षण थोड़ी लचर था लेकिन हम टीम के प्रदर्शन से खुश हैं। इसमें कोई शक नहीं कि भारत वापसी करेगा। भारतीय टीम शानदार है जिसके पास विश्व स्तरीय खिलाड़ी हैं। वार्नर बेहतरीन फॉर्म में है। उनके जमने के बाद उन्हें गेंदबाजी करना कठिन है। वह मैदान के चारों ओर खेलते हैं, लिहाजा उन्हें रन बनाने से रोक पाना कठिन है। फिंच ने संकेत दिया कि दूसरे वनडे में पैट कमिंस या मिशेल स्टार्क की जगह जोश हेजलवुड को उतारा जा सकता है। फिंच ने कहा कि हम दूसरे वनडे के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। पिछले मैच में हमारी टीम की ओर से भी कुछ गलतियां हुई थी। हमारी कोशिश होगी कि इस मुकाबले में उन गलतियों को नहीं दोहराया जाए। भारतीय टीम एक मजबूत टीम है। यह टीम वापसी कर सकती है।

# लंदन में हुई तेज गेंदबाज भुवनेश्वर की सफल सर्जरी

**ढाका, एएफपी :** चोट से जूझ रहे भारतीय तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार की लंदन में स्पोर्ट्स हार्निया की सर्जरी हुई है और वह स्वदेश लौटने के बाद बेंगलुरु स्थित राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी (एनसीए) में रिहैबिलिटेशन प्रक्रिया से गुजरेंगे।

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआइ) ने गुरुवार को इस बात की जानकारी दी। हालांकि उसकी तरफ से से भुवनेश्वर की वापसी की कोई समयसीमा नहीं बताई गई। सूत्रों का कहना है कि यह तेज गेंदबाज न्यूजीलैंड दौरे से बाहर रहेगा और इंडियन प्रीमियर लीग (आइपीएल) के दौरान मैदान पर लौटेगा। आइपीएल का आगाज 29 मार्च से होगा। भुवनेश्वर इस प्रतिष्ठित टी-20 लीग में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते हैं। बोर्ड के सचिव जय शाह के अनुसार भुवनेश्वर नौ जनवरी को लंदन गए और 11 जनवरी को उनकी स्पोर्ट्स हर्निया सर्जरी हुई जो सफल रही। टीम इंडिया के फिजियोथेरेपिस्ट योगेश परमार ने उनकी मदद की। यही कारण था कि भुवनेश्वर को न्यूजीलैंड के खिलाफ घोषित टी-20 टीम में जगह नहीं दी गई थी। 21 टेस्ट, 114 वनडे और 43 टी-20 खेलने वाले भुवी ने चोट से उबरते हुए वेस्टइंडीज के खिलाफ हाल ही में हुई घरेलू टी-20 सीरीज में वापसी की थी लेकिन उसी दौरान उनकी यह चोट उभर आई और इसके बाद एनसीए पर सवाल भी उठे थे क्योंकि इससे पहले वह एनसीए में ही रिहैबलिटेशन प्रक्रिया से गुजर रहे थे और उन्हें फिट घोषित किया गया था।

# नई इबारत लिखेंगे बगान–एटीके

**विशाल श्रेष्ठ, कोलकाता**

**साझेदारी**

▶ **कोलकाता के प्रतिष्ठित क्लब मोहन बगान का आइएसएल फ्रेंचाइजी एटीके में विलय**

कोलकाता के प्रतिष्ठित फुटबॉल क्लब मोहन बगान का इंडियन सुपर लीग (आइएसएल) की फ्रेंचाइजी टीम एटीके के साथ गुरुवार को विलय हो गया। अब अगले सत्र से मोहन बगान का नाम बदलकर एटीके-मोहन बगान हो जाएगा। एटीके का मालिकाना हक वाला आरपी-संजीव गोयनका ग्रुप मोहन बगान फुटबॉल क्लब (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड की 80 फीसद हिस्सेदारी अधिग्रहित करेगा। इस तरह 131 साल पुराना फुटबॉल क्लब महज छह साल की उम्र वाली फ्रेंचाइजी टीम के साथ मिलकर भारतीय फुटबॉल में नई इबारत लिखने को तैयार है।

ग्रुप के चेयरमैन संजीव गोयनका ने विलय की घोषणा करते हुए कहा, 'आरपी-संजीव गोयनका ग्रुप में मोहन बगान का स्वागत करके हम खुद को सम्मानित महसूस कर रहे हैं। नए फुटबॉल क्लब में एटीके और मोहन बगान का ब्रांड नाम होगा। यह विलय बंगाल की समृद्ध फुटबॉल विरासत को और आगे ले जाएगा।'

नया क्लब इस साल जून में अस्तित्व में आएगा और 2020-21 में आइएसएल में शिरकत करेगा। मोहन बगान और एटीके का विलय न सिर्फ इन दोनों, बल्कि भारतीय फुटबॉल और आइएसएल की भी दशा-दिशा तय करेगा। भारतीय फुटबॉल पर करीब से नजर रखने वाले इसे आरपी-संजीव गोयनका ग्रुप के चेयरमैन संजीव गोयनका का मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं, जिन्होंने एक झटके में मोहन बगान के लाखों कट्टर समर्थकों को एटीके से जोड़कर उसे आइएसएल की सबसे हॉट टीम में तब्दील कर दिया है। उनके इस कदम से चिर-प्रतिद्वंद्वी ईस्ट बंगाल पर भी एक दबाव आ गया है। फुटबॉल जगत के दिग्गज इस कदम को आइएसएल के लिए सबसे बड़ा फायदा मान रहे हैं। भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान एवं मोहन बगान की तरफ से खेल चुके बाइचुंग भूटिया ने कहा, 'कोलकाता की दो बड़ी टीमों का विलय निश्चित रूप से बहुत अच्छा कदम है। इससे आइएसएल को भी बहुत फायदा होगा।' एक ही टीम के अलग-अलग तौर पर राष्ट्रीय लीग और आइएसएल खेलने के बारे में बाइचुंग ने कहा कि निश्चित रूप से इसे लेकर कोई योजना होगी।

## कोहली को गेंदबाजी करना मुश्किल

**राजकोट :** ऑस्ट्रेलियाई लेग स्पिनर एडम जांपा ने गुरुवार को कहा कि कोहली जैसे खिलाड़ी को गेंदबाजी करना बहुत मुश्किल है और उन पर हावी होने के लिए मजबूत व्यक्तित्व का होना जरूरी है। हालांकि वह सीमित ओवर के क्रिकेट में अभी तक उन्हें छह बार आउट कर चुके हैं। जांपा ने कहा कि मेरी गेंदबाजी आक्रामक होगी। मुझे लगता है कि अगर आप बैकफुट पर हो और आप रक्षात्मक होना चाहते हो तो कोहली आपके ऊपर हावी हो सकते हैं। भारत में इन शानदार खिलाड़ियों के खिलाफ खेलने के लिए सबसे अहम चीज है कि आपमें थोड़ा जज्बा होना चाहिए। जांपा ने वनडे में कोहली को चार बार और टी-20 में दो बार आउट किया है। 27 साल के स्पिनर ने कहा कि आप शायद जानते हो कि आपकी गेंद पर बाउंड्री लगेगी लेकिन आप इससे प्रभावित होते हो तो यह आपके लिए बुरा हो सकता है। मैंने उन्हें अब कई बार आउट कर दिया है लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें ज्यादा कुछ देखा जा सकता है। वह अब भी मेरे खिलाफ 100 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से रन बनाते हैं। जांपा ने 49 मैचों में 66 विकेट लिए हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें गेंदबाजी करना काफी मुश्किल है। मैंने अब तक जिन मुश्किल खिलाड़ियों को गेंदबाजी की है, वह उनमें से एक हैं। पहले वनडे के बाद वह और खुलकर खेलेंगे। यह एक बड़ी चुनौती होने वाली है। कोहली ने हाल में जांपा की तारीफों के पुल बांधे थे। इस पर उन्होंने कहा कि यह विराट से मिली बहुत अच्छी तारीफ है। मैं दुनिया के बेहतरीन लेग स्पिनरों में से एक नहीं हूं। कुलदीप और राशिद जैसे गेंदबाजों को खेलना सचमुच कठिन हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मजबूत जज्बे वाला खिलाड़ी बनूं।

**विविध**

# खूबसूरती में चार चांद लगा रहा फीलनगर का चुटीला

## जुल्फों को संवारने का भले बदला ढंग, नहीं बदला चुटीले का रंग

**जागरण विशेष**

**अंबुज मिश्र, शाहजहांपुर**

जमाने के साथ जुल्फों को संवारने का ढंग भले बदलता गया, लेकिन चुटीले के चटख रंग आज भी लुभाते हैं। उप्र के शाहजहांपुर में एक गांव ऐसा भी है, जिसकी पहचान ही इसी से है। करीब ढाई हजार लोगों का रोजगार भी समेटे है यह गांव। फीलनगर का पता पूछेंगे तो आसपास के गांव वालों का जवाब आएगा... कौन सा, वही चुटीले वाला...। फीलनगर केवल केशसज्जा में रुचि रखने वाली महिलाओं को ही नहीं, वरन ढाई हजार लोगों को भी फीलगुड कराने का काम कर रहा है। अनेक परिवारों का रोजगार समेटे है। उन कारीगरों के हुनर को जिंदा रखे हुए है, जिन्होंने फैशन के इस दौर में भी चुटेला को चूकने नहीं दिया। नए दौर की नई मांग के अनुरूप इसकी ऐसी वैराइटी दीं कि चुटीला जुल्फों में सजता गया।

राजस्थान और पंजाब सहित देश के अन्य हिस्सों तक फीलनगर के कारीगरों के बनाए चुटीले की खासी मांग रहती है। खास बात यह भी है कि इन्हें बनाने में किसी मशीन का नहीं, बल्कि हाथ का उपयोग होता है। चटक रंगों का चयन, डिजाइन और फिनिशिंग फीलनगर के चुटीलों को सबसे अलग साबित करती है। इन्हें दिल्ली के बाजार के जरिये राजस्थान, पंजाब सहित अन्य बाजारों को भेजा जाता है।

उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर के फीलनगर गांव में तैयार किए गए चुटीले। जागरण

कटरा ब्लाक से करीब पांच किमी दूर जलालाबाद स्टेट हाईवे के किनारे बसे इस गांव में लगभग हर घर में चुटीला बनाने का काम होता है। छोटे कारखाने हैं, जहां पुरुष काम करते हैं। वहीं से कुछ कच्चा माल घरों तक भी पहुंचता है, जहां महिलाएं इन्हें बनाने का काम करती हैं। जब वे इसे तैयार कर लेती हैं तो बना हुआ माल वापस कारखाने पहुंचता है। वहां से एजेंट के जरिये दिल्ली भेजा जाता है। इस काम में लगे रामचंद्र देवल कहते हैं कि करीब 15 साल पहले तक उत्तर प्रदेश और बिहार में भी चुटीला की काफी मांग थी। तब स्थिति यह थी कि आपूर्ति करना मुश्किल होता था। धीरे-धीरे फैशन बदलता गया तो बालों की खूबसूरती बढ़ाने वाला चुटीला चलन से बाहर होता दिखा। मगर पंजाब और राजस्थान में महिलाएं परंपरागत रूप से इसे पसंद करती रहीं। यही वजह है कि उप्र और बिहार में मांग कम हुई तो हम लोगों ने दूसरे प्रदेशों में सप्लाई शुरू कर दी। वह कहते हैं कि यहां कई परिवार तीन पीढ़ी से इस काम में लगे हुए हैं। कमला देवी की शादी को 29 साल हो गए हैं। ससुराल में कई पीढ़ियों से यह काम हो रहा है। पहले सिर्फ सादा चुटीला बनता था। अब डिजाइनर चुटीला की मांग अधिक है। करीब दस तरह की डिजाइन बनती हैं।

चुटीले बनाने के लिए सूती धागे का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा तिरपाल और तौलिया आदि के वेस्ट मैटीरियल का भी प्रयोग होता है। इसे पानीपत और अजमेर से लाया जाता है, जहां वस्त्र उद्योग हैं। धागे बनाकर उन्हें काले रंग से रंगा जाता है। जिसके बाद चुटीले बनाने का काम होता है।

शाहजहांपुर के घंटाघर निवासी दिव्यानी खुराना चुटीला यानी परांदे से श्रृंगार करते हुए। सौजन्य : दिव्यानी

### फीलनगर लाइव...

- 22 छोटे कारखाने हैं गांव में।
- 2500 लोग इनमें करते हैं कारीगरी।
- 100 रुपये लेकर 1000 रुपये तक की बिकती है 12 पीस की एक गड्डी।
- महीने में औसतन 10 से 15 हजार रुपये की कमाई।
- एक परिवार के चार से पांच सौ चुटीले महीने में बिक जाते हैं।
- इनमें मोती, शीशे, झालर लगाने का काम अन्य श्रमिक करते हैं।

जागरण विशेष की अन्य खबरें पढ़ें
www.jagran.com/topics/jagran-special

# देविंदर के बंगले का बड़ा हिस्से गिरेगा

**राज्य ब्यूरो, श्रीनगर**

आतंकियों के साथ पकड़े गए डीएसपी देविंदर सिंह का बादामी बाग सैन्य छावनी से सटा निर्माणाधीन बंगला अब निशाने पर आ गया है। नियमों का उल्लंघन कर बनाए गए बंगले के बड़े हिस्से को गिराने की प्रशासन ने तैयारी कर ली है। संबंधित प्रशासन ने सैन्य छावनी के साथ दीवार बनाने पर चार पर कार्रवाई की थी। देविंदर सिंह ने बीते पांच माह के दौरान मकान की ऊपरी दो मंजिलों का निर्माण कराया है। 12 मरला जमीन पर निर्माणाधीन तीन मंजिला बंगले व सैन्य छावनी की चाहरदीवारी में तीन फुट की दूरी है। छावनी की सुरक्षा के लिए बनाया निगरानी बंकर दीवार के साथ ही है।

सूत्रों ने बताया कि इंदिरानगर और शिवपोरा का इलाका बादामी बाग कैंट बोर्ड के अधीन आता है। दोनों कॉलोनियां में मकान बनाने के लिए न सिर्फ श्रीनगर नगर निगम की बल्कि बादामी बाग कैंटोनमेंट बोर्ड की अनुमति लेना भी जरूरी है। पुलिस अधिकारी होने और विभिन्न आतंकरोधी अभियानों में निभाई भूमिका के चलते उसकी कई सैन्याधिकारियों के साथ मित्रता थी। इसलिए उसे यहां मकान बनाने की अनुमति मिली है। उन्होंने बताया कि देविंदर सिंह ने तीन साल पहले मकान बनाने का काम शुरू कराया था। उसने जब अनुमोदित निर्माण योजना का उल्लंघन कर मकान और सैन्य छावनी की बाहरी दीवार के बीच दूरी को नहीं रखा तो चार बार दीवार को गिराया गया। उसके मकान की दूसरी मंजिल को लेकर एतराज जताया था। कई दिनों तक काम रुका रहा है। अलबत्ता, पांच अगस्त के बाद ही उसने अपने मकान की ऊपरी दो मंजिला को तेजी से तैयार कराया है, क्योंकि इस दौरान कश्मीर में सभी संबधित एजेंसियों का ध्यान हालात सामान्य बनाए रखने पर ही रहा है। बादामी बाग कैंटोनमेंट बोर्ड के अधिकारियों ने छह माह के दौरान एक बार भी उसके द्वारा किए जा रहे निर्माण को नहीं रोका है। देविंदर सिंह के करीबी ने बताया कि सन्नतनगर में टेलीफोन एक्सचेंज के पास भी एक मकान बनवाया था। उसने यह मकान छह माह पहले बेचा था। उससे मिली रकम को उसने इसी मकान पर खर्च किया है। मकान में पेंट और फर्निशिंग बाकी रह गई थी, शेष काम पूरा हो चुका था। वह मार्च के दौरान मकान के बचे काम को पूरा कराने जा रहा था। देविंदर के निर्माणाधीन मकान से कुछ दूरी पर जम्मू-कश्मीर पुलिस के बड़े अधिकारी के मकान का निर्माण हो रहा है। उसकी बाहरी दीवार को भी कुछ समय पहले बोर्ड के अधिकारियों ने नियमों के उल्लंघन पर गिराया था। इसके बाद में वह दीवार फिर खड़ी हो गई।

### देविंदर मामले पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री खामोश क्यों हैं : राहुल

नई दिल्ली, प्रेट्र : कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को जम्मू-कश्मीर के पूर्व डीएसपी देविंदर सिंह मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की चुप्पी पर सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि कौन अधिकारी उसे सुरक्षा प्रदान कर रहा था और क्यों? पुलवामा हमले में देविंदर की क्या भूमिका थी और कितने आतंकियों की उसने मदद की? राहुल ने ट्वीट किया कि देविंदर ने तीन आतंकियों को अपने घर पर ठहराया, जिनके हाथ भारतीयों के खून से रंगे हैं और उन्हें दिल्ली ले जाते हुए पकड़ा गया। छह महीने में फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा सुनवाई की जानी चाहिए और वह दोषी पाया जाता है, तो उसे देशद्रोह के लिए कठोरतम सजा दी जानी चाहिए।

### देविंदर मामले की एनआइए करेगी जांच

**जम्मू, प्रेट्र :** केंद्रीय गृहमंत्रालय ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) को डीएसपी देविंदर सिंह के दो आतंकियों संग पकड़े जाने के मामले में जांच शुरू करने का निर्देश दिया है। देविंदर को जम्मू-कश्मीर पुलिस की विशेष टीम ने गत शनिवार को श्रीनगर जम्मू हाईवे पर दो आतंकियों और एक ओवरग्राउंड वर्कर संग पकड़ा था। वह इन लोगों को कश्मीर से बाहर पहुंचाने का प्रयास कर रहा था। संबंधित अधिकारियों ने बताया कि एनआइए को इस मामले की जांच सौंपे जाने का औपचारिक आदेश जल्द जारी किया जाएगा। इसके बाद एनआइए अपने स्तर पर एफआइआर दर्ज करेगी।

# गौरव के हत्यारोपितों ने हफ्तेभर बाद गाजियाबाद में लूटी कार !

**आयुष गंगवार, गाजियाबाद**

उप्र के गौतमबुद्ध नगर में मल्टी नेशनल कंपनी के रीजनल मैनेजर गौरव चंदेल की छह जनवरी की रात लूटपाट के बाद हत्या की कड़ी में एक मामला सामने आया है। चंदेल से लूट-हत्या की वारदात के करीब हफ्तेभर बाद बदमाशों ने उनकी ही कार का इस्तेमाल गाजियाबाद में भी लूटपाट के लिए किया। लूट की यह वारदात 14 जनवरी की रात कविनगर थाना क्षेत्र की है।

**तीन घंटे घुमाते रहे आरोपित :** अवंतिका एक्सटेंशन के अंसल एंक्लेव में रहने वाले चिराग अग्रवाल नोएडा सेक्टर-62 स्थित एमएनसी में जॉब करते हैं। चिराग के मुताबिक, वह अपनी टाटा टियागो कार से 14 जनवरी की रात घर लौट रहे थे। महरौली स्टेशन के पास पीछे से एक कार ने उनकी गाड़ी में टक्कर मारी। अंधेरे के चलते शीशे में वह गाड़ी को सही तरीके से नहीं देख पाए। चिराग के मुताबिक वह गाड़ी से निकले ही थे कि पीछे वाली कार से तीन लोग निकले और उन्हें दबोच लिया। मारपीट कर आरोपितों ने चिराग को उन्हीं की कार में अगवा कर लिया। आरोपितों ने उनसे मोबाइल, घड़ी, अंगूठी, करीब 1500 रुपये समेत पर्स लूट लिया, जिसमें डीएल व डेबिट-क्रेडिट कार्ड भी रखे थे। आरोपित उन्हें एनएच-9 व आसपास के क्षेत्र में करीब तीन घंटे घुमाते रहे और फिर रात 12 बजे शिवालिक अस्पताल के सामने उतारकर फरार हो गए। गनीमत थी कि चिराग ने आरोपितों का ज्यादा विरोध नहीं किया।

> आकाशनगर में गौरव की कार छोड़ने आए आरोपितों की सीसीटवी फुटेज मिली है। इसमें दूसरी कार दिख रही है, जो छोटी (हैचबैक) है। कुछ स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता है। सीसीटीवी फुटेज स्पष्ट कराई जा रही है।
> – कलानिधि नैथानी, एसएसपी।

**वारदात के बाद फिर खड़ी कर दी कार :** बुधवार को मसूरी थाना क्षेत्र के आकाशनगर से गौरव की कार बरामद हुई। पता चला कि बदमाश 14 जनवरी की आधी रात के करीब ही कार को यहां खड़ी कर गए। मगर एक महिला ने बताया कि यह कार पास के ही प्लॉट में दो दिन से खड़ी थी। ऐसे में साफ है कि बदमाशों ने रेकी कर गौरव की कार को आकाशनगर में खड़ा कर दिया और दो दिन बाद 14 जनवरी को गाड़ी लेकर दूसरी कार लूटी और कुछ देर बाद उसी इलाके में कुछ दूरी पर गौरव की कार खड़ी कर गए। हालांकि कार के दो दिन खड़ी रहने के बारे में पुलिस को पुख्ता साक्ष्य नहीं मिले हैं।

## पैरोल के आखिरी दिन लापता हुआ मुंबई धमाकों में सजायाफ्ता

**विशाल सिंह, मिड डे (मुंबई) :** 1992 के मुंबई सिलसिलेवार धमाकों में सजायाफ्ता मुहम्मद जालिस शफीउल्लाह अंसारी पैरोल के आखिरी दिन गुरुवार को लापता हो गया। टाडा मामले में मिली उम्रकैद के तहत वह सेंट्रल जेल अजमेर (राजस्थान) में बंद था। अग्रिपाड़ा निवासी जालिस 28 दिसंबर 2019 को 21 दिनों की पैरोल पर घर आया था। सुप्रीम कोर्ट ने पैरोल देते हुए उसे रोज अग्रिपाड़ा थाने में सुबह 10:30 से 12 बजे तक हाजिरी लगाने के निर्देश दिए थे। कोर्ट के आदेश पर वह रोजाना हाजिरी लगा रहा था। पैरोल खत्म होने के बाद उसे शुक्रवार को आर्थर रोड जेल में उपस्थित होना था।

### मौसम विशेष

दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सुबह में अधिकांश भागों में घना कोहरा छाया रहेगा। कुछ स्थानों पर गरज के साथ वर्षा संभव है। एक-दो स्थानों पर ओलावृष्टि की संभावना है। जम्मू-कश्मीर, लद्दाख व हिमाचल प्रदेश में हल्की वर्षा व बर्फबारी जारी रहेगी।

भारत के मुख्य शहरों का तापमान:

| शहर | | शहर | |
|---|---|---|---|
| मुम्बई | 28/15/आंबा | अहमदाबाद | 28/10/आंबा |
| कोलकाता | 28/15/सा | बड़ोदा | 30/16/सा |
| चेन्नई | 30/21/आंबा | नागपुर | 30/15/आंबा |
| हैदराबाद | 30/19/सा | इन्दौर | 28/15/आंबा |
| बंगलूरू | 29/16/आंबा | रांची | 26/11/सा |
| त्रिवेन्द्रम | 32/23/सा | पटना | 24/11/आंबा |
| गुवाहाटी | 24/15/आंबा | जमशेदपुर | 28/13/सा |
| गंगटोक | 05/-9/आंबा | पुणे | 31/18/आंबा |

राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शुक्रवार 17 जनवरी 2020
# आजकल
16
www.jagran.com

## दक्षिणी ध्रुव पहुंचने वाले पहले भारतीय कर्नल जितेंद्र कुमार बजाज

1989 में आज ही कर्नल जितेंद्र कुमार बजाज दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले भारतीय और पहले एशियाई व्यक्ति बने। 1988-1989 में ग्यारह सदस्यीय अंतरराष्ट्रीय टीम के बतौर सदस्य 50 दिनों में करीब 12 सौ किमी से ज्यादा की दूरी तय कर दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचे।

## केबल कार का एंड्रयू स्मिथ हलीदी ने कराया पेटेंट

1871 में आज ही अमेरिकी एंड्रयू स्मिथ हलीदी ने भाप से चलने वाले इंजन वाली केबल कार का पेटेंट कराया था। इस तारीख को केबल कार दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। पेटेंट के दो साल बाद पहली केबल कार रेल रोड स्थापित की।

## पाकीजा के साथ अमर हो गए कमाल अमरोही

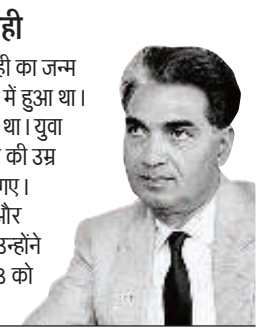

आज ही के दिन सुप्रसिद्ध निर्देशक कमाल अमरोही का जन्म 1918 में ब्रिटिश भारत के संयुक्त प्रांत के अमरोहा में हुआ था। उनका पूरा नाम सैयद आमिर हैदर कमाल नकवी था। युवा अवस्था में उन्होंने उर्दू कहानियां लिखनी शुरू की। 16 साल की उम्र में भागकर लाहौर पहुंचे। केएल सहगल के कहने पर मुंबई गए। 1949 में फिल्म महल का निर्देशन किया। 1956 में दायरा और 1972 में काफी उतार-चढ़ाव के बाद पाकीजा रिलीज हुई। उन्होंने कमालिस्तान स्टूडियो की भी स्थापना की। 11 फरवरी 1993 को मुंबई में निधन हो गया।

### इधर-उधर की

## तलवारबाजी से विवाद सुलझाने की मांग

**न्यूयॉर्क, एजेंसी :** पारिवारिक कलह और अशांति किस तरह किसी को भी तनावग्रस्त कर देती है, इसका यह एक नमूना भर है। तलाक के मामले से परेशान यहां एक शख्स ने जज से अजीबोगरीब मांग कर डाली। कंसास के डेविड ओस्ट्रोम ने पत्नी के साथ चल रहे कानूनी विवाद का निपटारा दोनों के बीच जापानी तलवार से मुकाबले के जरिये किए जाने की मांग की है। डेविड ने कोर्ट में इसे लेकर अर्जी दाखिल की है। उसका कहना है कि पत्नी ने उसे कानूनी तौर पर तबाह कर दिया है। इसलिए जज को चाहिए कि वह हमारे बीच जारी झगड़े का कानूनी रूप से लड़ाई के क्षेत्र में निपटारा करें। साथ ही उन्होंने जोड़ा कि अमेरिका में युद्ध के जरिये ट्रायल पर प्रतिबंध नहीं है। डेविड का कहना है कि वह अपनी पत्नी के वकील मैथ्यू हडसन से भी परेशान है। हालांकि जज ने डेविड के इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है।

# सीपों से भी हथियार बनाते थे निएंडरथल

- कोलराडो यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने इटैलियन गुफा में मिले सीपों के खोल का किया विश्लेषण
- कहा- इन्हें एकत्र करने के लिए प्राचीन मनुष्य बिना किसी उपकरण के महासागरों में लगाते थे गोते

**ह्यूस्टन, प्रेट्र :** प्राचीन समय में मनुष्य आखेट के लिए पत्थरों से बने हथियारों के साथ-साथ समुद्री सीपों की मदद से बनाए गए औजारों का प्रयोग भी करते थे। एक नए अध्ययन में शोधकर्ताओं ने निएंडरथल (प्राचीन मनुष्यों की एक प्रजाति) के निवास स्थलों पर मिली सीपों के विश्लेषण के आधार पर यह दावा किया है। इसमें बताया गया है कि इन हथियारों को तैयार करने के लिए निएंडरथल न सिर्फ समुद्री किनारों पर पड़ी सीप का प्रयोग करते थे, बल्कि महासागरों की तलहटी में गोता भी लगाते थे।

अमेरिका की कोलोराडो यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने इटैलियन गुफा में मिले 170 से अधिक सीप के उपकरणों का आकलन किया। वैज्ञानिकों ने इन सीपों के घर्षण के आधार पर निएंडरथल द्वारा समुद्र के किनारे वाले और पानी के अंदर से इकट्ठा किए गए सीप में साफ तौर पर अंतर देखा। इन उपकरणों का बारीकी से अध्ययन के बाद उन्होंने पाया कि लगभग तीन-चौथाई सीप अपारदर्शी थे। साथ ही, थोड़े बाहर की तरफ उभरे हुए थे, जैसे कि वर्षों तक रेत से इस पर पॉलिश की गई हो। यह बतलाता है कि इन्हें रेतीले समुद्री तट पर धोया गया था। अध्ययन में बताया गया है कि बाकी के सीप चमकदार और बाहर से बिल्कुल चिकने थे। वैज्ञानिकों के अनुसार, यह मुमकिन है कि इन सीपों को जीवित जानवरों के रूप में सीधे समुद्र की सतह से उठाकर लाया गया हो।

कोलोराडो यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता और अध्ययन के सह-लेखक पाओला विल्ला ने बताया, 'यह संभव है कि निएंडरथल समुद्र के दो से चार मीटर नीचे तक सीप इकट्ठा करने में सक्षम थे। बेशक उनके पास स्कूबा वाले उपकरण नहीं थे।'

**90 हजार वर्ष पुराने औजार :** पीएलओएस जर्नल में प्रकाशि अध्ययन में कहा गया है कि इटली के पश्चिमी तट पर स्थित ग्रोटा डे मॉस्करीनी नामक गुफा, जिसे 1930 के दशक के आखिर में खोजा गया। पुरातत्ववेत्ताओं ने 1949 में इस जगह पर दर्जनों समुद्री सीप खोजे। बाद में शोध से पता चला कि गुफा निएंडरथल का निवास स्थल थी और इन्होंने ही कई सीपों को पतले काटने वाले हथियारों के रूप में विकसित किया, जो लगभग 90 हजार वर्ष पुराने हैं।

**समुद्र से करीबी संबंध :** अध्ययन में बताया गया है कि मॉस्करीनी से 23.9 फीसद नमूने प्रत्यक्ष तौर पर निएंडरथल द्वारा समुद्र की सतह से जीवित जानवरों के रूप में इकट्ठा किए गए थे। विल्ला का कहना है कि वैज्ञानिक जितना मानते हैं, उससे कहीं अधिक इंसानों की इस प्रजाति का समुद्र से करीबी संबंध था। मौजूदा अध्ययन के निष्कर्ष के इस दावे को मजबूत करता है कि कुछ निएंडरथल कुशल तैराक भी होंगे, इसीलिए वे बिना किसी उपकरण के पानी में उतर जाते थे।

### फोटो न्यूज

## नदियों को प्लास्टिक कचरे से मुक्त कर रही नौका

प्लास्टिक कचरे से कराह रही नदियों को साफ करने के लिए मलेशिया की यह नौका महत्वत्वपूर्ण हथियार के रूप में देखी जा रही है। सौर ऊर्जा से संचालित 24 मीटर लंबी इंटरसेप्टर नाम की यह नौका नदियों से प्लास्टिक कचरे को छान लेती है। इसमें एक कन्वेयर बेल्ट लगा है जो कचरे को खींचकर एक डंपस्टर में जमा करता जाता है। यह नदी से एक दिन में 50 टन कचरा निकाल सकती है। मलेशिया ने इस वक्त यह नौका अपनी सबसे प्रदूषित कांग नदी की सफाई में लगाई गई है। अक्टूबर में कांग नदी में इंटरसेप्टर को तैनात करने के वक्त उसमें नौका चलने की स्थिति नही थी। लेकिन तीन महीने में स्थिति में काफी सुधार आया है। बता दें कि समुद्र में पहुंचने वाला 80 फीसदी कचरा नदियों के माध्यम से बहकर पहुंचता है। एएफपी

## यहां धूमपान न करने पर कर्मचारियों को मिलती है अतिरिक्त छुट्टी

**नेशनल डेस्क, नई दिल्ली :** ब्रिटेन के स्वीडन में एक कंपनी ने कर्मचारियों की धूमपान की लत छुड़ाने का एक नायाब तरीका खोज निकाला है। कंपनी की शर्त है कि यदि आप धूमपान छोड़ते हैं तो आपको चार दिन की अतिरिक्त छुट्टी दी जाएगी। नए नियम लागू होते ही कई कर्मचारियों ने इसका लाभ उठाना भी शुरू कर दिया है।

रिक्रूटमेंट एजेंसी केसीजे ट्रेनिंग एंड इंप्लॉयमेंट सॉल्यूशन के प्रबंध निदेशक डॉन ब्रायडन ने उम्मीद जताई है कि नई नीति कर्मचारियों को धूमपान की लत छोड़ने के लिए प्रेरित करेगी और इससे कंपनी को भी फायदा होगा। दरअसल, कंपनी कर्मचारियों की धूमपान की आदत से तंग आ चुकी है। काम के घंटों में कर्मचारी तलब लगने पर सिगरेट आदि पीने चले जाते थे। इससे कंपनी का काम प्रभावित हो रहा था। तमाम प्रयासों के बाद भी लोग अपनी आदत बदल नहीं रहे थे, जिसके बाद कंपनी ने एक लुभावना तरीका खोजा और कंपनी प्रबंधन ने इसे लागू कर दिया।

# समुद्री पानी से बनेगा हाइड्रोजन ईंधन

**तलाशी राह** ▶ आइआइटी मद्रास के अनुसंधानकर्ताओं ने खोजा ईको-फ्रेंडली तरीका

### ईंधन को स्टोर करने की नहीं पड़ेगी जरूरत, मांग के मुताबिक होगा उत्पादन

**नई दिल्ली, प्रेट्र :** भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइटी) मद्रास के शोधकर्ताओं ने एक ऐसी तकनीक ईजाद की है, जिससे समुद्री पानी से हाइड्रोजन ईंधन बनाया जा सकता है। इस विधि की मदद से भविष्य में स्वच्छ ईंधन बनाने का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। इसके बारे में जर्नल एसीएस स्टेनेबल केमिस्ट्री एंड इंजीनियरिंग में विस्तार से बताया गया है। शोधकर्ताओं का दावा है कि अब हमें ईंधन को स्टोर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नई तकनीक की मदद से मांग के मुताबिक हाइड्रोजन का उत्पादन किया जा सकता है। इससे भंडारण करने की चुनौतियां भी कम हो जाएंगी, क्योंकि जरा-सी असावधानी पर ईंधन के टैंक में विस्फोट होने का खतरा बना रहता है।

उन्होंने कहा कि भविष्य में हाइड्रोजन ऊर्जा का एक सबसे अच्छा स्रोत बन सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि जब हाइड्रोजन का दहन किया जाता है तो जीवाश्म ईंधन की वनिस्पत इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन नहीं होता है, जिससे यह ऊर्जा का 'स्वच्छ' स्रोत बन जाता है यानी इसका ईंधन पर्यावरण के अनुकूल होगा और ग्लोबल वार्मिंग का कारक नहीं बनेगा।

आइआइटी मद्रास के शोधकर्ताओं का यह अध्ययन जर्नल एसीएस स्टेनेबल केमिस्ट्री एंड इंजीनियरिंग में प्रकाशित हुआ है। फाइल

**हाइड्रोजन से बाइक कार चलाने का लक्ष्य :** शोधकर्ताओं का कहना है कि सड़कों पर डीजल-पेट्रोल से चलने वाले वाहनों की बढ़ती संख्या और साल-दर-साल बढ़ते तापमान को देखते हुए भविष्य में हाइड्रोजन ईंधन का ही है। आज हमारे आसपास जितनी भी मशीनें चलती हैं, ज्यादातर कार्बन का उत्सर्जन करती हैं। लेकिन, हाइड्रोजन का उपयोग बढ़ने से उत्सर्जन का काफी हद तक कम किया जा सकता है। विश्व के कई देशों में हाइड्रोजन से चलने वाली बसों का ट्रायल भी शुरू हो चुका है। वैश्विक स्तर पर वायु प्रदूषण के बढ़े हुए स्तर को देखते हुए शोधकर्ता समुद्री पानी से हाइड्रोजन पावर बनाकर कारों और बाइक को चलाने का लक्ष्य बना रहे हैं।

**इसरो और डीआरडीओ को देंगे ईंधन :** आइआइटी मद्रास के केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के अब्दुल मलिक ने कहा, 'चूंकि हाइड्रोजन का उपयोग ऑन-डिमांड के आधार पर किया जा सकता है, इसलिए हाइड्रोजन के भंडारण और परिवहन से जुड़े सुरक्षा मुद्दों से बचा जाता है। मलिक ने कहा, 'हाइड्रोजन भविष्य है। हम इसे वर्तमान बनाना चाहते हैं। मैं उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा हूं जब हमारा आविष्कार भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के रॉकेट या रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) की मिसाइलों को ईंधन देगा।'

**एक कमरे के तापमान में तैयार होगी ऊष्मा :** आइआइटी मद्रास के एसोसिएट प्रोफेसर टीजू थॉमस ने कहा कि वे वाहनों के लिए हाइड्रोजन का एक विशेष सिस्टम विकसित कर रहे हैं ताकि वैश्विक स्तर पर ऊर्जा के लिए एक समाधान पेश किया जा सके। उन्होंने कहा कि हमारा सेट अप इतना एडवांस है कि एक बटन दबाते ही यह पानी को ऊर्जा में तब्दील कर सकता है। उन्होंने कहा कि इस सेट अप की एक खासियत यह भी है कि इसके जरिये हम अपनी आवश्यकतानुसार हाइड्रोजन के उत्पादन को नियंत्रित कर सकते हैं। शोधकर्ताओं ने कहा, 'सामान्यतः बिजली तैयार करने के लिए लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस तापमान और 25 बार प्रेशर (दबाव) की जरूरत होती है। लेकिन नए सिस्टम के जरिये एक कमरे के तापमान और एक बार प्रेशर पर भी बिजली पैदा हो सकती है।

**कम होगी ग्लोबल वार्मिंग :** शोधकर्ताओं का कहना है कि नई तकनीक भविष्य में ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव लाएगी। साथ ही, ग्लोबल वार्मिंग को भी कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। क्योंकि पेट्रो वाहनों से निकलने वाला हुआ इसका सबसे बड़ा कारक है।

### ऐसे तैयार होती है हाइड्रोजन

आइआइटी मद्रास के अब्दुल मलिक ने कहा, 'हम कॉफी मशीन की तरह ही एक मशीन बनाना चाहते थे, जिसमें बटन दबाते ही हाइड्रोजन का उत्पादन हो सके। नई मशीन को हमने दो भागों में विभक्त किया गया है। एक कंपार्टमेंट में पानी डालने पर जब वह बहते हुए दूसरे कंपार्टमेंट तक पहुंचता है तो इस दौरान इसमें लगी सामग्री में घर्षण और केमिकल रिएक्शन से हाइड्रोजन उत्पादन होता है।'

## कम वसा वाला दूध पीने से दूर रहेगा बुढ़ापा

### शोध अनुसंधान

अगर आप बुढ़ापे को दूर रखना चाहते हैं तो अभी से कम वसा वाला दूध पीना शुरू कर दीजिए। एक नए अध्ययन में इस तरह के दूध के सेवन का संबंध बुढ़ापे की रफ्तार धीमी होने से पाया गया है। यह अध्ययन मौजूदा खानपान संबंधी उस दिशा-निर्देश का भी समर्थन करता है, जिसमें उच्च वसा युक्त दूध पीने की सलाह नहीं दी गई है।

ऑक्सीडेटिव मेडिसिन एंड सेल्युलर लांगविटी जर्नल में छपे अध्ययन के अनुसार, 5,834 वयस्कों पर किए गए एक शोध के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया है। उच्च वसायुक्त दूध पीने वाले प्रतिभागियों की तुलना में निम्न वसायुक्त दूध पीने वाले लोगों में बुढ़ापा आने की गति धीमी पाई गई। अमेरिका की ब्रिघम यंग यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता लारी टकर ने कहा, 'अगर आप उच्च वसायुक्त दूध का सेवन करने जा रहे हैं तो इसके परिणाम से भी अवगत हो जाना चाहिए। यदि जल्दी बूढ़ा नहीं होना चाहते तो कम वसा वाला दूध पीजिए' -प्रेट्र

### ट्यूमर में ही दिखी कैंसर से मुकाबले की नई उम्मीद

शोधकर्ताओं ने ट्यूटर में गहराई में छुपी ऐसी 'फैक्ट्री' की पहचान की है, जो इम्यून सेल्स (प्रतिरक्षा कोशिकाएं) से भरी होती हैं। ये सेल्स कैंसर से मुकाबले में मदद करती हैं। इससे कई कैंसर रोगियों को भी उबरने में मदद मिल सकती है। हाल के वर्षों में डॉक्टरों ने कैंसर के नए उपचार के तौर पर इम्यूनोथेरेपी का रुख किया है। शोधकर्ताओं का दावा है कि यह थेरेपी ट्यूमर से मुकाबले में शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली के बल पर काम करती है और कैंसर कोशिकाओं से लड़ती है।

पेरिस डेसकोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेडिकल स्कूल के शोधकर्ताओं ने नई विधि में खासतौर पर टी-सेल्स नामक श्वेत रक्त कोशिकाओं पर ध्यान दिया गया है। इन कोशिकाओं को कैंसर सेल्स पर हमले के लिए प्रेरित किया जाता है। यह नया उपचार हालांकि महज 20 फीसद रोगियों पर ही कारगर हो पाता है। नेचर जर्नल में प्रकाशित अध्ययन में कुछ ट्यूमर में ऐसी संरचना की पहचान की गई, जो प्रतिरक्षा कोशिकाओं के लिहाज से 'फैक्ट्री या स्कूल' की तरह काम करती है। इससे कैंसर से मुकाबले में मदद मिल सकती है। शोधकर्ताओं ने कहा कि भले ही यह तकनीक कुछ ही रोगियों पर काम करती हो पर कैंसर जैसी घातक बीमारियों से बचा जरूर सकती है। -प्रेट्र

### फिल्म रिव्यू

**1917**

**निर्देशन :** सैम मेंडिस
**प्रमुख कलाकार :** जॉर्ज मैके और डीन-चार्ल्स चैपमैन, मार्क स्ट्रांग
**अवधि :** 2 घंटे 2 मिनट

### युद्ध की विभीषिका के परिणाम

फिल्म '1917' को इस साल ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म, निर्देशक, समेत दस श्रेणी में नामांकित किया गया है। प्रथम विश्व युद्ध के दौर की कहानी वाली इस फिल्म के निर्देशक और सहलेखक सैम मेंडिस हैं। सैम मेंडिस अपनी पहली फिल्म 'अमेरिकन ब्यूटी' के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीत चुके हैं। वह जेम्स बांड सीरीज की आखिरी दो फिल्में 'स्काईफॉल' और 'स्पेक्टर' बना चुके हैं। इस बार उन्होंने प्रथम विश्वयुद्ध के दौर की कहानी गढ़ी है। उन्होंने यह फिल्म अपने दादा को समर्पित की है, जिन्होंने उन्हें युद्ध की कहानियां सुनाई थीं। उनके दादा ने युद्ध में हिस्सा लिया था।

फिल्म की शुरुआत छह अप्रैल, 1917 को उत्तरी फ्रांस में तैनात दो ब्रिटिश सैनिकों विलियम स्कॉफील्ड (जॉर्ज मैके) और टॉम ब्लेक (डीन चार्ल्स चैपमैन) से आरंभ होती है, जिन्हें एक अन्य बटालियन को जरूरी पत्र पहुंचाने का आदेश दिया जाता है। पत्र में बटालियन को एक हमले को रोकने का आदेश है। दरअसल, जर्मनी ने कई महीनों से जाल बिछाया था, जिसके तहत अगर यह बटालियन हमला करती तो 1600 सैनिकों की जान चली जाती। नरसंहार को रोकने और जल्द पहुंचने के लिए दोनों सैनिक दुश्मन के इलाके से गुजरते हुए आगे बढ़ते हैं। 'ब्लेक' को इसलिए भी जल्दी पहुंचना है, क्योंकि उसका बड़ा भाई भी उसी बटालियन में तैनात है, जिन्हें हमले को अंजाम देना है। इस रास्ते में युद्ध की विभीषिका के परिणामों को बहुत संवेदनशीलता और संजीदगी से लेखक-निर्देशक दिखाते हुए आगे बढ़ते हैं। राइफल और सैन्य सामान से लैस दोनों सैनिक गीली मिट्टी, कंकरीले, ऊबड़-खाबड़ रास्ते, वहां पर बिखरी सैनिकों और जानवरों की दुर्गंध देती लाशें, उन्हें नोचकर खाते कौव्वे जैसे मंजरों के बीच सैनिकों की निजी जिंदगी के कुछ पहलू सामने आते हैं। रास्ते में वीरान पड़े बंकरों में दुश्मनों के बिछाए जाल से जूझते सैनिक मंजिल की ओर बढ़ रहे होते हैं कि इस बीच दुश्मनों के हमले में ब्लेक शहीद हो जाता है। उसकी मौत से व्यथित स्कॉफील्ड अकेले ही उस खत को पहुंचाने का बीड़ा उठाता है। इस सफर में सैनिकों के साथ कैमरा उनका तीसरा साथी जैसा बन जाता है। लगता है जैसे फिल्म को एक टेक में ही शूट किया गया हो।

फिल्म का चुस्त स्क्रीनप्ले व कसी पटकथा 1917 के सफर में बांध कर रखती है। रॉजर डीकिन्स की सिनेमैटोग्राफी लाजवाब है। साउंड वर्क, विजुअल इफेक्ट्स और ली स्मिथ की एडीटिंग भी काबिलेतारीफ है।

फिल्म युद्ध के परिणामों, उसके भुक्तभोगियों की मनोदशा, सैनिकों के जज्बात को भी उकेरती है। पानी में तैरती लाशों के ऊपर से सैनिक का निकलना और फफक कर रोने का दृश्य हृदयविदायक है। फिल्म की खासियत यह है कि इसमें कम पात्र हैं और डायलॉग भी ज्यादा नहीं हैं। इसके बावजूद सैनिक के साहस, समय पर पहुंचने का जुनून और मेडल को लेकर उसके दृष्टिकोण जैसे पहलुओं को बहुत बारीकी से लेखक और निर्देशक ने कहानी में पिरोया है। स्कॉफील्ड और ब्लेक के रूप में जॉर्ज मैके और डीन-चार्ल्स चैपमैन की कास्टिंग बेहतरीन है। उन्होंने सैनिकों की मनोदशा का चित्रण सहजता से किया है। बाकी कलाकारों की भूमिका संक्षिप्त है, लेकिन संवाद दमदार हैं। फिल्म का संगीत बेहद प्रभावी है।

**स्मिता श्रीवास्तव**

★★★★★ उत्कृष्ट ★★★★ बहुत अच्छी ★★★ अच्छी ★★ औसत ★ औसत से कम

### स्क्रीन शॉट

## ...जब लंदन में सहम गईं सोनम कपूर

सोनम कपूर के लिए लंदन में उबर कैब से सफर करना काफी डरावना साबित हुआ है। इसकी जानकारी सोनम ने सोशल मीडिया पर दी, जिसके बाद उनके फैंस उनका हालचाल पूछने लगे। सोनम कपूर इन दिनों लंदन में हैं। सोनम ने जो ट्वीट किया है, उसके मुताबिक उन्होंने लंदन में उबर कैब की थी, जिसके ड्राइवर ने उनके साथ ऐसा बर्ताव किया, जिससे वह सहम गई थीं। सोनम ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'लंदन के उबर में मुझे एक डरावना अनुभव हुआ है। आप भी सावधान रहें। अच्छा यही होगा कि आप अपनी सुरक्षा के लिए लोकल पब्लिक ट्रांसपोर्ट और पब्लिक कैब का ही इस्तेमाल करें। मैं इस वक्त सहमी हुई हूं।' सोनम के इस ट्वीट के बाद यूजर्स ने उनसे पूरे घटनाक्रम की जानकारी लेनी चाही। सोनम ने बताया कि लंदन में उन्होंने कहीं जाने के लिए कैब मंगवाई थी। जब वह कैब में बैठीं, तब उन्हें कैब का ड्राइवर थोड़ा अस्थिर लगा। वह उन पर चिल्लाने लगा। ड्राइवर के जोर-जोर से चिल्लाने की वजह से सोनम कूपर डर गईं। इस पर उबर ने सोनम को जवाब देते हुए लिखा, 'हमें यह सुनकर खेद हुआ। क्या आप अपना मोबाइल नंबर और इमेल आइडी मैसेज कर सकती हैं।' इस पर सोनम ने लिखा, 'आपको अपने ऐप को अपग्रेड करने की जरूरत है। वहां पर मैंने शिकायत दर्ज करने की कोशिश की थी। जो होना था, हो गया है, अब कुछ नहीं किया जा सकता है।' जिसके बाद सोनम के फैंस ट्विटर पर लगातार उनका हालचाल लेते रहे।

## फिर एक साथ होंगे प्रियंका चोपड़ा और जोनास

हिंदी सिनेमा की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा जोनास और निक जोनास की जोड़ी सबसे चर्चित जोड़ियों में से एक हैं। दोनों जल्द ही जोनास ब्रदर्स के म्यूजिक वीडियो 'व्हाट अ मैन गॉटा डू' में एक बार फिर साथ दिखेंगे। इससे पहले प्रियंका और निक जोनास ब्रदर्स के ही गाने 'सकर' में नजर आ चुके हैं। इस गाने में तीनों जोनास भाई केविन, जो और निक ने अपनी पत्नियों के साथ काम किया था। प्रियंका और निक ने इस म्यूजिक वीडियो का पोस्टर अपने सोशल मीडिया पर साझा किया। पोस्टर में निक और प्रियंका बहुत ही रोमांटिक अंदाज में नजर आ रहे हैं। पोस्टर के साथ प्रियंका ने निक और जोनास भाइयों को टैग करते हुए लिखा, 'मैं रिस्की हूं, वह बिजनेस हैं।' 'व्हाट अ मैन गॉटा डू' जल्द आ रहा है।' यह म्यूजिक वीडियो आज (शुक्रवार को) रिलीज होगा। पोस्टर देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह म्यूजिक वीडियो साल 1983 में बनी टॉम क्रूज अभिनीत हॉलीवुड फिल्म 'रिस्की बिजनेस' से प्रेरित है। प्रियंका ने हाल ही में सोशल मीडिया पर ही रूसो ब्रदर्स के साथ वेब सीरीज 'सिटाडेल' में काम करने की जानकारी दी थी।

## कंगना रनोट ने किया साफ, खुद पर अभी फिल्म नहीं बनाएंगी

'मणिकर्णिका : द क्वीन ऑफ झांसी' और तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की बायोपिक 'थलाइवी' फिल्म करने वाली कंगना रनोट ने कुछ समय पहले कहा था कि वह खुद पर फिल्म बनाना चाहती हैं। अपनी बायोपिक का निर्देशन भी वही करना चाहती थीं। खबरें थीं कि उनकी बायोपिक की स्क्रिप्ट लेखक केवी विजयेंद्र प्रसाद लिखेंगे, लेकिन अब कंगना ने बताया कि फिलहाल वह खुद पर आधारित फिल्म नहीं बना रही हैं। अपनी फिल्म 'पंगा' के प्रमोशन में व्यस्त कंगना ने बताया कि खुद पर फिल्म बनाना अभी जल्दबाजी होगी। इसलिए वह इस पर अभी नहीं सोच रही हैं। कगंना 'पंगा' फिल्म की रिलीज के बाद अपनी फिल्म 'अपराजित अयोध्या' में व्यस्त हो जाएंगी। इस फिल्म से कंगना रनोट निर्माता बनने वाली हैं। 'अपराजित अयोध्या' राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद पर आए फैसले पर आधारित होगी। फिल्म की स्क्रिप्ट के वी विजयेंद्र प्रसाद ही लिखेंगे। इस फिल्म से कंगना बतौर निर्माता ही जुड़ी रहेंगी। वह फिल्म में अभिनय नहीं करेंगी।

## सिद्धार्थ मल्होत्रा के जन्मदिन पर 'शेरशाह' का तोहफा

अपने 35वें जन्मदिन के पर सिद्धार्थ मल्होत्रा ने अपनी आगामी फिल्म 'शेरशाह' के तीन पोस्टर जारी किए हैं। फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा वर्ष 1999 में हुए कारगिल युद्ध के दौरान शहीद हुए कैप्टन विक्रम बत्रा का किरदार निभा रहे हैं। फिल्म में सिद्धार्थ डबल रोल में नजर आएंगे। सिद्धार्थ ने सोशल मीडिया पर फिल्म की पहली झलक साझा करते हुए लिखा, 'बहादुरी और त्याग के अलग-अलग रंगों को बड़े पर्दे पर उकेरना मेरे लिए सम्मान की बात है।' फिल्म का निर्देशन विष्णुवर्धन ने किया है। फिल्म के निर्माता करण जौहर ने भी पोस्टर साझा करते हुए लिखा, 'कारगिल युद्ध के हीरो के सम्मान में हम अपना सिर झुकाते हैं। इस फिल्म के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। पेश है कैप्टन विक्रम बत्रा की अनकही सच्ची कहानी शेरशाह।' कैप्टन विक्रम बत्रा का कोड नाम शेरशाह था।

फिल्म में कियारा आडवाणी विक्रम बत्रा की मंगेतर का किरदार निभाएंगी। 'शेरशाह' 3 जुलाई को रिलीज होगी।

## कश्मीरी पंडितों के लिए 'शिकारा' की स्पेशल स्क्रीनिंग...

वास्तविक घटनाओं पर बन रही फिल्मों में 'शिकारा' फिल्म भी शामिल है। यह फिल्म तीस साल पहले कश्मीर में कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार की कहानी बयां करेगी। 19 जनवरी 1990 को कई कश्मीरी पंडितों को उनके घर से बेघर कर दिया गया था। इस घटना के तीस साल पूरे होने पर फिल्म के निर्माता-निर्देशक विधु विनोद चोपड़ा इस पलायन के पीड़ित कश्मीरी पंडितों के लिए फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग रखेंगे। फिल्म को वास्तविकता के करीब रखने के लिए उस वक्त के कई वास्तविक विजुअल्स का इस्तेमाल भी फिल्म में किया गया है। साथ ही चार हजार कश्मीरी पंडितों को भी फिल्म में शामिल किया गया है। 'शिकारा' फिल्म 7 फरवरी को रिलीज होगी।

## डिजिटल पर होगी वीर दास की हैट्रिक

अभिनेता वीर दास डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी स्टैंडअप कॉमेडी शो से जगह बनाए हुए हैं। नेटफ्लिक्स पर पहले ही उनके दो कॉमेडी शो 'अब्रॉड अंडरस्टैंडिंग' और 'लूजिंग इट' चल रहे हैं। हैट्रिक करते हुए अब वीर दास अपना नया स्टैंड अप कॉमेडी शो 'वीर दास : फॉर इंडिया' लेकर आ रहे हैं। वीर दास के मुताबिक, यह शो देश की संस्कृति के लिए उनका प्रेम पत्र होगा। शो में वीर दास भारतीय रीति-रिवाजों, मान्यताओं, संस्कृति, फिल्मों व कलाकारों पर बात करेंगे। वीर दास का कहना है कि हमारी विविधता ही हमारी ताकत है। हम संस्कृति और मूल्यों की वजह से एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। नया शो 26 जनवरी से शुरू होगा।